हरियाणा विधान सभा
की
कार्यवाही

22 मार्च, 2006

खण्ड 2, अंक 4

अधिकृत विवरण

विषय सूची

बुधवार, 22, मार्च 2006

	पृष्ठ संख्या
तारांकित प्रश्न एवं उत्तर	(4)1
वाक आउट	(4)1
तारांकित प्रश्न एवं उत्तर (पुनरारम्भ)	(4)2
नियम 45 (1) के अधीन सदन की मेज पर रखे गए तारांकित प्रश्नों के लिखित उत्तर	(4)63
अनुपस्थिति संबंधी सूचना	(4)65
वर्ष 2006-07 के बजट अनुमानों पर सामान्य चर्चा	(4)65
वाक आउट	(4)104
वर्ष 2006-07 के बजट अनुमानों पर सामान्य चर्चा (पुनरारम्भ)	(4)105
बैठक का समय बढ़ाना	(4)106
वर्ष 2006-07 के बजट अनुमानों पर सामान्य चर्चा (पुनरारम्भ)	(4)107
बैठक का समय बढ़ाना	(4)112
वर्ष 2006-07 के बजट अनुमानों पर सामान्य चर्चा (पुनरारम्भ)	(4)112
वर्ष 2005-06 के बजट अनुदानों की माँगों पर चर्चा तथा मतदान	(4)116
वर्ष 2006-07 के बजट अनुदानों की माँगों पर चर्चा तथा मतदान	(4)120
बैठक का समय बढ़ाना	(4)124
वर्ष 2006-07 के बजट अनुदानों की माँगों पर चर्चा तथा मतदान (पुनरारम्भ)	(4)124

मूल्य : 115

HUS/Lib/11

हरियाणा विधान सभा

बुधवार, 22 मार्च, 2006

विधान सभा की बैठक, हरियाणा विधान सभा हाल, विधान भवन, सैक्टर-1, चण्डीगढ़ में सुबह 9.30 बजे हुई। अध्यक्ष (डॉ० रघुवीर सिंह कादियान) ने अध्यक्षता की।

तारांकित प्रश्न एवं उत्तर

Mr. Speaker : Hon'ble Members, now the Questions Hour.

Development of Residential Sectors in Cities and Town by HUDA

*** 347. Sh. Karan Singh Dalal :** Will the Chief Minister be pleased to state—

whether there is any proposal under consideration of the Haryana Urban Development Authority to develop residential sectors in Cities and Towns in the State where such residential sectors have not been developed so far, if so, the details thereof along with the names of Cities and Towns where such sectors are to be developed ?

वाक आउट

श्री रणदीप सिंह सुरजेवाला : डॉ० साहब अब आप अपने कान पकड़े लें क्योंकि मैं सवाल का जवाब देने लग रहा हूँ।

डॉ० सुशील इन्दौरा : अध्यक्ष महोदय, माननीय मंत्री जी अशोभनीय भाषा का इस्तेमाल करते हैं। इनको इस तरह का बिहेव नहीं करना चाहिए।

श्री बलवन्त सिंह : अध्यक्ष महोदय, मंत्री जी को इस तरह से नहीं बोलना चाहिए। ये एक गरिमामय पद पर हैं इनको इस बात का ध्यान रखना चाहिए।

डॉ० सीता राम : अध्यक्ष महोदय, इनको इस तरह से नहीं बोलना चाहिए।

श्री अध्यक्ष : आप सभी बैठ जाएं। (शोर)

डॉ० सीता राम : अध्यक्ष महोदय, हम आपसे यही कह रहे हैं कि इनको इस तरह से नहीं बोलना चाहिए।

श्री अध्यक्ष : डॉक्टर साहब, आप सीजन्ड पार्लिमैंटेरियन हैं। (शोर एवं व्यवधान) आपको इस तरह से नहीं बोलना चाहिए। इस तरह से आप सदन का समय खराब न करें। (शोर एवं व्यवधान)

डॉ० सीता राम : सर, आप उनको कहें कि वे इस तरह से बिहेव न करें। (शोर)

Mr. Speaker : Dr. Sahib, You are a seasoned Parliamentarian. This is not the way.

डॉ० सीता राम : सर, मंत्री जी बिहेव ऐसा कर रहे हैं। आप उनको ऐसा करने से रोकें।

Mr. Speaker : I warn you Dr. Sita Ram. Please sit down.

डॉ० सीता राम : अध्यक्ष महोदय, आप उनको प्रोटैक्शन न दें।

Mr. Speaker : I warn you Dr. Sita Ram. No protection is given at all. You should amend your behaviour. (Interruptions)

डॉ० सीता राम : अध्यक्ष महोदय, मंत्री जी इस तरह की बातें करते हैं, उनका हमारे प्रति बिहेवियर ठीक नहीं है। चूंकि इनका नाम बोलकर रिपोर्ट के विवरण में आया है। हम इनको सुनना नहीं चाहते इसलिए हम इसके विरोध में सदन से वाक-आउट करते हैं।

(इस समय सदन में उपस्थित इण्डियन नैशनल लोकदल के सभी सदस्य सदन से वाक-आऊट कर गए।)

तारांकित प्रश्न एवं उत्तर (पुनरारम्भ)

Transport Minister (Sh. Randeep Singh Surjewala) : Yes, Sir. The land for development of residential sectors in the Urban Estate of Jhajjar and Pataudi has been recently acquired.

श्री कर्ण सिंह दलाल : अध्यक्ष महोदय, मैं आपके माध्यम से माननीय मंत्री जी का धन्यवाद करता हूँ कि इन्होंने सवाल के जवाब में झज्जर और पटौदी जैसे शहरों में अर्बन स्टेट के माध्यम से रैजीडैंशियल कालोनिज बना रहे हैं। क्या मंत्री जी झज्जर और पटौदी की तर्ज पर दूसरे छोटे शहरों में भी इन्कवायरी करवाकर हाऊसिंग कालोनिज बनाने का कष्ट करेंगे। अध्यक्ष महोदय, मैं आपके माध्यम से माननीय मंत्री जी को बताना चाहूँगा कि उन छोटे-छोटे शहरों में अन-डवैल्पमैंट की वजह से वहां के लोग बड़े-बड़े शहरों की ओर पलायन करने लग गए हैं जिससे उन छोटे शहरों में बहुत दिक्कत आ रही है। अध्यक्ष महोदय, आप भी अच्छी तरह से जानते हैं पिछली सरकार ने अपना ध्यान सिर्फ फरीदाबाद और गुड़गांव की तरफ ही लगाया हुआ था जिसकी वजह से छोटे शहरों का विकास नहीं हो सका था। क्या मंत्री जी बाकी के छोटे शहरों में रिहायशी कालोनिज इस पर्टिकुलर अथौरिटी के तहत बनाकर वहां पर विकास करने पर विचार करेंगे। अगर ऐसा ये कर रहे हैं तो उन शहरों का भी नाम ये बता दें।

श्री रणदीप सिंह सुरजेवाला : अध्यक्ष महोदय, माननीय साथी ने बहुत ही सही सवाल उठाया है। माननीय मुख्यमंत्री चौधरी भूपेन्द्र हुड्डा जी द्वारा इस एक वर्ष में जो प्रयास किए हैं मैं उनके बारे में बता देता हूँ। इनकी कोशिश है कि लोग छोटे शहरों और कस्बों में अच्छी तरह से बस सकें। झज्जर में सैक्टर 6 और 9 में कालोनिज का निर्माण होगा और पटौदी में भी 242.79 एकड़ जमीन एक्वायर करके वहां पर रिहायशी कालोनी बनाई जाएगी। इसी तरह से हुड्डा द्वारा कैथल, पुण्डरी,

लाडवा, असंध, तरावड़ी, चरखीदादरी, नरवाना और सफीदों में जहां पर आबादी बढ़ गई है वहां पर भी रिहायशी कालोनिज बनाने के बारे में कार्यवाही की जा रही है।

श्री कर्ण सिंह दलाल : अध्यक्ष महोदय, चूंकि पिछले कुछ सालों में जमीनों की कीमतें बहुत ज्यादा बढ़ी हैं जिसके कारण आम आदमी को रिहायशी प्लाट खरीदने के लिए बहुत ही ज्यादा खर्च झेलना पड़ता है। जिस तरह से हाउसिंग बोर्ड मल्टी स्टोरीज फ्लैटस बनाकर वहां के एरियाज में स्कूल, डिसपैंसरी, पार्क और कम्यूनिटी सैंटर्ज बनाकर देता है तो क्या मंत्री जी और मुख्यमंत्री जी तमाम हरियाणा के अंदर रिहायशी इलाकों की कीमतें कम करने के बारे कोई ऐसी योजना पर विचार करेंगे जिससे हरियाणा के लोगों को, छोटे कर्मचारियों को, छोटे दुकानदारों को या बढ़ते हुए परिवारों के सभी सदस्यों को कम कीमत पर रिहायशी प्लाट तमाम हरियाणा में उपलब्ध हो सकें? स्पीकर सर, जहां पर सरकार जमीनें एक्वायर करती है वहां पर इनका कंट्रोल्ड एरिया बनाते हैं, उनके जोनिंग प्लान तैयार करते हैं। इस तरह के सैक्टर्ज में अच्छे तरीके से पार्क्स भी हों, स्कूल्ज भी हों, डिसपैंसरीज भी हों यानी सब चीजों का इंतजाम हो तो बहुत अच्छा रहेगा। अध्यक्ष महोदय, जो प्राईवेट कालोनाइजर्ज को लाइसैंस देते हैं तो उनके लिए भी ये बातें सरकार को अनिवार्य करनी चाहिए और उनको इसके लिए बाध्य करना चाहिए। क्या सरकार इस बारे में अपने नियमों में बदलाव करने पर विचार करेगी कि ये प्राईवेट कालोनाइजर्ज भी लोगों की सहूलियतों के लिए अच्छे पार्क, डिस्पैंसरी या स्कूल बगैरा बनाएंगे? मैं यही बात उनसे जानना चाहता हूँ।

श्री रणदीप सिंह सुरजेवाला : अध्यक्ष महोदय, माननीय सदस्य ने बड़ी रैलेवैण्ट सप्लीमैंट्री पूछी है कि समाज का ऐसा हिस्सा जो मध्यम वर्गीय या गरीब परिवारों से संबंधित है और जो शहर की सुविधा या तरक्की के अंदर हिस्सा चाहता है, उनके लिए भी क्या सरकार कोई कार्य करेगी। मैं आपके माध्यम से पूरे सदन को और माननीय सदस्य को बताना चाहता हूँ कि चौधरी भूपेन्द्र सिंह हुड्डा जी के नेतृत्व में इस सरकार के गठन के बाद स्वयं मुख्यमंत्री महोदय ने इंटरवीन करके यह फैसला किया है कि इकोनोमिकली वीकर सैक्शन के लिए जो पहले एक पोलिसी बीस परसैंट प्लाट्स रिजर्व रखने की थी परन्तु पिछले 6 वर्षों में इस पोलिसी को कहीं पर भी फॉलो नहीं किया जा रहा था। लेकिन अब सरकार ने निर्णय लिया है कि जो जमीनें हुडा रिहायशी सैक्टर के लिए एक्वायर करेगा उसमें से 35 परसैंट इकोनोमिकली वीकर सैक्शन के लिए आरक्षित किया जाएगा। स्पीकर सर, सरकार ने यह भी फैसला किया है कि इस 35 परसैंट में से 50 प्रतिशत हिस्सा हाऊसिंग बोर्ड को ट्रांसफर कर दिया जाएगा ताकि वे छोटे-छोटे मकान, छोटे-छोटे फ्लैटस बनाकर जो समाज का गरीब वर्ग और मध्यम वर्गीय वर्ग है जिसकी पहुंच से सम्पत्ति बाहर हो गई है इसलिए वह वहां तक नहीं पहुंच सकता लेकिन वह प्रदेश की तरक्की में भागीदार बनना चाहता है, उसको दिए जाएं और बाकी 50 प्रतिशत में हुडा के प्लाट्स आएंगे। स्पीकर सर, मैं यह भी बताना चाहूँगा कि हमारी सरकार ने जिस नयी रिजर्वेशन नीति का फैसला किया है उसके तहत शिड्यूल कास्टस, शिड्यूल ट्राईब्ज और ई०डब्ल्यू०एस० के लिए 4 और 6 मरले के प्लाट्स में 15 प्रतिशत की रिजर्वेशन की है और अप टू 3 मरले में बीस प्रतिशत की रिजर्वेशन की है। इसी तरह से बैकवर्ड क्लासिज के लिए चार और 6 मरले के प्लाट्स में तीन प्रतिशत का आरक्षण किया गया है। ई०डब्ल्यू०एस० में पांच प्रतिशत का आरक्षण रखा गया है। वार विडोज और डिसऐबल्ड सोल्जर्ज जोकि हमारे देश के सिपाही रहे हैं, उनके लिए तीन प्रतिशत का आरक्षण चार और 6 मरले के प्लाट्स में रखा गया है और पांच प्रतिशत आरक्षण अप टू 3 मरले के लिए रखा गया है। अंदर दैन वार विडोज के लिए दो-दो प्रतिशत आरक्षण तीन मरले, चार मरले और 6 मरले के प्लाट्स में किया गया है। इसी तरह से फ्रीडम फाइटर्ज और उनके बच्चों के लिए तथा उनके पोतों के

[श्री रणदीप सिंह सुरजेवाला]

लिए दो परसैंट आरक्षण दोनों कैटेगरीज में किया गया है। हैंडीकैप्ट और ब्लाईड्स के लिए दो-दो प्रतिशत आरक्षण दोनों कैटेगरीज में किया गया है। स्पीकर सर, हरियाणा सरकार के इम्प्लाइज के लिए और उसके बोर्ड और कोरपोरेशंज के इम्प्लाइज के लिए भी दस-दस प्रतिशत आरक्षण दोनों कैटेगरीज में किया गया है। डिफैंस पर्सोनल, एक्स सर्विसमैन और पैरा मिलीटैरी फोर्सिज के लिए भी दस-दस प्रतिशत आरक्षण किया है। लीगली हीयर और उनके डिपेण्डैंटस को तथा पुलिस पर्सोनल जो एक्शन में मारे गये उनके आश्रितों को भी दो-दो प्रतिशत आरक्षण दोनों कैटेगरीज में किया है। स्पीकर सर, हरियाणा सरकार ने पहली बार यह फैसला किया है कि हम डिफैंस सैक्टर भी काटेंगे। जो हमारे देश की रक्षा करने वाले फौजी हैं उनके लिए सरकार ने यह फैसला किया है कि झज्जर, रेवाड़ी, रोहतक और जीन्द में डिफैंस सैक्टर काटे जायेंगे। माननीय स्पीकर महोदय, माननीय सदस्य के विधान सभा क्षेत्र में भी सैक्टर 12 में रेजीडैंशियल और सैक्टर 21 में ट्रांसपोर्ट नगर बनाने का मामला सरकार के विचाराधीन है, आशा है कि यह काम जल्दी ही पूरा किया जायेगा।

श्री महेन्द्र प्रताप सिंह : अध्यक्ष महोदय, सरकार विभिन्न सिटीज को सुधारना चाहती है। अभी माननीय मंत्री जी ने कहा कि विभिन्न वर्गों के लिए हुडा के प्लाट्स में रिजर्वेशन भी की है। जैसा कि भाई दलाल साहब ने फरमाया कि हुडा बड़े शहरों की तरफ ज्यादा ध्यान दे रहा है। उनकी यह बात सही है। इसके बारे में मैं विशेष तौर पर कहना चाहता हूं कि छोटे शहरों की तरफ और छोटे कस्बों की तरफ भी सरकार को ज्यादा ध्यान देना चाहिए और यह उचित भी है। अध्यक्ष महोदय, यह भी स्वाभाविक है कि गुड़गांव और फरीदाबाद दोनों शहर दिल्ली के साथ सटे होने के कारण वहां पर इण्डस्ट्रियल एरिया है इसलिए मेरा अनुरोध है कि इन शहरों में रेजीडैंशियल जौन की तरफ भी विशेष ध्यान देने की जरूरत है। लेकिन इसके बारे में मैं एक बात विशेष तौर पर कहना चाहूँगा कि पिछले दिनों गुड़गांव और फरीदाबाद में काफी ज्यादा संख्या में अन-अथोराइज्ड कालोनिज डिवैल्प हुई हैं जिसके कारण इन शहरों का स्वरूप बिगड़ा है। इसका एक सबसे बड़ा कारण यह भी है कि आवश्यकता के मुताबिक चाहे कोई भी एजेंसी हो, उन्होंने सैक्टरों को डिवैल्प नहीं किया है। इसी के परिणामस्वरूप प्रोपर्टी डीलर्ज ने वहां पर जमीन खरीदकर अन-अथोराइज्ड कालोनियां बनाकर उस जमीन को डिवैल्प कर दिया। लेकिन जो छोटे वर्ग हैं जिनको 100 गज और 150 गज के प्लाट चाहिए थे उसकी पूर्ति के लिए कोई कार्य नहीं किया गया। अगर हुडा के माध्यम से सरकार ऐसे छोटे-छोटे प्लाट्स डिवैल्प कर देती तो ऐसी स्थिति पैदा नहीं होती। मैं आपके माध्यम से मंत्री जी से पूछना चाहता हूँ कि क्या सरकार की छोटे प्लाट्स और छोटी कालोनियां काटने की कोई नीति है? चाहे यह नीति हाउसिंग बोर्ड के माध्यम से हो या चाहे छोटी-छोटी एजेन्सियों के माध्यम से हो लेकिन इस बारे में नीति जरूर होनी चाहिए तभी इस समस्या का समाधान हो सकता है। दूसरी बात यह है कि छोटे-छोटे कस्बों और शहरों में आबादी का बहुत तेजी से बढ़ाव हो रहा है इसका कारण शहरों में मिलने वाली सुविधाओं का अट्रैक्शन है। क्या बड़े गांवों में जो शहर और कस्बों के नजदीक हैं, उनमें भी सैक्टर काटने की सरकार की कोई योजना है? तीसरी बात मैं यह कहना चाहता हूँ कि जब किसी किसान की जमीन सरकार द्वारा एक्वायर की जाती है तो क्या हर खाताबाईज किसानों को उनकी एक्वायर हुई जमीन की मात्रा के हिसाब से सरकार प्लाट देने पर विचार करेगी। क्या ऐसी कोई सरकार की योजना है?

श्री रणदीप सिंह सुरजेवाला : स्पीकर सर, मैं आपकी अनुमति से माननीय सदस्य को बताना चाहता हूँ कि सरकार ने सात कैटेगरीज बनाई हैं जो इस बात की चिन्ता जाहिर करती हैं कि ऐसे

वर्ग जो बड़े साईज के प्लाट नहीं खरीद सकते क्या उनको प्लाट देंगे। सरकार ने सात छोटी कैटेगरीज बनाई हैं जिसमें 3 मरला, 4 मरला, 6 मरला, 8 मरला, 10 मरला, 14 मरला और 1 कनाल के प्लाट शामिल हैं। जिन 7 कैटेगरीज की माननीय सदस्य ने चिन्ता जाहिर की है उनको हम पूरा करेंगे। अलग-अलग वर्ग, अलग-अलग साईज के प्लाट ले सकते हैं। स्पीकर सर, माननीय सदस्य ने यह भी पूछा है कि क्या बड़े गांवों और कस्बों में शहर की तर्ज पर कालोनियां काटी जावेंगी। स्पीकर सर, जो छोटे कस्बे और शहर विकास से वंचित रह गये थे हमारा प्रयास है कि हाउसिंग बोर्ड, हुडा, दूसरी एजेंसीज और निजी क्षेत्र के लोग भी गांवों में कालोनियां डिवैल्प करें। माननीय मुख्यमंत्री जी ने भी यह चिन्ता जाहिर की है इसलिए उन्होंने हुडा को निर्देश दिए हैं कि वह गम्भीरता से इस बात का चिन्तन करें कि जिन गांवों की आबादी 10 से 15 हजार तक है क्या वहां पर हुडा, हाउसिंग बोर्ड या दूसरी एजेंसीज द्वारा कालोनियां डिवैल्प की जा सकती हैं। अगर कहीं पर यह वायबल होगा और डिमांड के मुताबिक मिलेगा तो इस पर सरकार अवश्य विचार करेगी। तीसरी बात माननीय सदस्य ने पूछी कि जो जमीन एक्वायर होती है, अध्यक्ष महोदय, आपको भी मालूम है कि पहले किसानों को 50-50 हजार रुपये प्रति एकड़ के हिसाब से मुआवजा जमीन एक्वायर होने पर दिया जाता था। हमारी सरकार ने जमीन अधिग्रहण की नई पोलिसी बनाई है जिसके तहत 15-15 लाख रुपये प्रति एकड़ के हिसाब से किसानों की जमीन एक्वायर होने पर उनको मुआवजे के तौर पर दिए हैं। यह पैसा रोहतक, झज्जर, करनाल आदि शहरों में जमीन एक्वायर होने पर दिया गया है इसके अतिरिक्त चण्डीगढ़ और दिल्ली के आसपास के एरियाज में जिन किसानों की जमीन एक्वायर हुई है उनको 25 से 30 लाख रुपये तक प्रति एकड़ के हिसाब से मुआवजा दिया गया है। मैं समझता हूँ कि यह हमारी सरकार का बहुत ही साहसिक कदम है।

श्री सुखबीर सिंह जीनपुरिया : अध्यक्ष महोदय, यह बहुत अच्छी बात है कि वीकर सैक्शन के लिए प्लाटों में रिजर्वेशन 20 प्रतिशत से बढ़ाकर 35 प्रतिशत की गई है। आपको भी मालूम है कि दूसरे प्रदेश के लोग जो थोड़े समय पहले हमारे यहां आते हैं वे भी वीकर सैक्शन के कोटे में प्लाट एप्लाई करते हैं। ये लोग 6000 रुपये में मिलने वाले प्लाट को दस लाख रुपये में से बेचकर अपने प्रदेश वापिस चले जाते हैं। मेरी मंत्री महोदय से प्रार्थना है कि इसमें हरियाणा प्रदेश के वीकर सैक्शन के लोगों को ही यह सुविधा दी जाए और इसमें हरियाणा का डोमिसाइल प्लाट भरते वक्त मांगना चाहिए ताकि बाहर के लोग इसका फायदा न उठा सकें।

श्री रणदीप सिंह सुरजेवाला : अध्यक्ष महोदय, माननीय साथी के सवाल का जवाब जो साथी कर्ण सिंह दलाल ने सवाल पूछा था उसी में आ गया है। अध्यक्ष महोदय, इसी बात की चिन्ता को ध्यान में रखते हुए हमने फैसला किया है कि वीकर सैक्शन को जो 35 प्रतिशत का रिजर्वेशन दिया जायेगा उसमें से 50 प्रतिशत हाउसिंग बोर्ड को दिया जायेगा ताकि केवल प्लाट ही न काटे जायें बल्कि छोटे-छोटे मकान हाउसिंग बोर्ड गरीब लोगों को बनाकर दे। अध्यक्ष महोदय, जहां तक संपत्ति के हस्तांतरण का सवाल है उस पर रोक नहीं लगाई जा सकती और इन कैटेगरीज में डोमीसाइल एटोमैटिक है। जैसे वार विडोज हैं या एस०सी० हैं इनसे एस०सी० का सर्टीफिकेट लिया जाता है। इस आधार पर हम इनको वंचित नहीं कर सकते कि उनके पास हरियाणा का डोमीसाइल नहीं है। जो एस०सी० का सर्टीफिकेट होता है वही काफी है। इसके अतिरिक्त आऊस्टीज के कोटे के बारे में मैं बताना चाहूँगा कि जिन आरिजनल आनर्स की लैंड एक्वायर हुई है उनके लिए हुडा की आऊस्टीज पोलिसी है। उसके तहत उनको प्लाट दिए जाएंगे।

———

Number of NGOs Registered in Haryana State

* **438. Sh. Dharam Pal Singh Malik :** Will the Chief Minister be pleased to state—

(a) the district-wise name and number of NGOs registered in the Haryana State and the grant released to them during the year 2003-04 and 2004-05; and

(b) whether any case of misappropriation in utilization of grants by these NGOs has come to notice of the Government; if so, the number thereof, together-with the action taken against them ?

Indutries Minister (Sh. Lachhman Dass Arora) : A statement is placed on the Table of the House

STATEMENT

Number of NGOs Registered in Haryana State.

(a) During the year 2003-04 and 2004-05, 3579 and 3051 societies respectively were registered under the Societies Regd. Act, 1860. The societies registered under the said Act are termed as NGOs as the NGOs are not separately registered in the Haryana State under any legislation. During the year 2003-04 and 2004-05, grant of Rs. 3.26 crore and Rs. 3.76 crore was released to 107 and 157 societies respectively by the various State departments/organisations. District-wise information in respect of number of societies registered and the name of societies to whom the grant has been released is enclosed at Annexure "A".

(b) No Sir ! No case of misappropriation in utilisation of grants in respect of NGOs to whom grant was released by the State departments/ organisations during the year 2003-04 and 2004-05 has come to the notice of the State Govt.

ANNEXURE-"A"

AMBALA

	2003-2004	2004-05
No. of Societies Registered	144	94
No. of Societies to whom grant has been released.	6	10
Total amount of grant released	5.20 Lac	9.99 Lac

Details of grant released (Amount in Lac)

Sr. No.	Name of the Society	Grant Released		Name of the organization which have released the grant
		2003-04	2004-05	
1.	Khadi Gramoudyag Samiti Milik, Naraingarh.	2.40	1.50	Department of Women & Child Development
2.	Sewahar (Society for Education Welfare, Naraingarh.	1.00	2.80	-do-
3.	Gram Sudhar Samiti, VPO Khanpur Brahmin, Tehsil. Naraingarh, Ambala.	—	1.00	-do-
4.	Ujala Welfare Society, Ambala.	0.30	0.38	Department of Rural Development.
5.	Tagore Social Welfare Charitable Society, Ambala	0.20	0.43	-do-
6.	S.D. Braille cum Tape Library, Ambala Cantt.	1.00	0.78	Department of Social Justice and Empowerment.
7.	S.D. Institue of Blind, Ambala Cantt.	0.30	0.76	-do-
8.	M.R.D. Shikhsa Samiti, Dhanana	—	0.79	Haryana Prathmik Shiksha Pariyojna Parishad.
9.	Gram Sudhar Samiti Khanpur Brahman	—	0.23	-do-
10.	Nehru Yuva Kendra	—	1.32	-do-

BHIWANI

	2003-2004	2004-05
No. of Societies Registered	186	248
No. of Societies to whom grant has been released.	7	6
Total amount of grant released	7.25 Lac	6.06 Lac

[Sh. Lachhman Dass Arora]

Details of grant released (Amount in Lac)

Sr. No.	Name of Society	Grant Released		Name of the organization which have released the grant
		2003-04	2004-05	
1.	Akhil Bhartiya Nav Yuvak Kala Sangam, Bhiwani	1.50	1.25	Department of Women & Child Development
2.	District Council for Child Welfare Bhiwani	0.10	1.10	-do-
3.	Carrier Point Education Organisation, Bhiwani	—	0.25	Department of Rural Development
4.	Adhunik Woman Welfare Organisation, Bhiwani.	—	0.25	-do-
5.	Carrier Point Education Organisation, Bhiwani.	—	0.25	-do-
6.	Adhunik Woman Welfare Organisation, Bhiwani.	3.23	—	-do-
7.	Centre for Education & Social Welfare, Vidya Nagar, Meham Road, Bhiwani.	0.44	—	Reproductive and Child Health Project.
8.	Woman, 174, Ward No. 8, Bawani Khera, Bhiwani	0.86	—	-do-
9.	Common Weal International, 365, Vikas Nagar, Bhiwani.	0.43	—	-do-
10.	Gramin Vikas Mandal Sewa Sadan, Ghikara Road, Ch.Dadri, Bhiwani.	0.69	0.23	-do-
11.	Asia Society for Enterpreneurship Education and Development, New Delhi.	—	3.96	Haryana Prathmik Shiksha Pariyojna Parishad.

FARIDABAD

	2003-2004	2004-05
No. of Societies Registered	203	276
No. of Societies to whom grant has been released.	5	10
Total amount of grant released	13.20 Lac	19.29 Lac

Details of grant released (Amount in Lac)

Sr. No.	Name of the Society	Grant Released		Name of the organization which have released the grant
		2003-04	2004-05	
1.	Ashray Bhawan, V.P.O., Barouli, District Faridabad.	—	1.21	Department of Social Justice and Empowerment
2.	District Red Cross Society	8.06	7.96	-do-
3.	National Associsation for the Blind, Faridabad.	2.10	2.22	-do-
4.	Educational cum Vocational Association for Disabled Ballabgarh	0.90	1.02	-do-
5.	Naveen Samaj Vikas Samiti, Hodel	0.81	1.62	-do-
6.	Nari Parmarath Chetna Samiti, Faridabad.	1.37	2.27	Department of Rural Development
7.	M.S.E.D.S., VPO Bisru	—	0.37	Deptt. of Schedule Caste & Backward Classes.
8.	Adi Gram Samiti, New Delhi.	—	1.05	Haryana Prathmik Shiksha Pariyojna Parishad.
9.	Y.M.C.A., Hodal	—	0.52	-do-
10.	Nehru Yuva Kendra	—	1.05	-do-

[Sh. Lachhman Dass Arora]

FATEHABAD

	2003-2004	2004-05
No. of Societies Registered	238	139
No. of Societies to whom grant has been released.	1	3
Total amount of grant released	2.51 Lac	2.51 Lac

Details of grant released (Amount in Lac)

Sr. No.	Name of the Society	Grant Released		Name of the organization which have released the grant
		2003-04	2004-05	
1.	District Council for Child Welfare, Fatehabad	2.51	2.51	Department of Social Justice and Empowerment
2.	DISHA, Sirsa	—	2.54	Haryana Prathmik Shiksha Pariyojna Parishad.
3.	Lifeline Awareness and Serving Welfare Society, Sirsa	—	2.54	-do-

GURGAON

	2003-2004	2004-05
No. of Societies Registered	136	230
No. of Societies to whom grant has been released.	14	14
Total amount of grant released	60.61 Lac	59.85 Lac

Details of grant released (Amount in Lac)

Sr. No.	Name of Society	Grant Released		Name of the organization which have released the grant
		2003-04	2004-05	
1.	District Council for Child Welfare,Gurgaon	2.51	2.51	Department of Social Justice and Empowerment Haryana

		2003-04	2004-05	
2.	Aravali Vikas Sanathan, Plot No.36-41, Udyog Nagar, Gurgaon	2.51	2.51	-do-
3.	Mahil Mandal, Singhalari, Gurgaon.	3.00	—	Department of Women & Child Development.
4.	Gram Vikas Samiti. Gurgaon.	2.00	—	-do-
5.	Adrash Rural Development	2.00	2.00	-do-
6.	Society for Services to Voluntary Agencies, 88-89, IDC, Mehroli Road, Gurgaon.	—	1.00	Reproductive & Child Health Project.
7.	Zile Bal Kalyan Parishad, Bal Udhan, Civil Lines, Gurgaon.	2.51	2.51	Department of Rural Development
8.	All India Confederation of the Blind, Vill. Behrampur, Gurgaon.	11.63	12.30	-do-
9.	Muk and Bghir Viklang Kalyan Kendra, ITI Campus, Gurgaon.	9.88	9.88	-do-
10.	Sadhbhawana Charitable Trust 174, Sector 22, Gurgaon.	6.53	5.62	-do-
11.	Khushbu Welfare Society, Sector 10-A, IOC Staff Colony, Gurgaon.	3.99	4.14	-do-
12.	S.N.S. Foundation, 88-89, IDC, Mehroli Road, Gurgaon.	0.50	0.50	Reproductive & Child Health Project.
13.	Janata Blindness Rehabilitation and Training Centre, Gurgaon.	3.48	2.99	Department of Rural Develoment
14.	Nashamukti & Pramarsh Kendra, Bal Udhan, Civil Line, Gurgaon.	7.56	7.56	-do-
15.	Street Children Arawali Vikas Sangthan, Vill. Alipur, Block Sohana, Distt. Gurgaon.	2.15	—	-do-
16.	Adi Gram Samiti, New Delhi.	—	5.28	Haryana Parathmik Shiksha Pariyojna Parishad.
17.	Mewat Talimi Society, Ferozpur-Jhirka.	—	1.05	-do-

[Sh. Lachhman Dass Arora]

HISAR

	2003-2004	2004-05
No. of Societies Registered	339	343
No. of Societies to whom grant has been released.	6	5
Total amount of grant released	13.99 Lac	10.63 Lac

Details of grant released (Amount in Lac)

Sr. No.	Name of the Society	Grant Released		Name of the organization which have released the grant
		2003-04	2004-05	
1.	Royal Foundation of India, H.No. 979, Vikas Nagar Hisar.	2.51	2.51	Department of Social Justice & Empowerment
2.	Jan Kalyan Samiti, Arya Samaj Mandir, Ward No. 2, Hisar.	2.78	2.17	-do-
3.	District Red Cross Society, Hisar.	1.40	1.40	-do-
4.	Gram Swaraj Sansthan, Hisar.	0.90	2.00	Reproductive & Child Health Project.
5.	Haryana Psycho Social Health Welfare Society, Hisar.	5.40	2.55	Department of Women & Child Development.
6.	Gram Swaraj Sansthan, Hisar.	1.00	----	-do-

JIND

	2003-2004	2004-05
No. of Societies Registered	124	169
No. of Societies to whom grant has been released.	1	3
Total amount of grant released	0.25 Lac	5.79 Lac

Details of grant released (Amount in Lac)

Sr. No.	Name of the Society	Grant Released		Name of the organization which have released the grant
		2003-04	2004-05	
1.	Rashtria Gaushala, Dharauli, Jind.	0.25	0.25	Department of Animal Husbandry, and Dairying Department.
2.	ASEED, New Delhi	—	5.28	Haryana Prathmik Shiksha Pariyojna Parishad.
3.	Gramin Shiksha Sudhar Samiti, Singhana.	—	026	-do-

JHAJJAR

	2003-2004	2004-05
No. of Societies Registered	128	139
No. of Societies to whom grant has been released.	3	5
Total amount of grant released in Lac	5.12 Lac	6.05 Lac

Details of grant released (Amount in Lac)

Sr. No.	Name of the Society	Grant Released		Name of the organization which have released the grant
		2003-04	2004-05	
1.	Kritie Charitable Society, Public Health Colony, Rohtak	2.96	2.51	Department of Social Justice and Empowerment
2.	Distt. Council for Child Welfare, Jhajjar.	—	1.21	-do-
3.	Bhartiya Kalyan Samiti Bahadurgarh.	1.81	—	Department of SC/BC, Haryana.

[Sh. Lachhman Dass Arora]

		2003-04	2004-05	
4.	Akhil Bhartiya Surkhsa Samiti, Jhajjar.	0.35	1.27	Reproductive & Child Health Project.
5.	Mahipal Memorial Shiksha Samiti, Bahadurgarh.	—	0.26	Haryana Prathmik Shikhsa Pariyojna Parishad.
6.	Bhart Vikas Sangh, Rohtak	—	0.80	-do-

KARNAL

	2003-2004	2004-05
No. of Societies Registered	213	218
No. of Societies to whom grant has been released.	8	12
Total amount of grant released	20.48 Lac	21.54 Lac

Details of grant released (Amount in Lac)

Sr. No.	Name of the Society	Grant Released		Name of the organization which have released the grant
		2003-04	2004-05	
1.	Adarsh Gram Udyog Samiti, Karnal.	0.90	2.00	Department of Reporductive and Child Health Project.
2.	District Red Cross Society, Karnal.	—	1.83	Haryana Aids Control Society.
3.	District Council for Child Welfare, Karnal.	2.51	2.51	Department of Social Justice & Empowerment.
4.	Haryana Rajya Bal Bhawan, Madhuban, Karnal.	24.24	23.71	-do-
5.	Mission to the Desparates and Destitute of India, Karnal.	1.11	2.43	-do-

		2003-04	2004-05	
6.	District Red Cross Society, Karnal.	4.85	4.81	-do-
7.	Purshotam Charitable Trust, Karnal.	0.35	1.25	Department of Women & Child Development.
8.	Shri Raghunath Mandir, Sabha, Karnal.	—	1.00	-do-
9.	National Foundation of Social Activities, Karnal.	—	0.25	Department of Rural Development.
10.	Jan Kalyan Samiti, Karnal.	—	0.25	-do-
11.	Haryana Yuva Jagriti Manch, Karnal.	—	0.25	-do-
12.	Haryana Yuva Jagriti Manch, Karnal.	5.82	2.25	-do-
13.	Haryana Yuva Jagriti Manch, Karnal.	2.70	—	-do-

KURUKSHETRA

	2003-2004	2004-05
No. of Societies Registered	137	121
No. of Societies to whom grant has been released.	2	4
Total amount of grant released	2.28 Lac	7.07 Lac

Details of grant released (Amount in Lac)

Sr. No.	Name of the Society	Grant Released		Name of the organization which have released the grant
		2003-04	2004-05	
1.	Jan Jagriti Sangthan Kurukshetra.	0.92	2.00	Reporductive and Child Health Project.

[Sh. Lachhman Dass Arora]

		2003-04	2004-05	
2.	District Red Cross Society, Kurukshetra..	—	1.83	Haryana Aids Control Society.
3.	Vishwas Bal Ashram, Shahabad.	1.36	1.31	Social Justice & Empowerment. Department.
4.	District Red Cross Society, Kurukshetra.	—	1.93	-do-

KAITHAL

	2003-2004	2004-05
No. of Societies Registered	145	154
No. of Societies to whom grant has been released.	3	4
Total amount of grant released	4.01 Lac	6.56 Lac

Details of grant released (Amount in Lac)

Sr. No.	Name of the Society	Grant Released		Name of the organization which have released the grant
		2003-04	2004-05	
1.	Mahavir Jain Kalyan Trust, Kaithal.	1.00	—	Deptt. of Women & Child Developmenmt.
2.	Gramin Yuva Vikas Mandal, Kaithal.	—	1.00	-do-
3.	District Red Cross Society, Kaithal.	—	1.83	Haryana Aids Control Society Panchkula.
4.	District Council for Child Welfare, Kaithal.	2.29	2.51	Department of Social Justice & Empowerment.
5.	District Red Cross Society, Kaithal.	0.72	1.22	-do-

MOHINDERGARH

	2003-2004	2004-05
No. of Societies Registered	292	58
No. of Societies to whom grant has been released.	1	6
Total amount of grant released	1.58 Lac	9.25 Lac

Details of grant released (Amount in Lac)-

Sr. No.	Name of the Society	Grant Released		Name of the organization which have released the grant
		2003-04	2004-05	
1.	District Council for Child Welfare, Narnaul.	—	2.51	Department of Social Justice and Empowerment.
2.	District Red Cross Society, Narnaul.	1.58	1.80	-do-
3.	Mahila Chetna Samiti, Parkash Niwas, Nizampur Road, Narnaul.	—	1.30	Department of Women & Child Development.
4.	Society for Education and Welfare Association, Budhwal, Distt. Narnaul.	—	1.00	-do-
5.	Shanti Shikha Samiti, Narnaul.	—	1.32	Haryana Prathmik Shikhsa Pariyojna Parishad.
6.	Nehru Yuva Kendra	—	1.32	-do-

PANIPAT

	2003-2004	2004-05
No. of Societies Registered	157	98
No. of Societies to whom grant has been released.	3	6
Total amount of grant released	6.24 Lac	8.45 Lac

[Sh. Lachhman Dass Arora]

Details of grant released (Amount in Lac)

Sr. No.	Name of the Society	Grant Released		Name of the organization which have released the grant
		2003-04	2004-05	
1.	District Red Cross Society, Panipat.	—	1.83	Haryana Aids Control Society.
2.	Lok Kalyan Foundation, Panipat.	3.82	2.51	Department of Schedule Caste & Backward Classes.
3.	Gandhi Samark Nidhi, Patikalyana.	1.21	1.21	-do-
4.	Arsh Gurukul Sanskrit Maha Vidyalya, Panipat.	1.21	—	-do-
5.	Lok Kalyan Foundation, Samalkha.	—	0.60	-do-
6.	Lok Kalyan Foundation, Samalkha, Panipat.	—	1.00	Department of Women & Child Development.
7.	Chetna Yuvti Samiti, Samalkha	—	1.30	-do-

PANCHKULA

	2003-2004	**2004-05**
No. of Societies Registered	98	82
No. of Societies to whom grant has been released.	11	14
Total amount of grant released	98.97 Lac	80.55 Lac

Details of grant released (Amount in Lac)

Sr. No.	Name of the Society	Grant Released		Name of the organization who have released the grant
		2003-04	2004-05	
1.	Piya Sharma Caritable Trust H.No. 496, Sector 6, Panchkula	2.51	2.51	Department of Social Justice and Empowerment
2.	Bal Sadan Association, 1-9, Sector 12, Panchkula.	1.16	1.36	-do-
3.	S.O.S. Children Village Association, Bal Niketan, Sector 2, Panchkula.	2.91	2.91	-do-
4.	Association for Social Health in India, Ashiana Bhawan, Sector 16, Panchkula.	3.43	2.43	-do-
5.	Haryana Welfare Society for Hearing and Speech Handicapped, Panchkula.	55.00	37.52	-do-
6.	Hind Kusht Nivaran Sangh, Haryana, Panchkula.	11.00	11.00	-do-
7.	Haryana Saket Council, Chandimandir.	9.00	9.00	-do-
8.	Bhartiya Gramin Mahila Sangh	5.00	3.00	Department of Women and Child Development
9.	Piya Sharma Charitable Trust H.No. 496, Sector 6, Panchkula.	2.00	1.50	-do-
10.	C.A.P.S. India Panchkula.	6.00	5.32	-do-
11.	Society for Women and Children Health, Near S.D. Mandir, Sector 16, Panchkula.	—	1.00	Reproductive and Child Health Project.
12.	Unnet Bharat Vikas Samiti, Panchkula.	0.96	2.00	-do-
13.	National Sulabh, Panchkula.	----	0.50	Rural Development Department
14.	Jan Kalyan Sulabh, Panchkula.	----	0.50	-do-

[Sh. Lachhman Dass Arora]

ROHTAK

	2003-2004	2004-05
No. of Societies Registered	153	158
No. of Societies to whom grant has been released.	12	16
Total amount of grant released	17.89 Lac	24.45 Lac

Details of grant released (Amount in Lac)

Sr. No.	Name of the Society	Grant Released		Name of the organization who have released the grant
		2003-04	2004-05	
1.	District Council for Child Welfare, Rohtak.	2.51	2.51	Department of Social Justice and Empowerment.
2.	Women Welfare Association 876/22, Chinout Colony, Rohtak.	—	1.93	-do-
3.	Bharat Vikas Sangh, 1674/22, Srinagar, Colony, Rohtak.	2.04	1.94	-do-
4.	Chaudhary Lakhi Ram Arya Anathala, Gohana Road, Dayanand Math, Rohtak.	2.33	2.13	-do-
5.	Vishwas Bharti Shiksha Sansthan, Rohtak.	2.33	2.86	-do-
6.	Manav Sewa Sangh (Anathalya), Bhiwani Road,, Rohtak.	1.21	1.36	-do-
7.	District Red Cross Society, Rohtak	4.47	4.79	-do-
8.	All India Mahila Sewa Samiti, V.P.O. Lakhan Majra, Rohtak.	0.50	0.50	Reproductive and Child Health Project.
9.	Public Health Society, V.P.O. Sampla, Rohtak.	0.50	0.50	-do-

		2003-04	2004-05	
10.	Nav Chetna Education Society, Community Centre, Sukhpura, Rohtak.	0.50	0.50	Reproductive & Child Health Project.
11.	B.S.A. Education Society, Arya Bhawan, Farmana, Rohtak.	0.50	0.50	-do-
12.	All India Commonweal Society, 94/122, Lakshmi Nagar, Rohtak.	0.75	0.75	-do-
13.	Centre for Education and Social Welfare, 665/20, Prem Nagar, Rohtak.	0.35	1.27	-do-
14.	Manav Sewa Gram, Udyog Sangh, Rohtak.	—	0.72	Haryana Prathmik Shiksha Pariyojna Parishad.
15.	Golden Carrier Educational Society, Rohtak	—	0.52	-do-
16.	Nehru Yuva Kendra, Rohtak	—	1.67	-do-

REWARI

	2003-2004	2004-05
No. of Societies Registered	64	34
No. of Societies to whom grant has been released.	1	4
Total amount of grant released	1.96 Lac	4.30 Lac

Details of grant released (Amount in Lac)

Sr. No.	Name of the Society	Grant Released		Name of the organization who have released the grant
		2003-04	2004-05	
1.	District Red Cross Society, Rewari.	1.96	1.96	Department of Social Justice & Empowerment.
2.	Morning Glory Public Society, 1260, Upper MIG, New Housing Board, Sector 3, Rewari.	—	1.30	Department of Women & Child Development

[Sh. Lachhman Dass Arora]

		2003-04	2004-05	
3.	Vidya Niketan Education Society, Baghthla	—	0.52	Haryana Prathmik Shiksha Pariyojna Parishad.
4.	Morning Glory Public Society, Rewari.	—	0.52	-do-

SONEPAT

	2003-2004	2004-05
No. of Societies Registered	125	119
No. of Societies to whom grant has been released.	14	21
Total amount of grant released	33.11 Lac	51.17 Lac

Details of grant released (Amount in Lac)

Sr. No.	Name of the Society	Grant Released		Name of the organization who have released the grant
		2003-04	2004-05	
1.	District Council for Child Welfare, Sonepat.	—	2.74	Department of Social Justice and Empowerment.
2.	Nari Chetna Sangthan, Adarsh Nagar, Sonepat.	2.51	2.51	-do-
3.	S.O.S. Children Welfare Vill. Bal Gram Rai, Sonepat.	18.77	20.56	-do-
4.	Adrash Education Samiti Sonepat.	1.38	5.15	Department of Scheduled Caste and Backward Classes
5.	Kasturi Devi Memorial Education	1.80	1.65	-do-
6.	Modern Education Society, Sonepat.	1.71	—	-do-

		2003-04	2004-05	
7.	Aryavart Vidyala, Shikhsa Samiti	0.92	—	-do-
8.	Modern Educational Society, Monodora, Sonepat.	3.50	1.70	Department of Women & Child Development
9.	Ramjas Shiksha Samiti, Gobind Nagar, Sonepat.	—	0.90	-do-
10.	Akhil Bhartiya Jan Kalyan Samiti, Sonepat.	—	1.00	-do-
11.	Smt Kasturi Devi Memorial Shiksha Samiti, Sonepat	—	1.30	-do-
12.	Ramjas Hindi Sanskrit Mahavidalya, Sonepat.	—	0.30	-do-
13.	Vivekanand Education Society Shastri Nagar, Sonepat.	—	0.30	-do-
14.	Yuva Samaj Sewa Sangthan Ganour.	—	2.05	-do-
15.	District Red Cross Society, Sonepat.	—	1.83	Haryana Aids Control Society.
16.	Prerna, 477/31, Ashok Vihar Mehlana, Sonepat.	0.33	1.25	Reproductive & Child Health Project.
17.	Nari Chetna Sangthan, 103, Sector 14, Sonepat.	0.33	1.25	-do-
18.	Adarsh Saraswati Shiksha Samiti, Kakori Road, Sonepat.	0.33	1.25	-do-
19.	Kirti Yuva Kendrta, Kirti Nagar, Sonepat.	0.33	1.25	-do-
20.	Modern Education Society Mandouri Road, Mandoura, Sonepat.	0.50	0.50	-do-
21.	Aryan Yuva Club, Kherakhurd, Sonepat.	0.35	1.27	-do-
22.	Multi Vision Foundation, Sonepat.	0.35	1.27	-do-
23.	All India Centre for Urban and Rural Development.	—	1.14	Haryana Prathmik Shiksha Pariyojna Parishad.

[Sh. Lachhman Dass Arora]

SIRSA

	2003-2004	2004-05
No. of Societies Registered	622	214
No. of Societies to whom grant has been released.	3	6
Total amount of grant released	5.72 Lac	13.34 Lac

Details of grant released (Amount in Lac)

Sr. No.	Name of the Society	Grant Released		Name of the organization who have released the grant
		2003-04	2004-05	
1.	Disha Organisation, Sirsa.	2.50	2.30	Department of Women and Child Development.
2.	District Council for Child Welfare, Singikat Mohalla, Sirsa.	2.29	2.29	Social Justice and Empowerment Department.
3.	District Council for Child Welfare, Kalawali Jangir Colony, Sirsa.	—	2.74	-do-
4.	District Red Cross Society, Sirsa	0.93	0.93	-do-
5.	Disha, Sirsa	—	2.54	Haryana Prathmik Shiksha Pariyojna Parishad
6.	Lifeline Awareness and Serving Welfare Society, Sirsa.	—	2.54	-do-

YAMUNANAGAR

	2003-2004	2004-05
No. of Societies Registered	75	57
No. of Societies to whom grant has been released.	6	8
Total amount of grant released	25.44 Lac	23.97 Lac

Details of grant released (Amount in Lac)

Sr. No.	Name of the Society	Grant Released		Name of the organization who have released the grant
		2003-04	2004-05	
1.	PARYAS, Yamuna Nagar.	—	1.00	Department of Social Justice and Empowerment.
2.	District Council for Child Welfare, Yamuna Nagar.	2.51	2.51	-do-
3.	Haryana State Council for Child Welfare, Yamuna Nagar.	8.13	14.69	-do-
4.	District Red Cross Society, Yamuna Nagar.	1.52	1.67	-do-
5.	All India Samaj Sewa Kendre,	2.77	0.10	Rural Development Department.
6.	Indian Red Cross Society, Yamuna Nagar.	9.51	—	Haryana Aids Control Society.
7.	UTTHAN, Institute of Development and Studies, Yamuna Nagar.	1.00	2.00	Reproductive and Child, Health Project.
8.	Family Planning Association of India, Yamuna Nagar.	—	1.00	-do-
9.	Sri Ram Kishan Sehgal Charitable Trust, Yamuna Nagar.	—	1.00	-do-

चौधरी धर्मपाल सिंह मलिक : अध्यक्ष महोदय, माननीय मंत्री महोदय ने मेरे सवाल का जवाब बहुत डिटेल में दिया है इसके लिए मैं उनका धन्यवाद करता हूँ और आपके माध्यम से एक बात और पूछना चाहता हूँ कि इन सोसायटीज की ग्रोथ मशरूम की तरह हो रही है। जो गैर सरकारी संगठन हैं इनके माध्यम से सरकार को पैसे मिल जाते हैं जिनका बहुत अधिक मिसयूज होता है। मंत्री जी ने अपने जवाब में लिखा है कि सोसायटीज रजिस्ट्रेशन एक्ट 1860 के अलावा और कोई प्रावधान सोसायटीज रजिस्ट्रेशन करने का नहीं है। इसी के तहत सभी सोसायटीज की रजिस्ट्रेशन होती है चाहे हिन्दू कालेज, सोनीपत और जाट कालेज, रोहतक की तरह कोई बड़ी संस्था हो, चाहे ये छोटे-छोटे एन०जी०ओज० हों। इनको एन०जी०ओ० कहा जाता है जो कि अपने आप में पैदा किया हुआ नाम है। यह नाम किसी एक्ट के तहत रजिस्टर्ड नहीं है। मैं मंत्री जी से पूछना चाहता हूँ कि क्या इन सोसायटीज में करप्शन को रोकने के लिए सरकार कोई नया एक्ट लाने पर विचार करेगी तथा यह भी पूछना चाहता हूँ कि ये सोसायटीज सरकारी ग्रांट के अलावा क्या कहीं और से भी पैसा इकट्ठा करती हैं और उन पर सरकार की तरफ से किसी प्रकार का आडिट किया जाता है या नहीं।

श्री लछमन दास अरोड़ा : स्पीकर सर, मेरे आदरणीय साथी मलिक साहब ने जो सवाल किया है, जहां तक इण्डस्ट्रीज डिपार्टमैंट का संबंध है, इस सवाल से हमारा कोई वास्ता नहीं है। हमारा वास्ता सिर्फ सोसायटीज को रजिस्टर्ड करने से है। रजिस्ट्रेशन के बाद वे सोसायटीज डिपार्टमैंटवाइज लोन लें, चाहे भारत सरकार से लें या कहीं और से लोन लें उन्होंने जो भी लेखा-जोखा देना है वह उन्हीं को देना है जहां से उन्होंने लोन लिया है। इण्डस्ट्रीज डिपार्टमैंट का इनके लोन से कुछ भी लेना देना नहीं है। इण्डस्ट्रीज डिपार्टमैंट का ताल्लुक केवल उनके रजिस्ट्रेशन तक का है।

Ch. Dharam Pal Singh Malik : Speaker Sir, this Question entered in the name of Industries Minister, so, we can ask supplementaries from the concerned Minister. खासतौर से यह मामला इनके डिपार्टमैंट से संबंधित है क्योंकि ये सोसायटीज इनके डिपार्टमैंट से रजिस्टर्ड होती हैं।

Mr. Speaker : Malik Sahib, please ask your specific supplementary.

चौधरी धर्मपाल सिंह मलिक : अध्यक्ष महोदय, सवाल यह है कि कोई इन एन०जी०ओज० के बारे में बताए तो सही। दो लाख रुपये स्कूलों में बिस्कुट बांटने के लिए ले जाते हैं। न उन बिस्कुटों को कोई बांटता है और न ही उनको कोई खाता है। वह सारा पैसा यूं का यूं मिसयूज हो जाता है। अध्यक्ष महोदय, इसके साथ ही मैं एक और बात पूछना चाहता हूँ। मेरे पहले सप्लीमैंटरी सवाल का सैटिस्फैक्टरी उत्तर मुझे नहीं मिला है। एन०जी०ओ० को सरकार ग्रांट देती है। मन्त्री महोदय ने कहा है कि इनका महकमा ग्रांट नहीं देता है। कौन सा महकमा इनको ग्रांट देता है, ये किस विभाग से संबंधित हैं, मंत्री जी इसके बारे में जवाब दे दें। उन एन०जी०ओज० से जो काम करवाए जाते हैं उनसे करप्शन बढ़ती हैं। क्या वे कार्य गवर्नमैंट अपनी किसी एजैंसी से नहीं करवा सकती है, मंत्री जी इसका जवाब दे दें। अध्यक्ष महोदय, मैं मंत्री महोदय से यह पूछना चाहता हूँ कि लोगों की डिमाण्ड मानकर क्या ऐसा करने के बारे में कोई विचार हो सकता है ?

श्री लछमन दास अरोड़ा : अध्यक्ष महोदय, माननीय साथी ने जो बात कही है मैंने उसका जवाब दे दिया है। जहां तक एन०जी०ओज० को पैसा, लोन या ग्रांट लेने देने का सवाल है, न हम उनसे लेने वालों में हैं और न ही देने वालों में हैं। हम तो एन०जी०ओज० को सिर्फ रजिस्टर्ड करते हैं। इसके

बाद में चाहें किसी भी महकमे से वे लोन लें या किसी भी महकमें को हिसाब किताब दें इसमें इण्डस्ट्रीज डिपार्टमैंट द्वारा कोई कानून बनाने वाली बात तो है नहीं।

परिवहन मंत्री (श्री रणदीप सिंह सुरजेवाला) : अध्यक्ष महोदय, माननीय मंत्री जी ने जो कहा है मैं माननीय साथी की जानकारी के लिए उसमें केवल इतना ऐड करना चाहूंगा कि एन०जी०ओज० का सरकार और समाज के साथ प्रगति के कार्यों में भागेदारी में एक विशेष स्थान है। प्रांतीय सरकारें, देश की सरकार और अन्तर्राष्ट्रीय स्तर तक एन०जी०ओज० को रैकोग्नाईज किया गया है। अध्यक्ष महोदय, अगर किसी एन०जी०ओ० से माननीय साथी को कोई शिकायत है तो वे लिखकर मंत्री महोदय को दे दें हम उसकी जांच करवा लेंगे। माननीय सदस्य द्वारा यह कहना कि सारी एन०जी०ओज० को पार्टिसिपेशन से महरूम कर दिया जाए यह उचित नहीं लगेगा।

श्री लछमन दास अरोड़ा : अध्यक्ष महोदय, हम फाईनैंस डिपार्टमैंट को लिख देंगे। मैं इनकी जानकारी के लिए इनको यह बताना चाहूँगा कि इनका ऑडिट होता है।

Desilting and Repair of Canals of Narnaul

***441. Shri Radhey Shyam Sharma :** Will the Minister for Irrigation be pleased to state—

(a) whether there is any proposal under consideration of the Government to desilt and repair the canals of Narnaul Constituency; if so, by what time the aforesaid work is likely to be started;

(b) whether there is any proposal under consideration of the Government to link the Hameedpur, Jorsi and other dams with the canals in the Narnaul Constituency; if so, by what time the aforesaid work is likely to be executed; and

(c) whether there is any proposal under consideration of the Government to link the village Ghatasar, Pawera, Napla, Gawri Jat, Panchnauta, Musnauta, Nangal Durgu, Bayal and villages of Shahbazpur area with the canal from Mukendpura deegh?

Revenue Minister (Capt. Ajay Singh Yadav) :

(a) Yes Sir, the desilting and repair of canals in Narnaul Constituency are in progress and efforts shall be made to complete the same with in three months.

(b) The scheme for linking of Hameedpur Bund with the canal has already been sanctioned by the Government with an estimate of Rs. 242.39 lacs and it is likely to be completed within one year. The scheme for linking of Jorashi Dam and other Dams of Narnaul Constituency with Canals are not feasible because these dams were basically constructed for retention of rain water and back feeding from canal set up shall

[Capt. Ajay Singh Yadav]

need multiple lifts which are not viable keeping in view the cost and feasibility of infrastructure needed for the same. Moreover availability of surplus water at tail end is also major constraint.

(c) The scheme is under investigation and the proposal after investigation shall be implemented if found feasible with the approval of Government.

श्री राधेश्याम शर्मा अमर : अध्यक्ष महोदय, जहां तक हमीदपुर के बांध की बात है, मेरे सवाल देने के बाद यह मंजूर हुआ है इसके लिए मैं सरकार को बधाई देता हूँ तथा सरकार का धन्यवाद भी करता हूँ। दूसरे जुरासी बांध के बारे में माननीय मंत्री जी ने यह कहा है कि यह फीजिबल नहीं है और यह रेन वाटर कलैक्ट करने के लिए बनाया गया है। अध्यक्ष महोदय, मैं यह कहना चाहता हूँ कि यह बांध फीजिबल है और इसमें कहीं पर भी पानी को लिफ्ट करने की जरूरत नहीं पड़ती है। विभाग के अधिकारियों की कोआपरेशन से इसका कन्टेनर बना कर देखें वे पानी एक तरफ से चलाते हैं और पानी को लिफ्ट करना पड़ता है। दूसरी तरफ से बाई वे ऑफ ग्रेविटी पानी अपने आप जाता है और बिना लिफ्ट किए आता है। मैं माननीय मंत्री महोदय से यह जानना चाहता हूँ और उनसे रिक्वैस्ट भी करना चाहता हूँ कि दूसरी तरफ से पानी को चलाया जाए क्योंकि नारनौल के अन्दर इस पानी का लाभ होगा और कहीं से तो पानी वहां पर जाएगा, यदि नहीं, तो क्या मंत्री महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि दूसरी तरफ से सर्वे करवा कर पानी कब तक छोड़ने की मेहरबानी करेंगे?

कैप्टन अजय सिंह यादव : अध्यक्ष महोदय, जैसा कि मैंने बताया है कि हमीदपुर बांध को भरने के बारे में पिछली सरकार ने गैली गांव की तरफ से एक्सकेप चैनल के द्वारा भरने की कोशिश की गई थी। उसमें लाखों रुपए खर्च हो गए थे। हम टैक्नीकल वायब्लीटी देखकर 2 करोड़ 42 लाख रुपये से इसके कार्य को पूरा करवायेंगे। मैं विधायक जी के क्षेत्र में स्वयं गया था और ये भी जानते हैं कि हमने हसनपुर डिस्ट्रीब्यूटरी से इसको लिंक करके भरने का काम किया है। जहां तक जोरासी और दूसरे डैम्ज हैं तो अध्यक्ष महोदय, मैं इनको बताना चाहूँगा कि वह पथरीला इलाका है। अध्यक्ष महोदय, इसमें कई लिफ्टस लगेंगी। इसके अलावा जो टेल्ज हैं वे फीड नहीं हो पा रही हैं। ये स्वयं जानते हैं कि उन डिस्ट्रीब्यूटरीज की हालत इतनी खराब है कि पिछले 10 सालों में वहां पर किसी ने एक नया पैसा नहीं लगाया था। हमने वहां पर 65 लाख रुपये की लागत से कहीं पर रिपेयर की है और कहीं पर डिसिल्टींग की है। जहां तक डैम्ज की बात तो इस बारे में हम कोशिश करेंगे और अगर वहां पर ग्रैवेटी से पानी आने वाली कोई बात होगी तो उसको भी हम चैक करवा लेंगे।

Opening of Government College in Kanina

***368. Shri Naresh Yadav :** Will the Minister for Education be pleased to state whether there is any proposal under consideration of the Government to open the Govt. College in Kanina, district Mahendergarh; if so, by what time the classes are likely to be started in the said college?

Education Minister (Shri Phool Chand Mullana) : No, Sir.

श्री नरेश यादव : अध्यक्ष महोदय, मैं आपके माध्यम से कहना चाहता हूँ कि कनीना कस्बे में लोगों ने सामाजिक रूप से एक कमेटी बनाकर दो लाख रुपए लगाकर एक बिल्डिंग बनाई हुई है। वहां पर 19 एकड़ जमीन है, 20-30 कमरे बने हुए हैं, लाईब्रेरी भी बनी हुई है और वहां पर प्लेग्राउण्ड भी बना हुआ है। वहां पर कॉलेज का पूरा ढांचा तैयार है। मुख्यमंत्री जी भी वहां पर जाकर आए थे और इन्होंने भी उसको देखा है। क्या मंत्री जी वहां पर कॉलेज बनाने की घोषणा करेंगे? इसमें सिर्फ गवर्नमैंट की मंजूरी की ही जरूरत है ताकि इस सैशन से वहां पर कॉलेज शुरू हो सके।

श्री फूल चन्द मुलाना : अध्यक्ष महोदय, मौजूदा सरकार ने शिक्षा की ओर विशेष ध्यान दिया है और हमारी कोशिश है कि हमारे यहां पर गुणात्मक शिक्षा मिले। हम शिक्षा को गुणात्मक बनाना चाहते हैं। अध्यक्ष महोदय, मैं आपके माध्यम से माननीय साथी को बताना चाहूँगा कि महेन्द्रगढ़ जिले में 8 सरकारी और एक प्राईवेट कॉलेज है। कनीना से 15 किलोमीटर की दूरी पर अटेली में भी एक कॉलेज है। आज के आधुनिक युग में 15 किलोमीटर की दूरी कोई मायना नहीं रखती है। हमारी वहां पर ट्रांस्पोटेशन की भी बहुत अच्छी सर्विस है इसलिए इन्होंने जो मांग की है उसकी कोई आवश्यकता नहीं है।

श्री अमीर चन्द मक्कड़ : अध्यक्ष महोदय, मेरे हल्के के गढ़ी गांव में एक स्कूल की बिल्डिंग पहले से ही बना रखी है। उस गांव का एक डैपूटेशन मुख्यमंत्री जी से और शिक्षा मंत्री जी से भी मिला था। क्या शिक्षा मंत्री जी वहां पर स्कूल बनवाने का कष्ट करेंगे क्योंकि वह बिल्डिंग स्कूल बनाने के लिए जो नार्मज चाहिएं होते हैं वे सभी पूरे करती है?

श्री फूल चन्द मुलाना : अध्यक्ष महोदय, इनकी सप्लीमेन्टरी मूल तारांकित प्रश्न से मेल नहीं खाती है। ये इसके लिए अलग से सवाल करके पूछ लें, जवाब दे दिया जाएगा।

Report regarding Performance in Games

*373 **Shri Ranbir Singh Mahendra :** Will the Minister for Sports and Youth Affairs be pleased to state—

(a) whether any report has ever been submitted to the department by the officers who accompained/attended Olympics, Asiad and Commonwealth Games in respect of the performance of the participants; if so, the details thereof; and

(b) the names of the sports of the previous Asiad, Olympics and Commonwealth Games alongwith the names of the officers who accompained/attended the said games togetherwith the observations thereof?

Education Minister (Shri Phool Chand Mullana) : Yes, Sir.

A statement is placed on the Table of the House.

[Shri Phool Chand Mullana]

Statement

Sr. No.	Name of the Tournament/ Venue/Dates	Name of Officer attended	Report of performance of the Participants/ observation
1.	**Olympic Games**		As per
	27th Olympic Games Sydney (Australia) 15-9-2000 to 2-10-2000	(i) Shri Naresh Gulati, IAS Commissioner & Secretary Sports, Haryana, (ii) Dr. B.K. Sinha, IPS Director, Sports, Haryana	**Annexure-A**
2.	**Olympic Games**		As per
	28th Olympic Games Athens (Greece) 13-8-04 to 29-8-04	(i) Shri D.S. Dhesi, IAS Commissioner & Secretary Sports, Haryana, (ii) Shri Anil Malik, IAS Deputy Principal Secretary to C.M. Haryana	**Annexure-B**
3.	**Commonwealth Games**		As per
	17th Commonwealth Games Manchester (U.K.) 25-7-02 to 4-8-02	(i) Shri D.S. Dhesi, IAS Commissioner & Secretary Sports, Haryana, (ii) Shri M.S. Mann, IPS Director, Sports, Haryana	**Annexure-C**
4.	**Asian Games**		As per
	14th Asian Games Busan (South Korea) 5-10-02 to 14-10-02	Shri M.S. Mann, IPS Director, Sports, Haryana	**Annexure-D**

Annexure-A

The XXVII Olympic Games : A Report

The 27th Olympic games were held at Sydney from 15th September, 2000 to 2nd October, 2000. The competitions were held in 28 events. Many new world records were created during these games. India participated in 13 disciplines, namely Athletics, Badminton, Hockey, Judo, Rowing, Shooting, Swimming, Table Tennis, Weightlifting, Wrestling and Equestrain. The total Indian contigent of 121 persons comprised 71 sportspersons, 28 coaches, doctors, masseurs and 22 managers. The Indian Government also sent Official Delegations during this period. The Government of Haryana nominated the Commissioner, Sports and the Director,

Sports to visit Sydney during the Olympic Games.

Almost all the Observers, including the President of the International Olympic Committee, have rated the Sydney Olympic Games as the best ever organized Olympic Games in the World. The most important feature was the creation of the latest designed infrastructure and the best possible security and transport arrangements. These Olympic Complexes have given Sydney a new sporting focus. The new stadia and other Olympics facilities marked a dramatic shift from the previous sporting complexes centered around the Moore Park. The Olympic events were held at Olympic Park, Darling Harbour, Bondy Beach and some other venues.

Sydney Olympic Park was an epicenter of the Sydney Olympics. The park which was the venue for the Opening and Closing ceremonies of the 27th Olympic Sports was in a radius of 2.5 KM. The park a master plan gives a full view of the open space, plaza, Athletics and some important stadia and sporting venues. This Olympic Stadium is the largest outdoor venue in the Olympic history. The stadium is as high as a sixteen storey building which can accommodate 1.10 lacs spectators. The special designed roof minimizes shadow and dark sunlight on the competition area creating ideal condition for spectators and television coverage.

The Sydney International Aquatic center present high standard of International Competitions hall, with its 10 lane main pool has a wide roof with excellent spectators view. The 50 metre competition pools has a movable bulk head to transfer it into 2.5 metre pool for short course events. The pool has been designed to promote the best kind of performances in the Equatic events. The Superdome is another example of the latest architecture for providing the best infrastructural support. Basketball and Gymnastic were held in this Superdome. The other stadia also had the latest architectural design to gives the Athletes/Sportspersons an opportunity to perfom their best.

From the Atlanata Olympics, a new system of participation, by qualification, was introduced in place of free participation. Various Championships were recognised by International Federations and on the basis of these championships the sportspersons and the countries were allowed to participate in the Olympics. Thus it is very easy to evaluate the sports potential of the country by looking at the number of participants from that particular country. Apart from this a system of Hardship Quota and Wild Card was also introduced. Passing through various levels of selections, the Indian team finally got clearance to participate in 13 major sports.

This is a proper occasion to evaluate our system of selection and training in depth because most of the Indian Sportspersons could not perform their best during the Olympics. Some of them could not reach even the performance which they have achieved in India or in other International Competitions. In Athletics and Hockey, our performances was totally disappointing.

The important feature for the upliftment of sports standard in India is the SELECTION OF THE SPORTS TALENT. All the major countries in the world who have been doing well in the sports have tried to select their sportsperson at a very

[Shri Phool Chand Mullana]

early age. In some of the countries the sportspersons are identified even at the age of five or six and then they are made to undergo a basic training and finally they are picked up for their specialized training.

After discussing this issue of identifying the talent at an early age, we realized that India is far behind in conceiving this idea and it is highly recommended that we must identify our talent at a very early age and put them for BASIC PHYSICAL TRAINING and before the age of ten every sportsperson should be identified for a SPECIALIZED TRAINING in a particular sport. This exercise is very beneficial in a State like Haryana where standard of communication system is above the national average.

It is also very essential to IMPROVE OUR INFRASTRUCTURE at the school level. This will give an opportunity for our school children to participate increasingly in competitive sports. This will also help us in identifying our talent in a better way and we will get more and more competitors for the same event. Haryana has a lot of potential in the rural areas. Hence, we must take advantage of Government of India Rural Schemes and improve our infrastructure in the rural areas also. This will automatically improve the general standard of sport in the State.

It is also very essential to ORGANIZE MORE STRUCTURED COMPITITIONS. For instance, the whole of the Indian Sub-Continent has only six major water courses whereas a country like Australia has more than 200 recognised water sports centres. Hence, it is obvious that the competitions in such countries will improve the standard of sports. In a State like Haryana if we organize competitions at the Panchayat, Block and Municipality levels also then the general standard of sports shall improve.

India, in general, and Haryana in particular is far behind in incorporating the concept of TRAINING FOR TRAINERS.In many of the developed and developing countries coaching community is being imparted regular training. We have now started in Haryana, also this kind of concept to train our own coaches. Proper Assistance shall be taken from the Sports Authority of India. However, some kind of incentives and also the system of reward and punishment need to be devised to improve the standard of coaches and technical officials in the State of Haryana.

Haryana needs to adopt the SCIENTIFIC METHODS IN TRAINING. Our coaches and also sportpersons are not exposed to use scientific methods for their training. Scientific support should be provided at every stage to our sportspersons. Scientific support should be taken to identify a particular person for a particular event and later on in his training adequate scientific support and knowledge should be given to ensure performance in various competitions. This is an upcoming concept and soon after coming from Sydney we have approached the Sports Authority of India and they have sanctioned the latest concept of Weight Management Centre at Hisar while sanctioning the various training centres to Haryana.

It is also very important to create a GENERAL ATMOSPHERE AND AWARENESS for sports in our country. The Education Department, Panchayat

Department and other agencies can be used to POPULARIZE SPORTS AT THE GRASS ROOT LEVEL. In a State like Haryana it is also essential that till we achieve a particular level of supervision and monitoring should remain with the State. The various schemes should be implemented through the State agencies.

By taking of the STATE RESPONSIBILITIES IN PROMOTING THE GAMES AND SPORTS in State of Haryana, we should not totally neglect the PARTICIPATION OF VARIOUS PRIVATE AND PUBLIC SECTORS, Boards and Corporations in sponsoring the sports activities in the State. Many a time it is impossible for the State to financially support by the activities. Hence, these agencies should help the State to give the financial support to all the sports activities. Now Government of India has provided TAX EXEMPTION for all kind of sports competitions, hence it will not be difficult for the corporate sector to come forward to help in promotion of sports in the State.

The Government of Haryana has started a NEW INCENTIVE SCHEMES for promotion and games in the State but we also need certain amount of PROFESSIONALISM to reach international level. Methods should be devised to give INTERNATIONAL EXPOSURE to our sportspersons. Some of the Asian Countries are not very far off and sending our Athletes on exchange basis will not be very expensive. We can also take full SUPPORT FROM THE SPORTS AUTHORITY OF INDIA and various National Federations in improving our general standard of Sports. The visit to Sydney given us an enlightening exposure to the latest infrastructure in sports, the various level of selection for sportspersons, the training and also competitions and exposure to be provided to the young sportspersons. Haryana has a lot of scope to perform better at the National and international level by utilizing our resources and strengthening our system. By implementing the above recommended actions we can certainly produce better results at the international level also.

ANNEXURE - B

REPORT REGARDING ATHENS OLYMPICS, 2004

In 2004, the Olympic Games returned to Greece after more than a Century. The first ancient Olympics were staged in 776 BC and the 1st modern Olympic Games were held in 1896. The Athens 2004 Olympics were the biggest sporting event to be held in the beginning of the new millennium. Though the Olympics owe their origin to Greece, yet it was the smallest country ever to host the modern games, which have been growing in magnitude with every edition. Greece is also financially the weakest country ever to have hosted the modern Olympics in their current scale.

Security was a major area of concern for the organizers of the 2004 Olympic Games. No Country in the world paid as much for security as Greece. The security bill started at 300 million Euros and ultimately rose to 1.2 billion Euros.

Opening Ceremony

The opening ceremony is the most attractive feature of any international sports event because the host nation tries to create a good impact at the very

[Shri Phool Chand Mullana]

beginning. So was the case at Athens. The opening ceremony was held on 13th August, 2004. The duration of the ceremonies was four hours from 8.30 PM to 12.30 AM. The event was a spectacular mix of the ancient and modern. The ceremony extensively used images derived from the rich history and diversity of Greek art and history. The ceremony narrated the story of early Greece and the birth of the Olympic Games through Music, Dance and pageantry. It provided an insight into the modern games that were revived in Athens 108 years ago. The history of the Olympic Games was screened on huge video screens for the benefit of the 70,000 spectators, who were inside the main stadium.

The cultural programme took the spectators through time using various items of Greek sculpture which symbolized the growth and evolution of Greek civilization and human consciousness. About 200 contingents representing different countries of the world took part in the March-past. Indian contingent was at Sr. No. 58. The Greek flag was ushered in ahead though the Greek contigent walked in last. The ceremony came to an end with the formal lighting of the Olympic flame. This was done in a hi-tech manner. A pyrotechnics brust marked the moment the games were formally declared open.

The most interesting and fascinating event was the creation of Olympic rings with fire in water. The main performance area was filled with 2162 cubic metre of water covering an area of 9645 Sq. metre. After the display was over the water was drained out through underground drains below the performance area just within a matter of 30 seconds. For the opening ceremony 37 Km. of steel net was used. As many as 72 computers controlled steel wire winches mounted on 18 platforms moved the various scenic elements. In all 2428 volunteers from 14 countries performed during the ceremony. The entire ceremony was conducted in a very professional manner. The spectators also were active participants in the ceremony and contributed to the show by creating various patterns with electronic lights given to each spectators by the organizers.

Sports Infrastructure

World -class facilities were newly created for the games. Given below is a venue-wise description :—

(1) Athens Olympic Sports Complex (OAKA)

This was the biggest venue consisting of the following :—

(i) Olympic Stadium

(ii) Tennis Centre

(iii) Indoor Hall

(iv) Aquatic Centre

(v) Velodrome

The total area of (OAKA) is 3.80 lac Sq. metres

(2) **Olympic Stadium**

The stadium has a capacity of 60,000. It was used for Opening and Closing ceremonies, Athletics and Football men's final.

(3) **Olympic Indoor Hall**

This venue was used for Gymnastics & Basketball. It has a capacity of 15,000.

(4) **Olympic Tennis Centre**

This centre consists of 9 courts.

Centre court has a capacity of 6,000

Court-I	—	3200
Court-II	—	1400

Courts -3-9 have a capacity of 2000 each.

(5) **Olympic Aquatic Centre**

This consists of 3 different pools. The venue was used for swimming, driving, water polo and synchronized, swimming. The capacity of the centre is for 6200 spectators.

(6) **Olympic Velodrome**

This has a capacity of 3300 and was used for cycling events.

(7) **Peace and Friendship Stadium**

This stadium has a capacity of 9400 spectators and was the venue for volleyball.

(8) **Sports Pavilion**

This venue is located in Faliro Coastal Zone Olympic Complex and has a capacity of 5800 spectators. It was used for handball and taekwondo.

(9) **Olympic Beach Volleyball Centre**

This is located in Faliro Coastal Zone. It has a spectators capacity of 7300 and was used for beach volleyball.

(10) **Helliniko Olympic Complex**

After OAKA, this was the second largest complex and consisted of the following :—

(i) Helliniko Baseball Centre.

(ii) Helliniko Olympic Softball Centre.

[Shri Phool Chand Mullana]

(iii) Helliniko Olympic Hockey Centre.

(iv) Helliniko Indoor Arena.

(v) Helliniko Olympic Fencing Hall.

(vi) Helliniko Olympic Canoe/Kayak Slalom Centre.

(i) Olympic Baseball Centre

The venue consists of two fields :—

Field One has a capacity of 6700.

&

Field Two has a capacity of 3300.

(ii) Olympic Softball Centre

This venue has a spectators capacity of 3400 and was used for softball game.

(iii) Olympic Hockey Centre

Pitch One has a capacity of 5200

&

Pitch two has a capacity of 1200.

(iv) Helliniko Indoor Arena

This venue has a spectators capacity of 10,700 and was used for Basketball and Handball games.

(v) Fencing Hall

This venue has a spectators capacity of 3400 and was used for Fencing.

(vi) Olympic Canoe/Kayak Slalom Centre

This venue has a spectators capacity of 6700 and was used for Canoe/Kayak/Slalom.

(11) Anoliossia Olympic Hall

This venue has a spectators capacity of 6000 and was used for judo and wrestling.

(12) Peristeri Olympic Boxing Hall

This venue has a spectators capacity of 5600 and was used for boxing event.

(13) Nikaia Olympic Weight Lifting Hall.

This venue has a spectators capacity of 3500 and was used for weight lifting event.

(14) **PARNITHA OLYMPIC MOUNTAIN BIKE VENUE**

The Olympic Mountain Bike course covers an area of one square KM. It has a spectators capacity of 14,700. This venue was used for mountain bike event.

Panathinaiko Stadium.

The Panathinaiko Stadium is one of Athens' major archaeological sites. Built at the end of the 4th century BC, it went through extensive renovation in the 1890s to host the modern Olympic games of 1896. It is made of white marble. The stadium has the capacity of 28400 and was used as venue for Marathon finish. (Men and Women).

(15) **Galatsi Olympic Hall.**

This venue has a spectators capacity of 4400. It was used for table tennis and Rhythmic Gymnastic.

(16) **Goudi Olympic Complex.**

The Goudi Olympic complex consists of two venues :- Goudi Olympic Hall where badminton took place and the Olympic Modern Pentathion Centre.

(17) **Voluiagmeni Olympic Centre.**

This venue has a capacity of 2200 and was used for Triathlon.

(18) **Schinias Olympic Rowing and Canoeing Centre.**

This venue is located quite far from the town Athens and is near the village Marathon. It was used for rowing and canoeing and has a spectators capacity of 10,000.

(19) **Markopoulo Olympic Shooting Centre.**

This venue is located outside the town of near the Athens International Airport. This was used for shooting and consists of 9 competitions areas. It has a spectators capacity of 1500.

OLYMPIC TRANSPORT SYSTEM

A very extensive and integrated transport system was developed by the Government for providing easy and trouble free access to the various venues where the different events were being staged. The system consisted of the following :—

(i) The Metro.
(ii) The Olympic Bus Lines.
(iii) Tram System
(iv) Suburban Railway.

These systems were connected to each other to form an extensive public transport network that covered all Olympic venues.

[Shri Phool Chand Mullana]

The Olympic ticket holders were entitled to free transport on the Olympic Transport System on the day for which the ticket was valid upon displaying the ticket. However, this facility was restricted only to get to or leave the venue where the competition was being held.

The most impressive and efficient was the Metro consisting of three Lines viz Line-1, Line-2 and Line-3. The ticket charges for use of the Metro were also kept very reasonable. A single journey ticket was for 70 cents. (Rs. 42), a day ticket (for all means of transport) was only for 2.90 Euros (Rs. 160) and a 7 days ticket (for all means of transport) was 10 Euros (Rs. 560).

The frequency of the service was 5 minutes during peak hours and 10 minutes during non-peak hours. The maximum rush was at the time of Opening and Closing ceremonies where about 70,000/- spectators had assembled at the OAKA (Athens Olympic Sports Complex) Even for evacuating this massive crowd, the waiting time was only 30 minutes.

The Greek Government and the Athens civic Authorities made a lot of investment on improving and upgrading the transport system, for which there was all-round appreciation. The transport arrangements were stated to be the best in any Olympics held in recent times. Any venue could be reached from any part of the town within 45 minutes. Majority of the main venues could be reached within 30 minutes.

ACCOMMODATION:

Greece was one of the smallest countries to host the Olympic Games. Therefore, the total number of hotel rooms available was smaller compared to previous venues like Sydney or Seoul. However, it was observed that Government of Greece did not at all intervene to ensure proper and reasonable priced accommodation for the visitors from other countries who had come to witness the games. The Private trade was given a free hand to manipulate the situation to their advantage. As a result, tour operators/agents made bulk bookings creating an artificial shortage. Rentals upto two and a half/three times of the normal rent were charged. This created a lot of ill will and resentment against the Greek Government amongst the visitors from other countries.

Just like the Greek Government had played a very pro-active role in the matters of security, transport and other infrastructure, it should have played an equally active role in the matter of management of accommodation for visiting citizens from other countries. This was considered to be one of the biggest flaws in the conduct of the Athens Olympics.

Greece's Olympic bill

The cost to Greece of hosting the 2004 Olympic Games came in at 9bn Euros ($11.6bn ; £ 6.3bn), double the original target, Greece is struggling to trim it's

budget deficit, which breaches European Union limits and has earned an EU rebuke. The Finance Minister said the final cost of organizing the 2004 Games--the most expensive ever - could go higher. He said 9bn euros was "the immediate cost for the state and does not include expenditures for infrastructure."

It excludes project such as the new airport and a high-speed tramline linking the airport to central Athens. Greece originally budgeted 4.6bn euros ($ 6bn ; £3.2 bn) for the games, compared to a budget of roughly $ 2bn (£ 1bn) for the 2000 Olympic Games, hosted by Sydney, which also suffered from cost overruns. Heightened security fears after the 9/11 attacks added unforeseen costs after Athens won its bid to become host city.

Construction delays also pushed up costs, leading to a hasty and expensive last-minute push to get venues ready in time.

INDIA'S PERFORMANCE AT THE OLYMPICS

India has won just 14 medals, including 8 Gold medals won by the hockey team, in the 104 years history of modern Olympics. The last time India won a Gold medal was in the Moscow Olympics in 1980. For the Athens Olympics India fielded a 75-members contingent, which included 19 Athens (14 women).

The India boxers and weightlifters could not proceed beyond the initial rounds. Sh. Jitender Kumar and Sh. Vijender lost their opening bouts in boxing. Kunjarani Devi, ended fifth in the 48th Kg. Category of the weightlifting competition. The only encouraging performance was by Indian tennis doubles team of Leander Paes and Mahesh Bhupathi. Before reaching the man's doubles semi-final, they defeated top players like Andy Roddick & Mardy Fish of USA and Roger Federer & Yves Allegro of Switzerland.

The only medal winning performance was given by Major Rajyavardhan Singh Rathore, who won a silver medal in men's double trap shooting. He not only ended the medal drought for India, but also became India's first individual Olympic silver medalist since Independence. Medal hopes in 63 kg. Women's weightlifting from Karnam Malleswari, Bronze medallist of Sydney Olympics, evaporated after she retired after her first attempt to clear a snach of 100 kg. failed. She subsequently complained of stomachache and withdrew from the event.

Two other Indian women wightlifters, Pratima Kumari and Sanmacha Chanu, were disgraced following positive dope tests. This raised a serious question mark regarding the credibility of SAI testing laboratory. All Indian weightlifters, participating in the Athens Olympics, had been subjected to testing in SAI dope testing laboratory in New Delhi.

Indian Athlete K.M. Binu who had set a new national record of 45.08 seconds in 400 metres in the first heat did not perform well in the semi-final and finished 7th clocking 45.97 seconds.

The Indian Hockey team, from whom, much was expected, gave a pathetic performance. The team lost four matches from Holland, Newzealand, Australia and Pakistan. It was with great difficulty that they secured the 7th position after defeating South Korea. The Indian not only looked disappointed but did not learn

[Shri Phool Chand Mullana]
from their mistakes. In addition, there were differences between some players and the team management.

In wrestling, great hopes from the Indian wrestlers were belied. While Palwinder Cheema (120kg.) lost both his preliminary bouts, the performance of Sh. Anju Kumar (84 Kg.) and Sh. Yogeshwar Dutt (55 Kg.) was no better. Sh. Ramesh Kumar (66 Kg.) was the only saving grace, who after losing his first bout came back to win the second. In Greco-Roman wrestling, India's lone entry Sh. Mukesh Khatri was also eliminated in the first round.

Anju Bobby George, even though she set a National record of 6.83 metres in the women's long jump event, could finish only sixth. The Russians made a clean sweep by winning all the three medals.

CONCLUDING REMARKS

Dis-appointment and dis-qualifications marked the 28th Olympic Games for India. Rajyavardhan Rathore's silver medal was the only bright spot for the country of more than one billion people.

No one expected the 28th Olympic Games to go so well. All who had forecast that the games would be a general disaster had to take back their words. Actually, hosting of the Olympics has turned out to be a big bonanza for Athens. Its infrastructure is really looking up. Millions of people who may otherwise never visit Greece and Athens have taken very fond memories after spending a lot of Euros. This has significantly boosted tourism and other related infrastructure. The city and its suburbs have gained in as big way in terms of broad, freshly-laid, four laned road network, new metro lines, new Airport and a general mass sanitation drive. The fact that Athens could host such an event successfully and still make some money speaks for itself. In today's world, good marketing ensures that any mega event involving expenditure of billions of Euros can be managed efficiently provided there is a proper vision, proper marketing and resolve to achieve lofty targets. It has also been learnt that the next Olympics in Beijing have already achieved financial closure. They are going to be money-spinners and leave behind a very impressive infrastructure for the Chinese citizens. Delhi is going to host 2010 Commonwealth Games. We have been making tall claims about ensuring world-class infrastructure for these games. However, mere involvement of Government or Sports Officers is not going to achieve much. The role of multinational corporations and other private sectors companies cannot be limited to a few routine things. Many of the jobs will have to be out sourced just as it was done in Athens.

All in all, it was a very rewarding experience being part of the Olympics movement. We are grateful to the Government of Haryana for giving us the opportunity to witness the Olympic Games. We hope that the observations and suggestions given above will be helpful to the State Government in planning and organizing activities related to sports infrastructure and sports competitions in future.

Annexure — C

THE XVIIITH COMMONWEALTH GAMES AT MANCHESTER

A REPORT REGARDING THE VISIT OF SH. D.S. DHESI, IAS, COMMISSIONER & SECRETARY TO GOVT. HARYANA, SPORTS AND YOUTH WELFARE DEPARTMENT AND SH. M.S. MANN, IPS DIRECTOR, SPORTS & YOUTH WELFARE DEPARTMENT, HARYANA.

AIMS & OBJECTIVES

Everybody is aware that Haryana is an emerging State in the field of sports. The Hon'ble Chief Minister has laid special emphasis on development of sports infrastructure for better end results.

The objectives of the visit of the official delegation was to study the following.

1. Lay out of sports infrastructure.
2. Sports facilities.
3. Standard of sports.
4. Interaction with sportspersons, sports personalities and sports officials for the benefit of sports in Haryana.

During the XVIIth Commonwealth Games at Manchester from July, 25th to August, 4th, 2002, the competitions were held in 14 individual sports and three team sports at 11 venues, 72 nations participated consisting of approximately 5000 sportspersons. The most impressive part of the games was the organisation and conduct of the opening and closing ceremony of the games. The most important feature was the creation of latest designed infrastructure and the best possible invisible security system and transport arrangements. City of Manchester Stadium was the epicentre of the Commonwealth Games.

On 25th July, we attended the inaugural ceremony of the Commonwealth Games. The ceremony was held in the main Stadium— ***City of Manchester Stadium***. This has a capacity to seat 50,000 spectators. The Presentation was extra-ordinary. The Chief Guest for this ceremony was the Queen of England.

The Indian women's hockey matches were held in the Belle Vue Regional Hockey Centre. We witnessed the league matches in progress. We also took the opportunity of inspecting the wonderful water based synthetic surface infrastructure.

The Indian badminton team was star studded and consisted of International names like - Pulela Gopichand and Aparna Poput. To see the Indian team play in the competition, we went to the magnificient Bolton Arena venue for the games of badminton.

We had the opportunity of witnessing the track and field events. The venue for this was the ***City of Manchester Stadium***. India had some athletes participating here. We saw some spectacular performances by Anju George who won bronze

[Shri Phool Chand Mullana]

medal. Neelam J. Singh — a girl from Haryana now selected in Punjab hurled the discuss to win the bronze medal for the Nation. The facilities and management of the stadium were exemplary and we picked up many good points for our benefit.

We had inspected the G-Mex Indoor Stadium-the venue for Judo/Wrestling competition. We had the opportunity of witnessing the Indian Judokas/Wrestler in action. The Stadium had excellent facilities. Here we saw the Indian specially the Haryana Wrestler in action. Indian wrestlers mainly two from Haryana in the 66 Kg. category--Ram Singh and in 55 Kg. category--Krashan won the gold medals and made India and Haryana proud.

The closing ceremony of the XVIIth Commonwealth Games was held on 4th of August, 2002. The ceremony was attended by the dignitaries of sports, all the important personalities of the United Kingdom were present. The presentation was excellent with hightech display of fire works. The sportsmen coming from various Countries and Cultures were emotional as they were being seen off by the hosts England.

India's Performance at the Games

India's inspired performance in the 17th Commonwealth Games has not only come as a breath of fresh air for a country which has always struggled to make a mark at the international level but will also serve as launching pad for the sportsperson to attain greater heights.

The 148-member contigent return with the best-ever haul of 32 gold, 21 silver and 19 bronze medals to take the third position on the medals table and emerge as a major force in the Commonwealth sporting fraternity.

The spectacular display of the Indian sportspersons warned the hearts of millions of countrymen and the gold booty was all more creditable since it had never exceeded 13 gold in the history of the Games.

Though the Indians did not pose a serious challenge to traditional powerhouses Australia and England who expectedly occupied the first two positions, their unprecedented gold collection made them the surprise package of the Games.

The Indian were expected to put up an improved show at the Games this time around, but nobody really thought they would take in as many as 72 medals.

Although there were many star performers and first-time achievements in India's dream run at this north-western English city,the shooters and the lifters did the bulk of the shopping as many as 27 of the 32 gold.

But in India's phelenomenal success at the Games lost some sheen with lifter Krishan Madasamy testing positive for the performance enhancing drug nandrolone- the only moment of disgrace for the Indians. The 28 years old lifter was stripped of all the three silver medals, he won in the 56 Kg. category.

The shooters were the toast of the nation as they virtually set the ranges in

Bisley ablaze with their gold grabbing feasts to complete their engagements with a rich haul of 14 gold, 12 silver and 2 bronze medals-their best showing in the Commonwealth Games so far.

Pistol King Jaspal Rana and Anjali (Ved Pathak) Bhagat provided the sparks by clinching as many as gold medals each while talented youngester Abhinav Bindra (one gold and one silver) also made his presence felt with his heroics.

The weightlifting arena proved to be a happy hunting ground for the Indians as it brought 13 gold medals thanks to the women lifters who amply proved their class by fetching the bulk of the golds.

Seasoned lifter N. Kunjarani Devi (48 kg.), Sanamach Chanu (53 kg.) and Shailaja Pujari (75 kg.) reigned supreme as they made a clean sweep of all the three gold medals in their respective categories.

The women's weightlifting event was held for the first time in these Games and the Indian eves made the most of it.

Satheesha Rai also had his moment of glory picking up two gold medals in the men's 77 kg. while Partima Kumari narrowly missed clean sweep in the women's 63 kg. and had to be content with two gold and a silver.

The Indian women's hockey team also fulfilled a long-cherised dream of winning a gold medal in the event which had never brought them a medal till now.

The Indian eve fought back brilliantly after almost being knocked out of the championship at stage to clinch their first medal in women's hockey though the Summit showdown against hosts England ended in controversial fashion.

India's moment of glory had to wait for a brief while as the umpire initially disallowed the golden goal by Mamta Kharab, the young player from Haryana, but changed her mind after discussing with her fellow umpire and consulting technical committee officials, prompting protests from the England team.

It was indeed a remarkable performance from the Indians as they demolished highly rated teams like South Africa, New Zealand and England during their giant-killing spree.

After finishing third in pool-B, the Indians were a transformed lot in the play-off stage and the two come-from-behind victories against South Africa and New Zealand boosted their confidence ahead of the final.

The dream victory should go a long way in giving the desire confidence to the team which has struggled to make a mark at the international level because of its in consistency.

Light flyweight pugilist Mohammed Ali Qamar also made history by becoming the first Indian Boxer to clinch a gold medal in the Commonwealth Games by prevailing over England's Darren Langley in a closely contested final.

Another Indian boxer Som Bahadur Pun managed to reach the final but could not defeat Pakistan's Hyder Ali and had to be contented with the silver medal.

[Shri Phool Chand Mullana]

The India grapplers, who joined the action towards the later stage of the Games, contributed to the gold deluge by claiming three gold and two silvers and one bronze.

Krishan Kumar (up to 55 kg.). Ramesh Kumar (up to 66 kg.) and Palwinder Singh Cheema (up to 120 kg.) were the gold winners from the wrestling arena while Anuj Kumar fetched a silver in the up to 84 kg. category.

While the squads in most of the disciplines brought cheer to the country, the shuttlers and the paddlers failed to strike gold though they did manage to pick up a couple of bronze medals.

Star performers Pullela Gopi Chand and Aparna Popat failed to live upto their awesome reputations in these Games much to disappointment of Badminton fans.

Gopi Chand suffered a stunning straight-set defeat at the hands of Malaysia's Choong Haan Wong in the quarter finals to make a premature exit in the men's singles while Popat could not advance beyond the semi-final stage.

The Indians took part in ten disciplines and won medals in nine with only the gymnasts returning home empty handed. The medal deluge in the Commonwealth Games will raise the level of expectation when contingent leaves for the Asian Games in Busan but it remains to be seen whether they can come anywhere near the record tally of 72 medals.

Performance of Sportsmen from Haryana

The Sportsmen from Haryana gave an outstanding performance during the games for which they deserve to be congratulated and given every type of incentive.

Out of the 72 medals won by India, 9 medals were won by the players of Haryana. The details are given below:—

Sr. No.	Name of the Players	Game	Medal won by the player
1.	Sh. Charan Singh S/o Sh. Birbal, Gurgaon	Shooting	Gold Bronze
2.	Sh. Ramesh Kumar S/o Sh. Balwan Singh, Sonepat	Wrestling 66 Kg.	Gold Medal
3.	Sh. Krishan Kumar S/o Sh. Suraj Bahn Kundu, Panipat	Wrestling 54 Kg.	Gold Medal
4.	Smt. Pritam Siwach W/o Sh. Kuldeep Siwach	Hockey	Gold Medal
5.	Km. Suman Bala D/o Sh. Tej Pal Saini, Kurukshetra	Hockey	Gold Medal

Sr. No.	Name of the Players	Game	Medal won by the player
6.	Km. Mamta Kharb D/o Sh. Hari Pal, Rohtak	Hockey	Gold Medal
7.	Sita Gosain D/o Sh. Umarao Singh, Ambala	Hockey	Gold Medal
8.	Pratima, Yamunanagar	Weight Lifting	Gold Medal
9.	Sweta Chaudhary D/o Sh. Ramesh Chaudhary, Faridabad	Rifle Shooting	Siver Medal
10.	Neelam J. Singh, Rohtak	Discus Throw (Ath)	Silver Medal
11.	Jitender Kumar S/o Sh. Om Parkash	Boxing	Bronze Medal

OBSERVATIONS

Infrastructure

Modern and scientific infrastructre is a very important aspect to improve the standard of sports in any country. This is very evident from the words of British Prime Minister Mr. Tony Blair on the occasion of the Commonwealth Games- " the facilties will leave behind the legacy of super sporting facilities which will serve the city and surrounding area and region for decades to come". This statement gives a very clear cut message that by sports we can produce world class sportsmen.

The basis of locating the staduas were :

1. Every stadium was well-linked with air, rail and road travel facilities.
2. Consisted of adequate utility system.
3. Consisted of world class communication facilities.
4. Sufficient area was ear-marked for parking in every stadium.

The infrastructure was perfect and we could see how the modern technology can be applied in sports.

City of Manchester Stadium

This was the main stadium which was the Centre piece of the Commonwealth Games. This was the venue for;

Opening ceremony

Closing ceremony

Track & field

[Shri Phool Chand Mullana]

The stadium was equipped with synthetic athletics track and had facility to stage competition during day and night. Capacity of the stadium was 38000 spectators.

Belle Vue Regional Hockey Centre

This is a stadium which has undergone renovation of 3.00 million pounds redevelopment plan. It now incorporates two water-based hockey pitches and many other new sports features. Since India is a Hockey Playing Country, we should create such modern facilities in the Hockey infrastructure in the Country.

The G-Max Indoor Stadium

This stadium has the capacity to host world class wrestling and has a seating capacity of 6000 spectators. The stadium has beautiful lighting system and acoustics are super. We recommend to have such facilities in our Country and State.

Bolton Arena

This was the stadium ear-marked for badminton at the games. This consisted of five main and five practice courts, well-lighted, wood based flooring having a beautiful three side (east south and north) spectator gallery.

MEN-Arena

It is a multipurpose stadium having a capacity of more than 25000 the site of Boxing events.

City Gymnastic Centre

It is a multipurpose hall and was venue of gymnastic events. The hall is equipped with latest infrastructural facilities.

Management Techniques

Principles of Management make the projects run successfully. This was seen in the **XVIIth Commonwealth Games at England.** The Government of England, at the very outset, created Principles of Management make the projects run successfully. This was seen in the **XVIIth Commonwealth Games at England.** The Government of England, at the very outset, created a company which was solely responsible for the **XVIIth Commonwealth Games—Manchester, 2002** limited. This company had to handle the Commonwealth games projects worth an amazing-165 million British pounds. The objects for the management team were very clear.

(i) To continue organizing and staging of successful international sporting events.

(ii) To help to provide a lasting sporting legacy for Manchester the north west region and the whole Country.

(iii) To support English sports governing bodies and their teams of athletics in their preparations for the games.

Here we can observe how the National prestige and pride is imbibed at every stage of managing the show.

We also observed that the total concept was divided into two parts the technical and non-technical which was further decentralized to achieve maximum output for bringing perfection in managing the games.

The seating arrangements at each venue of function/games were very impressive and well-organized. Although at most of the venues, the arrangement was temporary but at every venue each seat was numbered. The participation of voluntary organisations was praise worthy at every contact point at the venues of functions and other public places. The invisible security system and transport arrangements at each venue of functions, games and other public places was praiseworthy.

It was a matter of honour for us that we were deputed by the Government of Haryana to witness the Commonwealth Games. We are sure that experience gained from this tour will be useful for the benefit of sports and sportsmen of Haryana.

Annexure—D

The 14th Asian Games 2002

Busan Korea

A report regarding the visit of Sh. M.S. Mann, IPS, Director Sports & Youth Welfare Haryana.

AIMS & OBJECTIVES

Haryana is an emerging State in the field of sports. The principal aims of the new sports policy launched by the State Government is to create a sports culture in the State. The policy seeks to create infrastructure even at the village level.

The objective of the visit of the official delegation was to study the following :—

— Lay out of sports infrastructure.

— Sports facilities.

— Standard of Sports.

— Interaction with sportspersons, sports personalities and sports officials for the benefit of sports in Haryana.

During the 14th Asian Games 2002 at Busan Korea from September, 29th to October, 14th, 2002, the competitions were held in 38 games events at 44 venues i.e.31 venues in Busan and 13 venues in neighbouring cities that in Ulsan, Changwon, Masan, Yangsan. The 2002 Busan Asian Games the first Asian Games of the 21st century, was a great festival of 3.7 billion Asians unity and prosperity. comprised 38 events, 11,00 Athletics and staff and 7,000 press corpses. Most of all,

[Shri Phool Chand Mullana]
it was the largest Asian Games in terms of size. As North Korea participated in the Asian Games, it opened a new age of world peace and harmony. **The ideology of the Games "New vision, new Asia" and the slogan was "One Asia, Globle Busan".**

The most impressive part of the games was the organization and conduct of the opening and closing ceremony of the games. The most important feature was the creation of latest designed infrastructure and the best possible invisible security system and transport arrangements. City of Busan Main Sports Complex was the Epicenter of Asian Games. The role of non-governmental Agencies was extremely laudable.

The theme of the Opening Ceremony was "Beautiful Union", which revives the union between King Kim Suro and Hur Hwangok in Gaya (Busan in ancient times). This " Historical Union" symbolizes the unity and hope of 3.7 billion Asians.

The theme of the Closing Ceremony is "Going Home". The Koreans wish everyone a safe and pleasant journey back to their homelands. The ceremony also focused on Busan as a well-known migratory bird destination, symbol of safe and pleasant travels from one destination to another. Like a mother biding farewell to her children. Busan said goodbye to the more than 10 thousand visitors from the across Asia with a message from Vice President Samih Moudallal Olympic Council of Asia, **" I call upon the youth of Asia to assemble in 4 years...May they celebrate the Asian Games in the spirit of brotherhood and for the good of humanity".**

The emblem of the 14th Busan Asian Games embodies the spirit of Busan with Teageuk and the blue sea waves that symbolize Korea and Busan, respectively, as basic motifs. The complex image of the waves also expresses the prosperity and unity of the Asian people.

The Mascot of the 14th Asian Games was a sea gull, the city bird of Busan which emphasizes the dynamic and pure image of Busan, a vision of a world class city and the progressiveness of the citizens spirit. It expresses the ideal of the Games that promote unity and partnership and everlasting development among Asian Countries .

Infrastructure

By providing modern and scientific infrastructure and incentives the standard of Sports in the country can be considerable improved. This is evident as from the fact that with modern scientific infrastructure and spirit of competitiveness South Korea ranked IInd in the Asian Games with 96 Gold Medals 80 Silver Medals and 84 Bronze Medals whereas India ranked 7th with 11 Gold Medals 12 Silver Medals and 13 Bronze Medals.

The Asian Games were held at 44 venues i.e. 31 venues in Busan and 13 venues in neighbouring cities. Every venues was linked with Rail/Road travel facilities, consisted of adequate utility system, communication facilities and sufficient parking facilities. The main stadium and 11 others were newly built while

existing facilities were refurnished in other stadiums. The city had excellent sub way (Trains) and Limousine Bus Service, well-connected to the Airport.

Busan Sports Complex

It was the main stadium, **venue of opening and closing ceremonies,** Athletics Basketball, Swimming, Baseball and Soft Tennis. It was built on a 3,30,000 Sq. Met. Plot. The main stadium had a accommodating capacity of 54,000 spectators and 80% of them are covered with roofs. It is a mutipurpose sports complex that can accommodate various performances and cultural events. The stadium is designed in a ball-shaped building featuring the first domestic roof instructed in the form of a tensile cable dome structure that can cover 100% of the stand. The roof material used in connection with a Teflon coating film to provide subtle natural lighting. The basic scheme of the sheets follows that of Korean tradition and the seats are arranged to express unity and harmony.

In addition to the main Athletic Stadium, the main Sports Complex consists of Gymnasium, Swimming Pool, Basketball Stadium and the Tennis courts.

In the main stadium the undersigned had the opportunity of witnessing the performances of Sh. Shakti Singh and Sh. Anil Kumar (Discus Throw) Smt. Neelam, Jai Singh Athletics (Discus Throw) and relay race of the team consisting of Sh. Satbir Singh and Sh. Bhupinder Singh.

Geumjeong Sports Park

It was the venue of Basketball, Cycling and Tennis having an area of 291, 190 Sqr. Mtr.

Gangseo Sports Park

It had two sports complexes i.e. Hockey Stadium and the indoor stadium for Badminton Fencing and Archery. The Sports park was built on an area of 208,487 Sqr.Mtr. The Hockey stadium had wonderful water-based synthetics surface infrastructure. The Men Hockey match between India and Pakistan and India and Korea were the star attractions. However, the performance of the Indian Women Hockey team was very poor and it needs introspection into the causes of defeat.

The other mutipurpose stadium had practice courts, well-lighted, maple wooden flooring and spectator gallery. During the visit, I had the opportunity of witnessing the Game of Indian badminton Star Pulela Gopi Chand.

Gijang Gymnasuim

It was the venue of Volleyball. The main complex had been built on an area of 59,763 Sqr.Mtr. The Gymnasium had beautiful wooden flooring, excellent lighting arrangements and Spectators Gallery.

Masan Gymnasium

It was the venue of Boxing competitions. The Gymnasium capacity of 6,000 seats.

[Shri Phool Chand Mullana]

Yangsan Gymnasium

The venue of wrestling events. The gymnasium capacity of 3,500 seats. Although no medal had been won by Haryana wrestlers but their performance was extremely good.

Tongmyong University of Information Technology (Stadium)

It was the venue of Kabaddi. The Gymnasium had a seating capacity of 3,000. During the Games, the undersigned had the opportunity of witnessing the Indian Team in action. In the team six players i.e. Sh. Shamsher Singh, Sh. Ramesh Kumar, Sh. Jagdish, Sh. Ram Mehar, Sh. Sunder Singh and Sh. Nir Gulia were from Haryana. the team won a Gold medal.

Main Media Center

The International Broadcasting Center (IBC) and the Main Press Center were installed at the Busan Exhibition and Convention Center (BEXCO). The MMC served as a convenient and efficient platform to cover and file reports for Journalist from OCA member Countries.

Athletic Village

Athletic Village was constructed on an 1,15,000 Sqr.Met. plot in a convenient location. It was a superb blend of rocks and ravine, beautiful integrated township. Over 13,000 athletes and officials were housed in 2290 apartments. The village included a variety of facilities to keep the athletes in top physical conditions. The villages cultural programmes included Korean traditional folk music, city tours, corporate visits as well as performances and exhibitions showing traditional arts and entertainments from various Asian nations.

Performance of Sports Persons of Haryana

The performance of sports persons of Haryana was outstanding during the games. The Haryana sportpersons had won 2 Gold medals 1 Silver medal 4 Bronze medals. The details are as under :—

Sr. No.	Name	Game	Achievement	Remarks
1.	Sh. Shamhser Singh	Kabaddi	Gold Medal	Sr. No. 1-6, Team event— One Gold Medal
2.	Sh. Ramesh Kumar	—	—	
3.	Sh. Jagdish	—	—	
4.	Sh. Ram Mehar	—	—	
5.	Sh. Sunder Singh	—	—	
6.	Sh. Nir Gulia	—	—	

Sr. No.	Name	Game	Achievement	Remarks
7.	Smt. Neelam Jai Singh	Athletics-Discus Throw	Gold Medal	
8.	Sh. Shakti Singh	Athletics-Discus Throw	Bronze Medal	
9.	Sh. Anil Kumar	Athletics-Discus Throw	Bronze Medal	
10.	Sh. Inder Pal Singh	Rowing	Bronze Medal	
11.	Sh. Satbir Singh	Athletics-Relay	Silver Medal	Sr. No. 11-12, Team events
12.	Sh. Bhupinder Singh	Athletics-Relay	—	—
13.	Sh. I.S. Lamba	Equestrarian	Bronze Medal	Sr. No 13-14 Team event
14.	Major Deep Chand Ahlawat	Equestrarian	—	—

However after winning Gold Medals in Common wealth Games, the performance of Indian Hockey team was very discouraging, which needs introspection in the cause of defeat.

The Busan Asian Games Organizing Committee and the Busan City Government were actively associated in hosting the Games. In order to ensure that the games are success, programmes for each game have in produced and experts from the General Association of Asian Sports Federations have been invited to lend their accreditation to the Games. 22,000 Volunteers, crucial to the success of the Asiad were well trained and extremely cooperative. The Computer network and medical facilities were commendable. The accreditation system was very efficient. In addition to the various venues of games/athletics village, Hotel Lotte Busan, Asian Games Headquarters provided excellent opportunity of interaction among various sports personalities and sports officials. The seating arrangement at each venue of function/Games were very impressive and well-organized. Although at most of the venues, the arrangement was temporary but at every venue each seat was numbered. The participation of voluntary organizations was praiseworthy at every contact point at the venues of functions and other public places. The invisible security system and transport arrangements at each venue of function/games and other public places was praise worthy. The participation of the private sector was commendable. The Samsung's sport of the torch relay for the Asian Games was appreciated by all.

[Shri Phool Chand Mullana]

It was a matter of honour for us that I was deputed by the Government of Haryana to witness the 14th Asian Games. I am sure that experience gained from this tour will be useful for the benefit of sports and sportsmen of Haryana.

Submitted for perusal please.

श्री रणबीर सिंह महेन्द्रा : अध्यक्ष महोदय, मैं आपके माध्यम से मंत्री जी से पूछना चाहता हूँ कि क्या इसमें फोलोअप एक्शन हुआ है।

श्री फूल चन्द मुलाना : अध्यक्ष महोदय, हुआ है। जो हमारे मैम्बर्ज इन ओल्मपिक और एशियन गेम्ज में गए थे उन्होंने अपनी रिपोर्ट दे दी है। अध्यक्ष महोदय, उन्होंने जो हमें सुझाव दिए थे उस पर ऐक्शन हो रहा है।

श्री रणबीर सिंह महेन्द्रा : अध्यक्ष महोदय, मैं आपके माध्यम से माननीय मंत्री जी को बताना चाहूँगा कि यह रिपोर्ट श्री नरेश गुलाटी ने दी थी। उस रिपोर्ट में यह लिखा है कि —

10.00 बजे

"The important feature for the upliftment of sports standard in India is 'The Selection of the Sports Talent.' All the major countries in the world who have been doing well in the sports have tried to select their sportspersons at a very early age. In some of the countries the sportspersons are identified even at the age of five or six and then they are made to undergo a basic training and finally they are picked up for their specialized training ?"

Thereafter he has talked about infrastructure and then he has also suggested about 'Orgainse more structured competitions' at Panchayat level and Block level. And he has also talked about 'Training for Trainers'. These points have been suggested by Mr. Naresh Gulati. Has the Department at any stage given plan in a way to give it to the Finance Department so that necessary steps could have been taken ?

This has also been reported in this Report that Olympic Games and Commonwealth Games will be held in 2008 and 2010 respectively. Will the Minister for Sports & Youth Affairs be pleased to state that what preparations in this ragard are going to be made?

Shri Phool Chand Mullana : On the basis of the Report and feed-back received from various quarters, the Government is taking necessary steps to develop the infrastructure and talent of sports, what my friend Mr. Ranbir Singh Mahendra has said. These nurseries are running and children of the age from 10 to 15 are taken in these nurseries. So far as the question of putting the case to the Finance Department. Hon'ble Chief Minister, Haryana is very vigilant and curious about the development of Sports. And this year the Budget of Sports is going to be more than doubled.

मुख्यमंत्री (श्री भूपेन्द्र सिंह हुड्डा) : अध्यक्ष महोदय, क्योंकि यह स्पोर्टस से संबंधित सवाल है इसलिए मैं माननीय सदस्यों की जानकारी के लिए एक खुशी की बात बताना चाहता हूँ।

हमारी हरियाणा की बेटी सीमा अंतिल ने आस्ट्रेलिया के मेलबोर्न में चल रहे कामनवैल्थ गेम्ज में एक सिल्वर मैडल हासिल किया है। हरियाणा सरकार की तरफ से उसको पांच लाख रुपये पुरस्कार के रूप में दिए जाएंगे। (थम्पिंग) अभी नरेश गुलाटी की पत्रकारों से चर्चा की बात माननीय सदस्य ने की है। मैं सदन को बताना चाहूँगा कि गांवों में स्टेडियम हों, इस बात के लिए हम गहराई से सोच रहे हैं और हरियाणा सरकार ने यह फैसला किया है कि जहां-जहां पर गांवों में रूरल स्टेडियम की बात आएगी हम एच०आर०डी०एफ० से इस साल के बजट में कम से कम तीस या चालीस करोड़ रुपये इनके लिए अलॉट करेंगे।

Construction of Roads

*477 **Shri Ramkishan Fauji** : Will the Minister for P.W.D. (B&R) be pleased to state—

(a) whether it is a fact that the construction work of road from Hansi to Tosham, Hajampur to Tosham and Tosham to Bahal has been stopped in the middle ; if so ; what are the reasons thereof ; and

(b) whether there is any proposal under consideration of the Government to complete/repair the roads referred to in part (a) above ; if so, upto what time the said roads are likely to be completed/repaired ?

Transport Minister (Shri Randeep Singh Surjewala) :

(a) Yes, Sir. The work has been withheld because of complaints regarding quality of work and for reassessing the scope of work.

(b) After completing the investigation, further action will be taken as necessary.

श्री रामकिशन फौजी : अध्यक्ष महोदय, माननीय मुख्यमंत्री जी की मेहनत के कारण इस रोड के लिए 1775.64 लाख रुपये का बजट पास किया गया था और आज से 11 महीने पहले इस काम के लिए टैंडर हुए थे और काम शुरू हुआ था। प्रश्न के उत्तर में दिया गया है कि ठेकेदार ने इस काम में गलत काम किए हैं इसलिए इसकी इंक्वायरी चल रही है और इंक्वायरी पूरी होने के बाद ही काम शुरू किया जाएगा। अध्यक्ष महोदय, मैं आपके माध्यम से मंत्री महोदय से जानना चाहूँगा कि अब तक 11 महीने तो हो चुके हैं इसलिए यह काम शुरू करवाया जाना चाहिए। हाजमपुर से तोशाम और हांसी से तोशाम की सड़कों की बहुत बुरी हालत है। मंत्री जी बताएं कि कब तक यह इंक्वायरी पूरी करवाकर इस काम को शुरू करवा देंगे ?

श्री रणदीप सिंह सुरजेवाला : स्पीकर सर, जैसा कि माननीय सदस्य ने स्वयं कहा कि 1775.64 लाख रुपये इस सड़क के लिए सरकार ने दिये थे। इस सड़क की कुल लम्बाई 63.50 किलोमीटर है। स्पीकर सर, सरकार ने 15.4.05 को भिवानी डिवीजन के लिए और 22.7.2005 को चरखी दादरी डिवीजन के लिए ठेकेदार को कान्ट्रैक्ट भी दे दिया था। मैटलिंग स्टेज तक यह काम भिवानी डिवीजन में हो चुका था और आगे भी यह काम जारी है लेकिन वहां के लोगों से उस कान्ट्रैक्टर की काफी शिकायतें आई जिसके बाद विभाग ने उसकी शिकायतों की जांच के आदेश दे दिए। जांच

[श्री रणदीप सिंह सुरजेवाला]

पूरी होने के बाद अगर उस कान्ट्रैक्टर के काम में कोई कमी पाई गई तो उसके खिलाफ कार्यवाही की जायेगी। इस समय ऐसी सड़क बनाने का कोई लाभ नहीं होगा जो बनने से पहले ही टूट जाए। स्पीकर सर, वहां के नागरिकों की शिकायत पर ही जांच के आदेश दिए गए हैं, हम पूरे प्रयास करेंगे कि यह काम जल्द से जल्द पूरा करवाया जाए।

Construction of the Building of PHC's/Hospitals of Karora, Mundhri and Deoban Villages

*377. **Shri Tajendra Pal Singh Mann :** Will the Minister for Health be pleased to state—

(a) whether there is any proposal under consideration of the Government to construct the building for the PHC's Hospitals of Karora, Mundheri and Deoban Villages of Pai Constitutency in Kaithal district which are running in rented building presently and ;

(b) if so, upto what time the aforesaid proposal is likely to be materialized ?

स्वास्थ्य मंत्री (बहन करतार देवी) :

(क) जी नहीं, श्रीमान।

(ख) सवाल नहीं उठता।

श्री तेजेन्द्रपाल सिंह मान : स्पीकर सर, सरकार की पहली प्राथमिकता है कि लोगों को स्वास्थ्य सुविधाएं देने के लिए ख्याल रखा जाये। सरकार द्वारा 12-13 साल पहले एक पी०एच०सी० खोलने की घोषणा की गई थी। उस समय लोगों ने यह समझ कर जमीन और छोटा सा भवन दे दिया था कि सरकार द्वारा इसके लिए पैसा दे दिया जायेगा और पी०एच०सी० की बिल्डिंग बना दी जायेगी। बहन जी, उस वक्त भी हैल्थ मिनिस्टर थी। उस समय पाई और जाखौली में पी०एच०सीज़० मंजूर की गई थी, लेकिन आज तक भी वहां पर कोई बिल्डिंग नहीं बनाई गई है। सर, आप जानते हैं कि चिकित्सा एक ऐसा मसला है कि गरीब आदमी आजकल के महंगे माहौल के अन्दर प्राइवेट डाक्टरों के पास नहीं जा सकता। अगर सरकारी पी०एच०सी० नहीं होगी तो इसका खामियाजा गरीब आदमियों को भुगतना पड़ेगा।

Mr. Speaker : Mann Sahib, please ask your supplementary.

श्री तेजेन्द्र पाल सिंह मान : सर, वहां पर बिल्डिंग न होने के कारण डॉक्टर आते नहीं हैं जबकि गांव वालों ने जमीन भी दे रखी है। इसके कारण सिर्फ गरीब आदमियों को ही तकलीफ होती है। क्या सरकार आश्वासन देगी कि वहां पर पी०एच०सी० की बिल्डिंग बना दी जायेगी ? अगर वहां पर बिल्डिंग होगी तभी वहां पर डाक्टर जायेंगे।

बहन करतार देवी : स्पीकर सर, माननीय सदस्य बहुत वरिष्ठ हैं इनको सरकार की सारी नीतियों और प्रोग्रामों का पता है। जब पी०एच०सी० खोली जाती है तो पंचायत यह कहती है कि जब तक सरकारी भवन नहीं बनेगा तब तक के लिए ग्राम पंचायत स्वास्थ्य विभाग को कोई इस तरह के

भवन दे देती है उसके बाद ही ऐसी जगहों पर पी०एच०सी० खोलते हैं। उसके बाद सरकार उस भवन के लिए जमीन नहीं खरीदती है बल्कि जमीन पंचायत द्वारा ही दी जाती है। लेकिन अभी तक करोड़ा, देबन, मुंदड़ी की पंचायत की तरफ से कोई प्रस्ताव नहीं आया है। ऐसा पता लगा है कि इन दोनों गांवों की पंचायत ने जमीन देने का प्रस्ताव पास करके पंचायत विभाग को भेजा है। जब पंचायत विभाग इसकी स्वीकृति दे देगा तो वह जमीन स्वास्थ्य विभाग के नाम ट्रांसफर हो जायेगी और तभी उस प्रस्ताव पर अवश्य विचार किया जायेगा।

श्रीमती गीता भुक्कल : अध्यक्ष महोदय, मैं आपके माध्यम से माननीय मंत्री महोदया से जानना चाहती हूँ कि कलायत हल्के के गांव बड़सीखरी में एक पी०एच०सी० खोलने का प्रस्ताव काफी समय से पैंडिंग था। जैसा कि मुझे इन्फर्मेशन मिली है कि 10 तारीख को वहां पर चण्डीगढ़ से इनके विभाग की टीम ने जाना था। वहां पर हम उनका काफी इन्तजार करते भी रहे लेकिन चाहे कोई भी कारण रहे हों, वह टीम उस दिन वहां पर नहीं गई। यह उस गांव की काफी पुरानी मांग है और इस तरह की प्रोपोजल विभाग में पैंडिंग भी है। इसी तरह से सीसर गांव जो जिला जींद में पड़ता है उसमें पी०एच०सी० प्राईवेट बिल्डिंग में चल रही है। मंत्री जी बतायेंगी कि क्या ऐसी कोई प्रोपोजल सरकार के पास पैंडिंग हैं कि उस पी०एच०सी० को सरकारी भवन में बदल दिया जाये।

बहन करतार देवी : स्पीकर सर, वैसे तो यह सवाल पाई हल्के के गांवों से संबंधित था लेकिन फिर भी मैं एक बार फिर से यह बात दोहराना चाहती हूँ कि जब पंचायत द्वारा जमीन देने का प्रस्ताव पास करके पंचायत विभाग को भेजा जाएगा, और बाद में पंचायत विभाग द्वारा उसकी स्वीकृति दे देने के बाद जब वह जमीन स्वास्थ्य विभाग के नाम ट्रांसफर हो जायेगी तब ही इस तरह के प्रस्ताव पर विचार किया जायेगा।

अध्यक्ष महोदय, हुड्डा साहब के नेतृत्व में हरियाणा में हमारी सरकार बनी और माननीय श्रीमती सोनिया गांधी के निर्देश पर रूरल हैल्थ स्कीम की घोषणा सरदार मनमोहन सिंह जी ने की है। अध्यक्ष महोदय, हमारी सरकार की यह टोप प्रायरटी है कि हम स्वास्थ्य सेवायें गांवों तक ही नहीं बल्कि हर आदमी के घर तक पहुंचायेंगे चाहे उसके लिए हमें मोबाइल वैन सेवा ही शुरू करनी पड़े।

तारांकित प्रश्न संख्या 408

(यह प्रश्न पूछा नहीं गया क्योंकि इस समय माननीय सदस्य श्री सोमवीर सिंह सदन में उपस्थित नहीं थे।)

तारांकित प्रश्न संख्या 445

(यह प्रश्न पूछा नहीं गया क्योंकि इस समय माननीय सदस्य श्री जय सिंह राणा सदन में उपस्थित नहीं थे।)

Opening of I.T.I. in Safidon

Shri Bachan Singh Arya : Will the Minister for Industries be pleased to state—

(a) whether there is any proposal under consideration of the Government

[Shri Badan Singh Arya]

to open an Industrial Training Institute in Safidon Constituency ; and

(b) if so, upto what time the aforesaid proposal is likely to be implemented ?

Industries Minister (Shri Lachhman Dass Arora) :

(a) No, Sir

(b) In view of (a) above, question does not arise.

श्री बचन सिंह आर्य : अध्यक्ष महोदय, मैं आपके माध्यम से मंत्री जी से पूछना चाहता हूँ कि सफीदों में आई०टी०आई० की मांग बहुत पुरानी है। इस समय वहां पर आई०टी०आई० की कोई शाखा नहीं है। सफीदों से जींद 32, पानीपत 34 और गोहाना 44 कि०मी० की दूरी पर है। इससे पहले सफीदों के आसपास कहीं कोई आई०टी०आई० नहीं है। वहाँ पर लोगों की मांग है कि आई०टी०आई० बनवाई जाये उसके लिए पांच से छः एकड़ जमीन भी हम पंचायत के माध्यम से देने के लिए तैयार हैं। क्या आदरणीय मंत्री जी मुख्यमंत्री जी से सलाह करके सफीदों में आई०टी०आई० बनाने की कोई प्रपोजल बनायेंगे ?

श्री लछमन दास अरोड़ा : अध्यक्ष महोदय, यदि सफीदों शहर आई०टी०आई० बनाने के नार्म्ज पूरे करेगा तो वहां पर आई०टी०आई० बनाने पर विचार किया जा सकता है। मेरे साथी ने कहा कि 5 एकड़ जमीन पंचायत देने को तैयार है यदि वहां पर 10-12 कमरे भी बनाकर ये सरकार के पास प्रपोजल भेजेंगे तो वहां पर आई०टी०आई० खोल देंगे।

तारांकित प्रश्न संख्या 417

(यह प्रश्न पूछा नहीं गया क्योंकि इस समय माननीय सदस्य प्रो० छतरपाल सिंह सदन में उपस्थित नहीं थे।)

Construction of Bus Queue Shelters

***425. Sh. Rakesh Kamboj :** Will the Minister for Transport be pleased to state—

(a) whether there is any proposal under consideration of the Government to construct Bus Queue Shelter in the following villages of Indri Contituency, district Karnal :—

1. Jhanjhari (on Karnal to Pipli road);
2. Salaru (on Karnal to Yamuna Nagar road);
3. Darar-Kurali (on Karnal to Yamuna Nagar road);
4. Rambha (on Karnal to Yamuna Nagar road);

5. Janesaron (on Karnal to Yamuna Nagar road);
6. Dera situated between Rambha & Dadar Kurali (on Karnal to Yamuna Nagar road);
7. Norta (on Karnal to Yamuna Nagar road);
8. Dhumsi (on Karnal to Yamuna Nagar road);
9. Phusgarh (on Karnal to Yamuna Nagar road);
10. Samora (on Karnal to Yamuna Nagar road);
11. Budha Khera (on Karnal to Yamuna Nagar via Garhi Biral road);
12. Bara Gaon (on Karnal to Yamuna Nagar via Garhi Biral road);
13. Newal (on Karnal to Yamuna Nagar via Garhi Biral road);
14. Chogawan (on Karnal to Yamuna Nagar via Garhi Biral road);
15. Labkari (on Karnal to Yamuna Nagar via Garhi Biral road);
16. Kalsora (on Karnal to Yamuna Nagar via Garhi Biral road);
17. Randoli (on Karnal to Yamuna Nagar via Garhi Biral road);
18. Chorpura (on Karnal to Yamuna Nagar via Garhi Biral road);
19. Chora (on Karnal to Yamuna Nagar via Garhi Biral road); and

(b) if so, upto what time these Bus Queue Shelters are likely to be constructed?

Transport Minister (Sh. Randeep Singh Surjewala) :

(a) Sir, out of 19 villages mentioned in the question, Bus Queue Shelters in 10 villages mentioned at Sr. No. 2 to 5, 8, 10, 12 to 14 and 19 have already been constructed which are listed below--

Sr. No.	Name of Village
2.	Salaru (on Karnal to Yamuna Nagar road);
3.	Darar-Kurali (on Karnal to Yamuna Nagar road);
4.	Rambha (on Karnal to Yamuna Nagar road);
5.	Janesaron (on Karnal to Yamuna Nagar road);
8.	Dhumsi (on Karnal to Yamuna Nagar road);
10.	Samora (on Karnal to Yamuna Nagar road);
12.	Bara Gaon (on Karnal to Yamuna Nagar via Garhi Biral road);
13.	Newal (on Karnal to Yamuna Nagar via Garhi Biral road);
14.	Chogawan (on Karnal to Yamuna Nagar via Garhi Biral road);
19.	Chora (on Karnal to Yamuna Nagar via Garhi Biral road)

[Sh. Randeep Singh Surjewala]

For the ramaining nine villages mentioned in the question at Sr. No. 1, 6, 7, 9, 11, 15, 16, 17 and18, no proposal is under consideration for construction of Bus Queue Shelters.

अध्यक्ष महोदय, मैं इसके साथ ही साथ माननीय साथी को कहना चाहूँगा कि वे इस बारे में हमें लिखकर भिजवा दें। हम इस बारे में एग्जामिन करवाकर विचार कर लेंगे।

———

तारांकित प्रश्न संख्या 451

(यह प्रश्न पूछा नहीं गया क्योंकि इस समय माननीय सदस्य डॉ० सुशील इंदौरा सदन में उपस्थित नहीं थे)

———

Committee Constituted for Retrenched Employees

***421. Sh. Ram Kumar Gautam :** Will the Minister for Finance be pleased to state the progress made by the committee constituted by the Government for providing of jobs so to the emplyees retrenched from service during the regime of previous Government?

Finance Minister (Sh. Bhupinder Singh) : The Committee is considering the representations received from employees organizations/retrenched employees in this regard. The Committee is likely to submit its report to the State Government at an early date.

श्री राम कुमार गौतम : अध्यक्ष महोदय, यह जो कमेटी बनाई गई थी इसने बहुत समय कन्ज्यूम किया है फिर भी जिन कर्मचारियों की छंटनी की गई थी उनको कोई राहत नहीं दी गई है। हरियाणा में कांग्रेस पार्टी की सरकार बनने पर उन कर्मचारियों को हुड्डा साहब से बहुत आशाएं थी। चौटाला साहब ने 25 हजार कर्मचारियों की छंटनी करके यहां कांग्रेस की सरकार बनने में बहुत मदद की क्योंकि उन 25 हजार कर्मचारियों के परिवार वाले कांग्रेस की तरफ जुड़ गये थे और हरियाणा में कांग्रेस की लहर सुनामी लहरों से भी तेज बन गई थी।

श्री अध्यक्ष : आपका सवाल क्या है ?

श्री राम कुमार गौतम : अध्यक्ष महोदय, मेरा सवाल यही है कि जिन कर्मचारियों की छंटनी पिछली सरकार के समय में की गई थी उन कर्मचारियों को नौकरी दी जाये और उनके घरों में दोबारा से चूल्हे जलाये जायें।

Mr. Speaker : You ask your supplementary.

Shri Ram Kumar Gautam : This is my supplementary. I want to know the position. कांग्रेस पार्टी का इतना बड़ा वचन था, इतना बड़ा वायदा था। जिस दिन हुड्डा साहब मुख्यमंत्री बने थे उसी दिन उन कर्मचारियों के घरों में रोशनी होनी चाहिए थी उसी दिन उनको रोजगार दे दिया जाना चाहिए था। (विघ्न)। अध्यक्ष महोदय, चौधरी भजन लाल जी यहां पर बैठे हुए हैं और ये कांग्रेस पार्टी के अध्यक्ष हैं। यह रोज कहा करते थे कि मैं आया तो उनकी नौकरी बहाल कर दूंगा।

वे आये या हुड्डा साहब आए, कहानी तो एक ही है कि कांग्रेस पार्टी की सरकारी आई है।

श्री बीरेन्द्र सिंह : अध्यक्ष महोदय, मैं यह बात स्पष्ट करना चाहता हूँ कि जिन कर्मचारियों को न्यायोचित ढंग से सर्विस से नहीं निकाला गया बल्कि उनको सर्विस से बाहर फैंक दिया गया उन कर्मचारियों के साथ हमारी पूरी हमदर्दी है, थी और रहेगी। पिछली सरकार द्वारा कई अदायरों को, डिपार्टमैंटस को और बोर्डज तथा कारपोरेशन्ज को खत्म कर दिया गया। अध्यक्ष महोदय, हमने यह वायदा जरूर किया था कि जिन लोगों के साथ अन्याय हुआ है, जिनकी सही तौर पर रिट्रैन्चमैंट नहीं की गई है और गलत तरीका इस्तेमाल करके उनको नौकरी से निकाला गया है उन सभी लोगों के एक-एक केस पर हम विचार करेंगे। जब हमारी सरकार ने सत्ता सम्भाली तो उसके फौरन बाद मुख्यमंत्री जी ने अपनी कैबिनेट की एक सब कमेटी का गठन किया था जिसका मैं चेयरमैन हूँ और उप-मुख्यमंत्री जी तथा विनोद शर्मा जी उसके मैम्बर्ज हैं। हमने अभी तक इसके बारे में छः मीटिंग की हैं, यह मामला इतना आसान नहीं है कि आप कहें कि उनके चूल्हे बन्द थे पहले दिन जला देने चाहिए थे। अध्यक्ष महोदय, मैं यह कहता हूँ कि हमने हर पहलू पर विचार किया है और अगर आप इसकी कॉम्पलैक्सिटी को देखेंगे तो ऐप्रिशियेट करेंगे। हमने बहुत हद तक इस समस्या का निदान करने की कोशिश की है। 18 तारीख को हमने अपनी इनटैरिम रिपोर्ट कैबिनेट तथा मुख्यमंत्री जी को सौंपनी थी लेकिन सैशन होने की वजह से हमने यह कहा है कि 15 दिन इस सब कमेटी का समय और बढ़ा दिया जाए ताकि हम जिसको न्याय दें उसको आगे कोई तकलीफ नहीं होनी चाहिए वरना तो वह दूसरे आदमी जो किसी और की जगह लगे होंगे वे कोर्टस में जा सकते हैं अथवा किसी को तंग किया जा सकता है। उसमें कौन-कौन से पैमाने होने चाहिएं उनका निर्धारण हमने काफी हद तक कर दिया है। अध्यक्ष महोदय, सात हजार से ज्यादा कर्मचारी ऐसे हैं जो कारपोरेशन्ज, बोर्डज तथा फैडरेशन्ज में काम कर रहे थे और उनकी रिट्रैन्चमैंट हुई है। उनके केसों पर हम पूर्णतया फैसला कर चुके हैं और इसकी रिपोर्ट शीघ्र ही मुख्यमंत्री जी को चली जाएगी। दूसरे जो सरकारी विभागों के कर्मचारी है उनकी सिचुऐशन भी बड़ी कम्पलैक्सड है और उनके लिए हम एक और रिपोर्ट सबमिट करेंगे जिसमें उनकी समस्याओं का भी समाधान हो सकेगा। यह जो इस प्रकार की सारी बातें हैं यह एक ही दिन में या एक नजरिये से तय नहीं हो सकती हैं। कई कर्मचारी कोर्टस में चले गए हैं और कोर्टस ने उनके केसिज को खारिज कर दिया है। कई लोग आठ-आठ या दस-दस लाख रुपये लेकर गोल्डन हैंडशेक करके चले गए। कई कर्मचारी ऐसे हैं जिनके केसिज अभी भी कोर्टस में लम्बित हैं। इन सारी सिचुएशन्ज को आप एक फैसले से हल नहीं कर सकते हैं। अध्यक्ष महोदय, हमने कोशिश की है और मैं हाउस को यकीन दिलाना चाहता हूँ कि ऐसे कर्मचारियों को जिनके साथ नाइन्साफी हुई है हमारी सरकार इन्साफ देगी और जल्दी ही इन्साफ देगी।

मुख्यमंत्री (श्री भूपेन्द्र सिंह हुड्डा) : अध्यक्ष महोदय, हम किसी की आशा को निराशा में नहीं बदलने देंगे।

Providing of Drinking Water

*439. **Shri Dharam Pal Singh Malik :** Will the Minister for Public Health be pleased to state :—

(a) whether there are villages in District Sonepat wherein facilities of drinking water has not been provided so far; if so, the number thereof; and

[Shri Dharam Pal Singh Malik]

(b) whether the Government has formulated any scheme for providing of drinking water to the aforesaid villages; if so, the details thereof?

परिवहन मंत्री (श्री रणदीप सिंह सुरजेवाला) :

(क) नहीं श्रीमान्।

(ख) संबंधित नहीं है।

चौ० धर्मपाल सिंह मलिक : अध्यक्ष महोदय, मैं माननीय मुख्यमंत्री जी से पूछना चाहूँगा कि मैंने सोनीपत डिस्ट्रिक्ट का पर्टिकुलर सवाल दिया था कि कौन-कौन से गांवों में वाटर वर्कस की फैसिलिटीज हैं। सही मायनों में 50 प्रतिशत गांवों में वाटर वर्कस बिल्कुल काम नहीं करते हैं। 20 गांवों में वाटर वर्कस बनाए गए थे लेकिन उन पर कोई काम नहीं हुआ था और न ही आज उनमें पानी जाता है। इसके अलावा पानीपत डिस्ट्रिक्ट में बहुत इण्डस्ट्रीज हैं और उनका गंदा पानी सोनीपत के बहुत से गांवों में जाता है। उसकी वजह से वहां पर सोयल वाटर पीने के लायक नहीं रहा है। अध्यक्ष महोदय, वाटर पोल्यूशन कंट्रोल बोर्ड बिल्कुल इन-इफैक्टिव है। इसके बारे में मैंने पिछली बार भी यहां पर बात कही थी और डी०सी० साहब को भी कहा था कि इण्डस्ट्रीज का गंदा पानी ड्रेन्ज के अन्दर आता है जिसकी वजह से वहां का सब-सोयल वाटर खराब हो गया है। मेरा मंत्री जी से निवेदन है कांसड़ा, कासींडी और सरगथल गांवों की यह शिकायत है और यह शिकायत लिखित में भेज भी दी है। क्या मंत्री जी उन गांवों में कैनाल बेस्ड वाटर वर्क्स की फैसिलिटी देने के बारे में विचार करेंगे या नहीं करेंगे।

श्री रणदीप सिंह सुरजेवाला : स्पीकर सर, माननीय साथी जी ने दो प्रश्न पूछे हैं। मैं इन को बताना चाहूँगा कि सोनीपत के सभी गांवों की जांच हमने करवाई थी और सभी गांवों में एक बार जलघर दिए थे। अध्यक्ष महोदय, हमने जांच में पाया कि दो गांवों बिलबलान और कटवाल ऐसे थे जहां आज के दिन वरचुअली यह स्थिति है कि सोनीपत के उन दोनों गांवों में पीने के पानी की सुविधा नहीं थी। स्पीकर सर, हमने फौरी तौर पर बेहतर योजना बनाई है। उसमें से एक आंवली योजना है जिसमें हमने 47 लाख रुपये दे दिए हैं, इस योजना में बिलबलान गांव आ जाएगा। दूसरी बाली योजना बाली ग्रुप ऑफ गांव के लिए बाली योजना है। जिसमें 48 लाख 90 हजार रुपये का आबंटन किया गया है और इसमें कटवाल गांव भी आ जाएगा। मैं माननीय सदस्य को बताना चाहूँगा कि हमने कटवाल गांव में काम पूरा कर दिया है, ट्यूबवैल लगा दिया है, पाईप लाईन 30 अप्रैल, 2006 तक लगा देंगे। जो बिलबलान ग्रुप ऑफ गांव हैं तो जसराना के पास ट्यूबवैल लगा दिया गया है और पाईप लाईन लगा कर उसको 31 मई, 2006 तक चालू कर दिया जाएगा। इसके अलावा स्पीकर सर, जो सोनीपत जिला है इसमें 180 गांवों में हमें लगा कि वहां पर स्टेट की लिमिट से कम पानी मिल रहा है इसलिए 49 करोड़ 26 लाख 77 हजार रुपये पेय जल आपूर्ति के लिए दिए हैं। 22 करोड़ 82 लाख 66 हजार रुपये इस समय महकमे के पास हैं और उस पर सुधारीकरण का काम जारी है। इसके साथ ही 102 गांव ऐसे हैं जहां पर 40 लीटर से पानी 55 और 70 लीटर प्रति व्यक्ति के हिसाब से दिया जाना चाहिए था उसके लिए हमने 28 करोड़ 70 लाख 15 हजार रुपये मंजूर किए थे जिसमें से 14 करोड़ 73 लाख 9 हजार रुपये हमने जमा करवा दिए हैं और इस पर काम जारी है। अध्यक्ष महोदय, जल्दी ही यह काम पूरा कर दिया जायेगा।

चौ० धर्मपाल सिंह मलिक : अध्यक्ष महोदय, मैंने सब-सोयल वाटर के बारे में प्रश्न पूछा

था उसका मंत्री जी की तरफ से जवाब नहीं आया है। मेरी एक और सप्लीमैंटरी है मंत्री जी इस सप्लीमैंटरी के जवाब के साथ ही पहले प्रश्न का भी जवाब दे दें। स्पीकर सर, हमारे यहां पर बहुत से गांव ऐसे हैं जहां पर प्राईवेट लोगों ने अपने ट्यूबवैल्ज लगाए हुए हैं और वहां से लोगों को पानी दे रहे हैं। उन लोगों की यह नीति है कि गवर्नमैंट की फैसीलिटी अभी न आए ताकि उनका जो धंधा है वह ठप्प न हो जाए। इस बारे में मंत्री जी इन्क्वायरी करवा लें। इसी के साथ मैं मंत्री जी आपसे यह भी कहना चाहूँगा कि जिस तरह से शहरों के घरों में लोगों के पास पानी के इण्डीवीज्वली कनैक्शन होते हैं क्या उसी तर्ज पर गांवों में भी लोगों को उनके घरों में इण्डीवीज्वली पानी के कनैक्शन्ज देने के बारे में विचार करेंगे और इन कनैक्शंज को लेने का क्या क्राईटेरिया होगा?

श्री रणदीप सिंह सुरजेवाला : स्पीकर सर, माननीय साथी जी ने फिर से दो प्रश्न पूछे हैं। पहले तो इन्होंने जो बताया है कि इण्डस्ट्रीज का पानी वहां पर सब-सोयल वाटर को पोल्यूट कर रहा है। यह सवाल हमारे विभाग से भी जुड़ा हुआ है। ये इस बारे में हमें और इन्वायर्नमैंट मिनिस्टर जी को भी लिखकर दे दें हम उन इण्डस्ट्रीज पर कार्यवाही करेंगे और सुनिश्चित करेंगे कि सब-सोयल वाटर खराब न हो। अध्यक्ष महोदय, इन्होंने कार्सडा और कासंडी के बारे में विशेष तौर पर चर्चा की है। स्पीकर साहब, वे फिगर्ज मेरे पास हैं। 85 लाख रुपये दोनों गांवों में पीने के पानी की आपूर्ति के लिए दे दिए हैं। 17 लाख 85 हजार रुपए की राशि एस०सी० पब्लिक हैल्थ के पास जमा करवा दिए थे। स्पीकर सर, उसमें से आज तक 11 लाख रुपये की राशि खर्च हो चुकी है और उसका काम चल रहा है।

डॉ० शिव शंकर : स्पीकर सर, जब भी हम गांवों में जाते हैं तो हमें एक शिकायत जरूर मिलती है कि वहां पर पीने का पानी तीन-तीन दिन में मिलता है और कई जगहों पर तो यह पानी आठ-आठ दिन बाद भी नहीं आता है। क्या मंत्री जी यह सुनिश्चित करेंगे कि जिस तरह से शहरों में पीने का पानी रोज आता है उसी तरह से गांवों में भी पीने के पानी की सप्लाई हर रोज हो? कई बार यह भी देखा गया है कि लाईट न होने की वजह से भी पीने के पानी की सप्लाई में रूकावट आ जाती है। मैं आपके माध्यम से मंत्री जी से जानना चाहता हूं कि मंत्री जी, क्या वहां पर जैनरेटर की सुविधा उपलब्ध करवाई जाएगी ताकि बिजली न होने पर भी पीने के पानी की सप्लाई में कोई बाधा न आए?

श्री रणदीप सिंह सुरजेवाला : अध्यक्ष महोदय, माननीय सदस्य की यह बात सही है कि कई बार जो लाईट की साईकिल है वह गड़बड़ा जाती है। हमने इसके लिए विशेष रूप से पावर मिनिस्टर को रिक्वैस्ट की है कि जन स्वास्थ्य विभाग के एस०ईज० और पावर विभाग के एस०ईज० इस बारे में एक साथ बैठकर बात कर लेंगे और जब गांवों में पीने के पानी की सप्लाई देनी हो तो दो घंटे सुबह तथा दो घंटे शाम को लाईट उपलब्ध करवा दी जाए। स्पीकर सर, किसी वजह से जब लाईट ट्रिप हो जाती है तो पानी के प्रैशर बनने में और उसकी सप्लाई करने में दिक्कत आ जाती है। अध्यक्ष महोदय, माननीय पावर मिनिस्टर ने कहा है कि वे इस बारे में विशेष इंस्ट्रक्शंज जारी कर रहे हैं कि जिस समय पानी गांवों में चलता है उस समय बिजली बगैर ट्रिप के उपलब्ध हो। स्पीकर सर, जहां तक जैनरेटर्ज का सवाल है, आप भी जानते ही हैं कि हर गांव के अंदर जैनरेटर लगाना एक असंभव सी बात है और इसीलिए यह बात सरकार के विचाराधीन नहीं है।

मेजर नृपेन्द्र सिंह सांगवान : स्पीकर सर, मैं भी इसी बारे में बात करना चाह रहा था। मेरी खुद की कांस्टीच्यूएंसी के अंदर कई बार ऐसा हो जाता है कि पानी की सप्लाई रुक जाती है। चूंकि बिजली रात को मिलती है इसलिए पानी की सप्लाई भी रात को मिलती है। पहले ये कनैक्शन्ज इरीगेशन के फीडर से थे लेकिन अब ये इरीगेशन फीडर से हटाकर गांवों की लाईन के साथ लगा दिए

[मेजर नृपेन्द्र सिंह सांगवान]
गए हैं। मेरी मंत्री जी से गुजारिश है कि इंडिपैंडैन्ट फीडर पब्लिक हैल्थ डिपार्टमैंट के लिए भी होने चाहिएं ताकि पीने का पानी ठीक टाईम पर मिल सके।

श्री रणदीप सिंह सुरजेवाला : अध्यक्ष महोदय, माननीय सदस्य का जो सुझाव है वह काबिलेगौर है। मैं भी इस बारे में पावर मिनिस्टर से दरख्वास्त करूंगा लेकिन माननीय सदस्य भी अगर उनको लिखकर भेज दें तो ठीक रहेगा। हम बिजली विभाग के साथ इस बात का प्रयास कर रहे हैं कि कम से कम दो घंटे या चार घंटे जन स्वास्थ्य विभाग के लिए बिजली आरक्षित रहे ताकि पीने के पानी की सप्लाई की जा सके और प्रैशर रैगुलरली रहे क्योंकि अगर एक बार बिजली ट्रिप हो जाती है तो दोबारा से प्रैशर बनने में समय लग जाता है।

श्री अमीर चन्द मक्कड़ : अध्यक्ष महोदय, हांसी हल्के में खासकर शहर में हरिजन बस्तियों में पीने के पानी की बहुत दिक्कत है। मैंने पहले भी मंत्री जी को इस बारे में लिखकर दिया था। मेरे हल्के के कई गांवों जैसे ढाणा,हजामपुर आदि में पीने का पानी बहुत कम मिल रहा है। क्या मंत्री जी का ध्यान इस तरफ है ? हांसी में पिछले सालों में कोई अफसर टिका नहीं है इसलिए ये काम चालू नहीं करवाए जा सके। मैं आपके माध्यम से मंत्री महोदय से जानना चाहूँगा कि क्या मंत्री जी इन कार्यों को करवाएंगे ताकि लोगों को पीने का स्वच्छ पानी मिल सके ?

श्री रणदीप सिंह सुरजेवाला : अध्यक्ष महोदय, हालांकि इनका यह सवाल सीधा प्रश्न जो पूछा था, उससे जुड़ा नहीं है लेकिन मैं उनको बताना चाहूँगा कि हमने हाँसी विधान सभा क्षेत्र के लिए विशेष तौर पर पैसा दिया है जहां तक मुझे याद है तकरीबन दस करोड़ रुपये दिए गए हैं। मैंने सारी डिटेल माननीय सदस्य को लिखकर भिजवा दी थी। वे इस बात को वैरीफाई भी कर सकते हैं। लेकिन अगर कोई इनका स्पैसिफिक प्रश्न है, किसी गांव या कालोनी में कोई दिक्कत है तो उसे भी हम ठीक करवाने का प्रयास करेंगे।

Privatization of Bus Routes

***378. Sh. Tejender Pal Singh Mann :** Will the Minister for Transport be pleased to state—

(a) whether there is any new scheme under consideration of the Government to bring more routes under privatization; and

(b) if so, upto what time the aforesaid scheme is likely to be implemented?

Transport Minister (Sh. Randeep Singh Surjewala) :

(a) Yes, Sir. A new scheme to bring more routes under privatization is under active consideration of the Govt.

(b) The aforesaid scheme is likely to be implemented during the next financial year.

श्री तेजेन्द्रपाल सिंह मान : स्पीकर सर, यह प्राईवेटाइजेशन 12-13 साल पहले की गयी थी। बाद में जो सरकारें आयी उन्होंने इस प्राईवेटाइजेशन को ठंडे बस्ते में डाल दिया। बायब्लिटी ऑफ आपरेटर्ज हरियाणा में बिल्कुल खत्म हो गयी है। मन्त्री जी, सरकार नये रूट बना रही है। इसके बारे

में मैं यह बताना चाहता हूँ कि इन रूटों की बायब्लिटी होनी चाहिए। छोटे रूट भी होने चाहिएं क्योंकि अब थ्री व्हीलर जैसे व्हीकल भी आ गये हैं।

Mr. Speaker : Hon'ble Members, Now, the Questions hour is over.

नियम 45 (1) के अधीन सदन की मेज पर रखे गये तारांकित प्रश्नों के लिखित उत्तर

Cancellation of Bus Route Permit

***409. Sh. Somvir Singh :** Will the Minister for Transport be pleased to state—

(a) whether the private bus operators, who have been given route permits for plying buses from Satnali to Loharu, have requested in writing for the cencellation of their bus rout permits, if so, since when the said requests have been made together with the action taken thereon; and

(b) the time limit by which the Government buses will start plying on this route?

परिवहन मंत्री (श्री रणदीप सिंह सुरजेवाला) :

(क) नहीं, श्रीमानजी। क्योंकि किसी निजी संचालक ने अपना रूट परमिट रद्द करने हेतु आवेदन प्रस्तुत नहीं किया है अत: इस संबंध में किसी प्रकार की कार्यवाही करने का प्रश्न ही नहीं उठता।

(ख) सरकार अर्थात् हरियाणा राज्य परिवहन की बसों के अतिरिक्त दो अन्य प्राईवेट बसें इस मार्ग पर पहले ही चल रही हैं।

Lining of Bhambhewa Drain

***461. Shri Bachan Singh Arya :** Will the Minister for Irrigation be pleased to state—

(a) whether it is a fact that Bhambhewa drain damages the crops in Safidon Constituency due to its over flow; and

(b) if so, whether there is any proposal under consideration of the Government for lining the said drain and also to raise its banks from Burji No. 58000 to 66000?

राजस्व मंत्री (कैप्टन अजय सिंह यादव) :

(क) जी नहीं, श्रीमान जी।

(ख) भम्भेवा ड्रेन को पक्का करने तथा इसके बुर्जी संख्या 58000 से 66000 तक किनारे

[कैप्टन अजय सिंह यादव]

ऊंचे करने का भी कोई प्रस्ताव विभाग द्वारा विचाराधीन नहीं है क्योंकि ड्रेनों को शहरी क्षेत्र के अतिरिक्त पक्का नहीं किया जाता।

Investment made under Industrial Policy

***416. Prof. Chattar Pal Singh :** Will the Minister for Industries be pleased to state the details of the investment made so far under the new Industrial policy in Haryana?

उद्योग मंत्री (श्री लछमन दास अरोड़ा) : नई औद्योगिक नीति की घोषणा के उपरान्त राज्य में उद्योग लगाने हेतु 8000 करोड़ रुपये से अधिक के पूंजी निवेश के प्रस्ताव प्राप्त हो चुके हैं, जिसमें से 472.54 करोड़ रुपये के निवेश से 841 औद्योगिक इकाईयां स्थापित भी हो चुकी हैं। इसके अतिरिक्त राज्य सरकार को विशेष आर्थिक क्षेत्र व कैम्पस विकास हेतु एक लाख करोड़ रुपये से अधिक निवेश के प्रस्ताव प्राप्त हुए हैं।

Construction of Roads

***426. Shri Rakesh Kamboj :** Will the Minister for Agriculture be pleased to state—

(a) whether there is any Proposal under consideration of the Government (HSAMB) to construct the following roads of Indri Assembly Constituency in District Karnal :

1. Manak Majra to Butan Kheri 2. Jaimpur to Khera 3. Dhumsi to Indri (Khanpur side) 4. Rayatkhana to Dhumsi 5. Churni to Kamalpur 6. Nanhera to Badarpur 7. Islam Nagar to Badarpur Nanhera 8. Garhpur Khalsa to Nanhera Badarpur 9. Khera to Nanhera 10. Kalri Jagir Mukhala 11. Dara Ram Nagar to Tusang 12. Kalri Jagir to Shergarh Nathori 13. Dabkoli Kalan to Dabkoli Khurd 14. Chora to Dabkoli Khurd 15. Johar Majra Kalan to Fazilpur 16. Rajepur to Umarpur 17. Rajepur to Patehera 18. Nagla Roran to Gheer 19. Nanadi to Bhoji 20. Burhanpur Khalsa to Nanadi 21. Burhanpur Khalsa to Hinori 22. Indergarh to Fazilpur 23. Murdgarh to Indergarh 24. Kalri Jagir to Kalra 25. Kheri Man Singh to Gorgarh 26. Pandhana Mor to Gangar 27. Randoli to Byana 28. Murdgarh to Bara Baon via Fazilpur-Shahpur Nangal, Roran-Rindal-Landora 29. Garhi Birbal to Mukhala 30. Kadrabad to Garhi Sadan 31. Kadrabad to Burhanpur Bangar 32. Kardabad to Ramgarh 33. Samora to Bibipur 34. Fazilpur to Byana; and

(b) if so, upto what time the aforesaid roads are likely to be constructed?

कृषि मंत्री (सरदार हरमोहिन्द्र सिंह चट्ठा) :

(क) श्रीमान जी, क्रमांक सड़क 28 यानि मुरादगढ़ से बड़ा गाँव वाया फाज़िलपुर-शाहपुर मंगल रोड़ान-रिन्डल-लांडौरा सड़क लोक निर्माण विभाग (भवन व सड़कें) द्वारा

पहले ही निर्मित की जा चुकी है। शेष 33 सड़कों के निर्माण बारे मामला परीक्षणाधीन है।

(ख) इन शेष 33 सड़कों के निर्माण बारे कोई समय अवधि निश्चित नहीं की जा सकती।

अनुपस्थिति संबंधी सूचना

Mr. Speaker : Hon'ble Members, I am to inform you that I have received a letter from Sh. Habib-Ur-Rehman, M.L.A. vide which he has expressed his inability to attend rest of the Session of Haryana Vidhan Sabha from 21st March, 2006 afternoon onwards due to marriage of his son on 26th March, 2006.

वर्ष 2006-2007 के बजट अनुमानों पर सामान्य चर्चा

Mr. Speaker : Hon'ble Members, as some of the Members want to speak on Budget Estimates, therefore, general discussion on the Budget Estimates for the year 2006-07 will resume today and only one and a half hours is fixed. Thereafter, the Finance Minister will give the reply.

श्री निर्मल सिंह (नग्गल) : स्पीकर साहब, आपने मुझे बजट पर बोलने के लिए समय दिया, उसके लिए मैं आपका धन्यवाद करता हूँ। (शोर एवं व्यवधान)

डॉ० सीता राम : स्पीकर सर, ********

Mr. Speaker : Nothing to be recorded without my permission.

डॉ० सुशील इन्दौरा : स्पीकर सर, *******

श्री बलवन्त सिंह सढौरा : स्पीकर सर, *****

परिवहन मंत्री (श्री रणदीप सिंह सुरजेवाला) : स्पीकर सर, माननीय विपक्ष के साथी दस मिनट से ज्यादा बोल नहीं सकते। सब कुछ बोलकर उसके बाद ये भूल जाते हैं। सच बात तो यह है कि इनकी यह आदत बन गई है। मुझे माफ करें। लेकिन जिस प्रकार कुत्ते की दुम को चाहे 17 साल तक नली में रखें। वह सीधी नहीं हो सकती। शोरगुल के सिवाए इनके पास और कोई एजेण्डा नहीं है। केवल पत्रकार साथियों की तरफ देखकर इन्होंने तो सिर्फ वाक आउट ही करना है। इनके पास बोलने के लिए एजेण्डा कोई नहीं बचा है।

डॉ० सुशील इन्दौरा : स्पीकर सर, ******

श्री रणदीप सिंह सुरजेवाला : स्पीकर सर, माननीय सदस्य ने चेयर को थ्रैट किया है क्योंकि ये कहते हैं कि हम हाउस को चलने नहीं देंगे। ये सदन में जो आचरण कर रहे हैं तो उनका यह आचरण हम चलने नहीं देंगे। माननीय सदस्य श्री सढौरा जी और डॉक्टर साहब चेयर को थ्रैट कर रहे हैं। क्या इनको यह अख्तियार है, क्या इस प्रकार के कण्डक्ट की इनसे अपेक्षा की जा सकती है, क्या ये यह कह सकते हैं कि सदन की कार्यवाही नहीं चलने देंगे ? ये होते कौन हैं सदन की कार्यवाही को रोकने वाले ?

---

* चेयर के आदेशानुसार रिकॉर्ड नहीं किया गया।

[श्री रणदीप सिंह सुरजेवाला]

इनके इसी प्रकार के कण्डक्ट की वजह से इन लोगों को सफर करना पड़ा है। इनके नेता की तो एक साल से सदन के अन्दर आने की हिम्मत नहीं है वे तो भगोड़े की तरह अमेरिका में बैठे हैं। वे अपने पैसे को संभालने के लिए वहां गये हैं जबकि ये माननीय साथी बात परम्पराओं और मर्यादाओं की करते हैं। स्पीकर सर, आपने इन साथियों को बोलने के लिए कुल एक घण्टा 38 मिनट्स का समय दिया परन्तु सच बात तो यह है कि इन्होंने कुछ नहीं सीखा और न ही ये आगे भी सीखेंगे।

डॉ० सुशील इन्दौरा : स्पीकर सर, ******.

श्री रणदीप सिंह सुरजेवाला : स्पीकर सर, ओमप्रकाश चौटाला और उनके बेटे अपने विधायकों के साथ कैसा व्यवहार किया करते थे इसलिए वे दिन याद करें। उस समय विधायक के हाथ और पांव तोड़ दिए जाया करते थे और तेजाखेड़ा फार्म पर ले जाकर उनकी पीटा जाता था। अब भी इनको खतरा है (विघ्न)

Mr. Speaker : Hon'ble Dr. Sita Ram ji had walked out from the House at that time when the House was near to be adjourned. आप प्लीज बैठें।

डॉ० सीता राम : अध्यक्ष महोदय, मुझे बजट पर बोलने का मौका नहीं दिया गया। (शोर एवं व्यवधान)

श्री अध्यक्ष : प्लीज आप बैठें। आप एक-एक करके बोलें। डॉक्टर साहब, प्लीज आप बैठें। (शोर एवं व्यवधान)

डॉ० सुशील इन्दौरा : अध्यक्ष महोदय ****** (शोर एवं व्यवधान)

डॉ० सीता राम : अध्यक्ष महोदय, मुझे बजट पर बोलने का अवसर नहीं दिया। (शोर एवं व्यवधान)

Mr. Speaker : Please listen. Discussion on Budget is not concluded. डॉक्टर साहब, कन्क्लयूड होने के बाद आप कह सकते हैं कि आपको बजट पर बोलने का अवसर नहीं दिया। (शोर एवं व्यवधान)

श्री बलवंत सिंह : अध्यक्ष महोदय, आप बोलने के लिए समय दें या न दें लेकिन जिस तरह से कल आप हमें धमकाकर सदन से बाहर निकल जाने के लिए कह रहे थे, वह ठीक व्यवहार नहीं था। (शोर एवं व्यवधान) यदि हम अपनी बात कहना चाहते हैं तो हमारी बात आपको सुननी चाहिए। (शोर एवं व्यवधान)

डॉ० सीता राम : अध्यक्ष महोदय, ********** (शोर एवं व्यवधान)

डॉ० सुशील इन्दौरा : अध्यक्ष महोदय, ****** (शोर एवं व्यवधान)

श्री अध्यक्ष : आप एक-एक करके बोलें सभी एक साथ क्यों खड़े हो रहे हैं? आप ही बतायें कि किसकी बात रिकॉर्ड की जाये। (शोर एवं व्यवधान)

Mr. Speaker : Nothing to be recorded without my permission. (Interruptions)

---

* चेयर के आदेशानुसार रिकॉर्ड नहीं किया गया।

डॉ० सुशील इन्दौरा : अध्यक्ष महोदय, *******

श्री अध्यक्ष : मेरी इजाजत के बगैर जो सदस्य बोल रहे हैं उनकी बात रिकॉर्ड न की जाए। डॉक्टर इन्दौरा जी, आप सीजंड पार्लियामैंटेरियन हैं आप प्लीज अपनी सीट पर बैठें। (शोर एवं व्यवधान)

श्री रणदीप सिंह सुरजेवाला : अध्यक्ष महोदय, इनकी पार्टी के लोग एक घंटे 38 मिनटस बोले हैं और उसमें से इन्दौरा साहब अकेले ही एक घंटे तक बोले हैं। इन्दौरा साहब से ज्यादा दूसरा कोई सदस्य नहीं बोला। यह रिकॉर्ड की बात है, आप रिकॉर्ड निकलवा कर देख सकते हैं। (शोर एवं व्यवधान)

डॉ० सुशील इन्दौरा : अध्यक्ष महोदय, ******* (शोर एवं व्यवधान)

डॉ० सीता राम : अध्यक्ष महोदय, ****** (शोर एवं व्यवधान)

Sh. Randeep Singh Surjewal : Sir, they can't take the Chair for Granted. (Interruptions).

श्री अध्यक्ष : आप लोग फैसला करें कि किसने बोलना है। (शोर एवं व्यवधान)

श्री आनन्द सिंह दांगी : अध्यक्ष महोदय, बजट पर डिसकशन चल रही है और आप इनको बोलने के लिए समय भी दे रहे हैं लेकिन ये बोलना ही नहीं चाह रहे हैं। (शोर एवं व्यवधान) अध्यक्ष महोदय, ऐसा पहले कभी नहीं हुआ कि अध्यक्ष बोलने के लिए समय दें और विपक्ष के साथी बोलने के लिए तैयार ही न हों। (शोर एवं व्यवधान)

डॉ० सुशील इन्दौरा : अध्यक्ष महोदय, ***** (शोर एवं व्यवधान)

डॉ सीता राम : अध्यक्ष महोदय, ****** (शोर एवं व्यवधान)

मुख्यमंत्री (श्री भूपेन्द्र सिंह हुड्डा) : अध्यक्ष महोदय, मैं पहले भी इस सदन का सदस्य रहा और विपक्ष का नेता भी रहा। लेकिन आपके समय में इस सदन में क्वैश्चनआवर के दौरान जितने सवालों का जवाब दिया गया है उतना जवाब पहले कभी नहीं दिया गया। पिछली सरकार के समय में श्री राम पाल माजरा जी किसी एक प्रश्न के जवाब के लिए खड़े होते थे तो 45 मिनट तक एक ही सवाल का जवाब देते रहते थे और जवाब प्रश्न से संबंधित भी नहीं होता था। लेकिन मैं आपको मुबारिकबाद देता हूँ कि अब सबको अपने सवाल पूछने का अवसर मिल रहा है और रिकॉर्ड सवालों का जवाब प्रश्नकाल के दौरान दिया जा रहा है। (शोर एवं व्यवधान)

डॉ० सीता राम : अध्यक्ष महोदय, ******* (शोर एवं व्यवधान)

Mr. Speaker : I assure the House that my conduct and behaviour will be impartial and fair.

डॉ० सुशील इन्दौरा : अध्यक्ष महोदय, आपका व्यवहार हमारे लिए ठीक रहेगा तो इसके लिए हम आपका धन्यवाद करेंगे।

श्री अध्यक्ष : आपका रवैया ठीक रहेगा तो I will certainly pay due respect to all

* चेयर के आदेशानुसार रिकॉर्ड नहीं किया गया।

[श्री अध्यक्ष]

Hon'ble Members. Please now co-operate. (Interruptions).

शिक्षा मंत्री (श्री फूल चन्द मुलाना) : अध्यक्ष महोदय, मेरे माननीय साथी इन्दौरा साहब ने अभी थोड़े समय पहले कुछ ऐसे शब्द कह दिए जो सदन की कार्यवाही में नहीं आने चाहिएं। मेरी आपसे प्रार्थना है कि वे शब्द सदन की कार्यवाही से निकलवा दिये जायें।? (शोर एवं व्यवधान) मेरी आपसे यह भी प्रार्थना है कि विपक्ष के 6 सदस्य बोल चुके हैं सिर्फ दो बाकी बचे हैं इनको भी बजट पर बोलने का अवसर दे दिया जाये। (शोर एवं व्यवधान)

श्री अध्यक्ष : वे शब्द पहले ही कार्यवाही से निकलवा दिए गए हैं और इन दोनों सदस्यों को भी बोलने का अवसर देंगे। (शोर एवं व्यवधान) निर्मल सिंह जी, आप अपनी स्पीच कन्टीन्यू करो।

श्री निर्मल सिंह (नग्गल) : अध्यक्ष महोदय, आपने मुझे बजट पर बोलने के लिए समय दिया इसके लिए मैं आपका धन्यवाद करता हूँ। जो बजट पेश किया गया है इसमें सरकार का विजन और नीयत दोनों ही आज सामने हैं और स्टेट की आर्थिक दशा बहुत मजबूती के साथ उभर रही है। बजट की चारों तरफ तारीफ हो रही है। सरकार के प्रति लोगों का विश्वास बहाल हुआ है। उसका श्रेय हमारे चीफ मिनिस्टर जी तथा वित्त मंत्री जी का जो विजन है उसको जाता है, मुख्यमंत्री जी की नीयत को जाता है। लॉ एण्ड आर्डर की स्थिति को लेकर हरियाणावासियों में बड़ी चिन्ता थी उसके बारे में भी आज हरियाणा के लोग आश्वस्त हैं। स्पीकर साहब, दो बातों को लेकर बड़ी चिन्ता थी एक करप्शन तथा दूसरी लॉ एण्ड ऑर्डर की। करप्शन तथा लॉ एण्ड ऑर्डर दोनों मामलों में मुख्यमंत्री जी ने काफी सुधार किया है। करप्शन और लॉ एण्ड आर्डर की स्थिति यह थी कि स्टेट में गुण्डे और बदमाश पैदा हो गए थे। उनकी जड़ें इतनी गहरी हैं कि इसको खत्म करने के लिए दूर तक लड़ाई चलनी है। इस लड़ाई को लड़ने के लिए लोगों के सॉफ्ट कॉर्नर तथा सहयोग की बड़ी आवश्यकता पड़ेगी। मैं इस बात की तारीफ करता हूँ कि बजट में हैल्थ और ऐजूकेशन जैसी महत्वपूर्ण बातों को प्राथमिकता दी गई है। आदरणीय मुख्यमंत्री जी ने कहा है कि हर गांव में खेल ग्राउंड बनाए जाएंगे और सरकार ने उसके लिए 30-40 करोड़ रुपये का बजट भी दिया है। सरकार ने स्पोर्टस बजट को डबल कर दिया है यह बहुत ही सराहनीय कार्य है। आज शिक्षा में सुधार की जरूरत है। मैंने पहले भी कई बार यहां पर यह बात उठाई है कि ऐजूकेशन सिस्टम को टोटली बदलने की जरूरत है। आज टेलीविजन की हैल्प लेकर सभी स्कूलों में अच्छे टीचर्ज अथवा लैक्चरर्ज के लैक्चर बच्चों को पढ़ाए जाने चाहिएं। हमारे पास आज जो टीचर्ज हैं दुर्भाग्यवश वे उतने योग्य नहीं हैं कि बच्चों को बड़े अच्छे तरीके से पढ़ा सकें, वे टीचर्ज उनकी हैल्प करें यह भी काफी है। इसमें यह बात हो सकती है कि टेलीविजन के माध्यम से शिक्षा दी जाए। मैंने कई जगहों पर देखा है कि टेलीविजन के माध्यम से शिक्षा दी जा रही है। जहां तक स्वास्थ्य और स्पोर्ट्स की बात है, यह बात सही है कि हरियाणा में भी चैम्पियन पैदा हो सकते हैं, लेकिन इससे भी ज्यादा जरूरी बात यह है कि हर स्तर पर खेलें खेली जानी चाहिएं। आज की जो पीढ़ी है उसकी खेलों में रूचि कम हुई है। स्कूलों, कॉलेजों में आज स्टूडैंट्स को देखें तो पता लगता है कि उनकी सेहत बहुत कमजोर है। इसका एक बहुत बड़ा कारण यह है कि उनमें खेलने का कोई शौक ही नहीं है। वे खेलों का अपना शौक खुद न खेल कर केवल टेलीविजन देखकर ही पूरा कर लेते हैं। किसी भी लैवल पर देखें खेलों के मामले में गड़बड़ी है। ब्लॉक लैवल पर भी खेलों में गड़बड़ी है। खेलों के कोई भी काम सही टाईम और सही ढंग से नहीं हो रहे हैं। स्कूलों में जो टूर्नामैंट हुआ करते थे उनकी तरफ भी ध्यान देने की जरूरत है। स्पीकर साहब, आपने मुझे बोलने के लिए समय कम दिया है

इसलिए मैं दो तीन बातों की तरफ आपका ध्यान दिलाना चाहता हूँ। मैं हमेशा से कहता रहा हूँ और पिछले सैशन में भी मैंने यह बात कही थी कि नॉर्दर्न हरियाणा को भी पानी की जरूरत है। आदरणीय मुख्यमंत्री जी ने साउदर्न हरियाणा की प्यास तो बुझा दी है लेकिन नॉर्दर्न हरियाणा में कितना नहरी पानी मिलता है इस बात पर गौर करने की जरूरत है। मेरे डिस्ट्रिक्ट में लिफ्ट इरीगेशन स्कीम के तहत एक नहर निकलती है वह 167 क्यूसिक कैपेसिटी की नहर है लेकिन वह नहर इस समय 65 क्यूसिक पानी ही लिफ्ट कर रही है। उस नहर की कैपेसिटी इतनी ज्यादा नहीं रही है इसलिए उसको बढ़ाने की आवश्यकता है। इसी तरह से मैं माननीय मंत्री जी के नोटिस में लाना चाहता हूँ कि मंसूरपुर लिफ्ट इरीगेशन स्कीम पिछले छः साल से अधूरी पड़ी है। इसका अर्थ वर्क हो चुका है लेकिन अभी तक उस पर पम्प नहीं लगे हैं और किसी कारणवश यह नहर नहीं बन रही है। इसलिए इस तरफ भी ध्यान दिया जाए। नन्यौला माईनर पूरी तरह से टूटी हुई है उसकी कम्पलीशन तथा रिपेयर की जरूरत है। अध्यक्ष महोदय, इसी तरह से आपके माध्यम से माननीय मुख्यमंत्री जी से मेरी प्रार्थना है कि सरकार जो दादूपुर नलधी नहर बनाने जा रही है उसके लिए पैसा कम रखा गया है। इस नहर की बहुत ज्यादा जरूरत है इसलिए इसके काम को स्पीड-अप किया जाए और इसे जल्दी बनाया जाए। अध्यक्ष महोदय, इसके साथ ही हमारे सीजनल वाटर लैवल को ठीक रखने के लिए काम किया जाना चाहिए। इसी तरह से शहजादपुर से ताजेवाला तक भी एक नहर निकाली जा सकती है। अगर ऐसा होगा तो वाटर लैवल की हमारी दिक्कत हमेशा-हमेशा के लिए दूर हो सकती है। अगर इस बात पर गौर करें तो यह बात भी सिरे चढ़ सकती है। इसके अलावा अध्यक्ष महोदय, अम्बाला में पशुपालन विभाग का एक पोलीक्लीनिक बना हुआ था और चौटाला जी के राज में वे उसको सिरसा में ले गए थे। इस पोलीक्लीनिक की अम्बाला में भी जरूरत है। जब हम इस बारे में महकमें वालों से बात करते हैं तो वे कहते हैं कि यहां पर कोई कर्मचारी/अधिकारी आना नहीं चाहता है। अध्यक्ष महोदय, मैं आपके माध्यम से मंत्री जी से कहना चाहूँगा कि वहां पर सारा इन्फ्रास्ट्रक्चर मौजूद है लेकिन वहां पर जो पोस्टस खाली पड़ी हुई हैं, उनको भरकर दोबारा से पशुओं के लिए पोलीक्लीनिक खोलने का प्रावधान किया जाए। अध्यक्ष महोदय, मेरी कांस्टीचुएंसी में 165 गांव आते हैं और इसकी लम्बाई टोटल 77 किलोमीटर की है। आपको मेरी कांस्टीचुएंसी के लिए भी ज्यादा फंड रखना चाहिए और इसका विशेष ध्यान सरकार को रखना चाहिए। इसी के साथ मेरे यहां पर 3 टबीन गांव हैं और वहां की आबादी 50 हजार के करीब है। वहां के लोगों की मांग हैं कि वहां पर एक होस्पिटल बनाया जाए। मैं वहां की पंचायतों से बहन जी को एक रैजोल्यूशन भिजवा दूंगा। अध्यक्ष महोदय, मेरे से पहले बोलते हुए व्यक्तियों ने भी इस बारे में प्रकाश डाला है कि डिस्ट्रिक्ट अम्बाला में कोई ऐसी स्कीम बनाएं जिससे वहां के लोगों को फायदा हो। अम्बाला डिस्ट्रिक्ट बहुत पुराना डिस्ट्रिक्ट है और यहां के लोगों का ध्यान प्लांटेशन की तरफ है। इस वजह से हमारी बिजली और पानी की बहुत बचत होती है। यहां पर हर बार जीरी और कनक बहुत ज्यादा हो जाती है। सरकार को चाहिए कि वहां पर लोगों को सस्ते लोन दिलवाएं ताकि लोग प्लांटेशन की तरफ आकर्षित हों। अध्यक्ष महोदय, मैं आपका ज्यादा समय न लेते हुए अपने स्थान पर बैठता हूँ। आपका बहुत-बहुत धन्यवाद।

श्री सुरजभान सिंह (रोहट) : अध्यक्ष महोदय, आपने मुझे बोलने का समय दिया इसके लिए मैं आपका धन्यवाद करता हूँ और इस बजट का अनुमोदन भी करता हूँ। यह जो इस साल का बजट है यह सभी वर्गों के लिए है। पिछले 40 सालों में हरियाणा में जो-जो काम नहीं हुए थे वे सभी काम इस सरकार ने अपने एक साल के कार्यकाल में ही कर दिए हैं। जनता में इस सरकार पर विश्वास बढ़ा है। इस सरकार ने इस बजट में ऐजूकेशन पर बहुत ध्यान दिया है। (विघ्न)

Mr. Speaker : No running commentry while sitting. Please maintain decorum of the House.

श्री सुखबीर सिंह : अध्यक्ष महोदय, मैं आपके माध्यम से ऐजूकेशन मिनिस्टर का ध्यान खरखौदा में एक वूमैन कॉलेज की ओर दिलाना चाहूँगा। वह कालेज 50 गांवों के बीच में बना हुआ है। अध्यक्ष महोदय, काफी संघर्ष के बाद हमने उस कॉलेज को बनाया था अब उसको चलाने में बहुत मुश्किल हो रही है। मेरा आपसे निवेदन है कि सरकार उस कॉलेज को अपने अण्डर में लें ताकि वह कॉलेज सुचारू रूप से चल सके। अध्यक्ष महोदय, फरमाना गांव में वूमैन्ज के लिए एक आई०टी०आई० खोली गई थी लेकिन चौटाला सरकार के राज में उसको बंद कर दिया गया था। अध्यक्ष महोदय, मेरा आपके माध्यम से मंत्री जी से निवेदन है कि उस आई०टी०आई० को दोबारा से खोला जाए। अध्यक्ष महोदय, मैं आपके माध्यम से सरकार से निवेदन करना चाहूँगा कि चौटाला सरकार के राज में जो-जो काम गलत हुए हैं उनको ठीक किया जाए। इसके साथ ही मुरथल में इंजीनियरिंग कॉलेज है उसकी तरफ भी सरकार को ज्यादा से ज्यादा ध्यान देना चाहिए क्योंकि सोनीपत डिस्ट्रिक्ट में एक ही सरकारी इंजीनियरिंग कॉलेज है। अध्यक्ष महोदय, बिदलान गांव में हमने बहन जी से एक पी०एच०सी० खोलने के बारे में कहा था और वह मंजूर भी हो गई है। अध्यक्ष महोदय, मेरा आपके माध्यम से बहन जी से निवेदन है कि उस पी०एच०सी० का जल्द से जल्द नींव-पत्थर रखा जाए। अध्यक्ष महोदय, फरमाना गांव बहुत बड़ा गांव हैं और वहां पर बहुत पुरानी एक पी०एच०सी० है उसको सरकार सी०एच०सी० में बदलने का कष्ट करे। अध्यक्ष महोदय, फरमाना से आवली गांव तक की सड़क बनाई जाए। उसके बारे में हुड्डा साहब से भी कहा गया था और तायल साहब ने भी इस बारे में एक नोट लिखा था, लेकिन पता नहीं वह नोट कहां पर चला गया है? अध्यक्ष महोदय, तकरीबन, एक साल हो गया लेकिन उस सड़क पर काम नहीं हुआ। वह सड़क बनाना बहुत ज्यादा जरूरी है। इसी तरह से सोनीपत से जींद के लिए रेलवे लाईन बनना भी जरूरी है। सांगवान साहब सोनीपत से तीन बार एम०पी० रह चुके हैं लेकिन आज तक उस लाईन का कोई सर्वे नहीं हुआ है। वे कहते हैं कि वह मंजूर हो गयी है। स्पीकर साहब, अगर वह मंजूर हो गयी है तो उसके लिए पैसा दिया जाए। हुड्डा साहब, अगर आप इसका भी काम करवा देंगे तो आपका नाम भी उस रेलवे लाइन पर लिखा जाएगा और इसके बाद बी०जे०पी० की चुनावों में जमानत जब्त हो जाएगी। स्पीकर सर, नहरों में जो मौघे लगाये हैं वह बहुत तंग हैं इसलिए हर किसान इसकी शिकायत करता है कि पानी तो दे दिया लेकिन मौघों के तंग होने की वजह से उनको दिक्कत आ रही है। यह बात सही है कि अब नहरों में पानी आया है लेकिन अगर मौघे तंग हैं तो यह पानी देने का कोई फायदा नहीं है। इसलिए मैं कहना चाहूँगा कि इन मौघों को चौड़ा किया जाए। इसी तरह से सिसाना से सेहरी सड़क भी टूटी हुई है इस सड़क पर 6-7 साल से रोड़े पड़े हुए हैं जिसकी वजह से पशुओं और आदमियों के पैर कटने लग रहे हैं। जब हम इस सड़क को बनाने के बारे में कहते हैं तो कभी तो हमसे यह कह दिया जाता है कि यह सड़क पंचायत राज विभाग के अंडर हैं और कभी यह कह दिया जाता है कि यह सड़क पी०डब्ल्यू०डी० (बी०एण्ड आर०) के अंडर है। मेरा कहना है कि इस सड़क को भी तुरन्त बनवाया जाए। स्पीकर सर, वैसे तो सारी डिमांड्ज हुड्डा साहब ने मान ली है। हमारे यहां पर बस स्टैंड बनवा दिया है, दस जगह दो का स्कूल भी हो गया है और गांवों की छतों के ऊपर से जाने वाली तारों को भी हटवा दिया है या जो बदलने वाली तारें थीं उनको भी बदलवा दिया गया है। इसलिए मेरी प्रार्थना है कि यह सरकार दिन दूनी रात चौगुनी उन्नति करें। मैं हुड्डा साहब का भी और आपका भी धन्यवाद करता हूँ।

Mr. Speaker : Now, Naresh Malik will speak. But Malik Sahib B.J.P. has

already taken about 32 minutes. मलिक साहब, आपकी पार्टी के सदस्य गौतम साहब ने 32 मिनट पहले ही बोलने के लिए ले लिए हैं इसलिए अब आप 6 मिनट में अपनी बात समाप्त करो।

श्री नरेश मलिक (हसनगढ़) : स्पीकर साहब, धन्यवाद आपका। 6 मिनट में तो मैं विधान सभा के बारे में ही बोल पाऊंगा।

श्री अध्यक्ष : मलिक साहब, आप तजुर्बेकार आदमी हैं इसलिए आप 6 मिनट में सारे सुझाव दे सकते हैं सारी बातें कह सकते हैं।

श्री नरेश मलिक : अध्यक्ष महोदय, मैं दो तीन बातें ही कहना चाहता हूँ। एक तो मैं बिजली के बारे में कहना चाहूँगा। बजट में नये बिजली प्रोजैक्ट्स लगाने के बारे में कहा गया है। लेकिन मुझे एक बात समझ में नहीं आती कि केवल एक फरीदाबाद का प्रोजैक्ट ही ऐसा है जिस पर अभी काम चल रहा है जबकि बाकी प्रोजैक्टस के लिए किसी न किसी प्राईवेट कम्पनी के साथ समझौते हुए हैं। स्पीकर साहब, सबसे कम खर्चा बिजली बनाने में पानी से होता है फिर गैस से होता है और फिर कोयले से होता है। इसलिए इन प्रोजैक्टस पर कम से कम 25 या 30 हजार करोड़ रुपये खर्च आने का अनुमान है। जैसा मुख्यमंत्री जी ने बताया कि 9 हजार मेगावाट बिजली की जरूरत है और चार हजार मेगावाट बिजली ही इस समय हरियाणा में उपलब्ध है इस तरह से चार हजार मेगावाट बिजली का गैप होगा। स्पीकर सर, मैं वित्त मंत्री जी से और मुख्यमंत्री जी से एक बात कहना चाहता हूँ कि प्राईवेट कम्पनियों के साथ जो समझौते हुए हैं वह किस आधार पर हुए हैं? मेरे ख्याल से सदन को इस बारे में कुछ नहीं पता है कि अगर ये प्रोजैक्टस लगाएंगे तो इनके लिए गैस कहां से लाएंगे या इनसे बनने वाली बिजली का डिस्ट्रीब्यूशन सरकार खुद करेगी या ये कम्पनियां स्वयं करेंगी? इसलिए मेरा कहना है कि सदन को इस बारे में थोड़ा जरूर बताया जाए। अध्यक्ष महोदय, सारे भाइयों ने बजट की तारीफ की। मैं माननीय मुख्यमंत्री जी का ध्यान आकर्षित करना चाहूँगा कि सैंट्रल गवर्नमैंट ने पंजाब के कृषि विश्वविद्यालय के लिए 100 करोड़ रुपये बजट में रखे हैं। हमारे हिसार में जो एच०ए०यू० है उसने हजारों लोगों को शिक्षित किया है लेकिन केन्द्र सरकार ने हरियाणा जो सारे देश में नम्बर दो का प्रांत है, उसके लिए कुछ नहीं सोचा। इसके अलावा मेरा मुख्यमंत्री जी से अनुरोध है कि जो एन०सी०आर० जोन में डिवल्पमैंट के लिए उन्होंने कहा है, मेरा इसके बारे में सुझाव है कि नोएडा की तर्ज पर एन०सी०आर० के विकास के लिए भी एक बोर्ड बना दिया जाए। इससे प्रदेश के लोगों को सुविधा होगी। इसके अलावा सरकार जो रोहतक तक फोर-लेन का हाई-वे बनाने जा रही है उसके लिए बजट में भी कोई प्रावधान नहीं रखा गया है। शायद इसके लिए तो भारत सरकार ही पैसा देती है। सांपला में चौधरी ओम प्रकाश चौटाला ने एक बहुआयामी प्रोजैक्ट के लिए आधारशिला रखी थी लेकिन आज उस पत्थर का पता नहीं है। इस बारे में मुझे नहीं मालूम कि वह प्रोजैक्ट क्या था? पिछले दिनों चौटाला साहब ने रैली में उसके बारे में कहा था। इसके बारे में मैं कहना चाहूँगा कि अगर ऐसी कोई योजना है तो उसको जरूर चालू किया जाये। इसके अलावा सांपला सी०एच०सी० में जब मैं एक दिन रात को अढ़ाई बजे गया तो वहां पर ताला लगा हुआ था। सिर्फ चौकीदार और एक नर्स ही वहां पर मौजूद थे वह नर्स कहने लगी कि भाई मैं तो आपके गौत्र की हूँ। सर, मेरे पास इसकी वीडियो रिकार्डिंग है। वहां पर ऐसी हालत है कि न तो कोई बैड है और बिल्डिंग भी जर्जर हालत में है। मैं चाहूँगा कि इस बारे में ध्यान दिया जाए। इसके बाद मैं माननीय मुख्यमंत्री जी से अनुरोध करूंगा कि सांपला में एक आई०टी०आई० खोलने की भी कृपा करें क्योंकि वहां पर लोकल बच्चे टैक्नीकल शिक्षा ग्रहण करने से वंचित हो जाते हैं जिसके कारण बाहर के बच्चे वहां के कारखानों में नौकरी लगते हैं। पाकसमा माईनर के बारे में भी मैं कहना चाहूँगा।

[श्री नरेश मलिक]

इस माईनर के बारे में चौटाला साहब ने भी घोषणा की थी लेकिन वह आज तक नहीं बना है। इसके एस्टिमेट्स कई बार बन चुके हैं इसलिए मेरा अनुरोध है कि इसको भी बनाया जाए और उस क्षेत्र को पूरा पानी दिया जाए। धन्यवाद।

श्रीमती गीता भुक्कल (कलायत एस०सी०) : माननीय अध्यक्ष महोदय, मैं आपके माध्यम से माननीय मुख्यमंत्री श्री भूपेन्द्र सिंह हुड्डा और माननीय वित्त मंत्री श्री बीरेन्द्र सिंह जी का धन्यवाद करती हूँ और उन्हें बधाई देती हूँ कि उन्होंने एक अच्छा बजट यहां पर पेश किया है। मैं उस बजट का समर्थन करती हूँ। जब से हरियाणा में माननीय मुख्यमंत्री श्री भूपेन्द्र सिंह हुड्डा के नेतृत्व वाली सरकार बनी है।

11.00 बजे

श्री अध्यक्ष : बहन जी, आपके बोलने का समय 6 मिनट है।

श्रीमती गीता भुक्कल : अध्यक्ष महोदय, कांग्रेस पार्टी का यह नारा रहा है कि कांग्रेस पार्टी का हाथ आम आदमी के साथ और यह बजट उसी नारे को ध्यान में रखते हुये ही बनाया गया है जिसमें हर वर्ग, हर क्षेत्र का ध्यान रखा गया है। बजट में सबसे ज्यादा पैसे का प्रावधान सोशल सैक्टर के लिये किया गया है। इन्फ्रास्ट्रक्चर को भी टॉप प्रायोरिटी पर रखा गया है। जब से हरियाणा बना है, मैं समझती हूँ कि यह पहली सरकार है जिसमें माननीय मुख्यमंत्री जी ने और वित्तमंत्री जी ने एक विजन रखा है और सोशल सैक्टर में तकरीबन 1568.92 करोड़ रुपये का प्रावधान रखा है जो टोटल प्लान एलोकेशन का 47.54 प्रतिशत है। सोशल सैक्टर की जहां तक बात करें, इसमें बुढ़ापा पैंशन, हैंडीकैप्ड पैंशन, बेरोजगारी भत्ता यानि सभी तरह की पैंशंज को इसमें शामिल किया गया है। अध्यक्ष महोदय, हरियाणा में पहले प्रथा यह थी कि Haryana will follow Punjab लेकिन माननीय मुख्यमंत्री जी के नेतृत्व में इस सरकार ने ऐसे अच्छे निर्णय लिये हैं और बजट में उनके लिये पैसे का प्रावधान किया है। अब ट्रैंड चेंज हो गया है और नया ट्रैंड बना है कि Punjab will follow Haryana. हमारे बहुत से ऐसे निर्णय हैं जिनको पंजाब फोलो कर रहा है। जैसे चौकीदारों के भत्ते की बात है या नम्बरदारों के भत्ते की बात है पंजाब ये सब प्रावधान अपने यहां हरियाणा की तर्ज पर करने जा रहा है। इसके अलावा वूमैन सैक्शन पर भी बजट में विशेष ध्यान दिया गया है। वर्ष 2006 को बालिका वर्ष के रूप में मनाया जा रहा है। इंदिरा गांधी प्रिय-दर्शनी विवाह शगुन योजना सरकार ने शुरू की है और लाडली स्कीम भी शुरू की है। इसके अतिरिक्त महिलाओं को स्कूल अध्यापकों की भर्ती तथा हरियाणा आवास बोर्ड की आवास योजना में 33 प्रतिशत का आरक्षण भी दिया गया है और मकानों और प्लाटों की रजिस्ट्रेशन के लिए स्टैम्प ड्यूटी में भी उनको छूट दी गई है। अध्यक्ष महोदय, स्वास्थ्य की सेवाओं की तरफ भी हमारी सरकार ने विशेष ध्यान दिया है। स्वास्थ्य की सेवाओं के लिये हैल्पर लगाये गये हैं ताकि स्वास्थ्य की सेवाओं को न केवल शहरों तक बल्कि गाँवों तक भी पहुंचाया जाये। इसके लिये मैं सरकार का धन्यवाद करती हूँ। अध्यक्ष महोदय, मेरा एक छोटा सा सुझाव है कि जितने भी हमारे सैल्फ हैल्प ग्रुप हैं चाहे वे आई०सी०डी०एस० के हैं या पंचायती राज के हैं उनके आफिशियल्ज के लिये ओरिएन्टेशन कैम्पस का आयोजन किया जाये ताकि उनको नये तरीकों की जानकारी हो सके। अध्यक्ष महोदय, महिला शौचालयों को बनाने की बात पिछले बजट में भी कही गई थी लेकिन इस बजट में महिला शौचालयों को बनाने के लिए अलग से पैसे का प्रावधान नजर नहीं आता। महिला विधायक होने के नाते इस बारे में मैं कहना चाहूंगी कि गाँवों में महिलाओं के लिए शौच जाने की बहुत समस्या होती है। भारत सरकार की टोटल सैनीटेशन स्कीम के तहत हरियाणा में पैसा आ रहा है और मैं चाहूंगी कि इस बजट में भी महिला शौचालयों को बनाने के लिये अलग से पैसे का प्रावधान किया जाए। अभी

जो 600 रुपये एक शौचालय को बनाने के लियें दिया जाता है वह पैसा बहुत कम है। महिलाओं के शौचालयों से संबंधित बहुत सी समस्याएं हैं। ऐसे बहुत से इंसीडैंट्स हैं जिनको महिला शौचालय बनाकर दूर किया जा सकता है। यह वर्ष बालिका वर्ष के रूप में मनाया जा रहा है इसलिए इस ओर सरकार अवश्य ध्यान दे। अध्यक्ष महोदय, अब मैं पीने के पानी के बारे में बात करना चाहूंगी। सरकार ने पीने के पानी के अच्छे प्रबन्ध किए हैं और मेरे क्षेत्र कलायत को भी पाँच करोड़ रुपये पीने के पानी की व्यवस्था करने के लिये दिए हैं। लेकिन मैं यह कहना चाहूंगी कि हमारी सरकार ने वचन दिया था कि हरिजनों की बस्तियों में पीने का पानी पहुंचाया जायेगा। अब भी बहुत से ऐसे गाँव हैं जहां पर हरिजनों की बस्तियों में पानी नहीं है। ऐसा क्या कारण है कि जब एक गाँव में पानी की टंकी बनती है तो हरिजन बस्तियों में पानी पहुंचाने में क्या दिक्कत है ? इस तरफ सरकार ध्यान दे और हरिजन बस्तियों में भी पानी पहुंचाये। अध्यक्ष महोदय, इसके अलावा एस०सीज० और बी०सीज० के हितों के लिए हमारी सरकार ने बहुत अच्छे निर्णय लिए हैं। प्रिय-दर्शनी शगुन योजना के तहत कन्यादान की राशि 5000 रुपये से बढ़ाकर 15000 रुपये की गई है। हाऊस बनाने की ग्रांट, 10000 रुपये से बढ़ाकर 50000 रुपये की गई है। इसके अतिरिक्त डॉ० अम्बेडकर मेधावी योजना के तहत छात्रों को छात्रवृत्ति देने का कार्य किया है और 85वां संशोधन लागू करके सरकार ने बहुत महत्त्वपूर्ण कार्य किया है। इसके लिये मैं अपनी सरकार को बधाई देती हूं और धन्यवाद करती हूं। इसके अतिरिक्त पुस्तकों व लेखन सामग्री का भी गरीब बच्चों के लिए प्रावधान किया गया है। अध्यक्ष महोदय, ये सब कार्य हमारी सरकार में ही संभव हो सकते हैं। इसके अतिरिक्त मैं मुख्यमंत्री जी का धन्यवाद करना चाहूंगी कि इन्होंने 50 लाख रुपये का प्रावधान एच०आर०डी०एफ० के तहत विधायकों के हल्कों के लिये किया है जिससे वे अपने हल्कों में विकास कार्य करवा सकते हैं। जहां तक पंचायतों को स्ट्रैंथन करने की बात है एक डैमोक्रेटिक सिस्टम में जो हमारे जिला परिषद, ब्लॉक समितियां और पंचायत लेवल की संस्थाएं हैं, हमारी सरकार ने बजट में अलग से उनके लिए पैसे का प्रावधान करके उनको भी मजबूत किया है और उनके कामकाज को पूरी तरह से लोकतांत्रिक तरीके से पेश किया गया है। हमारे यहां पर पॉवर की बात की जा रही है। पॉवर की कमी का हमें जो आज सामना करना पड़ रहा है वह सब पुरानी सरकारों का किया धरा था। आज हमें बिजली के संकट से जूझना पड़ रहा है यह संकट पिछली सरकारों की नीतियों के कारण है। हमारी सरकार ने बनते ही जो चार पॉवर स्टेशनों का कार्य शुरू करवाया है उसके लिए हमारी सरकार बधाई की पात्र है। राजीव गांधी विद्युतीकरण योजना के तहत हर गाँव में बिजली पहुंचाने का कार्य हमारी सरकार कर रही है। अध्यक्ष महोदय, मैं यह मांग करूंगी कि कुछ ऐसे बैकवर्ड ऐरियाज हैं खासतौर पर कलायत जैसे क्षेत्र जिनके लिए एक पैकेज की घोषणा जरूर की जा सकती है ताकि उन पिछड़े हल्कों को भी उन्नत हल्कों के बराबर लाया जा सके। स्पीकर सर, जहां तक ट्रांसपोर्टेशन की बात है, 'सारथी' नामक जो बस सेवा शुरू की गई है यह बहुत ही अच्छी बात है। हमारे साथी राव दान सिंह जी ने यह बात कही थी कि हरियाणा रोडवेज की बस देखते ही आम नागरिक इसकी ओर आकर्षित होता है क्योंकि यह समझा जाता है कि हरियाणा रोडवेज की सेवा सबसे अच्छी है। इसके लिए भी मैं सरकार का धन्यवाद करती हूं और बधाई देती हूं। खासतौर से मैं सरकार को इस बात के लिए बधाई देती हूं कि हमारे कलायत बस अड्डे की जो 36 साल पुरानी मांग थी उसको हमारी सरकार ने माना है और बजट में उसके लिए पैसे का प्रावधान किया है। अध्यक्ष महोदय, सरकार से मेरी एक रिक्वैस्ट और है कि 'सारथी' नाम की बस सेवा हिसार चण्डीगढ़ तथा हिसार सिरसा तक चलाई जाए। अध्यक्ष महोदय, क्वालिटी ऐजूकेशन में सुधार को देखते हुए माननीय मुख्यमंत्री जी, मैं आपसे पुरजोर तथा हाथ जोड़कर प्रार्थना करती हूँ कि इस बार आपने इस वर्ष को 'बालिका वर्ष'

[श्रीमती गीता भुक्कल]

घोषित किया है। हमारा कलायत हल्का ऐजूकेशन में बरसों-बरसों से पिछड़ा हुआ रहा है इसलिए इस तरफ भी ध्यान दिया जाए। (विघ्न) जहां तक शिक्षा की बात है, कलायत क्षेत्र शिक्षा के मामले में बहुत पिछड़ा हुआ क्षेत्र रहा है। यहां पर गरीब जनता ने पैसा इकट्ठा करके नौ एकड़ लैण्ड पर कपिल मुनि महिला कॉलेज के नाम पर एक बिल्डिंग तैयार की है। हम लोग यह मांग करते हैं कि किसी भी तरह से किया जाए लेकिन इस वर्ष पिछड़े हुए कलायत हल्के को एक तोहफा दिया जाए तथा इस कॉलेज को गवर्नमैंट टेकओवर करके वहां पर आई०टी०आई० बनाए, पॉलिटैक्निक कॉलेज बनाए या कुछ न कुछ वहां पर जरूर बनाएं। जब भी पिछड़े हुए हल्के के विकास की बात आए तो कलायत क्षेत्र की ओर विशेष ध्यान दिया जाए। अध्यक्ष महोदय, मैं धन्यवाद करती हूं पर-कैपिटा इन्कम के हिसाब से हरियाणा प्रदेश देश भर में नम्बर वन राज्य है। इसी तरह से हमारी सरकार यदि अपना बजट पेश करती रही और जनकल्याण के कार्यों में कार्य कुशलता से काम करती रही तो शीघ्र ही हमारा प्रान्त देश का नं० 1 राज्य बनेगा। अध्यक्ष महोदय, आपने मुझे बोलने के लिए समय दिया, इसके लिए मैं आपका धन्यवाद करते हुए अपना स्थान ग्रहण करती हूं।

श्री शेर सिंह (जुलाना) : स्पीकर महोदय, आपका बहुत-बहुत धन्यवाद कि आपने मुझे बजट पर बोलने के लिए समय दिया। मैं इस बजट का समर्थन करता हूँ। मैं आपको बताना चाहूँगा कि मैंने पाँच बजट पिछली सरकार के देखे हैं और अपनी सरकार का यह दूसरा बजट भी देख रहा हूँ। पिछली सरकार के समय के जो बजट मैंने देखे हैं मैंने उनमें यह पाया है कि वे बजट स्टीरियो टाईप हुआ करते थे और लोगों की आकांक्षाओं के अनुरूप नहीं हुआ करते थे। अभी जो दो बजट हमारी सरकार ने प्रस्तुत किए हैं पिछले साल और इस साल यह एक वैल्फेयर स्टेट के लिए एक बहुत बड़ा मोड़ है। हमारा संविधान जब बनाया गया था तो उस समय हमारे संविधान निर्माताओं की यह आकांक्षा थी कि हमारा समाज अग्रसर हो और देश में तथा प्रदेश में जो सरकारें बनें वे समाज कल्याण के लिए बनें। यह एक बहुत बड़ा अच्छा और कल्याणकारी बजट है। इस बजट में जितने पैसे का प्रावधान किया गया है वह ज्यादातर सोशल सैक्टर में दिया गया है। लगभग 50% बजट कल्याणकारी कार्यों के लिए रखा गया है। जब तक इन्फ्रास्ट्रक्चर नहीं होगा विकास की कोई भी चीज तब तक लागू नहीं की जा सकती है। इस बजट के बारे में जितना भी वर्णन किया जाए, जितनी भी प्रशंसा की जाए वह कम है। यह बजट लोगों की आकांक्षाओं पर खरा उतरा है और लोगों का विश्वास इस सरकार पर बढ़ रहा है। अध्यक्ष महोदय, मैं आपको यह बताना चाहूंगा कि किसी भी कार्यक्रम को, किसी भी संस्था को किसी भी समाज को अगर आगे बढ़ाना है तो कानून-व्यवस्था का बहाल होना अत्यावश्यक है। अध्यक्ष महोदय, मैं सदन में एक बात कहना चाहूंगा कि आज दो चीजों पर हिन्दुस्तान टिका हुआ है एक किसानों पर और दूसरा जवानों पर। 'जय जवान और जय किसान' का नारा इसी बात को ध्यान में रखते हुए दिया गया था। आज जो जवान पैरामिल्ट्री फोर्सिज और आर्म्ड फोर्सिज में जाते हैं वे गाँवों के गरीब और किसान आदमियों के बच्चे ही जाते हैं, लोअर तबके के बच्चे ही जाते हैं। अधिकारी वगैरा तो बड़े लोग आ जाते हैं लेकिन जो जवान हैं वे लोअर तबके से ही भर्ती होते हैं। इस सरकार की तरफ से उनके लिए जो काम किया गया है उसकी वजह से उन लोगों का मनोबल बढ़ा है और इस सरकार की उस बारे में चारों तरफ तारीफ की जा रही है। अध्यक्ष महोदय, पहले हमारे यहां पर ज्वायंट फैमिलीज हुआ करती थीं लेकिन अब वे टूट रही हैं जिसकी वजह से अगर फौज में उस जवान को कुछ हो जाता है तो उसके पीछे से उसका परिवार आकेला ही रह जाता है। आदरणीय मुख्यमंत्री जी और फाईनांस मिनिस्टर जी ने जो कदम उनके लिए बढ़ाया है यह बहुत ही सराहनीय कदम है। आज

किसान और मजदूर जो भी काम करते हैं और जो वे मेहनत करके खेती करते हैं उसकी वजह से ही हमारा व्यापार चल रहा है। इसके अलावा हमारे यहां पर जो कारखाने लगे हैं उनसे भी हमारे व्यापार में बढ़ौतरी होती है। इस सरकार ने इन दोनों की तरफ ध्यान दिया है, सरकार का यह बहुत ही सराहनीय कदम है। अध्यक्ष महोदय, पिछली सरकार के वक्त में पुलिस की भर्ती में जवानों की हाईट बढ़ाकर 5 फुट 9 इंच कर दी गई थी लेकिन इस सरकार ने आकर उसको 5 फुट 7 इंच कर दिया है। हमारे हरियाणा में नार्मल हाईट 5 फुट 7 इंच ही है। अध्यक्ष महोदय, एक बात मैं आपके जरिए से सदन के ध्यान में लाना चाहूंगा कि हमने सभी विषयों की तरफ ध्यान दिया है लेकिन बढ़ती हुई पापुलेशन की तरफ क्या किसी ने ध्यान दिया है? आज हम जो भी दो कदम आगे बढ़ाते हैं पापुलेशन बढ़ने के कारण सहज ही वह एक कदम पीछे आ जाता है। यह क्यों है? हमें इस तरफ भी ध्यान देना चाहिए। इसके अलावा हमने लिंग-अनुपात को कम करने के लिए काफी अच्छे कदम उठाए हैं। लेकिन पापुलेशन को कंट्रोल करने के लिए जो गरीब तबका है, उसको इस बारे में शिक्षित करने की आवश्यकता है ताकि बढ़ती हुई पापुलेशन पर कंट्रोल हो सके। जय हिन्द।

श्री अध्यक्ष : डॉक्टर सीता राम जी, आप बोलिए। आपके अब 12 मिनट रह गए हैं। श्री बलवन्त सिंह सढ़ौरा जी ने भी अपनी बात कहनी है। यह अब आप देख लें कि आपने ही 12 मिनट बोलना है या दोनों ने आधे-आधे समय में अपनी बात कहनी है।

डॉ० सीता राम (डबवाली, एस०सी०) : अध्यक्ष महोदय, मैं आपकी इजाजत से बजट अनुमान पर जो चौधरी बीरेन्द्र सिंह जी ने प्रस्तुत किया है, उस पर चर्चा करने के लिए खड़ा हुआ हूं। मैं नेट-सैल में कोशिश करूंगा कि अपनी सारी बात कह सकूं। चौधरी बीरेन्द्र सिंह जी बहुत ही सूझबूझ वाले व्यक्ति हैं और इन्होंने बड़े ही शायराना अन्दाज में अपनी बात की थी। इन्होंने वह बात दिल से निकलती हुई बात की थी। हमारी हमेशा से उनसे हमदर्दी है, सहानुभूति है। स्पीकर सर, अब मैं थोड़ा सा बजट के बारे में जिक्र करना चाहूंगा। जो प्लान ऐक्सपैंडीचर है उसमें 2004-05 के अंदर 44 परसैंट की रिकार्ड वृद्धि हुई है जोकि बहुत अच्छी बात है लेकिन जो यह वृद्धि 2006-07 के बजट में दिखाई गयी है उसको देखकर लगता है कि इससे पहले जब हमारी सरकार थी, ओम प्रकाश चौटाला साहब की सरकार थी जिन्होंने उस समय प्रदेश को अच्छा इन्फ्रास्ट्रक्चर दिया था उसकी वजह से ही एकदम से इतनी भारी 44 परसैंट की रिकार्ड वृद्धि करने में ये लोग कामयाब हुए हैं। इसके अलावा मैं नॉन-प्लान ऐक्सपैंडीचर का भी जिक्र करूंगा। 2004-05 के अंदर नॉन-प्लान ऐक्सपैंडीचर के अंदर 9806.93 करोड़ रुपये थे लेकिन उसके बाद 2006-07 में नॉन-प्लान ऐक्सपैंडीचर में यह बढ़कर 11403.45 करोड़ रुपये हो गये हैं। इसको देखकर लगता है कि यह ऐक्सपैंडीचर ज्यादा बढ़ गया है जोकि नहीं बढ़ना चाहिए क्योंकि यह एक अच्छी अर्थदशा का सूचकांक नहीं है। स्पीकर साहब, रैवेन्यू डैफीशिट को भी इन्होंने कम करने की कोशिश की है। वर्ष 2005-06 में बहुत ज्यादा था लेकिन उसके बाद इसको रिवाइज करके इसको 603.33 करोड़ रुपये के ऊपर ये लेकर आये हैं जोकि अच्छी बात है। स्पीकर साहब, हमारे समय के अंदर यह 258 करोड़ रुपये था जोकि बहुत ज्यादा था लेकिन हमारी सरकार ने कोशिश करके अच्छे वित्तीय प्रबन्धन से इसको कम किया। इसके अलावा जो राजकोषीय घाटा है वह वर्ष 2004-05 के अंदर 1205.92 करोड़ रुपये था जोकि बाद में वर्ष 2006-07 के अंदर 1848.33 करोड़ रुपये हो गया है। स्पीकर सर, इन सब बातों को देखकर लगता है कि जो स्टेट की इकोनोमी है जिसको हम अपने समय के अंदर पटरी पर लेकर आए थे, वह धीरे-धीरे नीचे उतरनी शुरू हो गई है। स्पीकर साहब, जो मेजर ऐलोकेशनज की गयी थीं मैं उनका जिक्र नहीं करूँगा लेकिन मैं उनका जिक्र जरूर करूँगा जहां पर वर्ष 2005-06 के मुकाबले बजट को घटा दिया गया है। सोशल

[डॉ० सीता राम]

वैलफेयर, न्यूट्रिशियन वैलफेयर, एस०सी० और बी०सीज० का जो डिपार्टमैंट है उसको वर्ष 2005-06 में 859 करोड़ रुपये दिये गये थे लेकिन अब उसको घटाकर 811 करोड़ रुपये कर दिया गया है। इस तरह से एग्रीकल्चर डिपार्टमैंट में भी किया गया है। इसमें भी इस बार बजट कम हुआ है। इसी तरह से रूरल डिवैल्पमैंट डिपार्टमैंट में किया गया है इसका भी बजट कम किया गया है। इसी प्रकार से जो मेवात एरिया डिवैल्पमैंट बोर्ड है उसको वर्ष 2004-05 में 12.66 करोड़ रुपये दिये गये थे लेकिन अब इसको दस करोड़ रुपये दिये गये हैं। फ्लड कंट्रोल के लिए, विलेजिज एंड स्मॉल स्केल इंडस्ट्रीज के लिए, लार्ज एंड मीडियम इंडस्ट्रीज के लिए, इलैक्ट्रानिक्स एंड इंफोर्मेशन टैक्नोलॉजी के लिए, टूरिज्म के लिए, इंडस्ट्रियल ट्रेनिंग एवं वोकेशनल एजुकेशन के लिए भी इस बार कम बजट दिया गया है। स्पीकर सर, अब मैं आर्थिक सर्वेक्षण के बारे में कहना चाहूँगा। राज्य की अर्थव्यवस्था में वर्ष 2004-05 में उल्लेखनीय वृद्धि हुयी थी। वर्ष 2004-05 में हरियाणा प्रदेश का वित्तीय प्रबन्धन सारे देश में अच्छा था। 12वें वित्तीय आयोग ने भी इसको सराहा था। सर, आर्थिक सर्वेक्षण के अंदर लिखा है कि वर्ष 1998-99 में सकल घरेलू उत्पाद का जो वित्तीय घाटा था वह 5.1 परसैंट था जो वर्ष 2004-05 में हमारे समय में 1.4 परसैंट आ गया था। इस तरह से यह देखकर भी लगता है कि हमारे समय में वित्तीय प्रबन्धन अच्छा था। अच्छे वित्तीय प्रबन्धन की वजह से ही सरकार बजट के अंदर ऐक्सपैंडीचर में ज्यादा अमाउंट देने में सक्षम हुई है। स्पीकर साहब, मैं एक और बात और कहना चाहूँगा कि वर्ष 2002 से लेकर 2005 तक जिस समय हमारी सरकार थी उस समय हमने एक दिन भी ओवर ड्राफ्टिंग नहीं की यह बहुत बड़ा काम है। (विघ्न)

श्री अध्यक्ष : डाक्टर साहब, आपको बोलते हुये छः मिनट हो गये हैं। क्या आपने अपने साथी से कन्सलट कर लिया है कि उनका समय भी आप अपने समय में जोड़ लेंगे, क्योंकि आप दोनों को 12 मिनट मिले हैं ?

डॉ० सीता राम : अध्यक्ष महोदय, मैं संक्षिप्त में अपनी बात कह देता हूँ। अध्यक्ष महोदय, अब मैं ग्रान्ट-इन-ऐड के बारे में कहना चाहता हूँ। कोआप्रेटिव सैक्टर में वर्ष 2005-2006 में बजट 1076.17 करोड़ रुपये था जो वर्ष 2006-07 में 1031.28 करोड़ हो गया यानि यह घटा है। (विघ्न) एक्स रेवेन्यू आपका घट रहा है क्योंकि सरकार को टैक्स डिपार्टमैंट की कोई स्पोर्ट नहीं मिल रही है। वर्ष 2004-05 में में यह 17 प्रतिशत इन्क्रीज हुआ था जोकि इस सरकार के समय में वर्ष 2005-06 में यह 14.6 प्रतिशत रह गया है। सरकार ने जो नई एक्साईज पोलिसी बनाई है उसके बारे में मैं कहना चाहता हूँ। सरकार ने प्रोपोज किया है कि वर्ष 2005-06 में 18 प्रतिशत की एक्साईज में इन्क्रीज होगी लेकिन जब एक्चयूअल देखा गया तो पाया कि यह तो 9 प्रतिशत ही है। इतना ही नहीं सरकार ने जो शराब की क्वालिटी लीटर के हिसाब से बढ़ा दी है। सही तौर पर देखा जाये तो इसमें कोई इनक्रीज नहीं आई है। सरकार ने वर्ष 2006-07 के लिये एक्साईज पोलिसी लाकर शराब के ठेकों की नीलामी लॉटरी सिस्टम से की है। उसके बाद सरकार ने घोषणा की है कि इससे 20 प्रतिशत रेवेन्यू इन्क्रीज होगा लेकिन जब हमने अखबारों में पढ़ा तो पाया कि जो देशी शराब के ठेके थे उनमें 50 प्रतिशत एप्लीकेशंज नहीं लगी हैं। इस बारे में हमें थोड़ा डाउट होता है कि जो टारगेट सरकार ने फिक्स किया है, क्या उसको आप अचीव कर पायेंगे ?जो ठेके दिये हैं उसमें यह किया है कि एक गाँव में ठेका किसी का होगा और साथ लगते दूसरे गाँव में ठेका किसी और का होगा इससे यह होगा कि एक दूसरे ठेका के एरियाज में शराब सप्लाई की जाएगी और जिसके कारण गाँवों में और झगड़े बढ़ेंगे, पुलिस प्रशासन में भ्रष्टाचार बढ़ेगा और आने वाले समय में कानून-व्यवस्था की स्थिति और ज्यादा बिगड़ जाएगी।

श्री अध्यक्ष : डॉक्टर साहब, आपको बोलते हुये आठ मिनट हो गये हैं। Please wind up.

डॉ० सीता राम : सर, मैं कन्कलूड कर देता हूँ। अब मैं वैट के बारे में कुछ कहना चाहूँगा। देहली गवर्नमैंट ने वैट लागू करते समय देशी घी के टैक्स को जो 12.5 प्रतिशत था उसको घटाकर 4 प्रतिशत कर दिया है, एल०पी०जी० के टैक्स को जो 12.5 प्रतिशत था उसको घटाकर 4 प्रतिशत कर दिया है, कोको प्रोडक्ट के टैक्स को जो 12.5 प्रतिशत था उसको घटाकर 4 प्रतिशत कर दिया है, और बुलैन के टैक्स को जो 1 प्रतिशत था उसको घटाकर 0.1 प्रतिशत कर दिया है। मेरे कहने का भाव यह है कि हरियाणा प्रदेश में भी उन वस्तुओं पर टैक्स की छूट देहली की तर्ज पर ही होनी चाहिए नहीं तो हरियाणा प्रदेश का व्यापार चौपट हो जाएगा। इस बारे में सरकार को देहली सरकार से बातचीत करनी चाहिये कि इसको एक जैसा रखें क्योंकि हरियाणा दिल्ली के सबसे नजदीक पड़ता है।

Mr. Speaker : Dr. Sita Ram, please wind up. आपको बोलते हुए नौ मिनट हो गये हैं।

डॉ० सीता राम : सर, मैं कन्कलूड कर देता हूँ वैसे काफी जरूरी बातें कहने की हैं मेरे पास मैटीरियल बहुत है।

श्री अध्यक्ष : मुझे पता है डॉक्टर साहब, आप लिटरेरी आदमी है।

डॉ० सीता राम : सर, अब मैं एजूकेशन के बारे में कहना चाहता हूँ। आपने मॉडल स्कूल का जिक्र किया। पहले कहा कि नया मॉडल स्कूल बनाने के लिये तीन-साढ़े तीन करोड़ रुपये खर्च होगा और अब एक नया सांस्कृतिक पब्लिक स्कूल के बारे में जिक्र किया जोकि रजिस्टर्ड सोसायटीज सरकार की ऐड के साथ बनायेंगी। आप यह बतायें कि उनको जो ऐड दी जाएगी तो ये रजिस्टर्ड सोसायटीज प्राईवेट होंगी या सरकारी और ये स्कूल कब तक बनकर तैयार हो जायेंगे ? सरकार ने डॉ० अम्बेडकर मेधावी छात्र योजना नामक एक नई स्कीम भी बनाई है जिसमें एस०सी० और बी०सीज० (ब्लॉक-ए) के छात्र जो 60 प्रतिशत या 60 प्रतिशत से अधिक अंक दसवीं कक्षा में लेंगे उनको एक हजार रुपये प्रति माह दस जमा दो कक्षा तक देने की घोषणा की है उसके अन्दर छात्रों की संख्या 2000 एस०सीज० के लिये और एक हजार बी०सीज० के लिये निर्धारित की है। और बी०सी० के अन्दर दूसरी कैटेगरी को छोड़ दिया गया है। मैं सरकार से अनुरोध करता हूँ कि इसमें जो छात्रों की संख्या निर्धारित की गई है वह हटा देनी चाहिये और जो भी एस०सी० या बी०सी० कैटेगरी का विद्यार्थी 60 प्रतिशत या उससे अधिक नम्बर लेकर दसवीं कक्षा में पास होता है उनको सभी को यह भत्ता मिलना चाहिये।

श्री अध्यक्ष : डॉक्टर साहब, आपको बोलते हुये 10 मिनट हो गये हैं। प्लीज आप वाईड-अप करें।

डॉ० सीता राम : अध्यक्ष महोदय, मैं एक दो बातें कहकर वाईंड-अप करता हूँ। अध्यक्ष महोदय, अब मैं एजूकेशन के बारे में कहना चाहूँगा कि बजट में राजीव गांधी एजूकेशन सिटी बनाने का जिक्र किया गया है और इसके लिये 6 करोड़ रुपये का प्रावधान बजट में किया गया है। पिछले बजट में भी इसका जिक्र किया गया था। हमें तो यह एजूकेशन सिटी बनती नजर नहीं आ रही। क्या 6 करोड़ रुपये में कोई एजूकेशन सिटी बन सकती है। इसके अतिरिक्त नैशनल लॉ कॉलेज मानेसर में बनाने का भी जिक्र किया गया है लेकिन बजट में उसके लिये पैसे का प्रावधान नहीं है। इसी तरह से महिला विश्वविद्यालय बनाने का भी जिक्र किया है लेकिन बजट में इसके लिये भी पैसे का प्रावधान नहीं है। अध्यक्ष महोदय, अब मैं कुछ बातें बिजली के बारे में कहना चाहूँगा कि बिजली की इस समय बहुत समस्या है। सत्ता पक्ष के सदस्यों ने भी कहा है कि बिजली की समस्या आज के दिन हरियाणा प्रदेश में बहुत अधिक है।

श्री अध्यक्ष : डॉक्टर साहब, प्लीज, अब आप बैठें। आप जो बोलना चाहते हैं वह पढ़ा समझा जाएगा आप लिखित में दे दें। प्लीज, आप बैठें। आपको बोलते हुये 12 मिनट का समय हो गया है। अब रमेश कुमार गुप्ता जी बोलेंगे।

डॉ० सीता राम : अध्यक्ष महोदय, मुझे एक बात बहुत जरूरी कहनी है।

श्री अध्यक्ष : आप डिमांड पर बोल लेना या एप्रोप्रिएशन बिल पर बोल लेना। प्लीज, अब आप बैठें।

श्री रमेश कुमार गुप्ता (थानेसर) : अध्यक्ष महोदय, आपने मुझे बजट पर बोलने के लिए समय दिया इसके लिए मैं आपका धन्यवाद करता हूँ। आदरणीय वित्तमंत्री महोदय ने 17 मार्च को सदन में जो बजट वर्ष 2006-07 के लिये पेश किया है मैं उसके समर्थन में बोलने के लिए खड़ा हुआ हूँ। यह सरकार का दूसरा बजट है जिसमें चहुँमुखी विकास, बिजली, पानी, शिक्षा, स्वास्थ्य आदि जो भी मूलभूत सुविधाएं हैं उनकी तरफ विशेष ध्यान दिया गया है। इस बजट में आम जरूरतों को पूरा करने के लिये पंचायतों और नगर पालिकाओं को अतिरिक्त फंड दिया गया है। **(इस समय सभापतियों की सूची में से एक सदस्य श्री आनन्द सिंह डांगी पदासीन हुये।)** सभापति महोदय, यह प्रस्ताव व्यापक है तथा इसमें अर्थव्यवस्था का प्रत्येक पहलू कृषि से लेकर उद्योग तथा सामाजिक क्षेत्र से लेकर रोजगार तक जुड़ा हुआ है। यह बजट आम जनता के प्रति सरकार की भावना को दर्शाता है। सभापति महोदय, हमारी सरकार बनते ही मुख्यमंत्री महोदय ने बहुत अहम् फैसले लिए थे जिनमें किसानों के 1600 करोड़ रुपये के बिजली के बिल माफ करना एक अहम् फैसला था। जिसके मद्देनजर वर्ष 2005-06 का जो वित्तीय घाटा 48.15 करोड़ रुपये था। उस पर वित्त मंत्री जी ने बड़ी कुशलता से नियन्त्रण रखते हुए 53.91 करोड़ रुपये तक रखने का प्रयास किया है जो कि बहुत मनेजेबल है। सभापति महोदय, सरकार एक तरफ जहां जन-कल्याण के कार्यों पर खर्च कर रही है वहीं दूसरी तरफ राजस्व पर भी ध्यान रखे हुए है और हमारी सरकार के प्रयासों से 600 करोड़ रुपये के राजस्व की प्राप्ति होने का अनुमान है। इसके अतिरिक्त सरकार ने जो ऋण लिये हुये हैं जिन पर ब्याज दर 13 प्रतिशत थी उसको कम करवाया गया है जिससे सरकार को लगभग 200 करोड़ रुपये का फायदा होगा और इससे प्रदेश की आर्थिक स्थिति मजबूत होगी। इसके लिए मैं वित्त मंत्री जी को बधाई देता हूँ। इसके अतिरिक्त किसानों से भी ब्याज आने वाले समय में 10 प्रतिशत से कम लिया जाएगा इसलिए भी मैं सरकार को बधाई देता हूँ। सभापति महोदय, इसके अतिरिक्त वित्त मंत्री जी ने बताया है कि हरियाणा प्रदेश ने 12वें वित्त आयोग की शर्तों को पूरा कर लिया है। दिल्ली में अभी मुख्यमंत्रियों के स्तर की बैठक थी जिसमें सभी ने हमारे मुख्यमंत्री के प्रयासों को सराहा है और दूसरे राज्य भी हमारा अनुसरण कर रहे हैं। सभापति महोदय, बजट में सरकार की तरफ से जो भी घोषणाएं की गई हैं उनका पूरे प्रदेश में स्वागत हो रहा है। अब मैं सरकार का ध्यान कुरुक्षेत्र और थानेसर हल्के की कुछ बातों की तरफ दिलाना चाहूँगा। बेरोजगारी एक अहम् मुद्दा है। उसको देखते हुए वित्तमंत्री जी तकनीकी संस्थान, वोकेशनल कोर्सिज आदि उन जिलों में खोलने जा रहे हैं जहां पर ये संस्थान नहीं हैं। इसके अतिरिक्त युवाओं को विदेश भेजने के लिये भी समिति का गठन किया जा रहा है जो कि बेरोजगारी को खत्म करने का बहुत अच्छा प्रयास है। मैं वित्त मंत्री जी से निवेदन करूँगा कि इस तरह की समिति का गठन कुरुक्षेत्र में भी किया जाये। सभापति महोदय, इसके अतिरिक्त सरकार की नई एक्साईज पॉलिसी का हर जगह स्वागत हो रहा है। पहले शराब का कारोबार जहां कुछ लोगों के हाथों में था अब ऐसा नहीं होगा और जो स्थानीय लोग हैं उनको भी ठेकेदारी करने का अवसर मिलेगा। उनको भी काम करने का

मौका मिला है और इससे रेवेन्यू भी बढ़ा है और बेरोजगारी भी दूर हुई है। सभापति महोदय, बिजली एक बहुत ही अहम् मुद्दा है मैं उस पर थोड़ा बताना चाहूँगा। पिछले 40 साल के इतिहास में अभी तक केवल चार हजार मेगावाट बिजली हम पैदा कर रहे थे। मुख्यमंत्री जी के प्रयास से आगे तीन-चार वर्षों में चार हजार मेगावाट और बिजली पैदा करने की उन्होंने घोषणा की है। जब यह बिजली पैदा होनी शुरू हो जाएगी तो प्रदेश में बिजली की कमी दूर हो जाएगी। इसमें 600 मेगावाट बिजली थर्मल प्लांट यमुनानगर से और उपलब्ध हो जाएगी और दूसरी जगहों पर भी बिजली बनाई जा रही है। एक हजार मेगावाट बिजली कोयले पर आधारित संयंत्र हिसार और फरीदाबाद में बनाने का लक्ष्य है। सभापति महोदय, माननीय मुख्यमंत्री जी और वित्तमंत्री जी इस समय हाउस में उपस्थित नहीं हैं। मैं उनका ध्यान बिजली बनाने के लिये ईंधन की ओर दिलाना चाहूँगा। सभापति महोदय, पैडी का छिलका बॉयलर्ज में इस्तेमाल होता है और इससे स्टीम बनती है। हरियाणा में पैडी का छिलका पर्याप्त मात्रा में उपलब्ध भी है इसका पता लगाना चाहिए कि क्या इससे बिजली बन सकती है? इसकी स्टडी भी हुई है और इस छिलके से भी बिजली बनाने का कार्य किया जा सकता है। अगले दो वर्षों में 63 नये सब-स्टेशन्ज बनाने और 58 सब-स्टेशन्ज को अपग्रेड करने की योजना है जिसमें 109 किलोमीटर की ट्रांसमीशन लाईन बनाने के लिए 700 करोड़ रुपये उस पर खर्च होने हैं। थानेसर हल्के को भी तीन-चार स्टेशन्ज मिले हैं जिनको जल्दी पूर्ण करने की मांग मैं सरकार से करूँगा जिससे इनका लाभ लोगों को जल्दी से जल्दी मिल सके। मेरे हल्के में जो ट्रांसफारमर्ज खराब पड़े हैं, ट्रांसमिशन लाईन ढीली हैं और बिजली की तारें पुरानी हो चुकी है, उनको भी जल्दी से जल्दी बदलने का कार्य किया जाये। 252 करोड़ रुपये की राशि राजीव गांधी ग्रामीण विद्युतीकरण योजना के लिये रखी गई है (विघ्न) सभी गाँवों के लोग इसकी सराहना कर रहे हैं। सभापति महोदय, मैं मांग करूँगा कि डोमैस्टिक और ट्यूबवैल्ज की लाईन अलग-अलग होनी चाहिए। सरकार का विशेष ध्यान खेती के ऊपर है क्योंकि हमारे प्रदेश के 75% लोग खेती से जुड़े हुये हैं उसमें अति आधुनिक किस्म के नये तरीके अपनाने की जरूरत है। इसके लिये नयी किस्म के उत्तम बीज किसानों को उपलब्ध करवाने होंगे। सभापति महोदय, करनाल, कुरुक्षेत्र तथा कैथल में बासमती जीरी का काफी जोर है। बासमती की नई किस्मों को प्रोत्साहन देने के लिए बासमती की नयी किस्मों का पता करवाना होगा जो कि गुणवत्ता के हिसाब से ठीक हों और जिसकी ईल्ड भी अच्छी हो। यह बासमती एक्सपोर्ट भी हो सकती है जिससे विदेशी मुद्रा भी मिलेगी। इन सब बातों को देखते हुये आदरणीय मुख्यमंत्री तथा माननीय कृषि मंत्री महोदय से मैं मांग करूँगा कि हिसार कृषि विश्वविद्यालय का एक रीजनल सैन्टर कुरुक्षेत्र में खोला जाए ताकि हमारे किसानों को उसका लाभ मिल सके। सभापति महोदय, डाईवर्सीफिकेशन ऑफ क्रॉप्स को हमारी सरकार अगर चाहती है तो इसके मद्देनजर प्रदेश में बायोटैक इण्डस्ट्रीज, फूड प्रोसैसिंग इण्डस्ट्रीज स्थापित होनी चाहिए। (विघ्न)

श्री सभापति : ठीक है गुप्ता जी, अब आप अपनी सीट पर बैठें।

डॉ० कृष्णा पण्डित (यमुनानगर) : ऑनरेबल सभापति महोदय, आपके माध्यम से मैं अपने माननीय मुख्यमंत्री जी और अपने फाईनैंस मिनिस्टर चौधरी बीरेन्द्र सिंह जी का बहुत-बहुत धन्यवाद करती हूँ और उनको बधाई देती हूँ तथा उनके इस बजट का अनुमोदन करती हूँ। मैं उनको आज सिर्फ एक बात कहना चाहती हूँ कि प्रस्तुत बजट बहुत ही अच्छा है और आम जनता में इसके प्रति बहुत ही उत्साह है। आम आदमी के लिए, गरीब आदमी के लिए बजट बहुत ही अच्छा दिया गया है। मैं एक बात की तरफ सरकार का ध्यान दिलवाना चाहती हूँ हमारे एरिया में थोड़ी सी बिजली की समस्या है। इसके अलावा मेरे एरिया में प्लाईवुड की इण्डस्ट्रीज की बहुत भारी समस्या है इसके लिए

[डॉ० कृष्णा पण्डित]

मैं माननीय मुख्यमंत्री जी से यह सिफारिश करती हूँ और हाथ जोड़कर प्रार्थना करूँगी कि इस तरफ जल्दी से जल्दी ध्यान दिया जाए क्योंकि बाकी जो मुद्दे हैं जैसे बिजली और पानी की समस्या है वह सारी जगहों पर एक सी है और उनको देखा जा रहा है। मुझे पार्लियामैंटरी सैक्रेटरी नियुक्त किया गया और मुझे हैल्थ मिनिस्टर के साथ सहयोग करने का मौका दिया गया है उसके लिये मैं मुख्यमंत्री जी का धन्यवाद करती हूँ और सुशील इन्दौरा जी ने भी मुझे बधाई दी है इसके लिए मैं उनका भी धन्यवाद करती हूँ। जब मैं पार्लियामैंटरी सैक्रेटरी बनी तो मेरा सबसे पहले यह विचार था कि हमें हरियाणा में हैल्थ डिपार्टमैंट की जो पोजीशन है उसको ठीक करना है। जब मैं इस विषय में हैल्थ मिनिस्टर जी से मिली तो उन्होंने मुझे कहा कि आप 12 से 2 बजे तक जाकर चैकिंग करें। मेरे एक साथी ने भी इस विषय में पूछा था कि क्या आप इस चैकिंग पर गए थे, अगर गए थे, तो आपने क्या किया और आपने क्या कार्यवाही की है? सभापति महोदय, मैं आपके माध्यम से सदन में बताना चाहूँगी कि इस चैकिंग के दौरान मैंने तीन रिपोर्टस बनाई हैं और वे रिपोर्टस मैंने मुख्यमंत्री जी, हैल्थ मिनिस्टर जी और कमिश्नर साहिबा हैल्थ विभाग को पेश कर दी थीं। मुझे उम्मीद है कि उन रिपोर्टस पर जल्दी से जल्दी विचार किया जाएगा। सभापति महोदय, मैं आपके माध्यम से मुख्यमंत्री जी से एक सिफारिश और गुजारिश भी करना चाहूँगी कि सभी हास्पिटल्ज में आप्रेशन थियेटर्ज हैं, लेबर रूम्ज हैं और जितनी भी लैबोरेटरीज हैं वहां पर जो आपरेशन से संबंधित सामान है वह सारे का सारा कैडम हो चुका है, उस सारे सामान को बदलने की सख्त जरूरत है। सभापति महोदय, मैं आपके माध्यम से माननीय वित्तमंत्री जी से निवेदन करूँगी कि आपको आप्रेशन थियेटर्ज के लिए अलग से बजट देना चाहिए। आज जिस भी हास्पिटल में जाएं, वहां पर रोज आप्रेशन होते हैं या जो टैस्ट होते हैं जैसे अल्ट्रासाउंड या सिटी स्कैन टैस्ट हैं वे मशीनें खराब होने की वजह से या वहां पर मशीन न होने की वजह से वे टैस्ट नहीं हो पाते हैं। जिसकी वजह से मरीज का आप्रेशन होना बहुत मुश्किल हो जाता है। इसके लिए अगर मरीज बाहर जाकर टैस्ट करवाएं तो वह टैस्ट 1000 रुपये या इससे महंगा हो जाता है। सभापति महोदय, गरीब आदमी के लिए इतना ज्यादा खर्चा करना बहुत ही मुश्किल हो जाता है। मैं माननीय मुख्यमंत्री जी को बताना चाहूँगी कि मैंने हास्पिटल्ज में जाकर देखा है कि जो बी०पी०एल० के लोग हैं उनसे हास्पिटल्ज में वे कार्डज मांगे जाते हैं और उनसे कहा जाता है कि अगर आप वह कार्ड दिखायेंगे तो ही आपको दवाईयां दी जाएंगी या हास्पिटल्ज में जो फीस ली जाती है वह तभी माफ होगी जब वे कार्ड दिखायेंगे। सभापति महोदय, जो आदमी एमरजैंसी में जाएगा तो उसके पास इतना समय ही नहीं होगा कि वह घर से बी०पी०एल० कार्ड उठा सके। मेरा निवेदन है कि उन लोगों पर मेहरबानी करके उस कार्ड को दिखाने की छूट दी जाए। इसके अलावा आप्रेशन थियेटर्ज में असिस्टैंट, लैब टैक्नीशियंज, रेडियोग्राफर, रेडियोलोजिस्ट इत्यादि होते हैं उनकी भी बहुत कमी है मेरी हैल्थ मिनिस्टर महोदया से और मुख्यमंत्री महोदय से गुजारिश है कि वे जल्दी से जल्दी इन पोस्ट्स की कमी को दूर करने का कष्ट करें ताकि हास्पिटल्ज की वर्किंग को सुचारु रूप से चलाया जा सके। हमें पिछली सारी रिवायतों से हटकर हरियाणा में बैस्ट मैडीकल फैसीलिटीज देनी चाहिएं। सभापति महोदय, सबसे ज्यादा गम्भीर बात जो सामने आई है वह यह है कि हास्पिटल्ज में जो लावारिस लाशें पड़ी होती हैं उनको रखने का सही इन्तजाम नहीं है। इसकी वजह से जो फोर्थ क्लास आदमियों की ड्यूटी लाश के पास होती है वे वहां पर खड़े नहीं हो सकते हैं क्योंकि उन लाशों में से बहुत बदबू आती है। जब मैंने वहां के सी०एम०ओ० से इस बारे में पूछा और वहां पर बर्फ का इंतजाम करने की बात कही तो उन्होंने मुझे कहा कि हमारे पास बर्फ का कोई प्रावधान नहीं है। मेरा आपसे अनुरोध है कि हरियाणा में जितने भी हास्पिटल्ज की मोर्चरिज हैं वहां पर बर्फ का भी इन्तजाम करवाया जाए ताकि जो लावारिस लाशें हैं

उनको ठीक तरह से रखा जा सके। सभापति महोदय, हास्पिटल्ज में कोई भी इन्वैस्टीगेशन करवानी हो तो उसके लिए पैसे जमा करवाने होते हैं। अब जैसे हास्पिटल्ज में ब्लड ग्रुप आर एच है इसकी बहुत जरूरत लोगों को होती है। इसके लिये अगर हम हास्पिटल्ज में पैसे जमा नहीं करवाएं तो इससे सरकार को कोई फर्क नहीं पड़ेगा। सभापति महोदय, गरीब आदमी उस टैस्ट के लिए 50 रुपये नहीं दे सकता है। जिसकी वजह से उसका वह टैस्ट नहीं हो पाता है। इसके अलावा जैसे डिलीवरी के समय में अगर किसी का ब्लड ग्रुप आर० एच० नैगेटिव होता है और उस समय उसका टैस्ट न हो तो उसको एक टीका लगाया जाता है जो कि एन०टी०डी० होता है। इस टीके की कीमत 1600 या 1700 रुपये की होती है। अगर वह टीका समय पर उस पेशैंट को नहीं लगाया गया तो माँ और बच्चे के लिये खतरा हो सकता है। मेरी इस बारे में सरकार से गुजारिश है कि जैसे ट्यूमर क्लोसिज और कैंसर की दवाईयां मुफ्त दी जाती हैं तो उसी तरह इस इंजैक्शन को भी मुफ्त कर दिया जाए। सभापति महोदय, मेरी चैकिंग की जहां-जहां रिपोर्टस थी वह मैंने सौंप दी हैं और उसमें 15-20 हास्पिटल्ज की जो मांगें हैं उस बारे में भी सरकार द्वारा विचार कर लिया जाए। आज सभी लोग कहते हैं कि हमारी मैडीकल सर्विसिज में इम्प्रूवमैंट आई हैं तो यह सब स्वास्थ्य मंत्री जी और मुख्यमंत्री जी की बदौलत है। सभापति महोदय, मैं आज कमिश्नर साहब को भी बधाई देना चाहती हूँ कि जिस दिन भी जहां पर भी मैं चैकिंग करके आती हूँ और वहां की रिपोर्ट इनके पास देती हूँ तो उसके दूसरे दिन ही जहां पर जो मांग होती है उन मांगों का अनुमोदन होता है और उसके बाद डायरैक्टर हैल्थ सर्विस वहां पर जाकर पता करती हैं कि वहां पर वह डिमांड पूरी हुई है या नहीं हुई। इसके लिए वे बधाई के पात्र हैं। चेयरमैन साहब, यह सब चीजें माननीय मुख्यमंत्री जी की आज्ञा के कारण हुई हैं। हर आदमी यही सवाल उठाता है जिस दिन से सैशन चल रहा है उस दिन से सबका टोपिक यही होता है कि अस्पतालों के लिए आप क्या करते हो। इसलिए मेरी यही गुजारिश है कि इन चीजों को पूरा किया जाये क्योंकि बाकी चीजें तो सबके लिए होंगी ही। बिजली, पानी, नालियों का जहां तक संबंध है ये बातें तो पूरी होंगी ही। हमारे यमुनानगर की जो रोडज हैं उनको भी जल्दी से जल्दी ठीक करवाने का प्रबन्ध किया जाए क्योंकि वहां पर ऐक्सीडैंट्स रेट बहुत ज्यादा है जिसकी वजह से लोगों को काफी दिक्कतों का सामना करना पड़ता है। चेयरमैन सर, मुझे बोलने के लिए समय देने के लिए आपका बहुत-बहुत धन्यवाद।

श्री धर्मबीर गाबा (गुड़गांव) : चेयरमैन सर, धन्यवाद आपका कि आपने मुझे बोलने के लिये समय दिया। सर, मैं रस्म अदायगी के लिए नहीं खड़ा हुआ हूँ कि हम अच्छा कहें वो बुरा कहें या वो बुरा कहें तो हम अच्छा कहें। बजट तो डिस्कशन के लिए एक ऐसा आईटम होता है कि कौन सी मद में पैसा कम रखा गया है और हम उसके लिए सरकार से अपील करें कि वह इस मद में ज्यादा पैसा दे या फिर कौन सी सोसायटी की सैक्शन के लिये पैसा कम है और उसको ज्यादा किया जाए, यह देखना पड़ता है। चेयरमैन सर, अच्छा फाईनैंस मिनिस्टर वह होता है जो सैलरीज और पैंशन पर रेवेन्यू रिसीट का 35 से 40 परसैंट तक खर्च करे और सबसे ज्यादा खुशी की बात यह है कि हमारे फाईनैंस मिनिस्टर साहब ने पैंशन और सैलरीज पर करीब 39.47 परसैंट ही खर्च किया है। चेयरमैन साहब, जादू तो वही है जो लोगों के सिर चढ़कर बोले। इस बजट की मीडिया ने बहुत तारीफ की है। मैंने 18 तारीख का ट्रिब्यून अखबार का ऐडीटोरियल पढ़ा है। उसमें लिखा है कि अगर लायबिलिटीज रिड्यूस कर दी जाएं तो हमें उसके इंट्रस्ट पर बहुत बड़ी बचत हो जाएगी। इसके अलावा इस बजट में जो सबसे अच्छी बात हुई है वह यह है कि फाईनैंस मिनिस्टर साहब ने फिसकल रिसपोंसिबिलिटीज और बजट मैनेजमैंट के लिये जो फैसले लिए हैं वह बहुत ही अच्छे हैं। चेयरमैन सर, इसमें एक फैसला यह भी हुआ है कि सरकार ने हैड ऑफ दि डिपार्टमैंट को पावर डैलीगेट की हैं कि प्लानिंग का पैसा बजाए उसकी मंजूरी ऊपर से आए, वह निचले लैवल पर ही खर्च कर दिया जाए। मंत्री जी इस समय सदन में

[श्री धर्मबीर गाबा]

बैठे नहीं हैं। मैं उनको कहना चाहता हूँ कि इस तरह की मंजूरी के न आने के कारण ही पूरा एक साल हो गया लेकिन गुड़गांव के अंदर एक इंच न तो सीवर की लाईन पड़ी और न ही पानी की लाईन पड़ी है क्योंकि पैसे की सैंक्शन ही नहीं आती है। गुड़गांव जैसे शहर के अंदर जिस की बारह लाख की आबादी है और जहां पर आठ लाख की फ्लोटिंग आबादी है अगर वहां पर इम्प्रूवमैन्ट का, डिवैल्पमैंट का काम न हो तो आप अंदाजा लगा सकते हैं कि हमारी क्या हालत होगी, लोगों की क्या हालत होगी क्योंकि हम अपने आपको वहां का नुमाईन्दा कहते हैं, हम वहां को रिप्रजेन्ट करते हैं। इसके अलावा डैट्स को स्वीपिंग करने का भी अच्छा डिसीजन है। 28 लाख 46 हजार रुपये के डैटस कम करने के या खत्म करने के कुछ कदम सरकार ने उठाए हैं कि हुडा या एच०एस०आई०डी०सी० के असैटस रखे जाएं ताकि हम दिए जाने वाले इंट्रस्ट से बच सकें। चेयरमैन सर, मैं एक बात और कहना चाहता हूँ। मैं आदरणीय चीफ मिनिस्टर साहब को तीन चार बातों के लिए मुबारिकबाद देना चाहता हूँ। सबसे पहले मैं यह कहना चाहता हूँ कि जो एक्साइज पोलिसी सरकार ने एडाप्ट की है वह ऐसी पालिसी है जिससे आम लोगों को कुछ रोजगार भी मिल जाएगा और जो बदनामी पहले हुआ करती थी कि एक ही आदमी को सारे ठेके दे दिये तो उस बदनामी से भी हरियाणा सरकार अब बच जाएगी। सबसे बड़ी बात सी०एम० साहब मैं आपको कहना चाहता हूँ वह यह है कि आपने जो पानीपत थर्मल प्लांट का नाम बदलने का डिसीजन लिया है वह एक बहुत अच्छा डिसीजन है। मैं किसी की मुखालफत नहीं करता लेकिन पानीपत एक हिस्टोरीकल सिटी है और उसका हिस्टोरीकल नाम ही रहना चाहिए। इससे पहले भी ऐसी गलती सरकार ने एक बार की थी कि कुरुक्षेत्र यूनिवर्सिटी का नाम बदलकर बी०एन० चक्रवर्ती यूनिवर्सिटी रख दिया था लेकिन जब प्रदेश में इसके खिलाफ एजीटेशन हुए तो उसका नाम फिर से कुरुक्षेत्र यूनिवर्सिटी रखना पड़ा था। आपने जो पानीपत शहर को उसका हिस्टोरीकल स्टेटस दिया है वह बहुत अच्छा किया है। हमें किसी शहर का हिस्टोरीकल नाम नहीं बिगाड़ना चाहिए चाहे पानीपत हो और चाहे कुरुक्षेत्र हो। एक बात सी०एम० साहब मैं आपको और कहना चाहता हूँ चाहे आप मुझे अपना मानें या न मानें लेकिन मुझे इस बात की खुशी है कि आपकी नीयत बड़ी अच्छी है। आज प्रदेश में चारों तरफ कुछ न कुछ डिवैल्पमैंट होती ही रहती है। आज गुड़गांव में इतनी डिवैल्पमैंट हो रही है कि मैं उसका यहां पर विवरण नहीं कर सकता। चेयरमैन साहब, मैं रोडज के बारे में जरूर कहना चाहूँगा। रोडज बहुत इन्क्रीज किए गये हैं और इनके लिये पैसा भी बेइन्तहा रखा गया है। आज यह भी फैसला लिया गया है कि दिल्ली से रोहतक तक चार लेन का रोड बनाया जाएगा और जीरकपुर से कालका तक की रोड भी चार लेन का रोड बनाया जाएगा। मुझे यह सुनकर सबसे बड़ी खुशी हुई क्योंकि इसके लिए हम 40 साल से देखते आ रहे हैं कि यह रोड नहीं बन सका। मैं वर्ष 1982 में पहली बार एम०एल०ए० चुनकर आया था और 24 साल से हम इस बारे में कहते रहे लेकिन किसी के कान तक हमारी आवाज नहीं पहुंची। पानीपत शहर के रोडज के लिए कुछ किया जाए क्योंकि पानीपत शहर को क्रोस करने में एक घण्टा लग जाता है। लेकिन आज पानीपत शहर में भी रोडज का काम शुरू हो गया है इसके लिए मैं सी०एम० साहब को मुबारकबाद देता हूँ।

श्री सभापति : गाबा साहब, यह सारा कुछ अच्छी नीयत की बदौलत ही है।

श्री धर्मबीर गाबा : चेयरपर्सन महोदय, मेरी सी०एम० साहब से एक प्रार्थना है कि आप जो ये रोडज बनाने जा रहे हैं इन रोडज की रिकारपेटिंग करने के साथ ही साथ इनको चौड़ा करने की भी जरूरत है तभी सही तरीके से रोडज बन पाएंगी।

श्री सभापति : गाबा साहब, आपको बोलते हुए सात मिनट हो गए हैं।

श्री धर्मबीर गाबा : चेयरपर्सन महोदय, एक बात मैं यहां जरूर बताना चाहता हूँ कि पिछले महीने मुझे सिंगापुर से कुआलालामपुर बाई रोड जाने का मौका मिला था। यह 400 किलोमीटर का रास्ता था जो मैंने चार घण्टे में पार किया। सरकार को चाहिए कि वहां पर एफ०एम० को या पी०डब्ल्यू०डी मिनिस्टर साहब को भेजें और पता लगाएं कि रोडज कैसे बनते हैं और कैसे होने चाहिएं। मैंने बजट भाषण में पढ़ा कि सरकार बी०ओ०टी० के लिए कुछ कर रही है। अमेरिका हमारे से काफी अमीर है जब वह बी०ओ०टी० के आधार पर काम कर सकता है तो हम हिंदुस्तान में क्यों नहीं कर सकते? सरकार का यह फैसला बहुत अच्छा है।

श्री सभापति : गाबा साहब, आपका एक मिनट और है।

श्री धर्मबीर गाबा : चेयरपर्सन महोदय, मैंने तो आपको नहीं कहा कि मुझे बुलवाया जाए। आप कहते हैं तो मैं बैठ जाता हूँ मैं तो तीन दिन से इन्तजार कर रहा था।

श्री सभापति : गाबा साहब, और भी सदस्य काफी बोलने वाले हैं। सदन के केवल 12 मिनट समय खत्म होने में रहता है।

श्री धर्मबीर गाबा : चेयरपर्सन महोदय, मेरी सरकार से एक प्रार्थना है। सोशल वैल्फेयर के लिए सरकार ने बजट में 47.54 प्रतिशत की बढ़ौतरी की है। इस बारे में हैल्थ मिनिस्टर महोदया काम करेंगी या अर्बन डिवैल्पमैंट मिनिस्टर महोदया काम करेंगी यह मैं नहीं जानता लेकिन मैं उनसे एक बात कहना चाहता हूँ कि क्या आप शहरों में हैल्थ के बारे में भी कुछ करने जा रहे हैं? आज शहरों के अन्दर जो मीट मार्कैट है क्या उनके लिए आपने सीरियसली सोचा है? आज गुड़गांव में यह हालत है कि कोई सलाटर हाउस नहीं है। मीट बेचने वाले दुकानदार खुले में बैठकर मीट बेचते हैं। मैं तो मीट खाता नहीं हूँ और आप खाते हैं या नहीं, यह मुझे नहीं पता लेकिन वे दुकानदार आज लोगों को जहर बेच रहे हैं क्योंकि खुले में मिट्टी आती है मक्खियां आती हैं। वे लोग खुले में बैठकर मीट बेच रहे हैं और ऐसी एक जगह नहीं 15-20 जगह हैं जहां पर ये कार्यवाही हो रही है। जब मैं मिनिस्टर था उस समय हमने उनके लिए सरकार से एक एकड़ जमीन के लिए प्रार्थना की थी कि मिनी सचिवालय के पीछे की तरफ इसके जमीन दे दी जाए ताकि वहां पर जाली लगाकर सलाटर हाउस बना दिए जाएं। इन दुकानदारों को मीट बेचने का लाईसैंस दे दिया जाए। मेरी सरकार से अब प्रार्थना है कि इसको सीरियसली सोचें क्योंकि यह मामला केवल गुड़गांव का ही नहीं है बल्कि हर शहर में ऐसी समस्याएं हैं।

श्री सभापति : गाबा साहब, आपका बोलने का समय समाप्त हो गया है। प्लीज, आप बैठें।

मुख्यमंत्री (श्री भूपेन्द्र सिंह हुड्डा) : सभापति महोदय, मेरा प्वाइंट ऑफ आर्डर है। मेरे साथी ने अभी अपना मानूं या न मानूं वाली बात कही। मैं बताना चाहूँगा कि ये तो मेरी कांग्रेस पार्टी के सदस्य हैं, ये तो हैं ही मेरे अपने, मैं तो विपक्ष के साथियों को भी अपना मानता हूँ। (विघ्न)

श्री सभापति : मैम्बर्ज साहेबान, जिस फिराखदिली से अब विधान सभा की कार्यवाही चल रही है इस तरह पहले कभी नहीं चली।

श्री धर्मबीर गाबा : सभापति महोदय, मैं स्वास्थ्यमंत्री से अर्ज करना चाहता हूँ कि आपने गुड़गांव के हस्पताल को अपग्रेड कर दिया लेकिन वहां अपग्रेड करने के बावजूद भी न एम०आर०आई० की सुविधा दी है, न कोई दूसरी सुविधाएं दी हैं। (इस समय **श्री अध्यक्ष महोदय पदासीन हुए।**)

[श्री धर्मबीर गाबा]

अध्यक्ष महोदय, अगर होस्पिटल अपग्रेड कर दें और वहां कोई सुविधा न दें तो काम कैसे चलेगा। पंचकूला होस्पिटल के लिए एक एम०आर०आई० मशीन खरीदने के लिए सरकार ने मंजूरी दे दी है।

श्री अध्यक्ष : गाबा साहब, अब आप बैठें। आप लिखकर भिजवा देना। We will incorporate your suggestions.

श्री महेन्द्र प्रताप सिंह (मेवला महाराजपुर) : अध्यक्ष महोदय, दो दिन से बजट पर चर्चा चल रही है और हमारी सरकार बनने के बाद यह दूसरा बजट है। बजट पर बोलते हुए खासतौर पर बीजेपी के मैंबर गौतम जी जो इस समय यहां नही बैठे, वे विपक्ष में हैं लेकिन उन्होंने भी सरकार की और बजट की सराहना की है। वे पाँच बार हारने के बाद छठी बार बड़ी मेहनत से चुनकर आए हैं। लेकिन उन्होंने कहा है कि हमारे मुख्यमंत्री बड़े फिराखदिल हैं जिन्होंने कभी भी किसी के साथ भेदभाव नहीं रखा। इससे बड़ा सबूत अच्छे बजट का दूसरा कोई नहीं हो सकता कि विपक्ष के साथी भी बजट की और सरकार की तारीफ करें। अध्यक्ष महोदय, अगर सरकार के पिछले एक वर्ष के कार्यकाल पर बजट के माध्यम से गहन चिंतन करें तो जो किसान कभी भ्रम की स्थिति में बहकावे में पड़ गए थे और आर्थिक अव्यवस्था के कारण सामाजिक परिदृश्य से बाहर हो गये और जो अपने बिजली के बिल नहीं भर सकते थे, उन किसानों के 1600 करोड़ रुपये के बिजली के बिल एक कलम से माफ करना मैं समझता हूँ कि एक बहुत बड़ा काम है। अध्यक्ष महोदय, 1600 करोड़ रुपये की माफी ही नहीं बल्कि हर क्षेत्र में पिछले एक वर्ष के दौरान मुख्यमंत्री जी ने और सरकार ने जितनी उपलब्धियां हासिल की हैं उनका यदि यहां वर्णन किया जाए तो बहुत समय लगेगा। चाहे सरकार द्वारा भूमि अधिग्रहण का मामला हो। पहले किसान हाईकोर्ट और सुप्रीम कोर्ट तक धक्के खाया करते थे लेकिन उनको उचित मुआवजा उनकी जमीन एक्वायर होने पर नहीं मिलता था। हमारे मुख्यमंत्री जी ने जन भावनाओं को समझते हुए मुआवजे की वास्तविकता को देखते हुए ऐसा फैसला लिया जिसके तहत 15 लाख, 12.50 लाख और 5 लाख रुपये मिनिमम मुआवजा प्रति एकड़ के हिसाब से दूर-दराज के एरियाज के लिए फ्लोर रेट फिक्स किया है। सरकार का यह एक बहुत अच्छा निर्णय है इसके लिए मैं मुख्यमंत्री जी को बधाई देता हूँ। लेकिन मैं मुख्यमंत्री जी से प्रार्थना करना चाहता हूं कि गुड़गांव को तो 15 लाख प्रति एकड़ तक के मुआवजे क्षेत्र में रखा है लेकिन फरीदाबाद को उसमें नहीं रखा जबकि फरीदाबाद और गुड़गांव की स्थिति एक जैसी है। आज फरीदाबाद में भी जमीन के रेट्स प्रति एकड़ एक करोड़ रुपये से ज्यादा हैं और अगर वह जमीन साढ़े 12 लाख रुपये प्रति एकड़ में एक्वायर होती है तो मैं समझता हूँ कि वहां के किसान के लिए यह काफी घाटे का सौदा होगा। इसके साथ ही एक बात मैं और कहना चाहता हूं। मैंने भूमि अधिग्रहण के बारे में सवाल भी किए थे और उनके जवाब भी माननीय मंत्री जी ने दिये हैं। जो सैक्टर अब नये आ रहे हैं उनके बारे में मैं विशेष तौर से कहना चाहूँगा कि पिछले समय में किसान के लिए एक पॉलिसी हुआ करती थी कि जिस किसान की जमीन ऐक्वायर की जाएगी उसको एक प्लॉट हर हालत में सरकारी रेट पर उसी सैक्टर में दिया जाएगा, चाहे वह रैजिडैंशियल प्लाट ही हो। अगर इस समय ऐसी पॉलिसी नहीं है तो मैं यह निवेदन करूँगा कि इस पॉलिसी को जोड़ना चाहिए। यह बात मैं इसलिये कह रहा हूँ कि यह ठीक है कि जमीन की कीमत आज बहुत बढ़ गई है। वहां पर किसान को जो न्यूनतम रेट मुआवजे के फिक्स किए गए हैं यह कीमत उसकी वजह से बढ़ी है। दूसरे प्राईवेट कॉलोनाईजर्ज को रैजीडैंशियल समस्या के समाधान के लिए लाईसैंस का जो सरलीकरण किया गया है और उनको लाईसैंस दिया गया है उस की वजह से भी कीमतें बढ़ी हैं। वहां पर एक करोड़ की बजाए अगर जमीन ऐक्वायर करने का मुआवजा 20 लाख या 15 लाख रुपये प्रति एकड़ मिलता है तो वह

बहुत थोड़ा है इसके कारण उनके अन्दर हार्ट बर्निंग बढ़ेगी इसलिए भी हर खातेदार को अगर वे लेना चाहे तो एक प्लॉट मैं समझता हूँ कि अवश्य देना चाहिए। अध्यक्ष महोदय, बजट के बारे में माननीय डॉक्टर साहब ने कई चीजों पर शंका और खदशा का जिक्र किया है। इसके बारे में वैसे तो जवाब माननीय मंत्री महोदय देंगे लेकिन अध्यक्ष महोदय, उन्होंने एक बात कही है मैं उसका जवाब उनको देना चाहता हूँ। उन्होंने कहा है कि उनकी सरकार के बेहतरीन प्रबन्धन के कारण बजट जो अब 43-44% तक बढ़ा है वह उसका नतीजा ही था। उसके लिए मैं माननीय साथी को कहना चाहूँगा कि आपके जो पिछले बजट थे वह 2200 करोड़ से लेकर ऐण्ड में 2000 पर टिक गए थे। बजट में वह घाटा बढ़ा ही नहीं। उसी बजट को माननीय मंत्री महोदय ने तीन हजार करोड़ रुपये तक पहुँचाया है। यानि एक हजार करोड़ रुपये की बढ़ौतरी बजट में हुई जो कि तकरीबन 50% का इजाफा दर्शाती है वह उस प्रबन्धन की वजह से नहीं हुआ है बल्कि इस सरकार की पॉलिसीज की वजह से हुआ है जो कि इस सरकार की दूरदर्शिता और उसकी काबलियत का भी एक सुबूत है। अगर दोनों बजटों को देखा जाए तो 8-9% के इजाफे को मेनटेन किया गया है जोकि बहुत बड़ी उपलब्धि है। (विघ्न)

श्री अध्यक्ष : चौधरी साहब, आप थोड़ा टाईम को भी देख लें। आपको बोलते हुए ऑलरेडी 7 मिनट हो चुके हैं (विघ्न) आप इस बात को देखें कि सभी के लिए टाईम फिक्स किया हुआ है। आप तीन चार मिन्ट का समय और ले लें और अपनी बात को कन्क्ल्यूड करें।

श्री महेन्द्र प्रताप सिंह : अध्यक्ष महोदय, आपका धन्यवाद। हरियाणा की आय और हरियाणा का सकल उत्पादन 12% और 11% है। मैं समझता हूँ कि ऑल इण्डिया से अगर इसकी तुलना करें तो हरियाणा की आय कहीं ज्यादा है और दोनों चीजों में इजाफा है जो समृद्धि और विकास का सूचक है अध्यक्ष महोदय, इसमें कोई दो राय नहीं कि इस बजट को अगर प्रोग्रैसिव बजट कहा जाए तो उसमें कोई अतिश्योक्ति नहीं होगी। यह बजट का एक पापुलर और पापुलर गवर्नमैंट का एक प्रोग्रैसिव बजट है। अध्यक्ष महोदय, 4-5 बातों का मैं और जिक्र करना चाहूँगा। मैंने उनके बारे में सवाल किए थे मैं उनके नजदीक आ जाऊं क्योंकि मेरे पास बोलने के लिये समय भी थोड़ा है। अध्यक्ष महोदय, मैं परिवहन विभाग के विषय में थोड़ा कहना चाहता हूँ। हरियाणा का परिवहन विभाग का बेड़ा देश का बहुत ही श्रेष्ठ बेड़ा माना जाता है। इस बेड़े में तकरीबन 3500 बसें हैं। अध्यक्ष महोदय, मैंने फरीदाबाद, सैक्टर-12 में बस अड्डे का एक सवाल किया था। फरीदाबाद जिला हैडक्वार्टर है, वहां पर खेल परिसर बना हुआ है, मिनी सैक्रेटेरियेट भी वहां पर बन गया है, अदालतें भी वहां पर हैं, सारा सैक्टर आबाद है और मेन रोड के ऊपर है। इन दोनों क्षेत्रों में और विशेषकर मेरे क्षेत्र की आबादी तकरीबन 6-7 लाख के करीब है। वहां पर पहले बस अड्डा बनाने का प्रोविजन था। इन सब चीजों के बावजूद जहां आप इतने सुधार कर रहे हैं रैन बसेरे बना रहे हैं उनकी डिवैल्पमैंट कर रहे हैं, उनकी रैनोवेशन कर रहे हैं, वहां पर एक बस अड्डे की भी निहायत आवश्यकता है। माननीय मंत्री जी बैठे हुए हैं मैं उनसे आग्रह करना चाहूँगा कि वहां पर बस अड्डा बनाया जाने के बारे में जरूर विचार करें और जब वे जवाब दें तो मेहरबानी करके इसके बारे में अपने जवाब में बताएं। यदि वे इसके लिए 'हां' कर रहे हैं तो इस बजट में उसको डालने की कृपा करें। (विघ्न) अध्यक्ष महोदय, मैं सिंचाई के बारे में थोड़ी और बात कह दूं। इस बारे में मैं माननीय सिंचाई मंत्री जी से एक बात कहना चाहूँगा। सिंचाई विभाग के बारे में कोई दो राय नहीं है कि माननीय मुख्यमंत्री जी और सरकार ने यह पहल करके प्रदेश में समान जल का बंटवारा किया है। इस बारे में आज तक किसी ने नहीं सोचा था। इसमें कोई दो राय नहीं है कि जल का एक समान बंटवारा करके सरकार ने जनता को बहुत बड़ा न्याय दिया है जिसके लिए यह सरकार बधाई की पात्र है। इसके लिए तकरीबन एक हजार करोड़ रुपये की व्यवस्था की गई है।

[श्री महेन्द्र प्रताप सिंह]

मैं समझता हूँ कि किसान के लिए खेती एक रीढ़ है। जब तक बिजली और सिंचाई को प्राथमिकता नहीं दी जाएगी तब तक हम वह लक्ष्य नहीं प्राप्त कर सकते लेकिन इसके लिए सरकार ने बजट देकर के कई योजनाओं को शुरू किया है। दादूपुर नलवी जैसी नहर से रिचार्जिंग के अलावा उन क्षेत्रों को पानी भी मिलेगा। इसके लिए मैं कहना चाहता हूँ कि जहां आप समान जल बंटवारे की बात कर रहे हैं वहीं हमारे क्षेत्र को भी तरजीह दी जाए। 1994 में स्टेट्स का जो समझौता हुआ है उसमें हरियाणा का 43% पानी फरीदाबाद और मेवात को जाता है हमें वहां से तकरीबन 608 क्यूसिक पानी मिलना चाहिये था और दिल्ली को 238 क्यूसिक पानी मिलना चाहिये था। अध्यक्ष महोदय, लेकिन आज उल्टा हो रहा है। हमें सुप्रीम कोर्ट के फैसले के कारण दिल्ली को पानी देना जरूरी हो गया है।

12-00 बजे

श्री अध्यक्ष : महेन्द्र जी, आपका बहुत-बहुत धन्यवाद। अब आप अपनी सीट पर बैठ जाएँ।

श्री महेन्द्र प्रताप सिंह : अध्यक्ष महोदय, मैं एक मिनट और बोलना चाहूँगा। फरीदाबाद की नहरों में जाड़े के महीने में एक बूंद पानी भी नहीं गया है।

श्री अध्यक्ष : आप एप्रोप्रिएशन बिल पर बोल लेना। आप मेरे साथ कोआप्रेट करें। बाकी सदस्यों ने भी बोलना है।

श्री महेन्द्र प्रताप सिंह : सर, मैं एक मिनट में ही अपनी बात को कन्क्लयूड कर देता हूँ। अध्यक्ष महोदय, मैं मंत्री जी से निवेदन करूँगा कि पानी के समान बंटवारे की जहां तक बात है, अगर उत्तर प्रदेश को ताजेवाला से या मूनक से पानी दे दिया जाए तो वे ओखला बैराज से हमें पानी देने को तैयार हैं। इसके साथ ही मैं मेवात के बारे में भी बात कहना चाहूँगा। हमें छोटे-छोटे कामों को भी बढ़ावा देना चाहिए। अध्यक्ष महोदय, दादूपुर नलवी और इसके आस-पास के एरियाज में ऐसा प्रावधान सरकार को करना चाहिए कि रिचार्जिंग पानी के अलावा वे एरियाज बरसाती पानी का भी इस्तेमाल कर सकें। अध्यक्ष महोदय, मेवात में 650-700 गाँव हैं। वहां पर 50 गाँवों में तो पीने का अच्छा पानी है बाकी गाँवों में कड़वा पानी है। वहां पर या तो छोटे बाँध बनाए जाएं या नहरों के माध्यम से उन एरियाज को सिंचित करने का प्रावधान सरकार द्वारा किया जाए।

श्री अध्यक्ष : चौधरी साहब, बाकी की बातें आप लिखकर मंत्री जी को भिजवा देना। अब आप बैठें। अब बलवंत सिंह सढौरा जी बोलेंगे। सढौरा जी, आपकी पार्टी का समय 12 मिनट रह गया था और आपके साथी सीता राम जी उससे ज्यादा बोल चुके हैं। इस हिसाब से तो आपका समय भी खत्म हो चुका है फिर भी आप पाँच मिनट में अपनी बात कह दें।

श्री बलवंत सिंह (सढौरा एस०सी०) : स्पीकर सर, मैं आपका धन्यवाद करता हूँ कि आपने मुझे बजट पर बोलने का समय दिया। सर, वैसे तो हर साल बजट पेश होते हैं और यह बजट सरकार का आईना होता है इसमें सरकार का लेखा जोखा होता है और उससे सरकार की मंशा का पता चलता है कि उसकी मंशा कैसी है। अध्यक्ष महोदय, इस बजट में किसानों के लिए, कर्मचारियों के लिए और व्यापारियों के लिए कुछ भी नहीं है। (विघ्न) स्पीकर सर, इसमें आंकड़ों को देख कर ऐसा नहीं लगता है कि इस सरकार ने कोई बहुत बड़ी रियायत दी है। अध्यक्ष महोदय, चाहे वह प्लान का हैड हो या नॉन प्लान का हैड हो, चाहे हर साल बढ़ने वाला घाटा है, चाहे वह स्टेट रेवन्यू में टैक्स को कलैक्शन है, वह निरन्तर घटती जा रही है और घाटा बढ़ता ही जा रहा है। अध्यक्ष महोदय, जो प्वाइंट में दर्ज हैं अगर मैं उसके बारे में आंकड़े पढ़ने लगा तो बहुत समय लग जाएगा। (विघ्न)

श्री अध्यक्ष : बलवंत सिंह जी, वह सब तो डॉक्टर साहब बोल चुके हैं। आप कोई भी ऐसी बात न कहें जो पहले ही कही जा चुकी हो।

श्री बलवंत सिंह : सर, मैं भी तो यही कह रहा हूँ। अध्यक्ष महोदय, आज हरियाणा में हालात ऐसे बन गए हैं कि हरियाणा की अर्थव्यवस्था लगातार चरमराने की ओर बढ़ रही है। आज प्रदेश की उन्नति और तरक्की कहां जा रही है, इस बारे में स्टेट के बजट का जो इन्फ्रास्ट्रक्चर है उससे पता चलता है। आज इलैक्ट्रिसिटी, रोडज, एजुकेशन, सोशल वैल्फेयर को ले लें तो इनके लिए बजट में पैसे का कोई प्रावधान नहीं है। अध्यक्ष महोदय, मैं बिजली के बारे में कहना चाहता हूँ। मुख्यमंत्री जी अपनी हर रैली की अनाऊंसमैंट में कहते हैं कि बिजली की कमी है। सर, बिजली की वाकई में स्टेट में कमी है। इसके बारे में इन्होंने कहा है कि तीन साल में यह कमी पूरी कर देंगे। स्पीकर सर, एक साल तो गुजर गया इसलिए हमें बताया जाए कि ये तीन साल कब से शुरू होंगे? मैं वित्त मंत्री जी से यह जानना चाहता हूँ क्योंकि हमारे वित्त मंत्री जी बड़े काबिल वजीर हैं और उन्होंने अपने बजट भाषण में यह कहा है कि 11वीं पंचवर्षीय योजना जोकि 2007 से शुरू होगी और 2012 में खत्म होगी, में गैस बेस्ड चार पावर प्रोजैक्टस लगाएंगे। स्पीकर सर, 2012 में कौन घोड़ा होगा और कौन सवार होगा इसका तो जनता ही फैसला करेगी, यह हमारे कहने की बात नहीं है कि 2012 में राज किसका होगा, कौन राजा होगा, यह तो समय ही बताएगा, क्योंकि यह जनता के हाथ में है।

श्री अध्यक्ष : चौधरी साहब, कर्म करो और रिजल्ट की परवाह मत करो।

श्री बलवंत सिंह : ठीक है सर, अब मैं एजुकेशन के बारे में कहना चाहूँगा। इस बारे में बुलंगबांग दावे करते हुए कहा गया था कि राजीव गांधी के नाम से एक एजुकेशन सिटी बनेगा और उसमें हमारे बच्चे पढ़कर काबिल बनेंगे, अफसर बनेंगे लेकिन न तो पिछले साल के बजट में और न ही इस साल के बजट में इसके लिए पैसे का प्रावधान किया गया है।

श्री अध्यक्ष : चौधरी साहब, राजीव गांधी सिटी का प्वायंट तो पहले आ चुका है आप रिपीट न करें।

श्री बलवंत सिंह : स्पीकर सर, वीमैन यूनिवर्सिटी बनाने की बात भी कही गई थी लेकिन इसके लिए भी बजट में पैसे का प्रावधान नहीं किया गया। इसी तरह से नैशनल लॉ कालेज बनाने की बात भी थी लेकिन उसके लिए भी बजट में पैसे का कोई प्रावधान नहीं किया गया है। इसी तरह से एस०सीज० के लिए भी जिनकी रेशों करीब 25 परसैंट से ऊपर है, बजट में ज्यादा पैसों का प्रावधान नहीं किया गया है। इनके लिए पैसा बजट में घटता जा रहा है जोकि एक चिन्ता का विषय है। स्पीकर सर, बजट में ऐसा कोई भी प्रावधान नहीं किया गया है जिससे हमें खुशी हो। इसी तरह से लॉ एंड ऑर्डर के बारे में भी बड़े बुलंगबांग दावे किए गए कि हरियाणा में लॉ एण्ड ऑर्डर ठीक है और यहां पर कोई भी मर्डर नहीं हो रहे हैं, कोई डैकेती नहीं हो रही हैं और न कोई लूटपाट हो रही है। लेकिन आज सरेआम दिन में ही डैकेतियाँ हो रही हैं, कत्ल हो रहे हैं। एक साल का चिट्ठा है कि कितने मर्डर इस एक साल में हुए हैं। इनका कोई रिकार्ड ही नहीं है। (विघ्न) स्पीकर सर, करनाल में 16 तारीख को 24 घंटे के अंदर-अंदर 12 मर्डर हुए हैं जोकि चिन्ता का विषय है। (विघ्न)

चौ० अर्जुन सिंह : आन ए प्वायंट ऑफ आर्डर सर। अध्यक्ष महोदय, पिछली सरकार के समय में कानून व्यवस्था के बारे में मैं बताना चाहूंगा कि अगर उस समय चोरी हो गयी या किसी का ट्रक उठ गया तो फिर भी उसकी एफ०आई०आर० दर्ज नहीं होती थी। थानों में एस०एच०ओ०, थानेदार या एस०पी० को सख्त आर्डर सरकार ने दे रखे थे कि कोई भी एफ०आई०आर० दर्ज नहीं

[चौ० अर्जन सिंह]

करनी ताकि हम अपनी सरकार का ऐसा रिकार्ड न बनाये जिससे पता लगे कि हमारे समय में क्राईम हुए हों। (विघ्न) स्पीकर सर, उस समय ट्रक चोरी हो गया लेकिन एक महीने तक उसकी एफ०आई०आर० तक दर्ज नहीं हुई। जब हमने इस बारे में कहा कि भई आप एफ०आई०आर० तक दर्ज क्यों नहीं करते। यह एफ०आई०आर० तो दर्ज कर लो ट्रक पावे या न पावे क्योंकि अगर ट्रक से ऐक्सीडैंट वगैरा हो गया तो उस पर जुर्माना तो नहीं लगेगा। तब पुलिस वालों ने कहा कि सरकार के ऊपर से आदेश हैं कि कोई भी एफ०आई०आर० दर्ज नहीं करनी, चाहे कत्ल हो जाए, चाहे कोई मर जाए या कोई उजड़ जाए क्योंकि हमने तो अपना चिट्ठा साफ रखना है। स्पीकर साहब, क्या यह कोई उनका तरीका ठीक था?

श्री अध्यक्ष : चौधरी बलवंत सिंह जी, लॉ एण्ड आर्डर का प्वायंट तो डिटेल में आ लिया है। आपने चार प्वायंट उठाये हैं और वे चारों प्वायंटस ही रिपीटिशन हो रहे हैं। अगर आपने कोई नयी बात कहनी हो तो कह लें वरना तो आपका टाईम हो लिया है।

श्री बलवंत सिंह : सर, आप मुझे पाँच मिनट और दे दें। पाँच मिनट में मैं अपनी बात खत्म कर लूँगा। सर, हम रोज बोल्कर मुद्दे के बारे में बात कर रहे हैं। पार्लियामैंट्री अफेयर्ज मिनिस्टर साहब की हम बात नहीं सुन रहे हैं क्योंकि हमारी बात मनगढ़ंत नहीं है। * * * *

श्री अध्यक्ष : चौधरी साहब, जो आदमी हाउस में प्रेजैंट नहीं है उनका नाम न लिया जाये।

मुख्यमंत्री (श्री भूपेन्द्र सिंह हुड्डा) : अध्यक्ष महोदय, जो इस सदन का सदस्य नहीं है उनका नाम हाउस की प्रोसीडिंग्स में से डिलीट किया जाये।

श्री अध्यक्ष : ठीक है Nothing to be recorded.

श्री बलवंत सिंह : अध्यक्ष महोदय, * * * * * * *

डॉ० सुशील इन्दौरा : अध्यक्ष महोदय, * * * * * *

Mr. Speaker : Nothing to be recorded. ओरियण्टेशन प्रोग्राम में इस बारे में बताया गया था।

श्री बलवंत सिंह : अध्यक्ष महोदय, * * * * * * *

श्री भूपेन्द्र सिंह हुड्डा : अध्यक्ष महोदय, इस बात से सदन का कोई संबंध नहीं है। सदन का केवल एक बात से संबंध है कि श्री ओम प्रकाश चौटाला के खिलाफ सी०बी०आई० की इन्क्वायरी चल रही है ये उस बारे में चर्चा क्यों नहीं करते? सी०बी०आई० ने सुप्रीम कोर्ट के आदेश से चौटाला साहब के मकानों में कई जगह पर रेड की है उसके बारे में ये चर्चा करें।

कैप्टन अजय सिंह यादव : अध्यक्ष महोदय, इनका नेता तो विदेश भाग गया।

श्री बलवंत सिंह : अध्यक्ष महोदय, * * * * * * *

Mr. Speaker : Reading of any document is not allowed in the House. Please sit down.

श्री बलवंत सिंह : अध्यक्ष महोदय, * * * * * * (विघ्न)

---

* चेयर के आदेशानुसार रिकॉर्ड नहीं किया गया।

कैप्टन अजय सिंह यादव : अध्यक्ष महोदय, मेरा प्वायंट ऑफ ऑर्डर यह है (विघ्न)

श्री अध्यक्ष : कैप्टन साहब, आपका प्वायंट ऑफ आर्डर क्या है ?

राजस्व मंत्री (कैप्टन अजय सिंह यादव) : अध्यक्ष महोदय, मेरा प्वायंट ऑफ ऑर्डर यह है कि इनको रणदीप सिंह सुरजेवाला से कोई दिक्कत नहीं है कि उन्होंने चौटाला साहब को चुनाव में हरा दिया। इनको तो इस बात की तकलीफ हो रही है कि हमारा नेता हार क्यों गया ? वे अब विदेश भाग गये हैं ये उसको बुलाकर लायें। वह हारने के बाद यहां मुंह दिखाने लायक नहीं रहा। अपने नेता को सदन में लाकर बिठाएं ताकि उसको पता लगे। वह अपने सारे पैसे लेकर विदेश चला गया (विघ्न) (इस समय बहुत से इनैलो के सदस्य एक साथ खड़े होकर बोलने लग गये।)

डॉ० सुशील इन्दौरा : अध्यक्ष महोदय, ******

डॉ० सीता राम : अध्यक्ष महोदय, ****

प्रो० छतर पाल सिंह : स्पीकर सर, मेरा प्वायंट ऑफ ऑर्डर है। कैप्टन अजय सिंह ने एक बात कही है।

श्री अध्यक्ष : प्रोफैसर साहब, यह कोई प्वायंट ऑफ ऑर्डर नहीं है।

डॉ० सुशील इन्दौरा : अध्यक्ष महोदय, *****

श्री अध्यक्ष : इन्दौरा साहब आप सीजन्ड पार्लियामैंटेरियन हैं आप यह बात अच्छी तरह से जानते हैं कि जो आदमी इस हाउस में हाजिर नहीं है उसका नाम नहीं लिया जा सकता The discussion on the budget has been concluded. Now, the Revenue Minister will give the reply to the points raised pertaining to his Department, during the discussion on Budget. (Interruption)

श्री तेजेन्द्र पाल सिंह मान : स्पीकर सर, मैंने तो सरकार को कुछ सुझाव देने थे।

श्री अध्यक्ष : मान साहब, आप डिमाण्डज पर या एप्रोप्रिएशन बिल पर बोल लेना आपको समय दिया जायेगा। I will allow you.

श्री तेजेन्द्र पाल सिंह मान : स्पीकर सर, जब मैं कल कैथल गया था तो श्री रणदीप सिंह सुरजेवाला साहब को कहकर गया था कि मैं कल बोलूंगा।

Mr. Speaker : Mann Sahib, the revenue Minister is on his legs. He will give the reply pertaining to his Department. मान साहब, आपकी पर्ची आज आई है। आप एप्रोप्रिएशन बिल पर बोल लेना।

कैप्टन अजय सिंह यादव : अध्यक्ष महोदय, कुछ माननीय सदस्यों ने बजट पर बोलते हुए कुछ प्वायंट रेज किए हैं मैं उनके बारे में बताना चाहता हूँ। एक तो श्री धर्मपाल सिंह मलिक जी ने भालौठ सब ब्रांच पर न्यू माइनर बनाने के बारे में कहा था। इस बारे में कोई प्रोपोजल तो सरकार के पास नहीं आया है लेकिन जो इन्होंने फरमाणा माईनर की कंस्ट्रक्शन के बारे में बात की है, वह प्रोपोजल सरकार के पास आलरेडी एग्जिस्ट करता है उसकी रिमोडलिंग की जरूरत है, उसको हम जरूर करवायेंगे। तीसरी बात इन्होंने रामगढ़ माईनर के बारे में रखी थी। इस बारे में लैंड नोटिफिकेशन

* चेयर के आदेशानुसार रिकॉर्ड नहीं किया गया।

[कैप्टन अजय सिंह यादव]

भी हमने कर दी है। मैं समझता हूँ कि इसके टैण्डर 24.3.2006 तक हो जायेंगे और काम जल्दी ही शुरू हो जायेगा। बत्तरा साहब ने regarding the surplus water of Yamuna बहुत अच्छा प्वाइंट रेज किया था कि कुछ डैम्ज बगैरा बनने चाहिएं। मैं सदन को बताना चाहता हूँ कि माननीय मुख्यमंत्री जी ने 1994 में यमुना के पानी के बारे में जो समझौता हुआ था, उसके तहत उन्होंने सैंट्रल वाटर रिसोर्सिज मिनिस्टर श्री सैफूद्दीन सोज जी के पास स्वयं जाकर बात की और कहा कि वे अपर यमुना बोर्ड की बैठक बुलाएं और किशाऊ लखवार ब्यासी और रेणुका डैम हैं, इनको बनाया जाना चाहिए। सुप्रीम कोर्ट के फैसले के बारे में महेन्द्र प्रताप सिंह जी भी अभी बात रेज कर रहे थे कि 381 क्यूसिक पानी केवल हमें दिल्ली को देना होता है लेकिन हमें 1000 क्यूसिक पानी देना पड़ रहा है। लेकिन किशाऊ डैम बनने के बाद मैं समझता हूँ कि हमें बहुत राहत मिल सकती है। श्री बीरेन्द्र सिंह जी ने भी यह ईशू पहले रेज किया था इसके बारे में सरकार पूर्ण रूप से गम्भीर है और इस पर हम कार्यवाही कर रहे हैं। अध्यक्ष महोदय, एस०वाई०एल० कैनाल के बारे में भी कई साथियों ने मुद्दा रेज किया है। इन्दौरा जी भी कह रहे थे कि हम एस०वाई०एल० कैनाल के बारे में सीरियस नहीं हैं। मैं इनको बताना चाहता हूँ कि बाकायदा 1996 में आर्टिकल 131 के तहत हमने अपील सुप्रीम कोर्ट में की थी जिसके तहत सुप्रीम कोर्ट ने बाकायदा अलाऊ किया कि 5.1.2002 तक पंजाब सरकार एस०वाई०एल० कैनाल का निर्माण करवायेगी लेकिन उन्होंने नहीं बनवाया। आप सब जानते हैं कि जो पिछली सरकार थी उन्होंने केवल अपोज किया था चाहे वह राजीव लौंगोवाल समझौता था या दूसरे समझौते थे। उसके बाद पिछली सरकार ने अरली हियरिंग के लिए सुप्रीम कोर्ट में एक भी एप्लीकेशन नहीं दी। हमारी सरकार ने अभी तीन मार्च को अरली हियरिंग के लिए चीफ जस्टिस को एप्लीकेशन दी है और उनसे कहा है कि आप जल्दी से हियरिंग कीजिए। उन्होंने कहा कि इसके अलावा 38 मुद्दे और हैं जो उन्होंने हियरिंग करने हैं और वे समर वैकेशन के दौरान इसकी सुनवाई करेंगे। अध्यक्ष महोदय, हम कोर्ट के बारे में क्या कह सकते हैं। उन्होंने कहा है कि उनके पास और भी अर्जेंट मैटर हैं वे समर वैकेशन में हमें सुनेंगे। राष्ट्रपति रैफरैंस भी हमने दिया है हमारी सरकार ने केन्द्र सरकार को भी कहा है और बाकायदा हमने पब्लिक वर्क्स डिपार्टमैंट को दिया था।

परिवहन मंत्री (श्री रणदीप सिंह सुरजेवाला) : अध्यक्ष महोदय, सदन के कई सदस्यों ने कुछ लाईन्ज लिखकर भेजी हैं और मुझे कहा है कि ये लाईनें सदन के बहुमत से ही नहीं बल्कि सदन की यह भावना है। बड़े तरन्नुम से ये लाईनें लिखी गई हैं मैं इनको यहाँ सुनाऊं—

कर रहा था मैं बरबादी का हिसाब, चौटाला की याद बे हिसाब आई,
कल जो कहते थे बिस्तर से उठा नहीं जाता आज देश छोड़ने की नौबत आई। (हंसी)

कैप्टन अजय सिंह यादव : अध्यक्ष महोदय, मैं तो आपको इस बात के लिए मुबारकबाद देना चाहूँगा कि आपने पूरे बजट सैशन में सब सदस्यों को बोलने का अवसर दिया। पिछली विधान सभा में इन्दौरा साहब नहीं थे। उस समय विपक्ष के सदस्यों के साथ किस तरह का व्यवहार होता था यह इनको नहीं मालूम। हमने ही उनको झेला था। उस वक्त हमें बोलने नहीं दिया जाता था। इन्दौरा जी एक घंटा बोले। इनको किसी ने इन्टरप्ट नहीं किया। हमें उस समय पांच मिनट बोलने के मिलते थे और उसमें भी 10 बार इन्टरप्ट किया जाता था। अध्यक्ष महोदय, मेरे कहने का मतलब यह है कि आपने बड़ी फिराखदिली दिखाई है। डॉ० सीताराम जी यहां बैठे हुए हैं, इन्होंने देखा है कि हमें उस समय किस तरह मार्शल सदन से बाहर उठा-उठाकर फेंका करते थे। (विघ्न) अध्यक्ष महोदय, इसके अतिरिक्त चौधरी महेन्द्र प्रताप सिंह जी ने आगरा कैनाल के बारे में जिक्र किया। इसके बारे में मैं कहना चाहूँगा कि यह

बात सही है कि ओखला बैराज पर यू०पी० सरकार का ही कंट्रोल है। अभी पिछले दिनों हमने उनके मुख्यमंत्री जी को चिट्ठी भी लिखी है और वार्निंग भी दी है। हमने बाकायदा उनको वार्निंग दी है कि अगर वे हमारे साथ भेदभाव करेंगे और हमें हमारे हिस्से का पूरा पानी नहीं देंगे तो हमें हथनी कुण्ड बैराज से उनके हिस्से का पानी काटना पड़ेगा। इस बारे में मैं यह कहना चाहूँगा कि इनके एरिया को जो पानी नहीं मिल रहा है वह यू०पी० की वजह से नहीं मिल पा रहा है। अध्यक्ष महोदय, मैं यह बताना चाहूँगा कि हम इस मैटर को यू०पी० गवर्नमैंट से टेकअप कर रहे हैं। इसके अलावा हमारे साथी श्री राधेश्याम शर्मा जी ने नांगल दर्जू वाटर वर्क्स के बारे में जिक्र किया था। मैं इनको बताना चाहता हूँ कि हम इस वाटर वर्क्स की स्ट्रैंथनिंग का कार्य कर रहे हैं। जो शहजादपुर डिस्ट्रीब्यूटरी है उसकी भी हम स्ट्रैंथनिंग कर रहे हैं और हम पूरे एफर्टस कर रहे हैं ताकि इसका कार्य अप्रैल तक पूरा हो जाए और पानी यहां तक पहुंच सके। दूसरे झाकरी वाटर वर्क्स है वहां के बारे में इन्होंने पूछा है। तीसरे इन्होंने हमीदपुर बांध से एक नहर जोड़ने के बारे में डिमाण्ड की है। वहां के बारे में मैंने बता ही दिया है। भाखरी वाटर वर्क्स के बारे में हम कार्य करने वाले हैं और दोचाना माईनर की डि-सिल्टिंग का कार्य हम पूरा कर रहे हैं और उसकी मरम्मत का काम भी हम कर रहे हैं और यह कार्य अप्रैल, 2006 तक पूरा हो जाएगा। अध्यक्ष महोदय, हमारे साथी श्री नरेश मलिक जी ने पाकसमा माईनर के बारे में जिक्र किया है। मैं इनको ऐश्योर करता हूँ कि आदरणीय मुख्यमंत्री जी की जो एनांउसमैंट है सरकार उसको जरूर पूरा करेगी। अध्यक्ष महोदय, श्री निर्मल सिंह जी ने दादूपुर नलवी नहर के बारे में जिक्र किया है। मैं हाउस को ऐश्योर करता हूँ कि अगले महीने इस नहर का कार्य शुरू करवाएँगे। इसके अलावा श्री राम कुमार गौतम जी ने जिक्र किया है कि आउटलैटस का साईज हमने कम कर दिया है लेकिन ऐसी कोई बात नहीं है। हमने बिल्कुल बराबर साईज रखा है ताकि पानी टेल तक पहुंच सके। श्री हर्ष कुमार जी ने उझीना ड्रेन के बारे में जिक्र किया है और कहा है कि वहां पर बांध बनाया जाए। कुछ बांध हमने बनाए हैं और बाकी भी हम बनाएंगे ताकि उसमें पानी रिजर्व कर सकें और उस पानी को रिटेन कर सकें। अध्यक्ष महोदय, इसके बारे में हम कार्यवाही करेंगे। एक रूपगढ़ माईनर के बारे में श्री भारद्वाज जी ने जिक्र किया है। वहां पर पम्प हाउस की स्कीम के बारे में हम विचार कर रहे हैं। टैक्नीकल कमेटी ने उसे पास कर दिया है और उसका काम भी जल्दी ही शुरू करेंगे। इसके साथ सांगा माईनर और पालावास माईनर अण्डर एग्जामिनेशन हैं और इनके बारे में भी हम जल्दी ही कार्य करेंगे खासतौर से सिवानी के एरिया का श्री राम कुमार गौतम जी ने जिक्र किया था कि उनके एरिया का पानी हमने ले लिया। अध्यक्ष महोदय, मैं इनको बताना चाहूँगा कि हमने किसी के एरिये का पानी नहीं लिया है। अध्यक्ष महोदय, सिवानी के एरिया के बारे में ऐसा था कि मैं श्री सोमवीर तथा फौजी साहब के साथ वहां पर गया था। वहां पर पीने का पानी नहीं था। इस सरकार ने पहली बार उनको अधिकार दिया कि बालसमन्द से डायरैक्ट सिवानी एरिया में पीने के लिए पानी दे दिया जाए। यह जो फैसला किया गया था वह पीने के पानी के तहत किया है। अध्यक्ष महोदय, ये कुछ प्वांयटस थे जिनके बारे में मैंने अपनी बात कहनी थी। धन्यवाद।

Mr. Speaker : Hon'ble Members, Now, Education Minister will give reply on the points pertaining to the education departments.

Dr. Sushil Indora : Sir, I want to seek some clarification from the Hon'ble Minister इन्होंने जैसे कहा है कि यह अरली डिसीजन के लिए कोर्ट में गए कि जल्दी फैसला होना चाहिए। अध्यक्ष महोदय, मैं इनसे यह जानना चाहता हूँ कि पंजाब गवर्नमैंट का जो लैटर आया है वह Inter Treaty Water Act के बारे में था या एस०वाई०एल० के निर्णय के बारे में था?

श्री अध्यक्ष : इन्दौरा साहब, इस के बारे में तो मुख्यमंत्री जी ने स्पष्ट बता दिया है (विघ्न) डॉक्टर साहब, यह कोई प्वांयट ऑफ ऑर्डर नहीं है इसलिए आप बैठें। (विघ्न)

श्री रणदीप सिंह सुरजेवाला : स्पीकर सर, माननीय इन्दौरा साहब को शायद यह मालूम नहीं है कि हरियाणा के हक में जो राजीव-लौंगोवाल समझौता हुआ था और इराडी कमीशन जब हरियाणा में आया था उस समय चौधरी देवी लाल तथा ओम प्रकाश चौटाला जी ने उसे साईमन कमीशन की संज्ञा दी थी और उनको काले झण्डे भी दिखाए थे जो कि हरियाणा के हितों की हत्या है। (विघ्न)

Dr. Sushil Indora : Speaker Sir, I want to seek some clarification from the Hon'ble Irrigation Minister regarding SYL issue. (Interruptions)

Mr. Speaker : Indora ji, Please take your seat. Please maintain the dignity of the House. Have patience. Please take your seat. Now, Education Minister will give reply on the points concerned with the Education Department.

शिक्षा मंत्री (श्री फूल चन्द मुलाना) : अध्यक्ष महोदय, पहले तो मैं आपको बधाई देना चाहता हूँ कि इतिहास में पहली बार ऐसा हुआ कि अपोजीशन के हर मैम्बर को बजट पर बोलने का मौका दिया गया है। अपोजीशन के आठ मैम्बर्ज हैं और आठ मैम्बर्ज को ही बोलने का मौका दिया है। आप इसके लिए बधाई के पात्र हैं। अध्यक्ष महोदय, बजट पर बोलते हुए कुछ सदस्यों ने शिक्षा के बारे में अपनी बातें कहीं हैं। अध्यक्ष महोदय, मैं वर्ष 1972 से अब तक कई बार इस सदन का सदस्य रहा हूँ और इस दौरान कई बार मुझे मंत्री बनने का भी मौका मिला है। जितना साऊंड बजट वित्तमंत्री और मुख्यमंत्री जी ने इस बार पेश किया इतना पहले कभी पेश नहीं हुआ है और ऐसा पहली बार हुआ है। मैं इसके लिए वित्तमंत्री जी को, मुख्यमंत्री जी और सारे सरकारी तन्त्र को बधाई देना चाहता हूँ जो इस बजट को बनाने में इन्वालव्ड हैं। अध्यक्ष महोदय, मुख्यमंत्री जी ने और हमने शिक्षा के क्षेत्र में जो एक अभियान चलाया है उसमें नए स्कूल खोलना, अध्यापक प्रोवाईड करना, स्कूलों में अच्छी फैसिलिटी देना और अच्छी शिक्षा देना शामिल है। राजीव गांधी के नाम से एजुकेशन सिटी का कार्य भी जारी है। एक नैशनल लॉ इन्स्टीच्यूट भी बनाया जा रहा है। इसके अलावा खेलों के क्षेत्र में भी बहुत सारे कदम उठाए जा रहे हैं। इस बारे में मुख्यमंत्री जी ने कहा है कि खेलों को गांवों में भी प्रोत्साहित किया जाए और गांवों में मिनी स्टेडियम भी बनाए जाएं। हमारे मुख्यमंत्री जी की ऐसी मंशा है और इन्होंने गांवों में मिनी स्टेडियम बनाने के लिए घोषणा भी की है। अध्यक्ष महोदय, यहां बजट पर बोलते हुए कई सदस्यों ने स्कूलों की दशा पर अपनी चिन्ता व्यक्त की है और कईयों ने तो यहां तक कह दिया कि सरकारी स्कूलों में जो टीचर्ज पढ़ाते हैं वे अपने बच्चों को प्राईवेट स्कूलों में पढ़ाते हैं, सरकारी स्कूलों में पढ़ने के लिए नहीं भेजते हैं। इस विषय में अध्यक्ष महोदय, मैं आपके ध्यान में एक बात लाना चाहूँगा कि पिछली सरकार ने शिक्षा को इतना नैगलैक्ट कर दिया था और स्कूलों की दशा इतनी खराब कर दी थी कि बच्चों को उन स्कूलों में भेजा ही नहीं जा सकता था। लेकिन मौजूदा सरकार उन स्कूलों की दशा में सुधार ला रही है। स्कूलों की बिल्डिंग्ज की मरम्मत के लिए बहुत सारा फंड जारी कर दिया गया है। आप थोड़े से अर्से में देखेंगे कि सरकारी स्कूलों की बिल्डिंग्ज चमकेंगी और स्कूलों की दशा में भी सुधार आएगा और बच्चे प्राईवेट स्कूलों की तरह गवर्नमैंट स्कूलों में भी जाएंगे। इसके साथ ही अध्यक्ष महोदय, कई सदस्यों ने टीचर्ज की ट्रांसफर के बारे में भी चिन्ता व्यक्त की है। अध्यक्ष महोदय, मुख्यमंत्री जी का हरियाणा के स्कूलों में सैमैस्टर सिस्टम लागू करने का फैसला है और सैमैस्टर सिस्टम में उचित होगा कि नए साल में जरनल ट्रांसफर्ज न हो। केवल जैनुअन कैसिज और एडमिनिस्ट्रेटिव

ग्राउंडज पर ही ट्रांसफर करने का विचार किया जाएगा, ऐसी हमारे मुख्यमंत्री जी की मंशा है। इसके साथ ही कई साथियों ने यह भी कहा है कि स्टाफ की कमी है तो इस विषय में मैं माननीय साथियों को बताना चाहूँगा कि हमने स्टाफ की कमी को गैस्ट टीचर्ज की भर्ती से पूरा किया है। इस तरह का इन्तजाम सारे देश में कहीं नहीं है। इसके लिए हमारे मुख्याध्यापकों और प्रिंसिपल्ज को हिदायतें हैं कि जहां पर भी जिस सब्जैक्ट की पोस्ट खाली है और जब तक हम उस पर परमानैंट भर्ती नहीं करते हैं तब तक उस पोस्ट को उस गांव, ब्लॉक या जिले का बच्चा जो उस पोस्ट के लिए क्वालिफिकेशन पूरी करता हो, से भरा जाए। (विघ्न) अध्यक्ष महोदय, मैं इनको बताना चाहूँगा कि टीचर्ज की परमानैंट भर्ती के लिए हमने पहले से ही सोच रखा है। अध्यक्ष महोदय, इनको शायद मालूम नहीं है, हमने हाईकोर्ट में बयान दिया था कि हम तब तक गैस्ट टीचर्ज को नौकरी में रखेंगे जब तक हम परमानैंट भर्ती नहीं करेंगे और परमानैंट भर्ती करते समय उनको भी कंसीडर करेंगे। उसके बाद ही ये आर्डर्ज हुए थे। अध्यक्ष महोदय, इसके अलावा गैस्ट टीचर्ज की भर्ती करते समय रिजर्वेशन का ध्यान रखा जाए, ऐसी भी किसी सदस्य ने बात कही थी। अध्यक्ष महोदय, इस बारे में इनको थोड़ा सा समझना चाहिए कि अगर कहीं पर 4 या 5 पद खाली हों तो वहां पर इस बारे में ध्यान रखा जा सकता है और ध्यान रखा भी जाएगा। अध्यक्ष महोदय, मैं आपके माध्यम से सदन को बताना चाहूँगा कि 12,000 अध्यापकों की भर्ती की जाएगी। इसके साथ ही कई सदस्यों ने मांग की कि नए कालेज खोले जाएं। अध्यक्ष महोदय, आज कम्पीटीशन का जमाना है, सिर्फ इम्तिहान पास करने का युग नहीं है और हमारी सरकार का उद्देश्य है कि कालेजों में अच्छी एजुकेशन देनी चाहिए। इसके लिए हम कॉलेजिज में नए कोर्सिज एड कर रहे हैं, वहां पर इन्फ्रास्ट्रक्चर को बढ़ा रहे हैं। अध्यक्ष महोदय, बजट में पहली बार शिक्षा के लिए प्लान में 290 करोड़ और नॉन प्लान में 2432.79 करोड़ रुपये का प्रावधान किया गया है। इस बजट में लड़कियों की शिक्षा पर भी विशेष ध्यान दिया जा रहा है। इसके अलावा कई सदस्यों द्वारा मांग की गई कि यूनिवर्सिटी खोल दी जाए, नारनौल में यूनिवर्सिटी खोल दी जाए। अध्यक्ष महोदय, यूनिवर्सिटी क्या होती है? यूनिवर्सिटी में एम०ए० की क्लासिज या पी-एच०डी० की क्लासिज का प्रावधान होता है। हमने नारनौल के पास रिवाड़ी जिले में यूनिवर्सिटी का एक रीजनल सैंटर खोल दिया है जिसकी आधारशिला मुख्यमंत्री जी रखकर आये हैं। यह भी यूनिवर्सिटी ही होती है। अटेली में सरकारी कालेज है और मेवात के बारे में भी कुछ साथियों ने चर्चा की खासकर हर्ष कुमार जी ने की कि उनके क्षेत्र में मेवात डिवल्पमैंट बोर्ड के स्कूल हैं और उनकी फीस ज्यादा है। अध्यक्ष महोदय, मॉडल स्कूल्ज की फीस तो ज्यादा होगी ही लेकिन वे स्कूल बहुत अच्छे हैं। लेकिन अपने गरीब बच्चों को पढ़ाने के लिए यह जरूरी है कि सरकारी स्कूल्ज भी हों। अध्यक्ष महोदय, हथीन कांस्टीच्यूएंसी में 11 सीनियर सैकैंडरी स्कूल्ज, आठ हाई स्कूल्ज और 17 मिडल स्कूल्ज हैं। इन स्कूलों में हमारे गरीब बच्चे पढ़ सकते हैं। मेवात क्षेत्र में टोटल 159 स्कूल हैं इसलिए कोई पढ़ाई की दिक्कत नहीं है। स्पोर्ट्स के क्षेत्र में मुख्यमंत्री जी ने जैसा ऐलान किया है कि गांवों में मिनी स्टेडियम बनाये जाएंगे, नर्सरी खोली जाएंगी। अध्यक्ष महोदय, शिक्षा और खेल मिलकर साथ-साथ आगे बढ़ते हैं क्योंकि शिक्षा के क्षेत्र से ही बच्चे खेल के क्षेत्र में आते हैं। दोनों के तालमेल से ही खेलों और शिक्षा को बढ़ावा दिया जाएगा। मुझे पूर्ण आशा है कि यह बजट ज्यों-ज्यों लागू होगा त्यों-त्यों पूरे प्रान्त की दशा बदलेगी। जैसे मुख्यमंत्री जी की इच्छा है कि देश में हमारा प्रांत नम्बर वन हो तो वह मंशा पूरी होगी। (विघ्न) मॉडल स्कूल का जहां तक ताल्लुक है मुख्यमंत्री जी ने निर्णय लिया है कि हम प्राईवेट स्कूल के लैवल पर अच्छे स्कूल अपने प्रांत में बनाएंगे। फिलहाल यह निर्णय लिया है कि हर जिले में एक मॉडल स्कूल खोला जाएगा। हम ऐसे स्कूल नहीं खोलेंगे जैसे पिछली सरकार ने एक स्कूल खोल दिया और कह दिया कि वह मॉडल स्कूल हो

[श्री फूल चन्द मुलाना]

गया। उन्होंने उस स्कूल को केवल दस लाख या पांच लाख रुपया दिया था लेकिन हमारे मुख्यमंत्री जी ने कहा है कि फर्स्ट फेज में पचास लाख रुपये से हम मॉडल स्कूल शुरू करेंगे ताकि इनका इंफ्रास्ट्रक्चर ठीक हो। अध्यक्ष महोदय, पचास-पचास लाख रुपये में हम बीस के बीस मॉडल स्कूल्ज खोलेंगे। अध्यक्ष महोदय, इन शब्दों के साथ मैं अपने उन सभी साथियों का धन्यवाद करता हूँ जिन्होंने अपने विचार रखे हैं। मैं मुख्यमंत्री जी को भी बेहतरीन बजट पेश करने के लिए बधाई देता हूँ और अपना स्थान लेता हूँ।

Mr. Speaker : Now, the Chief Minister will speak.

मुख्यमंत्री (श्री भूपेन्द्र सिंह हुड्डा) : अध्यक्ष महोदय, विभिन्न दलों के मेरे सभी माननीय सदस्यों ने अपने-अपने विचार रखे हैं। जहां तक बजट का सवाल है वित्त मंत्री जी उसका जवाब देंगे लेकिन कुछ मुद्दे हमारे साथियों ने उठाए हैं उनके बारे में मैं कहना चाहता हूँ। एक तो कानून व्यवस्था की बात कही है, एस०वाई०एल० कैनाल की बात कही है और सैंट्रल स्पोंर्स्ड स्कीम्ज की बात भी यहां पर कहीं गयी है। इस तरह से तीन-चार मुद्दे उठाये गये हैं जिनके बारे में मैं सदन के माननीय सदस्यों की इंफर्मेशन के लिए बताना चाहता हूँ। जहां तक कानून व्यवस्था का सवाल है, इस बारे में बहुत से आंकड़े दिए गए हैं। अर्जन सिंह जी ने बोलते हुए कहा था कि पिछली सरकार के समय तो एफ०आई०आर० तक दर्ज नहीं होती थी। अध्यक्ष महोदय, प्रत्यक्ष को प्रमाण की जरूरत नहीं होती है। मेरा बलवन्त सिंह जी से एक ही निवेदन है कि आप किसी भी शहर का नाम ले लें या गांव का नाम ले लें। आप वहां चले जाएं और एक और सदन का सदस्य आपके साथ चला जाएगा तथा अध्यक्ष महोदय, आप भी अपना एक नुमाइन्दा इनके साथ भेज दें। ये लोग किसी भी गांव या शहर के लोगों को इकट्ठा करके पूछ लें कि आज के दिन कानून व्यवस्था की स्थिति क्या है और पहले क्या थी ? अध्यक्ष महोदय, उस समय जिस प्रकार से लोग हरियाणा प्रान्त में रह रहे थे वह सबको मालूम है। किस प्रकार से उस समय हरियाणा में अपराधियों को संरक्षण दिया जाता था, अपराधी खुलेआम हरियाणा में घूम रहे थे। यह पूरा हरियाणा जानता है प्रत्यक्ष को प्रमाण की जरूरत नहीं है जिस भी शहर का नाम आप लें जिस भी गांव का नाम आप लें जब भी तिथि तय करें आपको खुली छूट है। (विघ्न)

डॉ० सीता राम : स्पीकर सर, ***** (विघ्न)

Mr. Speaker : No recording, please. No iterference, I request you please have petience, लीडर ऑफ दि हाउस खड़े हैं।

श्री भूपेन्द्र सिंह हुड्डा : एस०वाई०एल० का मुद्दा उठाते हैं। एस०वाई०एल० का नाम लेकर हरियाणा के लोगों को जिस तरह से गुमराह कुछ लोगों ने किया है खासतौर से इनैलो के नेता ने उसका ही नतीजा यह हुआ कि पिछले चुनाव में कांग्रेस पार्टी को इतने भारी बहुमत से जिताकर लोगों ने भेजा क्योंकि ढोल की पोल खुल गई। झूठ ज्यादा दिन तक नहीं चलता। एस०वाई०एल० क्या है ? एस०वाई०एल० कब बननी शुरू हुई, किसने बनाई और किसके हुकम से बनी ? जब हरियाणा और पंजाब अलग-अलग प्रदेश बने उस समय श्रीमती इन्दिरा गांधी जी ने अपनी कलम से हरियाणा को अलग राज्य बनाया क्योंकि हरियाणा का उस समय कोई विकास नहीं हो रहा था। उसके बाद उन्होंने एक एस०वाई०एल० के नाम से एवार्ड दिया जिसका नाम इन्दिरा गांधी एवार्ड था। उस समय यह नहर नहीं बन सकी क्योंकि कांग्रेस पार्टी सत्ता में नहीं रही, चौधरी देवीलाल हरियाणा के मुख्यमंत्री बने और केन्द्र में जनता पार्टी की सरकार बनी। उस समय यह मुद्दा वहीं का वहीं खड़ा रहा और बहुत साल तक

* चेयर के आदेशानुसार रिकॉर्ड नहीं किया गया।

इसका कोई निपटान नहीं हो सका। उसके बाद श्री राजीव गांधी जी प्रधान मंत्री बने तो उन्होंने राजीव-लौंगोवाल नाम से एस०वाई०एल० के बारे में एक समझौता किया परन्तु उसके बाद भी क्योंकि कांग्रेस पार्टी की सत्ता नहीं रही इसलिए फिर भी एस०वाई०एल० का निपटारा नहीं हो सका। उसके बाद सुप्रीम कोर्ट ने एक फैसला एस०वाई०एल० को खोदने के लिए हरियाणा के हित में दिया। सुप्रीम कोर्ट ने यह फैसला तब दिया, जब श्री ओम प्रकाश चौटाला इस प्रदेश के मुख्यमंत्री थे और श्री अटल बिहारी वाजपेयी जी प्रधानमंत्री थे। दिल्ली में इनके सांसद उनका समर्थन कर रहे थे। भाई नरेश मलिक जी कह रहे थे कि हमने गलती की है, चौटाला को अन्दर नहीं किया। अगर हमने गलती की है तो तुमने तो इतने साल उनका समर्थन किया। (शोर) सुप्रीम कोर्ट का जो फैसला आया है। उसने भी इसका आधार जो इन्दिरा गांधी का एवार्ड था, राजीव-लौंगोवाल समझौता था, उसी के आधार मानकर अपना फैसला किया है। इस तरह से इस नहर के बनने के विलम्ब के लिए कौन दोषी है? एस०वाई०एल० बनने में विलम्ब का कारण इण्डियन नैशनल लोकदल के अध्यक्ष चौधरी देवी लाल और भारतीय जनता पार्टी रही हैं। राजीव-लौंगोवाल समझौते का विरोध चौधरी देवीलाल जी ने और डॉ० मंगल सैन जी ने किया था। अगर उस समय विरोध नहीं किया होता तो इस नहर का 90 प्रतिशत खुदाई का काम तो उस समय हो गया था?

डॉ० सीता राम : पानी वाले समझौते का विरोध हमने कब किया था।

डॉ० सुशील इन्दौरा : ******

श्री अध्यक्ष : इन्दौरा साहब, सदन के नेता खड़े हैं प्लीज आप अपनी सीटों पर बैठें। Please Indora Sahib, take your seat. Nothing to be recorded.

श्री भूपेन्द्र सिंह हुड्डा : अध्यक्ष महोदय, मैं इनसे पूछना चाहता हूँ कि न्याययुद्ध किसने चलाया था? आज सुप्रीम कोर्ट ने जो फैसला हरियाणा के हित में दिया है उसका आधार क्या है? इन्होंने तो इन्दिरा गांधी एवार्ड और राजीव गांधी-लौंगोवाल समझौते का विरोध किया था। श्रीमती इन्दिरा गांधी ने तो एस०वाई०एल० कैनाल को बनाने के आदेश दिये थे और राजीव गांधी ने इस नहर के निर्माण कार्य के लिए 700 करोड़ रुपये देकर इस कार्य को आगे बढ़ाया था। अब नई सरकार आने के बाद जब सरकार ने बी०एम०एल०-हाँसी-बुटाना नहर को बनाने का काम शुरू किया है तो ये माननीय सदस्य उसका भी विरोध कर रहे हैं। ये बताएं कि ये इसका विरोध क्यों कर रहे हैं? जो इसका विरोध कर रहे हैं वही ताकत, वही व्यक्ति एस०वाई०एल० का भी विरोध कर रहे हैं क्योंकि ये एस०वाई०एल० को बनाना नहीं चाहते। (शोर एवं व्यवधान) अध्यक्ष महोदय, इन्दौरा जी एक घंटे तक बोले हमने इनको बीच में नहीं टोका और अब ये सच्चाई और हकीकत को सुनने के लिए तैयार नहीं हैं। जो कुछ मैं कह रहा हूँ यह तो सुप्रीम कोर्ट के फैसले में लिखा हुआ है। पूर्ण रूप से एस०वाई०एल० कैनाल के विलम्ब के लिए ये लोग दोषी हैं। अध्यक्ष महोदय, यदि एस०वाई०एल० कैनाल की खुदाई हुई है तो कांग्रेस सरकार के कार्यकाल में हुई और एस०वाई०एल० कैनाल का पानी भी हम ही लेकर आयेंगे। इन लोगों ने तो एस०वाई०एल० के नाम पर जनता को धोखा दिया है। लेकिन जनता अब इनकी चालाकी समझ चुकी है। इसके अतिरिक्त इन्दौरा साहब ने सैंट्रल स्पोंसर्ड स्कीम्ज के बारे में कहा कि इनकी सरकार के समय में इन स्कीम्ज के तहत प्रदेश को बहुत पैसा मिलता था और अब नहीं मिल रहा है। मैं इनकी जानकारी के लिए बताना चाहूँगा कि वर्ष 2004-05 के दौरान जितनी भी सैंट्रल स्पोंसर्ड स्कीम्ज थीं

* चेयर के आदेशानुसार रिकॉर्ड नहीं किया गया।

[श्री भूपेन्द्र सिंह हुड्डा]

उनमें प्रदेश का शेयर केवल 263 करोड़ रुपये का था जबकि इन्होंने कहा कि यह शेयर 596 करोड़ रुपये का था। इनको यह नहीं मालूम कि वह शेयर नॉन प्लान को मिलाकर था। प्लान का तो 263 करोड़ रुपये का ही शेयर था। अगर इस बात का इनको ज्ञान नहीं है तो मैं क्या कर सकता हूँ? मैं इनको बताना चाहूँगा कि वर्ष 2005-06 में रिवाईज्ड एस्टीमेट्स 418 करोड़ रुपये थे जो इस बजट में बढ़कर 540 करोड़ रुपये हो गये हैं। अध्यक्ष महोदय, हम तो 263 से 540 करोड़ रुपये तक पहुंचे हैं। इसके अतिरिक्त जो 10 कि०मी० की लम्बाई में हाईवे बना है जिसमें 3.408 कि०मी० पानीपत का अलीवेटिड एरिया है जिसके बारे में गाबा साहब ने जिक्र किया था उस हाईवे को बनाने का कार्य इस वर्ष शुरू हो जायेगा। इसके अतिरिक्त रिवाड़ी से झज्जर-रोहतक की रेलवे लाइन बनाने की लोगों की बहुत पुरानी मांग थी उनकी यह मांग अब पूरी हो गयी है। यह हरियाणा के लिए फेट कोरीडोर है। यह रेलवे लाईन पूरे हरियाणा को कनैक्ट करेगी। इसके लिए भारत सरकार ने पैसा दिया है, यह रेलवे लाईन तीन साल में पूरी हो जायेगी। इसके अतिरिक्त दिल्ली से रोहतक रेलवे लाईन की इलैक्ट्रिफिकेशन के लिए भी भारत सरकार ने पैसा दिया है और 340 करोड़ रुपये रेलवे लाईन के अपग्रेडेशन के लिए 'भारत निर्माण' स्कीम के तहत भारत सरकार ने हमें दिए हैं। अध्यक्ष महोदय, सैंट्रल स्पोंसर्ड स्कीम्ज में कहीं पर भी कोई कमी नहीं है। इनके अतिरिक्त और भी बहुत सी बातें हैं लेकिन ये लोग शायद पढ़कर नहीं आते या हरियाणा के विकास में रुचि नहीं रखते इसलिए ये इस तरह की बातें करते हैं। इसके अतिरिक्त स्टेटवाईज रेंज नेटवर्क के लिए 102 करोड़ रुपये का प्रोजैक्ट है जिसमें 62.64 करोड़ रुपये का शेयर भारत सरकार का होगा। ई-गवर्नेंस प्रोग्राम की स्कीम भी 999.55 करोड़ रुपये की है। इसके अतिरिक्त भारत सरकार ने पानीपत में टैक्सटाईल कलैस्टर मंजूर किया है जिसकी लागत 54 करोड़ रुपये होगी। इसके अतिरिक्त भारत सरकार ने लाईट इंजीनियरिंग गुड्स कलैस्टर फरीदाबाद में 72 करोड़ रुपये की लागत का मंजूर किया है। इसी तरह से भारत सरकार नैशनल आटो टैस्टिंग रिसर्च इन्फ्रास्ट्रैक्चर प्रोजैक्ट मानेसर में लगाने जा रही है जिस पर 400 करोड़ रुपये का खर्चा आयेगा। इसी तरह से प्लास्टिक इंजीनियरिंग टैक्नोलोजी प्रोजैक्ट पानीपत में भारत सरकार की तरफ से लगाया जायेगा जिस पर बहुत भारी लागत आयेगी। इसके अतिरिक्त मेगा फूड पार्क भी मंजूर किया हुआ है। अध्यक्ष महोदय, इस तरह से भारत सरकार की कोई ऐसी स्कीम नहीं है जिसका फायदा हरियाणा प्रदेश को न हो रहा हो। अध्यक्ष महोदय, मैं अपने साथियों को बताना चाहूँगा कि जिस समय हमारी सरकार बनी और जब पहली कैबिनेट की मीटिंग हुई तो उस समय मैंने अपने साथियों को कहा था कि हमारी सरकार जनहित की सरकार है और कांग्रेस पार्टी का हाथ गरीब आदमी के साथ है इसलिए कोई भी फैसला करने से पहले आपने यह देखना है कि इस प्रदेश की गरीब जनता को उससे क्या-क्या लाभ मिल सकते हैं। हमारी कांग्रेस अध्यक्षा सोनिया गांधी जी का भी यही कहना है। इन्हीं बातों को ध्यान में रखते हुए बहुत से जनहित के फैसले हमने किए हैं। हरिजनों और बैकवर्ड क्लास के कल्याण के लिए जो 85वां अमैंडमैंट संविधान में किया गया है और इसके तहत जो 7000 पोस्टों का बैकलोग रिजर्व कैटेगरी का है, उसको जल्दी पूरा करने के आदेश सरकार ने दिए हैं। जो एस०सी० फाईनैंशियल कारपोरेशन का पैसा है सरकार उसके प्रति चिन्तित है इसलिए एस०सी० फाईनैंशियल कारपोरेशन का जो पैसा बैकवर्ड क्लासिज निगम का जो पैसा था उसको सरकार ने 4.69 करोड़ रुपये रि-इम्बर्स किया है। सफाई कर्मचारियों को चाहे वे म्यूनिसिपल कमेटीज में कार्य कर रहे हैं, चाहे सरकार में नौकरी कर रहे हैं, उनके वेतन में 200 रुपये प्रतिमाह की हमने बढ़ौतरी की है। (इस समय मेजें थपथपाई गईं) अनुसूचित जातियों के लोगों को दिए जाने वाले लोन के लिए हमने एक प्रतिशत रेट ऑफ इण्टरस्ट कम किया है

और उनको स्कॉलरशिप्स भी दिये हैं। गरीब लोगों के लिए 'इन्दिरा गांधी प्रियदर्शनी विवाह शुगन' योजना चलाई है और मकानों के निर्माण के लिए अनुदान राशि 10 हजार से बढ़ा कर 15 हजार रुपये की है। इसी प्रकार से 50 हजार रुपये तक की हमने दलित को जमीन खरीदने के लिए राशि दी है। अगर कोई दलित दो एकड़ जमीन खरीदेगा तो उसके लिए 5 लाख रुपये की कीमत में से सरकार द्वारा 50 हजार रुपये की सबसिडी देने का फैसला किया गया है। अध्यक्ष महोदय, इस प्रकार के बहुत से फैसले सरकार द्वारा किये गये हैं और हर वर्ग के लोगों के हित के लिए काम किए गए हैं। चौकीदारों को हमने 400 रुपये दिए हैं। गांव में एक गरीब चौकीदार होता है और सारे कामों की जिम्मेदारी उसकी होती है इसलिए उसको 400 रुपये की बढौतरी सरकार ने दी है। इसी प्रकार से नम्बरदारों को भी बढ़ौतरी दी है। अध्यक्ष महोदय, हर वर्ग के लोगों को हमने कई प्रकार की सुविधाएं दी हैं। सोशल वैल्फेयर स्कीमों के तहत हमने कई प्रकार की सुविधाएं दी हैं और इसके लिए हमने बजट में 40 करोड़ रुपये का प्रावधान किया है। अध्यक्ष महोदय, मैं वित्त मंत्री जी से कहना चाहता हूँ कि सोशल वैल्फेयर स्कीम्ज हमारी सरकार का ह्यूमन फेस है। ह्यूमन फेस को ध्यान में रखकर ही हमारी सरकार काम करती है और गरीब आदमी का ख्याल रखती है। इसी कारण 40 करोड़ रुपये का बजट में प्रावधान रखा गया है। हालांकि मेरे ख्याल से यह भी नाकाफी है इसलिए इस 40 करोड़ रुपये की राशि को बढ़ाकर 80 करोड़ रुपये का प्रावधान हम सोशल स्कीमों के लिए कर रहे हैं। 40 करोड़ की बजाए 80 करोड़ रुपये से हम सोशल स्कीमों का काम करेंगे ताकि हर आदमी तक उसका लाभ पहुँचे। अध्यक्ष महोदय, शिक्षा के प्रति हमारी सरकार जागरूक है। शिक्षा के बारे में बोलते समय कई सदस्यों द्वारा स्कूलों की बात कही गई है। बेहतर शिक्षा के लिए मॉडल स्कूलों का प्रावधान भी हम करने जा रहे हैं। शिक्षा के बारे में जैसे कि शिक्षा मंत्री जी ने बताया है कि तीन मॉडल स्कूल तो हम इस वर्ष में चालू कर चुके हैं। हमने जनता से जो वायदे किए थे वह सारे हम पूरे कर चुके हैं। हर जिले में एक-एक मॉडल स्कूल होगा। हम जो वायदे करते हैं उनको निभाते भी हैं और कोई झूठ नहीं बोलते हैं। हमने अलग हाईकोर्ट के बारे में कह रखा है और विधान सभा में पहले भी इस बारे में प्रस्ताव पास किया था। हाईकोर्ट के बारे में आज मैं फिर कह रहा हूँ। अध्यक्ष महोदय, हम जो कहते हैं वह करते हैं आज फिर मैं इस बात को दोहरा रहा हूँ कि हरियाणा का हाईकोर्ट अलग बनेगा। अध्यक्ष महोदय, इन्हीं शब्दों के साथ मैं कहना चाहता हूं कि सरकार ने जो काम किये हैं हमारे विपक्ष के साथी उनके प्रति कोई भी बात कहें लेकिन पहले उसके बारे में दरयाफ्त करके तसल्ली जरूर कर लें। अच्छे काम हमने किये हैं लेकिन हमारे विपक्ष के भाई उन्हें अच्छा नहीं बताते हैं। (विघ्न) अध्यक्ष महोदय, इन शब्दों के साथ मैं सभी सदस्यों का आभारी हूँ कि उन्होंने बजट पर बहुत अच्छे सुझाव रखे हैं। जो भी अच्छे सुझाव आए हैं उन पर हम पूरा ध्यान देंगे और जो सुझाव जनहित के होंगे उन पर कार्यवाही करके हम अमल करेंगे। बहुत-बहुत धन्यवाद।

Mr. Speaker : Hon'ble Members, now, the Finance Minister will give reply on the Budget Estimates for the year 2006-07.

शिक्षा मंत्री (श्री फूल चन्द मुलाना) : अध्यक्ष महोदय, इससे पहले कि माननीय वित्तमंत्री जी रिप्लाई दें मैं एक बात कहना चाहता हूँ। अध्यक्ष महोदय, माननीय मुख्यमंत्री जी ने एस०वाई०एल० कैनाल के मुद्दे पर भी कहा और कानून व्यवस्था के बारे में भी उन्होंने कहा है। अध्यक्ष महोदय, जब इनका राज था तो उसके बारे में मैं एक शेर अर्ज करने की इजाजत चाहता हूँ। अध्यक्ष महोदय,

अपने नापाक इरादों को यूं ना नंगा करो
ये कहीं बर्बाद न कर दें हमारे प्रांत को।

वित्त मंत्री (श्री बीरेन्द्र सिंह) : आदरणीय अध्यक्ष महोदय, मैं इस सदन के सभी सदस्यों का बहुत आभारी हूँ कि उन्होंने अपने अनुभव के अनुसार बजट 2006-07 के बारे में अपने विचार रखे और बहुत से बहुमूल्य सुझाव भी दिए। उनके बहुमूल्य सुझावों का ही यह नतीजा और फायदा है कि आज माननीय मुख्यमंत्री जी ने दो घोषणाएं की हैं। चालीस करोड़ रुपये जो एस०सीज० और बी०सीज० या समाज का जो गरीब तबका है, उसके लिए बजट में रखे गए थे लेकिन उनके लिए अब 40 करोड़ की बजाय 80 करोड़ रुपये होंगे यानी यह राशि डबल कर दी गई है। (इस समय मेजें थपथपाई गईं)। अध्यक्ष महोदय, मुख्यमंत्री जी ने सदन की इच्छा के अनुसार ही फाईनांस डिपार्टमैंट को यह कहा कि यह राशि बढ़नी चाहिए। अध्यक्ष महोदय, हमने सारा जोड़-तोड़ लगाकर 40 करोड़ रुपये की राशि दी है। मैं तो यही कह सकता हूँ कि समाज कल्याण के लिए हमें कितना धन देना पड़े हम उससे पीछे नहीं हटेंगे। (इस समय मेजें थपथपाई गईं।) इसके साथ जो दूसरा महत्वपूर्ण ऐलान हुआ है उससे मैं ज्यादा सन्तुष्ट हूँ क्योंकि मेरी पृष्ठभूमि खेलने की ही रही है। अध्यक्ष महोदय, 40 करोड़ रुपये खेलों को प्रोत्साहन देने के लिए, खेलों का मूलभूत ढांचा गांवों में तैयार करने के लिए एच०आर०डी०एफ० से मिले हैं। इसके अलावा डिपार्टमैंट का जो पैसा है। (विघ्न) अध्यक्ष महोदय, मैं समझता हूँ कि पंचकूला और गुड़गांव में जो बड़े-बड़े स्टेडियम बने हुए हैं वे अन्तर्राष्ट्रीय स्तर के संस्थान हैं। वहां पर जो लोजैस्टिकस इन्फ्रास्ट्रक्चर हैं उनसे हम दुनिया भर के ख्याति प्राप्त खिलाड़ियों को तो प्रोत्साहित कर सकते हैं लेकिन गांवों में और देहातों में रहने वाले जो प्रतिभाशाली युवा हैं वे उन सुविधाओं से वंचित रह जाते हैं। अध्यक्ष महोदय, खेलों के लिए यह जो पैसा हमने अब रखा है इसको हम देहातों और गांवों में ही लगाएंगे और इससे गांवों और देहातों के युवा खिलाड़ियों को फायदा होगा। (विघ्न) पिछली सरकार ने तो साढे पांच साल के राज में लोगों को पथ-भ्रष्ट करने की कोशिश की थी। किसान को उस समय बिजली नहीं मिलती थी, फसलों के उचित दाम नहीं मिलते थे। अध्यक्ष महोदय, इनके दलाल उत्तर प्रदेश का गेहूं खरीद कर पलवल की मण्डियों में बेचकर पैसा कमाते थे। इनके राज में युवाओं को निराशा ही निराशा हाथ लगी थी। हमारा युवा अपराधिक गतिविधियों की तरफ बढ़ने लगा था। अध्यक्ष महोदय, जब गांवों में युवाओं के रिक्रीएशन के लिए, उनके मनोरंजन के लिए और उनकी खेल प्रतिभाओं को उभारने के लिए पूरा मूलभूत ढांचा तैयार होगा तो उनका मन गांव में लगेगा। जो कुछ युवाओं के मन में कुरीतियां आ गई थी, उससे हटकर वह सकारात्मक काम करेगा। हमारे बच्चे बहुत ही प्रतिभाशाली हैं जिसकी मिसाल हमारी लड़की सीमा आंतिल ने कामनवैल्थ गेम्ज में रजत पदक जीत कर दी है। इसके अलावा और भी मैडल हमारे खिलाड़ियों को मिलेंगे। अध्यक्ष महोदय, अगर हम युवाओं को सही ढांचा तैयार करके देंगे तो हम अन्तर्राष्ट्रीय स्तर पर किसी से कम नहीं रहेंगे। इसलिए मुख्यमंत्री जी ने जो दोनों घोषणाएं की हैं यह हमारे लिए बहुत ही गर्व की घोषणाएं हैं। इस तरह से जो हरियाणा के युवाओं की जो निराशा की समस्या है उससे भी हम निपट सकेंगे। अध्यक्ष महोदय, मैं सदन में आपकी तारीफ करना चाहूँगा कि आपने बजट पर आम बहस के लिए 483 मिनट का समय दिया है। शायद ही बजट पर बहस के लिए इतना समय कभी मिला हो। बजट पर बहस के इस समय में लगभग 41 सदस्यों ने हिस्सा लिया है। इसमें कांग्रेस के 24 सदस्य बोले हैं, इनैलो के 8 सदस्य, बी०जे०पी० के दो सदस्य, 6 हमारे इन्डीपैंडेंट सदस्य और एन०सी०पी० का एकमात्र सदस्य बोला है, इन सब ने बजट पर हुई बहस में हिस्सा लिया है और अपने अमूल्य सुझाव उन्होंने दिए हैं। स्पीकर सर, मैं अपनी बात बजट पर दूसरे तरीके से शुरू करना चाहता हूँ। आनरेबल मैम्बर्ज ने बजट के बारे में हमें अपने सुझाव दिए हैं। मैं अगर बजट के बारे में चर्चा करूँगा तो ज्यादा ठीक रहेगा क्योंकि जब डिमांडज पर मैम्बर्ज बोलेंगे या जब वे अपने-अपने इलाकों की समस्याओं के बारे में जिक्र करेंगे तो

उनका जवाब संबंधित मंत्री देंगे। मेरे कुछ मंत्रिमंडल के साथियों ने भी जवाब दिए हैं और मुख्यमंत्री जी ने भी इंटरवैंशन करके पोलिसी डिसीजन के बारे में अपनी घोषणाएं की हैं। दूसरे मंत्री जी भी चाहते हैं कि जब डिमांडज आये तो अपने-अपने महकमों के बारे में पूरे विस्तार से जो सवाल आनरेबल मैम्बर्ज ने उठाए हैं, उनका जवाब दे सकें। लेकिन मैं एक बात कहकर अपनी बात शुरू करता हूँ कि जो यह संसदीय लोकतंत्र हैं इसको हमारे संविधान के निर्माताओं ने अनेक देशों के संविधानों को पढ़कर उन पर पूरा गहन विचार करके ही यह संसदीय प्रणाली देश को दी थी। संसदीय प्रणाली का मूल मंत्र जनमत और जनहित होता है। जनमत अगर किसी के साथ है और यदि वह जनहित के कार्य करता है, अपने कर्त्तव्य का निर्वहन करता है तो वह सही संसदीय लोकतंत्र है। सर, संसदीय प्रणाली कोई एक दिन में शुरू नहीं हुई। इतिहास गवाह है कि इसमें हजारों-हजारों साल लग गये। आज जो दुनिया की सबसे मैच्योर डेमोक्रेसी है इंग्लैंड की, उसको भी अपनी पार्लियामैंट्री डेमोक्रेसी को मजबूत करने में 1100 साल लग गये हैं। इसमें बहुत उतार चढ़ाव आये लेकिन उसकी जरूरत उस जमाने में भी और आज भी इसलिए महसूस की गयी क्योंकि दूसरी राज करने की कोई पद्धति, कोई गवर्नैंस ठीक नहीं हो सकती थी। चाहें वह राजतंत्र था, चाहे वह कोई डैसपोट था या चाहे वह कोई तानाशाह था उन्होंने सबने कोशिश यह की थी कि जब-जब उन्होंने सत्ता हासिल की तो एक मात्र तानाशाह के इशारे पर सब कुछ होता था और स्पीकर सर, एक समय तो ऐसा भी आ गया था जब फ्रांस के अंदर लुईफोर्टिस यह कहता था कि I am the State. मैं राजा हूँ मेरा हुक्म है और मैं जो चाहूँगा वही होगा। स्पीकर सर, ऐसे ही अंश श्रीमान चौटाला जी ने अपने साढ़े पांच साल के राज में दिखाये। मैं इसके कई रैफरैन्स आपको देकर बता सकता हूँ कि उनकी किस तरह की तानाशाही प्रवृत्ति थी। मैं इसमें इन भाइयों का दोष नहीं बताता। इनको दोषी मैं इसलिए मानता हूँ कि इन्होंने अगर अपने अधिकारों का प्रयोग अपनी निस्वार्थ भावना से किया होता, निडर होकर करते तो चौटाला साहब या उनके बेटों की इतनी हिम्मत नहीं हो सकती थी कि वे इतनी निरंकुशता से हरियाणा पर राज करते।

डॉ० सुशील इन्दौरा : आन ए प्वायंट ऑफ ऑर्डर सर। अध्यक्ष महोदय, इनको इस तरह की बातें सदन में करना शोभा नहीं देता। ऐसी बातें अगर ये किसी सभा में करें तो दूसरी बात है।

श्री बीरेन्द्र सिंह : कौन सी बातें। अध्यक्ष महोदय, मैं सदन की जानकारी के लिए बताना चाहूँगा कि पहली बार सन् 1215 में इंग्लैंड की जनता ने अपने बादशाह को आकर कहा कि हम आपका राज नहीं चलने देंगे। पहली बार किसी निरंकुश बादशाह ने अपने लोगों की बात से सहमत होकर एक समझौते पर हस्ताक्षर किये कि मैं आपकी बात मानता हूँ मुझे आप सिर्फ राज चलाने की इजाजत दे दीजिए बाकी काम जनता के चुने हुए प्रतिनिधि करेंगे। हालात यहाँ तक हो गये थे कि निरंकुशता की जो पराकाष्ठा है उसकी कोई सीमाएं नहीं होती। उस समय एक समय ऐसा भी आया कि इंग्लैंड का बादशाह देश छोड़कर भाग गया। हमने शुरू में ही यह बात मानी और हम इस बात को समझते थे कि चौटाला साहब एक रणनीति के तहत एक साल तक अपनी शक्ल हरियाणा की जनता को और हरियाणा की विधानसभा को नहीं दिखाना चाहते क्योंकि वे लोगों की निगाहों को फेस ही नहीं कर सकते।

13.00 बजे

डॉ० सुशील इन्दौरा : ऑन ए प्वायंट ऑफ आर्डर सर। अध्यक्ष महोदय, सदन के माननीय सदस्य चौटाला साहब बीमार हैं, स्वास्थ्य ठीक न होने के कारण वे सदन में नहीं आ सके। कई माननीय सदस्य ऐसे हैं जो अपनी बीमारी के कारण या किसी और वजह से सदन की कार्यवाही में पार्टीसिपेट नहीं कर पाये हैं दूसरे सदस्य जो बीमार हैं वे भी सदन में नहीं आ रहे हैं। इसलिए एक ही सदस्य के बारे में ऐसा कहना गलत बात है। (शोर)

श्री बीरेन्द्र सिंह : मैं आपकी बात पर सहमति जताता रहा क्योंकि तब वे अस्वस्थ थे हमने भी यह महसूस किया था लेकिन यह तो आप कहते हैं कि वे पब्लिक मीटिंग करते हैं और जनता में चार घण्टे तक अपना भाषण देते हैं। उन्हें एक बार तो ऐसा जोश आया कि उन्होंने स्ट्रैचर से उठकर कुर्सी पर बैठकर भाषण दिया। वे यहां पर भी कुर्सी पर बैठकर भाषण दे सकते थे। हम उनको यह नहीं कहते थे कि खड़े होकर बोलो।

डॉ० सुशील इन्दौरा : अध्यक्ष महोदय, सदन के माननीय सदस्य बीमार हैं इसलिए वे हाउस में नहीं आ सकते। इनके भी तो प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष बीमार हैं इसलिए वे सदन में नहीं आए हैं। इसलिए ऐसी बात करना ठीक नहीं है।

डॉ० सीता राम : अध्यक्ष महोदय, जो कांग्रेस पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष हैं वे भी सदन में नहीं आए हैं उनके बारे में आप बात क्यों नहीं करते?

Mr. Speaker : Don't interrupt. Please sit down.

श्री रणदीप सिंह सुरजेवाला : स्पीकर साहब, माननीय सदस्य अपनी आँखों का इलाज करवायें हमारी पार्टी के अध्यक्ष आज भी आये हुए थे और रोज आते हैं।

श्री बीरेन्द्र सिंह : हमने अपने घोषणा-पत्र में हरियाणा की जनता के सामने दो विकल्प छोड़ दिए। एक तो यह कि आप चौटाला का शासन-प्रशासन चाहते हो या पार्लियामेंटरी डैमोक्रेसी में विश्वास रखते हो। अपने घोषणा-पत्र के स्टारटिंग पैरा में हमने यह लिखा था। It is going to decided whether the State would lap into the total anarchy marked by local break-down by law and order, unmanageable crisis in agriculture, crisis in industry, education, health, employment and social harmony and other vital fields of socio-economic life of the State और एक बात यह कही थी कि आप किस किस्म का शासन चाहते हैं, किस किस्म की शासन पद्धति से आप गुजारा करना चाहते हैं। आप पिछड़ेपन को तरजीह देना चाहते हैं या फिर ऐसा राज्य चाहते हैं where it would emerge as a resurgent State rapidly marching to the prosperity and social harmony. स्पीकर सर, इस तरह के मुद्दों को लेकर हम हरियाणा की जनता के बीच में गये थे। उस समय जिस किस्म का मतदान हुआ वही एक वजह थी कि आज विपक्ष के लोग डिमोर्लाईज हो रहे हैं। आज इनकी पार्टी को टोटली रिस्ट्रक्चरिंग करने की जरूरत है। इनको चौटाला को छोड़कर कोई दूसरा लीडर छांट लेना चाहिए। वे या तो श्री सम्पत सिंह जी को छांट लें या फिर डॉ० सीता राम जी को छांट ले (शोर) जिस तरह की लीडरशिप चौटाला साहब ने इनकी पार्टी को दी है वह निरंकुश शासन और तानाशाही शासन पद्धति थी जिसके बारे में हम कुछ करते या न करते आज यह सवाल नहीं है क्या हरियाणा के लोग उस तरह के जालिम की सरकार को पांच साल बाद लाना चाहेंगे? एक भी हरियाणा का लोग इसका पक्षधर नहीं है (शोर) आप लोग सुनिये, यह बात मैं इसलिए कहता हूँ क्योंकि इनकी पार्टी ने चुनाव से पहले हरियाणा प्रदेश में एक सर्वे करवाया था और जिस एजेंसी ने यह सर्वे किया था वह एजेन्सी हमारी नहीं थी बल्कि वह एजेन्सी नेशनल इलैक्शन स्टैडी 2004 थी जिसने यह सर्वे किया था। वर्ष 2004 में एक स्टैडी हुई जिसमें पाया गया कि चौटाला के 45 प्रतिशत वर्कर यह मानते हैं कि उनके खिलाफ कोई भी बोल नहीं सकता। स्पीकर सर, ये लोग जो अब विपक्ष में बैठे हुए हैं इनको चौटाला नेता तो मानने नहीं देता। (विघ्न) Chautala's own party workers are of the view that under Chautala rule no one can

speak against him. (Interruptions).

श्री बलवंत सिंह : अध्यक्ष महोदय मेरा प्वायंट ऑफ ऑर्डर है। इनको चौटाला जी के एक छोटे से वर्कर ने ही चित कर दिया था। (विघ्न)

श्री बीरेन्द्र सिंह : अध्यक्ष महोदय, वर्कर ने चित नहीं किया था, इनकी झूठ ने चित किया था।

परिवहन मंत्री (श्री रणदीप सिंह सुरजेवाला): अध्यक्ष महोदय, मेरा भी प्वायंट ऑफ ऑर्डर है। ये छोटे से वर्कर की बात कर रहे हैं। लेकिन हमने इनके नेता को तीन–तीन बार चित किया है और इस बार भी किया है। (विघ्न) एक साल हो गया है इनके नेता की विधान सभा में आने की हिम्मत नहीं हुई है। (विघ्न) हमारे से चित होने के बाद इनके नेता में आज तक खड़े होने की हिम्मत नहीं हुई है।

श्री बीरेन्द्र सिंह : स्पीकर सर, मैंने भी इनके नेता को चित किया था क्या ये उस बात को भूल गये हैं। इसके अतिरिक्त हमारे मुख्यमंत्री महोदय ने चार बार उनके पिता चौधरी देवी लाल को चित किया था। (विघ्न) मैं तो इनको यही सलाह देता हूँ कि ये किसी भले आदमी को अपना नेता छांट लें। (विघ्न) मैं डरता नहीं, मैं यह महसूस करता हूँ कि जिस बेरहमी से प्रजातंत्र के सारे मूल्यों को, मर्यादाओं को ताक पर रखकर चौटाला ने साढे पांच साल राज चलाया उसको प्रदेश की जनता भूली नहीं है। उन्होंने प्रदेश के हालात ऐसे कर दिए हैं कि हमें संवारते–संवारते समय लगेगा। मैं यह कहता हूँ कि उस समय टोटल ब्यूरोक्रेसी में डीमोरलाईजेशन थी। यह कहां का प्रजातंत्र था कि कोई भी छुट्ट–भया अपने को नेता बताकर डी०सी० के आफिस में घुसकर अपने आप मोबाइल फोन मिलाकर डी०सी० को कहे कि लो भाई साहब से बात करो? जो अधिकारी थे उनके अंदर इन्होंने अपने राज के समय इन–सिक्योरिटी की भावना पैदा कर दी थी। जिसके परिणाम हमें आज भुगतने पड़ रहे हैं। यदि आप एक किस्म से प्रजातंत्र में अपनी कार्य प्रणाली को सुव्यवस्थित करके नहीं चलेंगे कि किसके क्या अधिकार हैं, क्या कर्तव्य हैं तो वह कार्य प्रणाली डूब जायेगी। इसलिए प्रजातांत्रिक कार्यप्रणाली में सभी के अधिकारों का बंटवारा करना बहुत जरूरी है लेकिन पिछली सरकार में ऐसा नहीं हुआ। यही कारण था कि जो अफसरशाही थी उसमें पूरे तौर पर दम नहीं था कि वे चौटाला के सामने कुछ बोल सकें। इन्दौरा जी ने तो बड़े सरल स्वभाव से यह कह दिया कि इनकी सरकार ने पिछली बार 40 प्रतिशत एनयुल प्लान में बढ़ा दिया था लेकिन इस बार केवल 8 प्रतिशत बढ़ाया है। अध्यक्ष महोदय, कभी इन्होंने अपने पांच साल का हिसाब देखा है? 1800 करोड़ रुपये से एनयुल प्लान की स्कीम इनकी शुरू हुई थी जिस समय ये सत्ता में आये थे और जब सत्ता से गये तो 2050 करोड़ रुपये पर बंद हुई थी। पांच साल में सिर्फ लगभग 200 करोड़ रुपये का इन्क्रीज हुआ था। अध्यक्ष महोदय, हमने तो एक साल के अंदर लगभग 1400 करोड़ रुपये का इन्क्रीज दिखाया है जो कि अपने आप में इतिहास है। यदि मेरे साथी तथ्यों की बात करते हैं तो इन्होंने अपने समय में तो प्रदेश में प्रगति के नाम पर कुछ नहीं किया। मैं तो यह कहता हूँ कि जिस समय हम सत्तासीन हुए हम यह समझते थे कि यदि हरियाणा के विकास की रफ्तार में तेजी नहीं आयेगी तो हम हरियाणा की जनता के साथ इंसाफ नहीं कर सकेंगे और हरियाणा की जनता ने जो मेनडेट हमें दिया है उस पर हम खरा नहीं उतरेंगे। हमारे जो पथ प्रदर्शक थे और जिस चीज को लेकर हम चले उसमें साफ था और चिदंबरम जी ने भी इस बार अपनी बजट स्पीच में कहा है कि—

"Growth will be our mount, equity will be our companion and civil justice will be our destination."

[श्री बीरेन्द्र सिंह]

इन चीजों को लेकर हम आगे बढ़े हैं और इन्हीं चीजों को अपना पैमाना मान कर हमने अपना बजट पेश किया है। इन्दौरा जी को मैं एक बात कहूँगा कि लोकमान्य तिलक, गोखले तथा महात्मा गांधी जी ने जो स्वतंत्रता की लड़ाई लड़ी थी तो उनका सबसे बड़ा निशाना यह था कि इस देश में कोई निरंकुश शासक न हो और यह देश प्रजातांत्रिक तरीके से चले। लेकिन जब-जब किसी ने इस प्रजातान्त्रिक ढांचे पर आक्षेप करने की कोशिश की, इस पर हमला करने की कोशिश की, इस देश की जनता ने उनको कभी बख्शा नहीं। यह कारण है कि हरियाणा की जनता के सामने आज मुखर होकर ये लोग यह नहीं कह सकते हैं कि इन्होंने लोगों के साथ इन्साफ किया होगा। कितने ही ऐसे लोग और राजनीतिक कार्यकर्त्ता मैं बता सकता हूँ जिनके विरुद्ध इन्होंने झूठे मुकद्दमे बनाए और धारा 120-बी का सहारा लेकर हर आदमी को फंसाने की कोशिश की। यहां पर कितने ही आदमी बैठे हुए हैं जिन्होंने इस प्रकार के मुकद्दमों का सामना किया है, आनन्द सिंह डांगी, तेजेन्द्र पाल सिंह मान और परली तरफ दो पंडित जी बैठे हुए हैं, वे ऐसे ही आदमी हैं। (विघ्न) अध्यक्ष महोदय, मैं एक बात कहना चाहता हूँ कि अगर द्वेष की भावना से अपने शासन में लोगों से पेश आते हैं तो यह प्रजातंत्र के लिए अच्छा लक्षण नहीं है। द्वेष भावना के कारण कितने ही ऐसे आदमियों के साथ इनकी सरकार द्वारा अन्याय किया गया। उन दिनों में एक कथा सुनने में आती थी क्योंकि लोगों को तंग करने के सैंकड़ों उदाहरण हैं। अध्यक्ष महोदय, यह आगे वाले दो एम०एल०ए० साहेबान हैं। यह तो पहले भी एम०एल०ए० थे। जब भी कभी चौटाला साहब से मिलना होता था तो ये चौटाला साहब से फोन पर पूछते थे कि मिलना है तो वे कहते थे कि चार बजे आ जाना। वे दफ्तर में बुलाते थे या घर पर बुलाते थे इसका तो मुझे पता नहीं। चार-पांच एम०एल०एज० को मिलने का टाईम दे दिया और उनसे 15 मिनट पहले हरियाणा के दस बड़े बदमाशों को टाईम दे दिया। (विघ्न) यह मनघड़ंत कहानी नहीं है। (विघ्न)

परिवहन मंत्री (श्री रणदीप सिंह सुरजेवाला) : अध्यक्ष महोदय, मैं माननीय वित्त मंत्री जी से अनुरोध करूंगा कि इनको वह समय याद न करवाएं क्योंकि इन दोनों को अभी भी कंपकंपी चढ़ती है। आप इन लोगों को देखिये सारे के सारे ऊपर से नीचे तक हिलने लग रहे हैं (विघ्न)

श्री बीरेन्द्र सिंह : अध्यक्ष महोदय, पता नहीं इनके साथ यह बीती या नहीं बीती लेकिन उनका एक मॉडस ऑफ एपरैंडिस था, एक तरीका था। अध्यक्ष महोदय, मैंने एक बहुत बड़े साधु को भी देखा है। हम भी एक दो बार वहां पर गए थे। वह भी ऐसा ही करता था। टाईम दे देता था और उससे पहले बड़े लोगों को बुला लेता था ताकि जो बाद में आए वह देखे कि यह तो बहुत बड़ा साधु है, इसके पास तो बड़ा माल है। इसके पास इतने बड़े-बड़े नेता आए हुए हैं। अध्यक्ष महोदय, इनके जो मुख्यमंत्री थे, वह 6-8 बदमाशों को बिठा कर उन एम०एल०एज० को दिखाते थे और फिर उनसे पूछते थे कि अब तूं उल्टे सीधे काम तो नहीं करता तो जवाब मिलता कि नहीं जी अब तो नहीं करता। वह फिर बदमाश से पूछते कि पहले कितने आदमी टपाए तो जवाब होता था कि 12 टपा दिए। (विघ्न)

मुख्यमंत्री (श्री भूपेन्द्र सिंह हुड्डा) : अध्यक्ष महोदय, जो यह बात बता रहे हैं यह उन दिनों आमतौर पर चलती थी। मैं एक जगह गया था तो मुझे कुछ आदमियों ने कहा कि हमारा विधायक पिट गया, मैंने कहा कि क्यों पिट गया, तुम लोग कहाँ थे ? वह तुम्हारा मुमाइंदा है इसलिए तुम्हारा फर्ज बनता है कि जिसे अपना मुमाइंदा चुना है अगर कहीं पर उसकी पिटाई होती है तो उस विधायक को बचाएं तो वे लोग बोले कि हम क्या करें अब तो वे जहाज में पीटते हैं। (हंसी) (शोर एवं व्यवधान)।

श्री आनन्द सिंह डांगी : डॉक्टर साहब, अन्दर से तो आप लोगों के भी यही बात आती है। (शोर एवं व्यवधान)

श्री अध्यक्ष : इन्दौरा जी, आपको अपनी बहादुरी की चर्चा सुनने के लिए बहादुरी चाहिए। आप इसको सुनने की बहादुरी दिखाएं। (शोर एवं व्यवधान) आपकी बहादुरी की तो बहुत चर्चाएं हैं। (शोर एवं व्यवधान)

श्रीमती अनीता यादव : अध्यक्ष महोदय, आपने भी इनके मोडे टूटे हुए प्रैक्टिली देखे हैं. (शोर एवं व्यवधान)

डॉ० सुशील इन्दौरा : आप यह बताएं कि एमरजैंसी किसने लगाई थी, कौन एमरजैंसी लगाने वाला था? आप भी उसमें शामिल थे।

श्री धर्मपाल सिंह मलिक : अध्यक्ष महोदय, मैं भी आपके माध्यम से सदन में एक वाक्या बताना चाहूँगा। (शोर एवं व्यवधान)

श्री आनन्द सिंह डांगी : अध्यक्ष महोदय, डॉक्टर इन्दौरा को एनिस्थीसिया का इन्जैक्शन लगवायें। (शोर एवं व्यवधान) इन्दौरा जी, अपनी बहादुरी सुनने की हिम्मत रखें। (शोर एवं व्यवधान)

श्री धर्मपाल सिंह मलिक : अध्यक्ष महोदय, मैं जो एक बात बताना चाहता हूँ उसके बारे में डांगी साहब भी जानते हैं। पिछले राज में इनके साथ हमारा एक भाई था, उसका एक हाथ टूटा हुआ था, वह मुझे मिल गया। मैंने उससे पूछा कि भाई साहब यह क्या हो गया? तो उसने कहा कि हाथ टूट गया है। मैंने उससे कहा कि मैंने सुना है चौटाला के लड़के ने यह हाथ तोड़ा है तो उन्होंने यह जवाब दिया कि मैंने भी यही सुना है। (हंसी)

श्री बीरेन्द्र सिंह : अध्यक्ष महोदय, मेरे कहने का अभिप्राय यह है कि हरियाणा की जनता कभी ऐसे आदमियों को जिन्होंने प्रजातन्त्र का गला घोटा हो, जिन्होंने आम आदमी से अपनी जिंदगी जीने का हक भी छीन लिया हो, माफ नहीं करती है। अध्यक्ष महोदय, हमने अपने इलैक्शन के मैनिफैस्टों में कोई ऐसे वायदे नहीं किए थे जो पूरे न हों। हमारा मुद्दा वही था जिस बारे में आम आदमी सोचता था। इनके राज में आम आदमी के जीने पर ही प्रश्न चिह्न लग गया था। वह सोचता था कि आज वह घर से जाएगा तो पता नहीं सही सलामत शाम को घर पर भी आ पाएगा या नहीं। अध्यक्ष महोदय, ऐसे प्रशासन पर से, ऐसी शासन पद्धति पर से, ऐसे मुख्यमंत्री पर से और ऐसी पार्टी पर आम आदमी का विश्वास उठ गया था। इसलिए आम आदमी ऐसी पार्टी को वोट देना भी पाप समझता था। (शोर एवं व्यवधान) अध्यक्ष महोदय, मुलाना साहब ने एक शेर कहा था। मैं भी वही कहता हूँ कि चौटाला साहब से और इनके लोगों से जनता को नाराजगी नहीं थी बल्कि नफरत थी नफरत। हमसे उनको नाराजगी हो सकती है नफरत नहीं हो सकती है। कांग्रेस पार्टी हमेशा गरीबों की साथी रही है। (शोर एवं व्यवधान) मैं यह कहता हूं कि आप इस बात के लिए सपने न लो कि आप लोगों को ज्यादा देर तक गुमराह कर सकते हो। (शोर एवं व्यवधान) अध्यक्ष महोदय, एक छोटे से बच्चे ने कहा है कि आपने राजनीति में झूठ कहा है। मैं तो यह कहता हूं कि जो भी राजनीति में झूठ कहते हैं या अपने घोषणा पत्र में झूठे वायदे करते हैं उनको बाद में जनता की मार तो सहनी ही पड़ती है। उन्होंने कहा था कि हम सत्ता में आएंगे तो बिजली मुफ्त देंगे। (शोर एवं व्यवधान) मैं इनसे पूछता हूँ कि इन्होंने अपने घोषणा में क्या कहा था। इन्होंने इनकी सरकार बनने के बाद भी झूठ बोला। (शोर एवं

[श्री बीरेन्द्र सिंह]

व्यवधान) क्यों बोला था कि हम बिजली मुफ्त देंगे और बिजली के बिल माफ कर देंगे। (शोर एवं व्यवधान) इनैलो की पार्टी ने बहुत झूठ बोला है। मैं भी मुलाना साहब की तरह एक शेर सुना देता हूँ।

रात को दिन से मिलाने की हवस थी उसको,
रात को दिन से मिलाने की हवस थी उसको,
काम अच्छा न था, अन्जाम भी अच्छा न हुआ।

(शोर एवं व्यवधान) पिछली सरकार के कार्यकाल का इतना बुरा होगा कि आने वाली पीढ़िया भी इनको माफ नहीं करेंगी। (शोर एवं व्यवधान) इन्होंने 12 लाख लोगों को सड़क पर छोड़ दिया था, बेरोजगार के अंधकार में डाल दिया था। (शोर एवं व्यवधान)

डॉ० सुशील इन्दौरा : अध्यक्ष महोदय, वित्तमंत्री जी बजट पर रिप्लाई दे रहें हैं या छींटाकसी कर रहे हैं। हम यहां पर यह सब सुनने के लिए नहीं आए हैं। **(इस समय इण्डियन नैशनल लोकदल के सभी सदस्य बिना इजाजत के बोलने के लिए खड़े हो गए।**

परिवहन मंत्री (श्री रणदीप सिंह सुरजेवाला) : अध्यक्ष महोदय, जब कोई दूसरा सदस्य बोल रहा हो तो इन्दौरा जी हर एक सैकेन्ड के बाद इन्ट्रप्ट करने के लिए खड़े हो जाते हैं। जब ये बोल रहे थे इनको किसी ने इन्ट्रप्ट नहीं किया था। अब वित्तमंत्री जी अपना रिप्लाई दे रहें हैं तो इनको आराम से बैठकर उनको सुनना चाहिए। (शोर एवं व्यवधान) अब ये बिना बात के ही खड़े होकर बोलने लग जाते हैं। (शोर एवं व्यवधान) अध्यक्ष महोदय, इनके बिहेवियर से ऐसा लगता है कि ये वाक-आउट करेंगे। इनके पास बोलने के लिए तो कुछ नहीं है और इनमें सुनने की हिम्मत भी नहीं है। (शोर एवं व्यवधान)

श्री बलवन्त सिंह : * * * * * * *

डॉ० सीता राम : * * * * * *

डॉ० सुशील इन्दौरा : * * * * * * *

श्री अध्यक्ष : ये जो भी बोल रहे हैं वह कुछ भी रिकॉर्ड नहीं किया जाए।

वाक आउट

डॉ० सुशील इन्दौरा : अध्यक्ष महोदय, वित्तमंत्री और दूसरे मंत्री हमारी पार्टी के नेता और हमारी पार्टी के खिलाफ छींटाकशी कर रहे हैं। इसलिए हम सदन से वाकआउट कर रहे हैं।

(इस समय इण्डियन नैशनल लोक दल के सदन में उपस्थित सभी सदस्य सदन से वाक आउट कर गए।)

परिवहन मंत्री (श्री रणदीप सिंह सुरजेवाला) : स्पीकर सर, इनको जल्दी से कान पकड़कर माफी मांगनी चाहिए। अभी इनको मुर्गा भी बनना चाहिए। स्पीकर सर, जिस तरह से स्कूल के बच्चे पीछे की दीवार को टापकर भाग जाते हैं वैसा ही ये कर रहे हैं। ये वैसे ही नालायक बच्चों में से हैं जिन्होंने पढ़ना नहीं है, सुनना नहीं है।

---

* चेयर के आदेशानुसार रिकॉर्ड नहीं किया गया।

वर्ष 2006-2007 के बजट अनुमानों पर सामान्य चर्चा (पुनरारम्भ)

Mr. Speaker : Finance Minister Sahib, please continue.

श्री बीरेन्द्र सिंह : स्पीकर सर, मेरे कहने का सिर्फ एक ही अभिप्राय है कि अब वह जमाना लद गया जब डंडे से, निरंकुशता से, अधिनायकवाद से कोई सत्ता में रहने के लिए अपने आपको सक्षम समझेगा। अब जनता उसको पसन्द करेगी जो जनहित के काम करेगा और जनता से जुड़कर रहेगा। अगर हम भी जनता से नहीं जुड़ेंगे तो हमको भी लोग रिजैक्ट कर सकते हैं। हमारे को भी इस बात की कोई गलतफहमी नहीं है लेकिन वह आदमी जो एक साल से इस सदन में पेश नहीं हुआ, उस समय इस कुर्सी पर बैठकर यह कहता था कि मैं तो अब सत्ता से जाऊंगा नहीं, सत्ता तो मेरे नाम हो चुकी है लेकिन हरियाणा की जनता ने उसका सत्ता का सर्टीफिकेट फाड़कर उसको असैम्बली से बाहर कर दिया। हालात यह है कि जिस तरह से हरियाणा को उन लोगों ने लूटा है वह देखने वाली बात है। स्पीकर सर, चालीस एकड़ जमीन का मालिक हो और उसकी बाउंडरी वाल पर सवा तीन करोड़ रुपये का खर्चा हो तो क्या यह सही है ? (विघ्न) चलो, 40 नहीं 42 एकड़ होगी, तीस एकड़ होगी। स्पीकर सर, मेरे पास 65-70 एकड़ जमीन है लेकिन मैं तो तीन करोड़ रुपये घर पर नहीं लगा सकता, चार दीवारी की तो बात ही क्या है। आज जो लाखों करोड़ों रुपये उन्होंने हरियाणा की जनता से लूटे हैं उसका हिसाब जनता उनसे मांगती है और मांगती रहेगी। जब तक जनता को हिसाब नहीं मिलेगा तब तक वह ऐसे लोगों को दोबारा शासन की बागडोर नहीं सौंप सकते। अगर वे ख्वाब देखते हैं तो देखें। लेकिन ऐसे लोगों को जनता रिजैक्ट कर चुकी है। स्पीकर सर, उन्होंने जिस तरह से हरियाणा में अपराध की जड़ें गहरी कर दी वह बहुत गलत बात थी और आज यहां पर इन्होंने बोल दिया कि कैथल में यह हो गया वह हो गया। आज ये चिट्ठा लिए फिरते हैं। मैं कहता हूँ कि सबसे बड़ा अपराधी अगर कोई है तो वे हैं जिन्होंने अपराध को हरियाणा में शह दी और अपराध के बीज हरियाणा में बोये। मुझे खुद पता है कि 1984-85 का इलैक्शन था उस समय सबसे ज्यादा उत्तर प्रदेश से कट्टे लाकर जिनका हम नाम तक नहीं जानते थे, हजारों की संख्या में नौजवान लड़कों के हाथों में थमा दिए गए और हालात यहां तक बिगड़े कि आज जब हरियाणा के बारे में बात करते हैं तो उत्तर प्रदेश के लोग भी यह कहते हैं कि अब तो अपराधों में हरियाणा भी कम नहीं है। स्पीकर सर, ये लोग इन अपराधियों के जननी हैं। हमने तो यह करके दिखा दिया है और मैं आज भरे सदन में यह कहता हूँ कि अगर कोई अपराधिक प्रवृत्ति का आदमी किसी भी राजनीतिक लोगों के साथ जो सत्तासीन हैं, उठता या बैठता है तो हम यह कहेंगे कि हमने अपने फर्ज में कोताही की है। स्पीकर सर, हमने पूरे तौर पर जिनको संरक्षण मिलता था, उनको ऐलानिया तौर पर यह कहा है कि अब हरियाणा में आपके लिए कोई जगह नहीं है, हरियाणा में अब अपराध नाम की चीज के लिए कोई जगह नहीं है इसलिए सबसे बड़ी कामयाबी अगर हमारी सरकार की एक साल की अगर कोई है तो वह यही है कि हमने लोगों के दिमाग में से उस भय के वातावरण को निकाला है जो उन्होंने बना दिया था। उस समय ऐसा वातावरण बना दिया गया था जिसमें लोगों को अपनी जिंदगी जीने का हक नहीं था। हमने उस वातावरण को खत्म किया है। जो भी अपराधिक प्रवृत्ति के लोग थे उनके खिलाफ हमारी सरकार ने सख्त कार्यवाही करने का काम किया है। यही नहीं महाराष्ट्र में बोम्बे के अंदर आप देखिए। Maharashtra Assembly has passed a resolution in this regard and that resolution is about 14 years old. Whenever there is a change of party that resolution is always followed. Whether Government is of Congress or coalition Government of Shiv Shiv Government with BJP that resolution is adopted. The resolution is that the administration would fight it out and would ensure that

[श्री बीरेन्द्र सिंह]

there should not be any underworld activities. हमारी तो यह भावना है। ये इस भावना को मानें या न मानें। हमारी यही भावना हरियाणा में विकास से बड़ी प्राथमिकता है। हमारी प्राथमिकता लोगों को सुरक्षा देने की, गरीब आदमी को सुरक्षा देने की, उनकी झोंपड़ी बचाने की, उनके मकान बचाने की, दुकानें बचाने की और जमीनें बचाने की भी है। पहली सरकार का निशाना होता था कि किसी दुकान पर कब्जा करें, किसी जमीन पर कब्जा करें। किस तरीके से उन्होंने गुड़गांव में जाकर लूट मचाई, फरीदाबाद में जाकर लूट मचाई। मैंने खुद देखा था। मैं हैरान रह गया। एक बार रात को मुझे पानीपत रुकना पड़ा। मैं टी०वी० पर एक सीरियल देखता था जब सीरियल का टाईम हुआ और मैंने टी०वी० ऑन किया तो मुझे एक बार ऐसा लगा कि यह सीरियल तो मैंने कल देखा है यह ऐपीसोड आज कैसे? जब अगले दिन मैंने पता किया तो पता चला कि यहां ऐसा ही होता है एक दिन पहले सीरियल की रिकार्डिंग होती है और अगले दिन उसको टेलीकास्ट करते हैं क्योंकि केबल का कंट्रोल यहां के गुण्डों के हाथ में है वे दूसरे किसी आदमी को अलाऊ इसके लिए नहीं करते। जहां पब्लिक के अधिकारों का इतना हनन हो कि टेलीविजन पर भी लोग अपने प्रोग्राम नहीं दिखा सकें तो आप अंदाजा लगा सकते हैं कि उस समय हालात क्या होंगे? लोगों ने ऐसे राज को आज रिजैक्ट किया है और इसलिए रिजैक्ट किया है कि वे लौटकर दोबारा नहीं आ सकते। अपराधिक दुनिया में आज यह मैसेज गया है कि अब हरियाणा प्रदेश में अपराधियों के लिए कोई जगह नहीं होगी। लेकिन मैं एक बात जरूर कहूँगा कि यहां पर उनकी जड़ें जम गई थी। आज यह शुक्र है कि पांच साल बाद उन लोगों को जाना पड़ा। अगर उनको और ज्यादा लम्बा समय मिल जाता तो हरियाणा प्रदेश में अपराधियों और गैंग्स्टर्ज के जो आरगेनाईजड क्राईम हैं वे हरियाणा में शुरू हो जाते। उस स्थिति से हम बचे हुए हैं। आज हमारे पुलिस के अधिकारियों ने जो कदम उठाये हैं वे सराहनीय हैं। लेकिन फिर भी ऐसे अपराधों की पुनरावृत्ति हो तो मैं यह मानकर चलता हूँ कि कहीं न कहीं हमारी कड़ी में कोई लूजनैस है कहीं कड़ी में जरूर गड़बड़ है। इस बात को हम समझते हैं और हमारा कर्त्तव्य है कि हम उसको देखें और इसको ठीक करें। बजट के बारे में मेरे काबिल दोस्त और हाउस के मैम्बर्ज साहेबान ने अनेक सुझाव दिए और अनेक प्रश्न भी उठाये हैं। उन्होंने पहला प्रश्न बजट के बारे में उठाया। माननीय इन्दौरा साहब जो इनैलो पार्टी के डिप्टी लीडर हैं, उन्होंने वैट के बारे में कहा कि वैट के हम पायनियर हैं क्योंकि वैट तो हमारी सरकार ने शुरू किया था। मैं उनको यह कहता हूँ कि जब वर्ष 1991 में केन्द्र में कांग्रेस पार्टी की सरकार बनी थी और श्री मनमोहन सिंह जी उस समय वित्त मंत्री थे तब उन्होंने इन सुधारों का क्रम शुरू किया था और उस क्रम के ही आज ये रिजल्टस आ रहे हैं क्योंकि सुधार और रिफोर्म्ज के रिजल्ट एक दो साल में नजर नहीं आ सकते उसमें कुछ समय लगता है। (विघ्न)

बैठक का समय बढ़ाना

Mr. Speaker : Is it the sense of the House that the time of the House be extended for half an hour.

Voices : Yes, Yes.

Mr. Speaker : Time of the House is extended for half an hour.

वर्ष 2006-2007 के बजट अनुमानों पर सामान्य चर्चा (पुनरारम्भ)

श्री बीरेन्द्र सिंह : स्पीकर सर, जब हरियाणा में चौटाला सरकार ने वैट को लागू किया तो हमने यह कहा था कि हम वैट लागू करने के लिए विरोध नहीं करते लेकिन हम यह जरूर चाहेंगे कि इस सिस्टम को यूनिफोर्मली लागू किया जाए। जब दूसरी सरकारें अपने प्रदेशों में इस सिस्टम को लागू करें तभी हरियाणा सरकार इसको लागू करे क्योंकि तभी इसके अच्छे परिणाम आ सकते हैं। लेकिन जिस तरीके से मिस डायरेक्टिड और एक खास कम्यूनिटी को, खास प्रोफैशन को निशाना बना कर वैट हरियाणा में पिछली सरकार ने लागू करने की जो कुचेष्टा की थी तो उसका हमने जरूर विरोध किया। लेकिन मैं यह भी कहता हूँ कि वैट से हमारी सरकार के अच्छे परिणाम आये हैं पिछले दो साल में पिछली सरकार का राज था और तीसरा साल हमारा था। जो इन्क्रीज हमें मिलनी चाहिए थी वह नहीं मिली। पंजाब ने इन्ट्रोडयूस किया उनको 27 प्रतिशत इन्क्रीज मिली है और इनके राज में हमें 22 प्रतिशत से अधिक इन्क्रीज नहीं मिली। माननीय सदस्य डॉक्टर सीता राम जी कह रहे थे कि हमारी तो रैवेन्यू कलैक्शन में और एक्साईज में 16 प्रतिशत की इन्क्रीज है। स्पीकर सर, मैं इनको बताना चाहता हूँ कि अबकी बार हमारा टार्गेट 5600 करोड़ रुपये से बढ़ाकर 6900 करोड़ रुपये का था जो 1300 करोड़ रुपये बनता है। हमने यह टार्गेट प्राप्त किया है और 660 करोड़ रुपये उससे अधिक कलैक्ट किया है। स्पीकर सर, हम जब प्लानिंग कमीशन के पास गये उन्होंने कहा कि हरियाणा का जो टैक्स कलैक्शन है, फिसकल मैनेजमैंट है, वह प्लानिंग कमीशन के हिसाब से सही है। अगर हरियाणा के प्लान आऊट ले को ज्यादा भी बढ़ायें तो कोई अतिश्योक्ति नहीं होगी। इसलिए उन्होंने हमारी 3059 करोड़ रुपये की प्लान आऊट-ले को बढ़ाकर 3300 करोड़ रुपये से भी ज्यादा किया है। अध्यक्ष महोदय, जो 10वीं फाईव ईयर प्लान है उसमें 12000 करोड़ रुपये का जो लक्ष्य पांच साल का था, उसको अगर हमारी सरकार नहीं आती तो हम पूरा नहीं कर पाते। अध्यक्ष महोदय, मैं इनकी फिगर्ज बताना चाहता हूँ। ये हमारे ऊपर आक्षेप लगाते हैं कि अब की बार एनुअल प्लान में हमारी 8 प्रतिशत की इन्क्रीज है। आप अंदाजा लगायें कि इन्होंने 1779 करोड़ रुपये से अपनी पहली एनुअल प्लान शुरू की थी और लास्ट 2058 करोड़ रुपये पर खत्म की थी। जबकि हमारी एनुअल प्लान के बारे में ये बातें करते हैं। हमारे साथी के०एल० शर्मा जी ने ठीक कहा था कि ओलम्पिक के अंदर या राष्ट्रीय स्तर पर कोई खिलाड़ी 22 फीट लॉंग जम्प करके कीर्तिमान स्थापित करता है तो यह नहीं हो सकता कि अगले साल वह खिलाड़ी 28 फीट लॉंग जम्प लगा देगा। वह 22 फीट से साढ़े 22 फीट या 23 फीट कूद सकता है। इन महानुभावों की प्लान यूटीलाईजेशन एक साल को छोड़कर कभी भी 90% या 91% से ज्यादा नहीं रही जबकि हमने अब की बार अपने एनुअल प्लान के टार्गेट अचीव किए हैं और उसके बाद 3300 करोड़ रुपये का अपना प्लान मंजूर करवाया है। एक बात मेरे साथियों ने और कही थी कि हमारा नॉन प्लान एक्सपैंडीचर बढ़ा है शायद डॉक्टर सीताराम और डॉक्टर इन्दौरा जी कह रहे थे। अध्यक्ष महोदय, आप भी यह एप्रीशियट करेंगे कि पहले जो कैपीटल असैट्स थे, हमारा इन्फ्रास्ट्रक्चर था, कहीं मिनी सक्रेटेरिट हैं, कहीं मिनी होस्पिटल हैं या कहीं स्कूल हैं, उनकी मेनटीनैंस के लिए पिछली सरकार के समय में बजट में जो पैसा रखा जाता था वह उनकी सफेदी करने लायक नहीं होता था लेकिन हमने उसमें बढ़ौतरी की है। बढौतरी इसलिए की है कि हमारे जो कैपीटल असैट्स हैं, हमारा जो इन्फ्रास्ट्रक्चर है उनकी maintenance is not only thing, it should be strengthen also. Strengthen in the sense कि अगर कोई बिल्डिंग 50 साल के लिए बनाई है तो उसका रख-रखाव ऐसा हो कि उसकी उम्र बढ़कर 60 साल तक पहुंचे। लेकिन इन्होंने इस मद की तरफ कभी ध्यान

[श्री बीरेन्द्र सिंह]

नहीं दिया। स्पीकर सर, यह ठीक है कि नॉन प्लान एक्सपेंडीचर जब बढ़ता है तो वह चिंता का विषय है। लेकिन मैं इसको चिंता का विषय नहीं मानता। मैं कोई अर्थशास्त्री नहीं हूँ लेकिन मैं एक बात समझता हूँ कि बहुत सी ऐसी चीजें हैं जिन्हें हम अब तक प्लान में लेकर बैठे हुए हैं। जैसे 500 करोड़ की बुढ़ापा पैंशन हम प्लान से खर्चते हैं, मैं कहता हूँ कि this should be the part of non-plan expenditure. प्लान पर हम वह काम करें जिससे प्रोडैक्टिविटी हो और असैट्स क्रिएट हो सकें। जो इन्होंने कहा कि नॉन प्लान एक्सपैंडीचर बहुत बढ़ा है मैं कहना चाहूँगा कि जो 12वीं फाईनैंस कमीशन के मापदण्ड हैं उनको मद्देनजर रखते हुए हमारा जो फिसकल डैफीसिट है which is less then 3 percent i.e. 2.6% which is very much within the limit of the prescribed norms of the 12th Finance Commission. सर, एक इन्होंने यह कहा कि सबसिडी खत्म कर दी गई है। There is no much increase in the subsidy. सर, पिछले साल 1392 करोड़ रुपये की सबसिडी हमने दी थी और इन्होंने कहा कि सबसिडी कम कर दी है। अब की बार हमारी सबसिडी 1547 करोड़ रुपये है क्योंकि हमने अब की बार पावर सैक्टर में जो सबसिडी देनी थी या गांवों में रहने वाले लोगों के 1600 करोड़ रुपये बिजली के बिलों के मुआफ किए थे वह सारा भार हमारे ऊपर पड़ा, वह भी हमने इस मद के अन्दर रखा है। स्पीकर सर, दूसरी बात यह है कि जैसे इन्दौरा जी ने कहा है कि गवर्नमैंट का जो डैब्ट है, सरकार पर जो कर्जा है वह इन्क्रीज हुआ है। सर, इनके टाइम में जो बजट था वह 11-12 हजार करोड़ रुपये का होता था और हमारे टाइम में अगर वह बजट 18 हजार करोड़ रुपये होगा तो उसी परपोरशन से कुछ न कुछ तो हमारा डैब्ट का बर्डन बढ़ता है। लेकिन मैं फिर भी यह कह रहा हूँ कि जो डैब्ट का बर्डन हमारे ऊपर है that is with in the limit. जो प्रिस्क्राईब्ड लिमिट्स हैं हमने उनको क्रॉस नहीं किया है। जैसे कि बताया गया है कि जो टोटल जी०डी०पी० है the qantum of debt may be viewed with regard to the State GDP. In fact our debt liability has declined from 37.16% in 2003-04 to 31.99% in 2005-06. Actually, there is a decline but still we are to come down as far as debt liability is concerned और सर, एक बड़ा अजीब सा सवाल इन्होंने उठाया है, एक दो और मैम्बर्ज ने भी इसका जिक्र किया है कि इनके राज में सिर्फ 51 किलोमीटर सड़क बनी। सर, मेरे पास अभी दो महीने की फिगर्ज अवेलेबल नहीं हैं लेकिन दो महीने पहले तक जो हमने सड़कों की इम्प्रूवमैंट की है वह 3213 किलोमीटर है और 62 किलोमीटर की सड़क दो महीने में और बन चुकी हैं। हमारा जो ऐजैण्डा है उसके हिसाब से 31 तारीख तक जो रिपोर्ट आएगी उसमें यह और भी बढ़ी हुई मिलेगी। अध्यक्ष महोदय, इसके साथ ही साथ एक साथी ने यह कहा कि इनकी सड़कों का जो बजट है वह कम दिया गया है। एक दो और साथियों ने भी यह बात कही और डॉक्टर इन्दौरा साहब ने भी यह बात कही। सर, मैं आपको बताना चाहूँगा कि 2006-07 में हमारी जो बजट एलोकेशन थी वह 210 करोड़ रुपये प्लान साईड में थी और नॉन प्लान साईड में 67.17 करोड़ रुपये थी। सर, इसके अलावा जो हमारे बजट का हिस्सा नहीं है उनमें नॉन प्लान, सैन्ट्रल रोड फण्ड, प्राईम मिनिस्टर ग्रामीण सड़क योजना है और नैशनल हाईवे ऐन्ट्रस्टिड टू पी०डब्ल्यू०डी० ये तीन ऐजैंसिज which does not form the part of Budget. इसमें भी हमारे को वहाँ से पिछले साल 160 करोड़ रुपये मिले हैं और अब जो भारत निर्माण की योजना है उसमें मैंने पहले भी बताया था कि इसके तहत हमें वहाँ से 725 करोड़ रुपये से ज्यादा मिलेंगे। जो हरियाणा की सरकार का वर्ष 2020 का विजन है। The first Department, which may be far ahead of the time, would be the PWD (B&R), as far as roads connectivity is concerned. इनका यह कहना है कि हमें इसमें कम पैसा मिला है यह निरर्थक बात है। हमने इस साल में इस हैड में जो पैसा जुटाया है वह पिछले

साल से ज्यादा है। इन्होंने अनइम्पलाईड गारन्टी स्कीम की बात कही है। अध्यक्ष महोदय, हरियाणा में मिनिमम वेजिज 100 रुपये है जबकि गवर्नमैंट ऑफ इण्डिया की इन्स्ट्रक्शन के मुताबिक 90 रुपये प्रतिदिन मिनिमम वेजिज के तहत मिलेंगे। इसके अलावा हरियाणा में एग्रीकल्चर लेबर को लेटेस्ट रिवाईज के अनुसार 95 रुपये समथिंग मिलेंगे। इनका यह कहना कि इनको 90 रुपये के हिसाब से मिलेंगे, यह गलत है। अध्यक्ष महोदय, सबको पता है कि हरियाणा में सीवरेज बिछाने के लिए अभी दो जिले ही लिए गए हैं। आने वाले तीन सालों के समय में जब भारत के 600 के 600 जिले कवर हो जाएंगे तब हरियाणा के सभी जिले भी उसमें कवर हो जाएंगे। अध्यक्ष महोदय, यह जो देश में रूरल इम्पलाईमैंट गारण्टी ऐक्ट आया है, यह सिर्फ श्रीमती सोनिया गाँधी जी की सोच का हिस्सा है। इस एक्ट के माध्यम से हमने आज के नौजवानों को बेरोजगारी वाली रट से बाहर निकालना है। जब यह एक्ट पूरी तरह से देश में लागू हो जाएगा तब इस एक्ट के माध्यम से 1 लाख 60 हजार करोड़ रुपये देश के दूरदराज क्षेत्रों के नौजवानों के हाथों में आ जाएगा और तब हमारे नौजवान कहेंगे कि हाँ, हम काम करना चाहते हैं and we are ready for any manual work. The State Government would be duty bound to provide them the jobs. If the Government would not be capable to provide them jobs then hundred days unemployment allowance should be given to that particular person. सर, मैं यह कहना चाहूँगा कि ये बहुत ही रैवोल्यूशनरी कदम है। सर, आज देश की जो सम्पदा है, धन है, लिक्विडिटी है वह चंद हाथों में घूम कर रह गयी है। इस स्कीम के माध्यम से उस धन का कुछ हिस्सा देश की जनता के हाथों में आ जाएगा। इसके साथ महोदय, मैं यह कहना चाहूँगा कि नई एक्साईज पालिसी आने के बाद रैवेन्यू में 16.75 करोड़ रुपये की इन्क्रीज आई है। ये कहते हैं कि यह इन्क्रीज इसलिए है क्योंकि शराब के ठेकेदारों का 33 प्रतिशत कोटा बढ़ा दिया गया है। यह बिल्कुल निराधार बात है। हमें यह इन्क्रीज कोटा बढ़ाने से नहीं मिली है। इस बारे में अध्यक्ष महोदय, मैं बताना चाहता हूँ कि इनके राज में एक सिस्टम था, जो शराब की दुकानें बेची जाती थीं, वह सिर्फ 5 या 6 बड़े लोगों को या ज्यादातर इनके रिश्तेदार या मिलने वालों को ही दी जाती थी। आप चाहें तो इस बारे में पिछले पांच साल का रिकार्ड उठाकर देख लें। इस वजह से इनके समय में 3 या 4 प्रतिशत से ज्यादा की इन्क्रीज रैवेन्यू में नहीं हुई थी।

उद्योग मंत्री (श्री लक्ष्मण दास अरोड़ा) : अध्यक्ष महोदय, मैं आपके माध्यम से सदन में बताना चाहूँगा कि दो साल पहले सारा हरियाणा बिल्लू के पास था।

श्री बीरेन्द्र सिंह : यह बिल्लू कौन था?

श्री लक्ष्मण दास अरोड़ा : अध्यक्ष महोदय, 2 साल पहले चौटाला के लड़के के पास सारे हरियाणा के ठेके थे।

श्री बीरेन्द्र सिंह : हमने तो उस मोनोपोली को तोड़ा है। स्पीकर सर, मैंने जैसे पहले बात कही कि वे क्रिमनल को या गैंगस्टर को तो हरियाणा में नहीं बना सके क्योंकि लोगों की भावनाओं के मुताबिक वोट के जोर से वह तोड़ दिया गया लेकिन लीकर माफिया जरूर बनाने में वे कामयाब हो गये परन्तु उसको भी हमने तोड़ा है और डंके की चोट पर तोड़ा है। मैं इस बारे में मुख्यमंत्री जी के लिए भी यह कहूंगा कि इनका बहुत बड़ा दिल है वरना तो ये ठेकेदार तो इन तक भी पहुंच गए होते। ये लोग हर जगह पहुंच जाते हैं। मुझे तो पता नहीं कि कौन पोंटी चड्ढा है या उसका क्या पूरा नाम है? लेकिन अगर वह पोंटी चड्ढा भी होगा तो अब तो ये हजारों की संख्या में होंगे और इसमें हमें कोई ऐतराज भी

[श्री बीरेन्द्र सिंह]

नहीं है क्योंकि एक-एक बैंड पर कम से कम दस लोगों को रोजगार मिलता है। अगर ये चार से ज्यादा दुकानें होंगी तो इस तरह से हरियाणा के चालीस हजार आदमियों को काम मिलेगा। पहले तो सब कुछ एक ही हाथ में होता था और कुछ लोग ही डिस्ट्रिक्ट बांट लेते थे। किसी को पांच जिले चले जाते थे किसी को 6 जिले चले जाते थे और इसके बाद ये लोग राजनीति में हस्तक्षेप करते थे। स्पीकर सर, हम जानते हैं कि किस प्रकार से इनका हस्तक्षेप तीखा होता था और किस प्रकार से वे एम०एल०एज० और मंत्रियों को एप्रोच करके मनमानी करने की कोशिश करते थे। लेकिन ऐसे कारटल को तोड़ने के लिए मुख्यमंत्री जी की भूमिका की सारे सदन को सराहना करनी चाहिए।

श्री लक्ष्मण दास अरोड़ा : स्पीकर सर, मैं एक बात सबमिट करना चाहूँगा। मुझे एक मिसाल याद आ गयी। चौटाला साहब जींद रैस्ट हाउस में बैठे थे। उनके साथ उनके दस बारह एम०एल०एज० भी बैठे हुए थे। वहां प्रैस वाले आकर कहने लगे कि चौटाला साहब आप कब अपनी कैबिनेट में एक्सपैंशन कर रहे हो। वे कहने लगे कि मैं तो ईब कर दूँ लेकिन कोई मंत्री बनना ही नहीं चाहता। प्रैस वाले कहने लगे कैसे? चौटाला साहब बोले, भाई इन्दौरा तूं बनना चाहवे के, डॉ० तू बनना चाहवे के, वे कहन लागे ना जी, मैं तो पहले ही मुख्यमंत्री हूँ, मैं मंत्री क्यों बनूं। वे जिसको भी पूछे वही कहने लगे न जी, मैं तो पहले ही मंत्री हूँ। वहां पर एक प्रैस वाला बोल पड़ा और बोला कि जी मेरे को एक बात याद आ गयी कि एक बार बादशाह अकबर को किसी ने कह दिया कि बकरी कभी भी धापती नहीं है हर रोज खाए ही जाती है और मिंगन करे जाती है। वह अकबर से बोला कि बकरी धपाकर दिखा दो। बादशाह अकबर ने ऐलान कर दिया कि जो बकरी को धपाएगा उसको मैं ईनाम दूँगा। सब कहने लगे कि यह तो मामूली सी बात है। कई लोग बकरी को ले गए और दो दिन रखने के बाद ले आए लेकिन बकरी धापे न। सब लोग तंग आ गए कि बकरी धापती नहीं है। अकबर ने इसके बाद बीरबल से कहा कि तू यह काम कर। बीरबल बोला कि मैं तो धपाऊँगा जी। बीरबल बकरी को ले गया और जाकर एक हरी घास मंगाकर बकरी के आगे डाल दी। बकरी जब मुँह मारने लगी तो उसके मुँह पर डंडा मारा। थोड़ी देर बाद उसने फिर घास उसके नजदीक कर दी बकरी फिर मुँह मारने लगी लेकिन उसने फिर डंडा मारा। मतलब चार पाँच बार उसने ऐसा ही किया फिर तो बकरी घास से डरने लगी। जब दो दिन के बाद उसने देखा कि अब यह बकरी घास नहीं खाएगी तो बीरबल बादशाह सलामत से बोला कि बादशाह सलामत मैं इस बकरी को धपा लाया हूँ। अकबर बोला कि लाओ भई घास लाओ। बहुत बढ़िया घास लाई गयी और बकरी के आगे रखी गयी। बकरी पीछे हट ले। लोग बकरी को खींचकर आगे करें लेकिन बकरी पीछे हटती ही जाए। तो इसी तरह से इनके एम०एल०एज० कहने लगे कि हम मंत्री नहीं बनना चाहते।

श्री बीरेन्द्र सिंह : स्पीकर सर, दूसरा इन्होंने आब्जैक्शन यह किया है कि जो सैंट्रली स्पोंसर्ड स्कीम्ज हैं या जो बड़े प्रोजैक्ट्स हैं वह हम अपने राज्य में लाने में नाकामयाब रहे हैं। स्पीकर सर, मैं इस बारे में ज्यादा बात नहीं करूँगा क्योंकि मुख्यमंत्री जी ने अपनी इंटरवैंशन करके उस वक्त बता दिया था कि कौन-कौन से ऐसे प्रोजैक्ट्स हैं जो हमें ऑफर तो हुए हों और हमने छोड़ दिए हों। हरेक प्रोजैक्ट हम लेकर आए हैं। बहुत बड़े-बड़े प्रोजैक्ट हैं हजारों की संख्या में बच्चों को रोजगार भी उनके माध्यम से मिलेगा। श्री रामकुमार गौतम जी ने एक सवाल उठाया कि हैल्थ के बजट में ऐलोकेशन कम की है। मैं उनको यह बताना चाहता हूँ कि हैल्थ के बजट में ऐलोकेशन पिछले साल 102 करोड़ रुपये थी जो हमने बढ़ाकर 114 करोड़ कर दी है, यह ऐलोकेशन प्लान साईड की है। इसके अलावा जो टोटल

नॉन-प्लान का और प्लान का साईज है वह भी बहुत बढ़ा है। अब यह 565 करोड़ रुपये है जबकि पिछले साल यह सिर्फ 474 करोड़ रुपये था। इसमें आप यह अंदाजा लगाएं कि कम से कम इसमें 100 करोड़ रुपये का इन्क्रीज किया गया है। इसके साथ-साथ मैं इनको यह भी बताना चाहूँगा कि जो दूसरी स्कीम्ज हैं जैसे टी०बी० रेडीकेशन की स्कीम और ऐड्ज कंट्रोल प्रोग्राम हैं, या जो सैण्ट्रली स्पोंसर्ड प्रोग्राम हैं उनके लिये बजट से अलग हमें कुल 27-28 करोड़ रुपया मिलता है। इसके अलावा जो आर०सी०एच०-2 स्कीम है उसके लिए हमें 350 करोड़ से ज्यादा पैसा मिलता है जोकि इस बजट का हिस्सा नहीं बनता। यह सारा पैसा भारत सरकार से आता है। जो सारी तनख्वाहें भी दी जाती हैं और दूसरे खर्चे भी किए जाते हैं तो वह सब इस स्कीम के तहत ही होते हैं। इसमें सारा पैसा भारत सरकार का होता है। हैल्थ से संबंधित जो प्रोग्राम हैं उनको हम प्राथमिकता के आधार पर लेकर चल रहे हैं जैसा कि स्वास्थ्य मंत्री महोदया जी ने कहा कि जहां-जहां रिमोट ऐरिया है, जहां पर हम पूरा इन्फ्रास्ट्रक्चर क्रिएट करने में फिलहाल कामयाब नहीं होते, वहां पर हम यह इन्श्योर करेंगे कि वहां पर मोबाईल होस्पिटल के माध्यम से हर आदमी तक स्वास्थ्य सुविधा को पहुँचाया जाए। ऐसी जगहों पर दवाई, डॉक्टर और जरूरी इलाज के लिए इस मोबाईल होस्पिटल को हम जरूर पहुँचाएंगे। इसी प्रकार से जो डिलीवरी हट्स की स्कीम है वह बहुत पापुलर हो रही है। पिछले 35 साल से जब से मैंने इस हाउस में आना शुरु किया है तब से मैं एक ही बात कहता आ रहा हूँ लेकिन मेरी बात जब भी कोई नहीं मानता था और आज भी कोई नहीं मानता। वह बात यह है कि मैं यह कहता हूँ कि डॉक्टर्ज जो हैं इनके दो कॉडर बना देने चाहिएं। एक कॉडर तो ऐसा हो जो रूरल कॉडर हो और जिन्होंने केवल रूरल एरिया में ही अपनी सर्विस करनी होगी। जब इनकी भर्ती के लिए एडवर्टाइजमैंट दी जाए तो कहा जाए कि यह टोटली रूरल कॉडर है जिसको लगना है तो लगो, आपकी मर्जी है। इसी प्रकार से रूरल कॉडर की जो नर्स, पैरा मेडिकल स्टाफ और डॉक्टर हैं, they should be employed for rural areas and there should be another cadre for urban areas. अगर ऐसा कोई प्रवधान कर दें तो अच्छा रहेगा। लेकिन ऐसा नहीं हो रहा है। मुझे अफसोस के साथ कहना पड़ता है कि पहले ऐसा होता रहा है कि 6-6 डॉक्टर एक सी०एच०सी० के दूसरी जगह शहरों में काम करते थे कोई करनाल में, कोई पानीपत में, कोई अम्बाला के अस्पताल में और वे तनख्वाह लेते थे किसी गाँव की पी०एच०सी० से या सी०एच०सी० से। गरीब आदमी और गाँव के लोगों के साथ इससे बड़ा मजाक और क्या हो सकता है? हमने इस पर रोक लगाई है। ऐसी जो प्रैक्टिस चल रही है वह यह सरकार चलने नहीं देगी। जो डॉक्टर गाँव में एप्वांट किया जाता है तो उसको गाँव में ही काम करना पड़ेगा। स्पीकर सर, श्री रणबीर सिंह महेन्द्रा जी ने एक्साईज पोलिसी के बारे में एक सवाल उठाया था कि पंजाब में और चण्डीगढ़ में लिकर पर एक्साईज ड्यूटी कम है जबकि वहां पर वैट लागू है और हमारे यहां वैट से यह एग्जैम्पट है। इसके लिए मैं माननीय सदस्य को बताना चाहता हूँ कि सरकार ने जो नई एक्साईज पोलिसी बनाई है उसमें हमने कण्ट्री लिकर पर एक्साईज ड्यूटी 13 रुपये से घटाकर 5 रुपये कर दी है और जो अंग्रेजी शराब है उस पर एक्साईज ड्यूटी 43 रुपये से घटाकर 25 रुपये कर दी है। हमने एक्साईज ड्यूटी घटाई है लेकिन फिर भी हमें इससे ज्यादा एक्साईज का पैसा मिलेगा, ऐसा हमारा अनुमान है। स्पीकर सर, बहुत से माननीय सदस्यों ने बिजली के बारे में अनेकों सवाल उठाये। इसके बारे में यही जवाब तो माननीय श्री विनोद शर्मा जो बिजली मंत्री हैं, वे डिटेल में बता सकते थे लेकिन मैं भी इसके बारे में माननीय सदस्यों को बताना चाहता हूँ। श्री नरेश मलिक जी ने बिजली के अनुबन्ध के बारे में सवाल उठाया, उसकी चर्चा मैं जरूर करना चाहूँगा। स्पीकर सर, मैं यह बताना चाहता हूँ कि हरियाणा प्रदेश में दो तरह के बिजली के संयंत्र लगे हुए हैं। एक तो वे हैं जो सरकारी संस्थानों द्वारा लगाये जाते हैं और दूसरे

[श्री बीरेन्द्र सिंह]

वे हैं जो प्राईवेट सैक्टर द्वारा लगाये जाते हैं जिनमें पैसा भी उन्हीं का होता है। सरकार तो उनको सिर्फ सुविधाएं ही देती है जैसे उनको जमीन दिलवाने में मदद करना या क्लीयरैंस में मदद करना आदि। फिर भी इस बजट में हमने 465 करोड़ रुपये का प्रावधान किया है कि अगर कहीं इक्विटी में हमें पार्टिसिपेशन करना पड़ेगा तो हम करेंगे। 465 करोड़ रुपये का मतलब यह है कि यदि किसी 2000 करोड़ रुपये के प्लांट में हमें पार्टिसिपेशन करना पड़ा तो हम 20 प्रतिशत हिस्से के साथ इक्विटी पार्टिसिपेशन कर सकते हैं। अध्यक्ष महोदय, फरीदाबाद के 1000 मेगावाट के गैस बेस्ड थर्मल पावर प्लांट के बारे में किसी साथी ने पूछा था कि इस पर क्या कार्यवाही चल रही है। इस बारे में मैं बताना चाहूँगा कि इस प्लांट के लिए जमीन उपलब्ध करवा दी गई है और गैस का भी अरेंज हो गया है। यह चर्चा सुनने में आई थी कि कोई कह रहा है कि गैस की कमी है। मैं बताना चाहूँगा कि gas is being arranged. गेल कंपनी के साथ हमारा एग्रीमैंट हुआ है जिसमें उन्होंने एश्योर किया है कि वे गैस उपलब्ध करवायेंगे। स्पीकर सर, भाई नरेश यादव ने भी एक प्रश्न उठाया था कि इस प्लांट की बिजली दूसरे प्रदेशों में चली जायेगी।

बैठक का समय बढ़ाना

Mr. Speaker : Is it the sense of the House that the time of the House be extended for half an hour.

Voices : Yes, Yes.

Mr. Speaker : Time of the House is extended by half an hour.

वर्ष 2006-07 के बजट अनुमानों पर सामान्य चर्चा (पुनरारम्भ)

Shri Birender Singh : Who will bye-pass from the private sector? स्पीकर सर, इसमें बड़ा स्पष्ट है कि प्राईवेट सैक्टर में जो भी प्लांट लगेगा उसकी 30 प्रतिशत बिजली प्रदेश से बाहर भेजी जा सकती है और बाकी की 70 प्रतिशत बिजली प्रदेश के लिए एवेलेबल होगी। यदि हमारे प्रदेश में 1000 मेगावाट का कोई प्लांट लगेगा तो 700 मेगावाट बिजली हरियाणा के लिए एवेलेबल होगी और 300 मेगावाट बिजली वे दूसरे प्रदेशों को दे सकते हैं। इसके अतिरिक्त मैं बताना चाहूँगा कि यमुनानगर का थर्मल पावर प्लांट मार्च, 2008 तक तैयार हो जाएगा जिससे प्रदेश को 600 मेगावाट बिजली मिलेगी। इसके अतिरिक्त जो कोल बेस्ड थर्मल प्लांट हिसार में लगाना है उसका इनीशियल वर्क शुरू हो गया है। यह जो हमारा प्रोजैक्ट है it is in the pipe line. उस पर भी हम जल्दी ही काम

11.00 बजे

करना शुरू कर देंगे। दिसम्बर, 2009 में इसकी फंक्शनिंग और प्रोडक्शन शुरू हो जाएगी। सर, इसके साथ ही साथ जैसा मैंने बताया कि गेल से हमारा समझौता हुआ है और उनसे फेसिलिटेट करने के लिए we have to help them to obtain land and water etc. जो प्राईवेट सैक्टर में लगेंगे। सर, इसके अलावा उनके ट्रांसमीशन का जो नैटवर्क है आगे बिजली देने के लिए और बिजली बेचने के लिए, वह भी स्टेट प्रोवाईड करेगी। सर, इसके अलावा मैं एक बात और कहना चाहूँगा कि VAT के अंदर कोई 76 के करीब हमारी आईटम्ज थीं। इसके बारे में विभिन्न ऐसोसियेशन्ज, ट्रेड ऐसोसियेशन्ज और मैन्यूफैक्चरर्ज ऐसोसियेशन्ज ने यह दलील देकर कहा है कि जो हमारी नेबरिंग स्टेट्स हैं उनका टैक्स परसैंटेज कम है जबकि हमारा टैक्स परसैंटेज ज्यादा है इसलिए हमें भी नेबरिंग स्टेटस के बराबर करें ताकि हम अपना व्यापार कम्पीटीशन बनाये रख सकें और हमें

कोई नुकसान न हो। सर, इसके हिसाब से 76 में से 20 आईटम्ज का फैसला हमारी सरकार कर चुकी है हालांकि इन आईटम्ज पर टैक्स परसैंटेज कम करने की वजह से हमारी सरकार को 84 करोड़ रुपये का रैवेन्यू लॉस होगा लेकिन क्योंकि ट्रेडज और मैन्यूफैक्चरर्ज की इस बात को भांपते हुए और इस बात को सोचते हुए कि उन्हें दूसरी स्टेट्स से कम्पीटीशन करना है हमने उनको यह छूट दी है। कई आईटम्ज पर जीरो परसैंट टैक्स लगता है और कई आईटम्ज पर साढ़े बारह परसैंट से चार परसैंट पर यह टैक्स ला दिया गया है। अगल-अलग से उन आईटम्ज के नाम हैं। जैसे एन्टरटेनमैंट टैक्स है इससे हमें फिलहाल छः करोड़ रुपये का नुकसान होगा। हमें ओरिजिनली जो इस वक्त ऐंटरटेनमैंट टैक्स से मिलता है वह 16 करोड़ रुपये के करीब है लेकिन हम समझते हैं कि 20 करोड़ रुपये अगले तीन साल के अंदर इससे हम अर्जित करने लग जाएंगे। क्योंकि इस टैक्स के कारण सिनेमा उद्योग एक किस्म से हरियाणा में बैठ गया था। इसके साथ जो मल्टीपलैक्स और दूसरे अदायरे वाले हमसे मिलने आये थे उनका भी यह तर्क था कि अगर यह टैक्स ऐज इट इज रहा तो हम दिल्ली के मुकाबले में कम्पीट नहीं कर पाएंगे। खासतौर से गुड़गांव के मल्टीपलैक्स। उनका कहना था कि अगर ऐन्टरटेनमैंट टैक्स अथवा ड्यूटी इतनी ही रखी जाएगी तो हम उनका मुकाबला नहीं कर सकेंगे। अध्यक्ष महोदय, इन सारी चीजों को मद्देनजर रखते हुए ही हमने यह फैसला किया था। स्पीकर सर, इसके अलावा फर्टिलाइजर हैं उन पर भी हमने यह टैक्स जीरों परसैंट पर रखा है। ऐम्पावर्ड कमेटी ने हमें कहा था कि आप फर्टिलाईजर पर 4% वैट लगाएं। फर्टिलाईजर्ज पर वह टैक्स न लगाने की वजह से हमें 60 करोड़ रुपये का नुकसान है लेकिन हम वह नुकसान बर्दाश्त करेंगे क्योंकि किसान के लिए यह जरूरी है और यह हमारी स्टेट का रॉ मैटीरियल है। हमने इस नुकसान वाली बात की परवाह नहीं की और कहा कि हम यह टैक्स नहीं लगाएंगे। इसी प्रकार से 12 परसैंट डीजल पर टैक्स है। दिल्ली ने हमें कहा था कि डीजल पर 20 परसैंट टैक्स लागू करें ताकि यूनिफोर्मिटी हो लेकिन हमने ऐसा नहीं किया और दिल्ली ने हमारी नकल करके फिर अपना टैक्स 12 परसैंट पर कर दिया। इससे हमारी स्टेट को 400 करोड़ रुपये का नुकसान है। इन दो आईटम्ज से 460 करोड़ रुपये हमें बजट में कम मिलेंगे लेकिन यह किसान के लिए जरूरी है कि हम उसको डीजल सस्ता दें उसको खाद हम सस्ती दें इसलिए 450-460 करोड़ रुपये का नुकसान हमारा राज्य बर्दाश्त करेगा, हमारी सरकार बर्दाश्त करेगी। लेकिन हमने किसान के ऊपर कोई अतिरिक्त भार नहीं डाला है। इस प्रकार से 84 करोड़ रुपये मिलाकर 550 करोड़ रुपये के करीब कन्सैशन हमने वैट लगाने के बाद दिए हैं। इन कन्सैशन के बारे में चौटाला सरकार ने कभी सोचा भी नहीं था क्योंकि इनकी इच्छा यह नहीं थी। वे तो व्यापारियों को भी खत्म करने की कोशिश करते थे। उन्होंने तो इण्डस्ट्रीज के पलायन के लिए भी इन्तजाम कर दिया था। वह उद्योगपतियों से कहते थे कि या तो पैसा दीजिए या हरियाणा छोड़कर चले जाइये। स्पीकर सर, एक दूसरी बात और कही गई कि ग्रान्ट-इन-ऐड हमने अब की बार कम दी है या यह कहें कि ग्रान्ट ऑफ हैड में इसका पैसा कम है। इसमें मैं आपको याद दिलाना चाहता हूँ कि इन्होंने प्राईमरी स्कूल्ज को जिला परिषद में ट्रांसफर कर दिए थे लेकिन अब हमने उसको दोबारा से सरकार के नीचे लिया है। तो इस तरह से जब उन्होंने इसका फैसला कर दिया था तो 45 करोड़ रुपये ग्रान्ट-इन-ऐड देते थे। हमें जिला परिषद में इस पैसे की जरूरत नहीं क्योंकि अगर यह पैसा हम अपने खजाने से देंगे तो एण्टायरली ग्रान्ट-इन-ऐड में वह पैसा कम आएगा। इसी प्रकार से 1984 के दंगों के जो विक्टिम्ज थे उनके लिए पिछले साल हमने 6 करोड़ 75 लाख रुपये रखे थे और सभी विक्टिम्ज को अदायगी हम कर चुके हैं इसलिए इस साल उसकी जरूरत नहीं है इसलिए वह ग्रान्ट-इन-ऐड भी इसमें कम हो गई है। इसलिए यह कहना कि ग्रान्ट-इन-ऐड कम हुई यह बिल्कुल गलत बात है। जिन जगहों पर पैसे की जरूरत नहीं थी उन मदों से हमने वह

[श्री बीरेन्द्र सिंह]

पैसा विदड्रॉ कर लिया है। स्पीकर सर, हमारा जो सबसे इम्पोर्टेन्ट सैक्टर है उसके बारे में भी इनैलो के साथियों ने कहा कि जो एस०सीज० और बी०सीज० या जो वीकर सैक्शन्ज के लिए सोशल सैक्टर में हमारा बजट है उसके हैड में भी पैसा कम रखा गया है। मैं बताना चाहूँगा कि 2005-06 में इस मद में 737 करोड़ रुपये रखे गए हैं। अब इस बार 2006-07 में इस हैड में 811 करोड़ रुपये का प्रावधान किया गया है। इसके साथ स्पीकर सर, हरियाणा सरकार ने केन्द्र सरकार को एक वूमैन सैनेटरी कम्पलैक्स एंड इन्डवीज्वल हाऊस होल्डज लैटरीन की पोलिसी बनाकर भेजी है। जिसके लिए भारत सरकार से 239 करोड़ रुपये की मांग की गई है। इस पोलिसी के तहत हरियाणा में साढ़े पाँच लाख इन्डवीज्वल टायलैट बनाए जाएंगे। अध्यक्ष महोदय, जहां पर गरीब लोग और महिलाएं रहती हैं और जिनको बाहर टायलैट जाने में दिक्कत होती है उनको यह सुविधा बड़े स्तर पर दी जाएगी। इस काम के लिये पहले पंचायतों को 30 हजार रुपये देने पड़ते थे लेकिन अब हमने इसको हटा लिया है क्योंकि अब सारे का सारा पैसा सरकार की तरफ से ही दिया जाएगा। अब पंचायतों को इसके लिए पैसा देने की कोई जरूरत नहीं है इन्डवीज्वल टॉयलैट्स के लिए अभी तक हमने 1 लाख 78 हजार रुपये दिए हैं। 1 लाख 42 हजार रुपये कम्यूनिटी कम्पलैक्सीज के लिए दिए हुए हैं। केन्द्र सरकार से 239 करोड़ रुपये इस योजना के तहत आने के बाद गाँवों के गरीब तबके को बहुत सहूलियतें मिलेंगी। जब हमने चुनाव से पहले गाँवों में जाते थे तब भी लोगों की यही मांग होती थी। इसलिए हमने बड़े स्तर पर स्कीम बनाकर केन्द्र सरकार को भेजी है। अध्यक्ष महोदय, दादूपुर नलवी के बारे में इरीगेशन मिनिस्टर साहब बता चुके हैं कि इस साल इस पर काम शुरू हो जाएगा। अध्यक्ष महोदय, यह हमारी प्राथमिकता का क्षेत्र है और इस पर किसी को ज्यादा चिन्ता करने की जरूरत नहीं है। हां, इसमें एक बात जरूर हुई कि जब हमने इस स्कीम के लिए रेट तय किए थे तब से लेकर आज के बीच में इस प्रोजैक्ट के रेट बहुत बढ़ गए हैं लेकिन हम इसको मैनेज करेंगे। हम इन रेट्स को कम करवाने की कोशिश करेंगे। अध्यक्ष महोदय, मैं सदन में आपके माध्यम से बताना चाहूँगा कि 40 साल में पहली बार हमने किशाऊ, लखवार व्यासी और रेणुका डैम का मुद्दा केन्द्र सरकार के साथ उठाया है और मुख्यमंत्री जी ने प्रधानमंत्री जी से बड़ी सख्ती से इस मामले को टेकअप किया है। अध्यक्ष महोदय, सदन के नेता ने सदन में कहा है कि आज तक लोग एस०वाई०एल० कैनाल को राजनीतिक मुद्दा बनाकर उसका फायदा उठाते रहे हैं। खासकर चौधरी देवी लाल और ओम प्रकाश चौटाला की पार्टी के लोग इसका फायदा उठाते रहे हैं। ये लोग लोगों को गलत रास्ते में डालने में कामयाब रहे हैं। मैं तो यह कहता हूँ कि जिस किस्म की राजनीति वे करते हैं उस राजनीति से यह समस्या हल नहीं हो सकती है। चौटाला साहब स्वस्थ होने पर या बीमार होने पर जब भी चण्डीगढ़ आते हैं तो बादल की कोठी में ठहरते हैं और फिर गाँव जाकर कहते हैं कि मर जाओ, मार दो। वे एस०वाई०एव० कैनाल के लिए न्याय के युद्ध की बात करते हैं। वे एस०वाई०एल० कैनाल से अपना लाभ अर्जित करने की बात करते हैं और दोस्ती उन लोगों से करते हैं जो एस०वाई०एल० कैनाल बनाने के विरोधी हैं। अध्यक्ष महोदय, हमें एस०वाई०एल० कैनाल के मुद्दे को एक अच्छे माहौल में हल करना चाहिए। एस०वाई०एल० कैनाल की वजह से हमारी पंजाब से दूरियां बन गई हैं लेकिन अब इन दूरियों को पाटने की बात है। पाकिस्तान से तो पंजाब और देश रिश्ते सुधारने की बात करें और हरियाणा एवं पंजाब के रिश्ते न सुधरें तो मैं इस चीज का हामी नहीं हूँ। इसलिए मैं समझता हूँ कि अगर अच्छे माहौल में बात हो तो इसमें कोई बुराई भी नहीं है क्योंकि उनको भी पता है कि आखिरकार इनका हिस्सा है। पंजाब इस बात को समझता है कि हमारा हिस्सा उसको देना पड़ेगा। स्पीकर सर, इन लोगों ने इस मुद्दे को पोलिटिसाइज करके

हमेशा राजनीतिक वैपन के तौर पर इस्तेमाल किया है लेकिन हरियाणा की जनता जान चुकी है और अब वह इनके बहकावे में आने वाली नहीं है। स्पीकर सर, इसके साथ ही मैं रेणुका, लखवार-व्यासी और किशाऊ डैम के बारे में बताना चाहता हूँ।

श्री राम कुमार गौतम : बीरेन्द्र सिंह जी, अगर दोनों सरकारों के आपस में विचार मिल जाएं फिर तो यह अच्छी बात है। आपको आगे बढ़ना चाहिए।

श्री बीरेन्द्र सिंह : स्पीकर सर, मैंने यह शुरुआत ही इसलिए की थी कि जो ट्रैंड है उसको रिवर्स करने की जरूरत है। जो एक घृणा का वातावरण है या दुश्मनी का वातावरण है उस चीज को हमको खत्म करना पड़ेगा। अगर हम ऐसा वातावरण तैयार नहीं करेंगे तो ये लोग हमेशा इस मुद्दे को गलत रास्ते पर डालते रहेंगे। लेकिन अब हमें उम्मीद है कि सुप्रीम कोर्ट का निर्णय आने के बाद हमारी यह नहर भी बनेगी और हमारा शेयर भी हमें मिलेगा। श्री शमशेर सिंह जी यहां बैठे हैं ये बहुत सीनियर मैम्बर हैं और ये कई साल तक इरीगेशन मिनिस्टर भी रहे हैं इसलिए इस बारे में इनको सारा पता है। कैप्टन अजय सिंह ने भी पिछले एक साल से इस बात को काफी ग्रोस्ट करने की कोशिश की है, समझने की कोशिश की है। अकेले यमुना के अंदर ही इतना पानी है कि राउंड दी ईयर अगर इस पानी को रेगुलेट किया जाए तो हमें साढ़े बारह हजार क्यूसिक पानी मिल सकता है। जो किसी न किसी तरीके से एस०वाई०एल० कैनाल से मिलने वाला पानी है, उससे वह ज्यादा ही पानी है। इसके साथ ही जो दो या ढाई महीने यमुना का पानी बेकार जाता है उसकी तरफ भी हमें ध्यान देना पड़ेगा। जैसे इरीगेशन मिनिस्टर ने कहा और हमारी चर्चा भी हुई तथा मुख्यमंत्री जी को इस बात का ध्यान भी है कि जो ऐरिड एरियाज हैं जिनको रेतीले इलाके बोलते हैं वहां अगर स्ट्रांग वाटर को हम एक बार कृष्णावती, दोहान या साहबी जैसी नदियों में डालने का कोई बड़ा प्रोजैक्ट बना दें तो साऊथ हरियाणा की सारी की सारी तस्वीर बदल सकती है। स्पीकर सर, आप अगर हमारे घोषणा पत्र को पढ़ोगे, मुख्यमंत्री जी की प्रोनाउंसमैंट को पढ़ोगे या कैबिनेट ने एवं इरीगेशन मिनिस्टर ने जो आज तक फैसले किए हैं तो वह उसी निशाने पर रखकर लिए हैं। हरियाणा के एक तिहाई हिस्से को जिसको पिछले 35 सालों से पूरा पानी नहीं मिला है, अगर उसको पूरा पानी मिलेगा तो वहां पर भी ग्रीन रैवोल्यूशनरी आएगी। इस तरह की भावना के साथ हमने काम किया है। स्पीकर सर, मैं तो आपको यही कहूँगा कि यह जो बजट है इसमें 65 करोड़ रुपये का हमने घाटा दर्शाया है। आप इस बात को एप्रीशिएट करोगे कि हमने 900 करोड़ रुपये के करीब रैवेन्यू डैफीशिट अनुमानित किया था लेकिन अब इसको भी हमने 600 करोड़ रुपये और घटा दिया है। पिछले साल के मुकाबले हमारा रैवेन्यू डैफीशिट कम हुआ है। बेहतरीन प्रबन्धन की वजह से यह हमें रिजल्ट मिले हैं। स्पीकर सर, मैं आपको यह कह सकता हूँ कि हरियाणा का जो वित्तीय प्रबन्धन है और हरियाणा का जो टैक्स कलैक्शन है वह बहुत ही अच्छा है। हमने आज हरियाणा में डैट कंट्रोल किया है। अब हमने कर्जे वर्जे लेने बंद कर दिए हैं। हमने तो यहां तक कहा है कि जो हमारी बड़ी-बड़ी संस्थाएं हैं जैसे हुडा या एच०एस०आई०डी०सी० है या पावर यूटिलिटीज है, वह अपनी गारन्टी अपने आप लें। अब हरियाणा सरकार इनकी गारंटी लेने के लिए तैयार नहीं है क्योंकि इनकी वित्तीय स्थिति अच्छी है और उनको मार्कीट से कितना ही पैसा मिल सकता है। हमने हर चीज पर कंट्रोल किया है। मैं इस बात पर गर्व महसूस करता हूँ कि आज हरियाणा की वित्तीय स्थिति बहुत अच्छी है। चौटाला साहब जाते-जाते 800 करोड़ रुपये का जो बोझ हमारे ऊपर डाल कर गये थे वह हमने झेला है। हमने 1300 करोड़ रुपये बढ़ाकर दिया और उसमें 650 करोड़ रुपये की और इन्क्रीज दिखाई है। उसके बाद जो हमने वित्तीय प्रबन्ध किया तो मैं यह कह सकता हूँ कि Haryana is economically most vibrant State in the country and you all should proud of it. यह

[श्री बीरेन्द्र सिंह]

हमारी सबसे बड़ी एचीवमैंट है। हमारी पर कैपिटा इन्कम भी बढ़ी है (शोर) इसके अलावा सारे हरियाणा में जो हमारे लाखों की संख्या में कर्मचारी हैं, अधिकारी हैं जिन्होंने सरकार को अच्छा सहयोग दिया है But there are certain aberrations. आपने देखा होगा कि पंजाब की विधान सभा में ब्यूरोक्रैसी के आचरण के बारे में पूरे एक दिन बहस चली और सारा सदन इस बारे में एक मत था। हमारी ब्यूरोक्रैसी उस हिसाब से बहुत अच्छी है लेकिन फिर भी पिछले 40 साल में दुर्भाग्यपूर्ण स्थिति यह रही कि मुख्यमंत्रियों ने अपने-अपने ग्रुप बनाने शुरू कर दिए जिससे प्रदेश का नुकसान हुआ और ब्यूरोक्रैसी की जो ऐफीशिएंशी है, वह भी कम हुई है। मैं तो यह कहता हूँ कि हमने इस हिसाब से नहीं सोचा। जब से इस सरकार ने सत्ता संभाली है हम यह समझते हैं कि हमारे हर ब्यूरोक्रैट को हम पर भरोसा होना चाहिए और हमें उन पर पूरा भरोसा होना चाहिए ताकि राज्य में जो बढ़ते हुए विकास के कदम हैं किसी वजह से, किसी कारणवश या किसी अच्छे-बुरे हिसाब से वे कदम हमारे धीमे न पड़ें इसलिए जैसा मैंने शुरू में कहा कि हमें गर्व इस बात का है that today we have better system, we have better governance and we have better employees. हमारी सरकार की नीयत, हमारे मुख्यमंत्री जी की नीयत और इस हाउस की नीयत भी राज्य को लोकतान्त्रिक तरीके से आगे बढ़ाने की है। भविष्य के लिए हम आपको और हरियाणा की जनता को यह यकीन दिला सकते हैं कि विकास के कामों के लिए एक-एक पैसा चाहे कहीं से भी हमें लाना पड़े, हम पैसा जुटायेंगे। हुडा हो, एच०एस०आई०डी०सी० हो, या मार्केटिंग बोर्ड हो, ये एजेन्सियां जो साल में एक हजार करोड़ रुपये बजट से अलग हमारे इन्फ्रास्ट्रक्चर के लिए खर्च करती हैं वह छोटी उपलब्धि नहीं है। इसलिए जहां तक विकास की बात है, विकास के परमानैंट एसैट्स हम पैदा कर सकें, ऐसा स्ट्रैक्चर, ऐसे रोड्ज़ हम बना सकें जिनके 10-10 साल टूटने की कोई गुंजाइश न हो तो अच्छा रहेगा। पिछली सरकार के समय ऐसा होता था कि आगे-आगे सड़क बनती जाती थी और पीछे-पीछे टूटती जाती थी क्योंकि उसमें भ्रष्टाचार था। जगह-जगह अपने आदमियों को तरजीह देने के लिए, अपने आदमियों को ठेके देने के लिए, कान्ट्रैक्ट देने के लिए पिछली सरकार के समय उन्होंने सारे सिस्टम को ही गड़बड़ कर रखा हुआ था और सारे सिस्टम में भ्रष्टाचार किया हुआ था। लेकिन हमने एक नई शुरुआत की है। स्पीकर सर, पिछले साल की जो हमारी प्राथमिकताएं थीं, उनको लेकर हम आगे बढ़ रहे हैं। मैं सभी सदस्यों से प्रार्थना करूंगा कि इस बजट को सर्वसम्मति से पास कर दिया जाए। धन्यवाद।

वर्ष 2005-2006 के बजट अनुदानों की मांगों पर चर्चा तथा मतदान

Mr. Speaker : Hon'ble Members, now discussion and voting on supplementary estimates for the year 2005-2006 will take place.

As per the past practice and in order to save the time of the House, the demands on the order paper (1, 2, 6, 7, 9, 13, to 16 and 21 to 25 will be deemed to have been read and moved together. Hon'ble Members can discuss any demand but they are requested to indicate the demand No. on which they wish to raise discussion.

That a Supplementary sum not exceeding **Rs. 2,26,07,000/-** for revenue expenditure be granted to the Governor to defray charges that will come in the course of payment for the year ending 31st

March, 2006 in respect of Demand No. 1-**Vidhan Sabha.**

That a Supplementary sum not exceeding **Rs. 3,35,78,000/-** for revenue expenditure be granted to the Governor to defray charges that will come in the course of payment for the year ending 31st March, 2006 in respect of Demand No. 2-**General Administration.**

That a Supplementary sum not exceeding **Rs. 1,000/-** for revenue expenditure be granted to the Governor to defray charges that will come in the course of payment for the year ending 31st March, 2006 in respect of Demand No. 6-**Finance.**

That a Supplementary sum not exceeding **Rs. 22,36,68,000/-** for revenue expenditure be granted to the Governor to defray charges that will come in the course of payment for the year ending 31st March, 2006 in respect of Demand No. 7-**Other Administrative Services.**

That a Supplementary sum not exceeding **Rs. 44,36,02,000/-** for revenue expenditure be granted to the Governor to defray charges that will come in the course of payment for the year ending 31st March, 2006 in respect of Demand No. 9-**Education.**

That a Supplementary sum not exceeding **Rs. 123,95,11,000/-** for revenue expenditure be granted to the Governor to defray charges that will come in the course of payment for the year ending 31st March, 2006 in respect of Demand No. 13-**Social Welfare & Rehabilitation.**

That a Supplementary sum not exceeding **Rs. 17,91,000/-** for revenue expenditure and **Rs. 25,67,05,000/-** for capital expenditure be granted to the Governor to defray charges that will come in the course of payment for the year ending 31st March, 2006 in respect of Demand No. 14-**Food & Supplies.**

That a Supplementary sum not exceeding **Rs. 136,04,00,000/-** for revenue expenditure and **Rs. 1,000/-** for capital expenditure be granted to the Governor to defray charges that will come in the course of payment for the year ending 31st March, 2006 in respect of Demand No. 15-**Irrigation.**

That a Supplementary sum not exceeding **Rs. 65,18,97,000/-** for revenue expenditure and **Rs. 2,01,70,000/-** for capital expenditure be granted to the Governor to defray charges that will come in the course of payment for the year ending 31st March, 2006 in respect of Demand No. 16-**Industries.**

That a Supplementary sum not exceeding **Rs. 130,94,60,000/-** for revenue expenditure be granted to the Governor to defray charges that will come in the course of payment for the year ending 31st March, 2006 in respect of Demand No. 21-**Community Development.**

[Mr. Speaker]

That a Supplementary sum not exceeding **Rs. 10,53,86,000/-** for capital expenditure be granted to the Governor to defray charges that will come in the course of payment for the year ending 31st March, 2006 in respect of Demand No. 22-**Co-operation.**

That a Supplementary sum not exceeding **Rs. 27,46,48,000/-** for revenue expenditure and **Rs. 1,70,00,000/-** for capital expenditure be granted to the Governor to defray charges that will come in the course of payment for the year ending 31st March, 2006 in respect of Demand No. 23-**Transport.**

That a Supplementary sum not exceeding **Rs. 17,28,000/-** for revenue expenditure and **Rs. 3,00,00,000/-** for capital expenditure be granted to the Governor to defray charges that will come in the course of payment for the year ending 31st March, 2006 in respect of Demand No. 24-**Tourism.**

That a Supplementary sum not exceeding **Rs. 43,10,88,000/-** for capital expenditure be granted to the Governor to defray charges that will come in the course of payment for the year ending 31st March, 2006 in respect of Demand No. 25-**Loans & Advances by State Government. (No member rose to speak)**

Mr. Speaker : Question is—

That a Supplementary sum not exceeding **Rs. 2,26,07,000/-** for revenue expenditure be granted to the Governor to defray charges that will come in the course of payment for the year ending 31st March, 2006 in respect of Demand No. 1-**Vidhan Sabha.**

That a Supplementary sum not exceeding **Rs. 3,35,78,000/-** for revenue expenditure be granted to the Governor to defray charges that will come in the course of payment for the year ending 31st March, 2006 in respect of Demand No. 2-**General Administration.**

The motion was carried.

Mr. Speaker : Question is—

That a Supplementary sum not exceeding **Rs. 1,000/-** for revenue expenditure be granted to the Governor to defray charges that will come in the course of payment for the year ending 31st March, 2006 in respect of Demand No. 6-**Finance.**

That a Supplementary sum not exceeding **Rs. 22,36,68,000/-** for revenue expenditure be granted to the Governor to defray charges that will come in the course of payment for the year ending 31st March, 2006 in respect of Demand No. 7-**Other Administrative Services.**

The motion was carried.

Mr. Speaker : Question is—

That a Supplementary sum not exceeding **Rs. 44,36,02,000/-** for revenue expenditure be granted to the Governor to defray charges that will come in the course of payment for the year ending 31st March, 2006 in respect of Demand No. 9-**Education.**

The motion was carried.

Mr. Speaker : Question is—

That a Supplementary sum not exceeding **Rs. 123,95,11,000/-** for revenue expenditure be granted to the Governor to defray charges that will come in the course of payment for the year ending 31st March, 2006 in respect of Demand No. 13-**Social Welfare & Rehabilitation.**

That a Supplementary sum not exceeding **Rs. 17,91,000/-** for revenue expenditure and **Rs. 25,67,05,000/-** for capital expenditure be granted to the Governor to defray charges that will come in the course of payment for the year ending 31st March, 2006 in respect of **Demand No. 14-Food & Supplies.**

That a Supplementary sum not exceeding **Rs. 136,04,00,000/-** for revenue expenditure and **Rs. 1,000/-** for capital expenditure be granted to the Governor to defray charges that will come in the course of payment for the year ending 31st March, 2006 in respect of Demand No. 15-**Irrigation.**

That a Supplementary sum not exceeding **Rs. 65,18,97,000/-** for revenue expenditure and **Rs. 2,01,70,000/-** for capital expenditure be granted to the Governor to defray charges that will come in the course of payment for the year ending 31st March, 2006 in respect of Demand No. 16-**Industries.**

The motion was carried.

Mr. Speaker : Question is—

That a Supplementary sum not exceeding **Rs. 130,94,60,000/-** for revenue expenditure be granted to the Governor to defray charges that will come in the course of payment for the year ending 31st March, 2006 in respect of Demand No. 21-**Community Development.**

That a Supplementary sum not exceeding **Rs. 10,53,86,000/-** for capital expenditure be granted to the Governor to defray charges that will come in the course of payment for the year ending 31st March, 2006 in respect of Demand No. 22-**Co-operation.**

That a Supplementary sum not exceedinmg **Rs. 27,46,48,000/-** for revenue expenditure and **Rs. 1,70,00,000/-** for

[Mr. Speaker]

capital expenditure be granted to the Governor to defray charges that will come in the course of payment for the year ending 31st March, 2006 in respect of Demand No. 23-**Transport.**

That a Supplementary sum not exceeding **Rs. 17,28,000/-** for revenue expenditure and **Rs. 3,00,00,000/-** for capital expenditure be granted to the Governor to defray charges that will come in the course of payment for the year ending 31st March, 2006 in respect of Demand No. 24-**Tourism.**

That a Supplementary sum not exceeding **Rs. 43,10,88,000/-** for capital expenditure be granted to the Governor to defray charges that will come in the course of payment for the year ending 31st March, 2006 in respect of Demand No. 25-**Loans & Advances by State Government.**

The motion was carried.

वर्ष 2006-07 के बजट अनुदानों की मांगों पर चर्चा तथा मतदान

Mr. Speaker : Hon'ble Members, now discussion and voting on Demand for Grants on Budget Estimates for the year 2006-2007 will take place.

As per the past practice and to save the time of the House, all the demands for grants on the order paper (1 to 25) will be deemed to have been read and moved. Hon'ble Members can discuss any demand but they are requested to indicate the demand number on which they want to raise discussion.

That a sum not exceeding **Rs. 13,61,20,000/- for revenue expenditure** be granted to the Governor to defray charges that will come in the course of payment for the year 2006-07 in respect of charges under Demand No. 1-**Vidhan Sabha.**

That a sum not exceeding **Rs. 178,04,29,000/- for revenue expenditure** be granted to the Governor to defray charges that will come in the course of payment for the year 2006-07 in respect of charges under Demand No. 2-**General Administration.**

That a sum not exceeding **Rs. 828,34,66,000/- for revenue expenditure** and **Rs. 30,00,00,000 for capital expenditure** be granted to the Governor to defray charges that will come in the course of payment for the year 2006-07 in respect of charges under Demand No. 3-**Home.**

That a sum not exceeding **Rs. 332,82,24,000/- for revenue expenditure** be granted to the Governor to defray charges that will come in the course of payment for the year 2006-07 in respect of charges under Demand No.4-**Revenue.**

That a sum not exceeding **Rs. 57,47,49,000/- for revenue**

expenditure be granted to the Governor to defray charges that will come in the course of payment for the year 2006-07 in respect of charges under Demand No.5-**Excise & Taxation.**

That a sum not exceeding **Rs. 1183,24,96,000/- for revenue expenditure** be granted to the Governor to defray charges that will come in the course of payment for the year 2006-07 in respect of charges under Demand No.6-**Finance.**

That a sum not exceeding **Rs. 38,95,64,000/- for revenue expenditure** and **Rs. 10,00,000 for capital expenditure** be granted to the Governor to defray charges that will come in the course of payment for the year 2006-07 in respect of charges under Demand No. 7-**Other Administrative Services.**

That a sum not exceeding **Rs. 470,40,00,000/- for revenue expenditure** and **Rs. 337,81,50,000 for capital expenditure** be granted to the Governor to defray charges that will come in the course of payment for the year 2006-07 in respect of charges under Demand No. 8-**Buildings & Roads.**

That a sum not exceeding **Rs. 2323,05,35,000/- for revenue expenditure** be granted to the Governor to defray charges that will come in the course of payment for the year 2006-07 in respect of charges under Demand No. 9-**Education.**

That a sum not exceeding **Rs. 926,04,48,000/- for revenue expenditure** and **Rs. 389,83,35,000 for capital expenditure** be granted to the Governor to defray charges that will come in the course of payment for the year 2006-07 in respect of charges under Demand No. 10-**Medical & Public Health.**

That a sum not exceeding **Rs. 168,87,48,000/- for revenue expenditure** be granted to the Governor to defray charges that will come in the course of payment for the year 2006-07 in respect of charges under Demand No. 11-**Urban Development.**

That a sum not exceeding **Rs. 125,96,20,000/- for revenue expenditure** be granted to the Governor to defray charges that will come in the course of payment for the year 2006-07 in respect of charges under Demand No. 12-**Labour & Employment.**

That a sum not exceeding **Rs. 799,85,87,000/- for revenue expenditure** and **Rs. 6,14,00,000 for capital expenditure** be granted to the Governor to defray charges that will come in the course of payment for the year 2006-07 in respect of charges under Demand No. 13-**Social Welfare & Rehabilitation.**

That a sum not exceeding **Rs. 31,64,17,000/- for revenue expenditure** and **Rs. 1278,57,00,000 for capital expenditure** be granted to the Governor to defray charges that will come in the

[Mr. Speaker]

course of payment for the year 2006-07 in respect of charges under Demand No. 14-**Food & Supplies.**

That a sum not exceeding **Rs. 2271,88,00,000/- for revenue expenditure** and **Rs. 771,00,00,000 for capital expenditure** be granted to the Governor to defray charges that will come in the course of payment for the year 2006-07 in respect of charges under Demand No. 15-**Irrigation.**

That a sum not exceeding **Rs. 83,12,73,000/- for revenue expenditure** and **Rs. 2,69,20,000 for capital expenditure** be granted to the Governor to defray charges that will come in the course of payment for the year 2006-07 in respect of charges under Demand No. 16-**Industries.**

That a sum not exceeding **Rs. 318,98,87,000/- for revenue expenditure** be granted to the Governor to defray charges that will come in the course of payment for the year 2006-07 in respect of charges under Demand No. 17- **Agriculture.**

That a sum not exceeding **Rs. 163,55,52,000/- for revenue expenditure** be granted to the Governor to defray charges that will come in the course of payment for the year 2006-07 in respect of charges under Demand No. 18-**Animal Husbandry.**

That a sum not exceeding **Rs. 14,74,53,000/- for revenue expenditure** be granted to the Governor to defray charges that will come in the course of payment for the year 2006-07 in respect of charges under Demand No. 19-**Fisheries.**

That a sum not exceeding **Rs. 149,02,25,000/- for revenue expenditure** be granted to the Governor to defray charges that will come in the course of payment for the year 2006-07 in respect of charges under Demand No. 20-**Forests.**

That a sum not exceeding **Rs. 548,77,35,000/- for revenue expenditure** be granted to the Governor to defray charges that will come in the course of payment for the year 2006-07 in respect of charges under Demand No. 21-**Community Development.**

That a sum not exceeding **Rs. 35,34,00,000/- for revenue expenditure** and **Rs. 13,18,00,000 for capital expenditure** be granted to the Governor to defray charges that will come in the course of payment for the year 2006-07 in respect of charges under Demand No. 22-**Co-operation.**

That a sum not exceeding **Rs. 704,06,95,000/- for revenue expenditure** and **Rs. 76,71,00,000/- for capital expenditure** be

granted to the Governor to defray charges that will come in the course of payment for the year 2006-07 in respect of charges under Demand No. 23-**Transport.**

That a sum not exceeding **Rs. 181,09,000/- for revenue expenditure** and **Rs. 8,00,00,000/- for capital expenditure** be granted to the Governor to defray charges that will come in the course of payment for the year 2006-07 in respect of charges under Demand No. 24-**Tourism.**

That a sum not exceeding **Rs. 185,73,80,000/- for capital expenditure** be granted to the Governor to defray charges that will come in the course of payment for the year 2006-07 in respect of Charges Under Demand No. 25-**Loans & Advances by State Government.**

श्री एस०एस० सुरजेवाला (कैथल) : अध्यक्ष महोदय, मैं डिमांड संख्या 2 और 3 को क्लब करके दोनों पर बोलना चाहता हूँ। डिमांड संख्या 2 जनरल एडमिनिस्ट्रेशन के बारे में है और डिमांड संख्या 3 लॉ एंड आर्डर के बारे में है। अध्यक्ष महोदय, चौटाला के राज में हरियाणा प्रदेश में अपराध चरम सीमा को छू गया था। उस समय बड़े अपराधी उनके घर और फार्म हाउस पर रहते थे जिसका नतीजा यह हुआ कि पिछले पांच साल के दौरान प्रदेश में अपराध की जड़ें बहुत नीचे तक चली गई थी। हमारी सरकार के बनने के बाद अपराधियों को बहुत भारी भय हो गया था और हमारी सरकार ने नामी अपराधियों के ऐनकाउंटर भी किए हैं। हमारी सरकार ने बदले की भावना का गुरेज करते हुए चौटाला के खिलाफ सी०बी०आई० को इन्क्वायरी दी है। सी०बी०आई० एक साल से इन्क्वायरी कर रही है उसका नतीजा अभी नहीं आया है लोग तो कार्यवाही तब मानते हैं जब अपराधी को सलाखों के पीछे धकेला जाता है। हमारी सरकार ने शुरू-शुरू में अपराधियों के खिलाफ बहुत अच्छी धर पकड़ शुरू की थी और अपराधी यहां से मूव कर गये थे लेकिन अब दोबारा से अपराधी सक्रिय हो गये हैं और अपराध करना शुरू कर दिया है। सभी को मालूम है कि एक गैंग अम्बाला में है, दो-तीन गैंग कैथल में हैं और पड़ोसी राज्यों में उनके साथी भी हैं। प्रदेश में बाकी जगहों पर भी इस तरह के गैंग होंगे जो अपराध करवाते हैं। इसलिए मैं सरकार को सुझाव देना चाहूँगा कि इन अपराधियों को और अपराध को प्रदेश से समाप्त करने के लिए एक स्पेशल टॉस्क फोर्स का गठन करने की जरूरत है जिसका हैड सीनियर पुलिस अधिकारी हो। इस फोर्स में उन सिलैक्टिड लोगों को रखा जाये जो अपराध को खत्म करने के लिए वचनबद्ध हैं। इस फोर्स के जवानों को मॉडर्न हथियार दिए जाएं और इनका आपरेशन एरिया पूरा प्रांत होना चाहिए। यह अपराधी और अपराध की जड़ें जहां कहीं पर भी मौजूद हैं उनको खत्म करने के लिए ऐसे इन्तजाम करने बहुत अनिवार्य हैं। जनरल ऐडमिनिस्ट्रेशन के बारे में मैं एक बार फिर कहना चाहता हूँ। पहले भी मैं पिछले सत्र में इसके बारे में हाउस में कह चुका हूं। हमारे हाउस में बहुत से वकील हैं। ऐसा मानते हैं कि सरकार का काफी रुपया इस तरीके से बचाया जा सकता है और सरकार के खर्च के अन्दर किफायत हो सकती है तथा गैर जरूरी खर्च खत्म हो सकते हैं। जैसे कि मैंने पहले कहा था कि बहुत सारे महकमें काफी भारी भरकम हैं और उनकी जरूरत नहीं है, उनकी बिल्कुल जरूरत नहीं है। सिवाय लोगों के कामों में रुकावट डालने के वे फेसिलिटेट नहीं कर रहे हैं। सरकार का जो पुराना ताना-बाना है उसको दोबारा से देखने के लिए किसी ऐडमिनिस्ट्रेटिव रिफोर्म कमीशन की जरूरत है जिसके द्वारा सरकार पर जो भी फालतू बोझ है उसे कम किया जा सके

[श्री एस०एस० सुरजेवाला]

इससे लोगों को भी बहुत राहत मिलेगी। सरकारी महकमे लोगों के कामों में बिना वजह अड़ंगे लगाते हैं जिसके कारण कोई भी काम करने में अनावश्यक देरी होती है। देरी के कारण भ्रष्टाचार होता है और लोगों को बहुत भारी परेशानी भी उससे होती है। अध्यक्ष महोदय, सच बात तो यह है कि आज के युग में जो बाबू है चाहे वह क्लर्क है, असिस्टैंट है या डिप्टी सुपरिन्टैंडैंट है वही मालिक है। वह फाईल पर जो लिख देगा सीनियर से सीनियर अधिकारी भी उसको बदल नहीं सकता तथा मिनिस्टर भी इसके लिए अपने आपको लाचार महसूस करते हैं। इसलिए इस पुराने ढांचे में आमूल-चूल परिवर्तन करने की जरूरत है ताकि आज की स्थिति के अनुसार एक नया ढांचा हमारे प्रांत को मिले जिससे प्रदेश की तरक्की हो, लोगों को ज्यादा सहूलियतें मिलें और सरकार की कारगुजारी ज्यादा प्रदर्शित हो, इसके लिए दोबारा से चिन्तन की जरूरत है। स्पीकर सर, अगर ऐसा सौल्यूशन होगा तो मैं समझता हूँ कि वह ज्यादा लाभकारी होगा। बातें तो मैंने और भी कई करनी थीं लेकिन समय नहीं है।

बैठक का समय बढ़ाना

Mr. Speaker : Is it the sense of the House that the time of the House be extended by 10 minutes.

Voices : Yes.

Mr. Speaker : Time of the House is extended by 10 minutes.

वर्ष 2006-07 के बजट अनुदानों की मांगों पर चर्चा तथा मतदान (पुनरारम्भ)

श्री एस०एस० सुरजेवाला : अध्यक्ष महोदय, एक बात मैं और कहना चाहता हूँ कि हरियाणा एग्रीकल्चर मार्केटिंग बोर्ड जैसे कई और भी अदायरे हैं। एग्रीकल्चर मार्केटिंग बोर्ड का जो ध्येय है वह उसको पूरा नहीं करता। एक तरह से उनकी जो बनतर है उनका कांस्टीच्यूशन है उसके मुताबिक मण्डियों से जो रुपया आता है वह किसान के लिए या मण्डियों के रख-रखाव के लिए या सड़कों के लिए यूज होता है खासतौर से किसानों के लिए यूज होता है। अध्यक्ष महोदय, एग्रीकल्चर मार्केटिंग बोर्ड का यह फंक्शन भी है कि वह रिसर्च और मार्किटिंग के बारे में किसानों को एडवांस में जानकारी उपलब्ध करवाए और यह सारे का सारा स्ट्रक्चर उनके पास होना चाहिए। लेकिन स्थिति यह है कि एक सरकार के बाद दूसरी सरकार इस रुपये को कभी बिजली बोर्ड को देती रही है कभी किसी और महकमे को दे देती है। वह रुपया खेती-बाड़ी के लिए, किसान के लिए, गांव के लिए या मंडियों के लिए पूरा खर्च नहीं हो रहा है। अध्यक्ष महोदय, मैं समझता हूँ कि चौधरी भूपेन्द्र सिंह हुड्डा की सरकार, जिन्होंने बहुत इन्कलाबी फैसले लिये हैं इस अदायरे के बारे में तथा इस जैसे दूसरे अदायरों के बारे में यह सुनिश्चित करेंगे कि वह रुपया जिस परपज के लिए इकट्ठा किया गया है उसी के ऊपर खर्च किया जाए। अध्यक्ष महोदय, आपका बहुत-बहुत धन्यवाद।

Mr. Speaker : Hon'ble Members, Now, the demands will be put to the Vote of the House.

Mr. Speaker : Question is—

That a sum not exceeding **Rs. 13,61,20,000/- for revenue**

expenditure be granted to the Governor to defray charges that will come in the course of payment for the year 2006-07 in respect of charges under Demand No. 1-**Vidhan Sabha.**

The motion was carried.

Mr. Speaker : Question is—

That a sum not exceeding **Rs. 178,04,29,000/- for revenue expenditure** be granted to the Governor to defray charges that will come in the course of payment for the year 2006-07 in respect of charges under Demand No. 2-**General Administration.**

The motion was carried.

Mr. Speaker : Question is—

That a sum not exceeding **Rs. 828,34,66,000/- for revenue expenditure** and **Rs. 30,00,00,000 for capital expenditure** be granted to the Governor to defray charges that will come in the course of payment for the year 2006-07 in respect of charges under Demand No. 3-**Home.**

The motion was carried.

Mr. Speaker : Question is—

That a sum not exceeding **Rs. 332,82,24,000/- for revenue expenditure** be granted to the Governor to defray charges that will come in the course of payment for the year 2006-07 in respect of charges under Demand No.4-**Revenue.**

The motion was carried.

Mr. Speaker : Question is—

That a sum not exceeding **Rs. 57,47,40,000/- for revenue expenditure** be granted to the Governor to defray charges that will come in the course of payment for the year 2006-07 in respect of charges under Demand No.5-**Excise & Taxation.**

The motion was carried.

Mr. Speaker : Question is—

That a sum not exceeding **Rs. 1183,24,96,000/- for revenue expenditure** be granted to the Governor to defray charges that will come in the course of payment for the year 2006-07 in respect of charges under Demand No.6-**Finance.**

The motion was carried.

Mr. Speaker : Question is—

That a sum not exceeding **Rs. 38,95,64,000/- for revenue**

[Mr. Speaker]

expenditure and **Rs. 10,00,000 for capital expenditure** be granted to the Governor to defray charges that will come in the course of payment for the year 2006-07 in respect of charges under Demand No. 7-**Other Administrative Services.**

The motion was carried.

Mr. Speaker : Question is—

That a sum not exceeding **Rs. 470,40,00,000/- for revenue expenditure** and **Rs. 337,81,50,000 for capital expenditure** granted to the Governor to defray charges that will come in the course of payment for the year 2006-07 in respect of charges under Demand No. 8-**Buildings & Roads.**

The motion was carried.

Mr. Speaker : Question is—

That a sum not exceeding **Rs. 2323,05,35,000/- for revenue expenditure** be granted to the Governor to defray charges that will come in the course of payment for the year 2006-07 in respect of charges under Demand No. 9-**Education.**

The motion was carried.

Mr. Speaker : Question is—

That a sum not exceeding **Rs. 926,04,48,000/- for revenue expenditure** and **Rs. 389,83,35,000 for capital expenditure** be granted to the Governor to defray charges that will come in the course of payment for the year 2006-07 in respect of charges under Demand No. 10-**Medical & Public Health.**

The motion was carried.

Mr. Speaker : Question is—

That a sum not exceeding **Rs. 168,87,48,000/- for revenue expenditure** be granted to the Governor to defray charges that will come in the course of payment for the year 2006-07 in respect of charges under Demand No. 11-**Urban Development.**

The motion was carried.

Mr. Speaker : Question is—

That a sum not exceeding **Rs. 125,96,20,000/- for revenue expenditure** be granted to the Governor to defray charges that will come in the course of payment for the year 2006-07 in respect of charges under Demand No. 12-**Labour & Employment.**

The motion was carried.

Mr. Speaker : Question is—

That a sum not exceedinng **Rs. 799,85,87,000/- for revenue expenditure** and **Rs. 6,14,00,000 for capital expenditure** be granted to the Governor to defray charges that will come in the course of payment for the year 2006-07 in respect of charges under Demand No. 13-**Social Welfare & Rehabilitation.**

The motion was carried.

Mr. Speaker : Question is—

That a sum not exceeding **Rs. 31,64,17,000/- for revenue expenditure** and **Rs. 1278,57,00,000 for capital expenditure** be granted to the Governor to defray charges that will come in the course of payment for the year 2006-07 in respect of charges under Demand No. 14-**Food & Supplies.**

The motion was carried.

Mr. Speaker : Question is—

That a sum not exceeding **Rs. 2271,88,00,000/- for revenue expenditure** and **Rs. 771,00,00,000 for capital expenditure** be granted to the Governor to defray charges that will come in the course of payment for the year 2006-07 in respect of charges under Demand No. 15-**Irrigation.**

The motion was carried.

Mr. Speaker : Question is—

That a sum not exceeding **Rs. 83,12,73,000/- for revenue expenditure** and **Rs. 2,69,20,000 for capital expenditure** be granted to the Governor to defray charges that will come in the course of payment for the year 2006-07 in respect of charges under Demand No. 16-**Industries.**

The motion was carried.

Mr. Speaker : Question is—

That a sum not exceeding **Rs. 318,98,87,000/- for revenue expenditure** be granted to the Governor to defray charges that will come in the course of payment for the year 2006-07 in respect of charges under Demand No. 17- **Agriculture.**

The motion was carried.

Mr. Speaker : Question is—

That a sum not exceeding **Rs. 163,55,52,000/- for revenue expenditure** be granted to the Governor to defray charges that will come in the course of payment for the year 2006-07 in respect of

charges under Demand No. 18-**Animal Husbandry.**

The motion was carried.

Mr. Speaker : Question is—

That a sum not exceeding **Rs. 14,74,53,000/- for revenue expenditure** be granted to the Governor to defray charges that will come in the course of payment for the year 2006-07 in respect of charges under Demand No. 19-**Fisheries.**

The motion was carried.

Mr. Speaker : Question is—

That a sum not exceeding **Rs. 149,02,25,000/- for revenue expenditure** be granted to the Governor to defray charges that will come in the course of payment for the year 2006-07 in respect of charges under Demand No. 20-**Forests.**

The motion was carried.

Mr. Speaker : Question is—

That a sum not exceeding **Rs. 548,77,35,000/- for revenue expenditure** be granted to the Governor to defray charges that will come in the course of payment for the year 2006-07 in respect of charges under Demand No. 21-**Community Development.**

The motion was carried.

Mr. Speaker : Question is—

That a sum not exceeding **Rs. 35,34,00,000/- for revenue expenditure and Rs. 13,18,00,000 for capital expenditure** be granted to the Governor to defray charges that will come in the course of payment for the year 2006-07 in respect of charges under Demand No. 22-**Co-operation.**

The motion was carried.

Mr. Speaker : Question is—

That a sum not exceeding **Rs. 704,06,95,000/- for revenue expenditure** and **Rs. 76,71,00,000/- for capital expenditure** be granted to the Governor to defray charges that will come in the course of payment for the year 2006-07 in respect of charges under Demand No. 23-**Transport.**

The motion was carried.

Mr. Speaker : Question is—

That a sum not exceeding **Rs. 181,09,000/- for revenue expenditure** and **Rs. 8,00,00,000/- for capital expenditure** be granted

to the Governor to defray charges that will come in the course of payment for the year 2006-07 in respect of charges under Demand No. 24-**Tourism.**

The motion was carried.

Mr. Speaker : Question is—

That a sum not exceeding **Rs. 185,73,80,000/-** for capital expenditure be granted to the Governor to defray charges that will come in the course of payment for the year 2006-07 in respect of charges under Demand No. 25-**Loans & Advances by State Government.**

The motion was carried.

Mr. Speaker : Now, the House stands adjourned till 9.30 a.m. tomorrow.

*14.35 Hrs. (The Sabha then*adjourned till 9.30 a.m. on Thursday, the 23rd March, 2006).

41312-H.V.S.-H.G.P., Chd.